





वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2017 को)

PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2017)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अध्यक्ष	**President**	श्री राम विलास पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	Shri Ram Vilas Paswan Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
उपाध्यक्ष	**Vice President**	श्री. सी.आर. चौधरी राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	Shri C. R. Choudhary Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
कार्यकारिणी समिति	**Chairman, Executive Committee**	श्रीमती अलका पंडा, महानिदेशक, बीआईएस	Smt. Alka Panda, Director General, BIS
महानिदेशक	**Director General**	श्रीमती अलका पंडा	Smt. Alka Panda
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	श्री सी.बी. सिंह	Shri C.B. Singh
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	श्रीमती सीमा शर्मा	Smt. Seema Sharma
उपमहानिदेशक (गतिविधि)	**Deputy Director General (Activity)**		
मानकीकरण	Standardization	श्री आर.के. मित्तल	Shri R. K. Mittal
परियोजना, आयोजना और समन्वय	Policy, Planning & Co-ordination	श्री आर. के. मित्तल	Shri R. K. Mittal
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री अनिल कुमार	Shri Anil Kumar
उपभोक्ता मामले	Consumer Affairs	श्री एच. एल. उपेन्द्र	Shri H. L. Upendar
प्रबंधन पद्धतियाँ	Management Systems	श्री वर्गिश जोय	Shri Varghese Joy
प्रमाणन	Certification	श्री ए. के. शर्मा	Shri A. K. Sharma
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री टी.बी. नारायणन	Shri T. B. Narayanan
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्री आर. के. बजाज	Shri R. K. Bajaj
वित्त	Finance	श्री एच. आर. आहूजा	Shri H. R. Ahuja
प्रशासन	Administration	कैप्टन अनुज कुमार	Captain Anuj Kumar
उप महानिदेशक (क्षेत्रीय)	**Deputy Director General (Region)**		
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री पी.एम. पंतलु	Shri P. M. Pantalu
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री विष्णु गुप्ता	Shri Vishnu Gupta
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री एम.वी.एस.डी. प्रसाद राव	Shri M. V. S. D. Prasada Rao
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री बी.वी.एस.एन. राव	Shri B. V. S. N. Rao
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री एम. सदाशिवम	Shri M. Sadasivam

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110 002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
बेबसाइट / website: www.bis.org.in

विषय सूची

विषय सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	सिंहावलोकन	1
2.	मानकीकरण	8
3.	प्रमाणन	25
4.	प्रयोगशाला सेवाएँ	28
5.	हॉलमार्किंग	30
6.	प्रबंध पद्धति प्रमाणन	32
7.	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ	35
8.	प्रशिक्षण सेवाएँ	41
9.	उपभोक्ता मामले	44
10.	प्रचार	47
11.	मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री	49
12.	हिंदी गतिविधियाँ	50
13.	योजनागत परियोजनाएँ	52
14.	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ	53
15.	परियोजना प्रबंधन एवं कार्य	56
16.	सतर्कता गतिविधियाँ	58
17.	मानव संसाधन विकास, प्रशासन एवं सामान्य सेवाएँ	60
18.	वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा	63

सिंहावलोकन

पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्था (आईएसआई) के कार्यों को हाथ में लेते हुए भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना बीआईएस अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में की गई । बीआईएस मानकीकरण गतिविधि से संबंधित विकास, वस्तुओं के मुहरांकन और गुणता प्रमाणन तथा उनसे संबंधित मुद्दों अथवा उससे प्रकारांतर से जुड़े मुद्दों के लिए उत्तरदायी है ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण के साथ विश्वभर के देशों ने प्रतिस्पर्धा की धार और आर्थिक लाभों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को स्थापित करना आरंभ किया है । मानक और अनुरूपता मूल्यांकन विश्व व्यापार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए देश ऐसी रणनीति अपना रहे हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के मंच पर ऐसी स्थिति में हों, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकें ।

मानकीकरण आर्थिक वृद्धि में सहायक है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है तथा प्रौद्योगिकी के विकास की गति को तेज करता है । यह सार्वजनिक नीतियों, जैसे स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण पर प्रभाव डालने के भी एक माध्यम के रूप में कार्य करता है । व्यवसाय में सभी की समानता सुनिश्चित करने और वस्तुओं की स्वीकार्यता के सामान्य मानदंड परिभाषित करने के माध्यम से मानक विनियामक फ्रेमवर्क में सहायता तथा व्यापार को सुकर बनाने के माध्यम के रूप में अधिकाधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं ।

मानकीकरण की अनुरूपता मूल्यांकन की मुख्य गतिविधि के माध्यम से बीआईएस सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणता की वस्तुएँ उपलब्ध कराने, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम को न्यूनतम करने, पर्यावरण का संरक्षण करने, निर्यात को बढ़ावा देने और आयात की स्थानापन्न वस्तुओं को उपलब्ध कराने, किस्मों की प्रचुरता नियंत्रित करने इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाता रहा है। बीआईएस के मानक और प्रमाणन योजनाएँ, उपभोक्ताओं और उद्योग को लाभ पहुँचाने के अलावा विभिन्न सार्वजनिक नीतियों, खास तौर से उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य निरापदता, पर्यावरण संरक्षण, भवन तथा निर्माण इत्यादि के क्षेत्र में सहायक हैं ।

वर्ष के दौरान बीआईएस ने विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अन्य सरकारी पहलों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया तथा व्यापार करने में आसानी आदि में अपनी मानकीकरण और प्रमाणन गतिविधियों के माध्यम से विशेष रूप से कार्य किया। बीआईएस ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा उन्नयन, मौसम में परिवर्तन, पर्यावरण तथा ऊर्जासंरक्षण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की स्थितियाँ तथा व्यापार को सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान देना जारी रखा । अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में बीआईएस ने प्रक्रियाओं को सरलतर और तीव्रतर बनाने की दिशा में कार्य किया । वर्ष के दौरान बीआईएस ने अपनी सभी गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति बनाए रखी।

सांविधिक ढांचा

बीआईएस 1986 के बीआईएस अधिनियम के ढांचे और इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के तहत कार्य करता है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 सामान्य सूचना के लिए सरकारी राजपत्र में 22 मार्च 2016 को प्रकाशित हुआ तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियम और विनियम बनाए जा रहे हैं । नए बीआईएस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- बीआईएस को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है ।
- मानकीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं के अलावा सेवाओं तथा पद्धतियों को शामिल करता है ।
- वैश्विक रीतियों के अनुरूप बहु–अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं की स्वीकृति देता है ।

- सरकार को बीआईएस के अलावा किसी अन्य एजेंसी को मानक के प्रति प्रमाणित करने तथा अनुरूपता के प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत करने में सक्षम बनाता है ।
- सरकार को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा कपटपूर्ण व्यापारिक रीतियों के परिहार के आधार पर उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत शामिल करने में सक्षम बनाता है ।
- सरकार को बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत शामिल करने में सक्षम बनाता है ।
- उपभोक्ता संरक्षण के उपाय उपलब्ध कराता है, जैसे मानक मुहर लगी गैर–अनुरूप वस्तुओं को वापस लेना, उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देना तथा अधिक कड़े दंड का प्रावधान करना ।

बीआईएस अधिदेश

गुणतापरक माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना बीआईएस का अधिदेश है।

बीआईएस के उद्देश्य

- मानकीकरण, मुहरांकन एवं सामान के गुणता प्रमाणन के क्रियाकलापों का सुसंगत विकास करना।
- उद्योगों की प्रगति एवं विकास के लिए मानकीकरण और गुणता नियंत्रण को गति देना और इसके साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना।

गतिविधियाँ

बीआईएस की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों में समूहबद्ध किया जा सकता है :

i) मानक निर्धारण

ii) प्रमाणन : उत्पाद (पंजीकरण सहित), हॉलमार्किंग तथा प्रबंध पद्धति

iii) प्रयोगशाला सेवाएँ

iv) उपभोक्ता मामले

v) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

vi) सूचना प्रोद्यौगिकी सेवाएँ

vii) प्रशिक्षण सेवाएँ

viii) भारतीय मानक एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ix) प्रचार

x) सतर्कता

xi) परियोजना प्रबंधन एवं कार्य

xii) प्रशासन, वित्त एवं लेखा

संगठनात्मक नेटवर्क

बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (पूर्व), चेन्नई (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम), चंडीगढ़ (उत्तर) और दिल्ली (मध्य) में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन 28 विभिन्न स्थानों पर 33 शाखा कार्यालय स्थित हैं। ये कार्यालय हैं अहमदाबाद, बंगलूरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बत्तूर, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, परवाणु, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट और विशाखापत्तनम। ये शाखा कार्यालय क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी संपर्क का काम करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जम्मू में 2016–17 में बीआईएस का शाखा कार्यालय खोला गया।

प्रमाणन गतिविधि में नमूने के परीक्षण की आवश्यताओं को पूरा करने के लिए बीआईएस की पूरे देश में 8 प्रयोगशालाएँ हैं, अर्थात् केन्द्रीय प्रयोगशाला (सीएल), साहिबाबाद, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (डब्ल्यूआरओएल), मुम्बई, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (एनआरओएल), मोहाली, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (ईआरओएल), कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (एसआरओएल), चेन्नई, बंगलौर शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (बीएनबीओएल), बंगलौर, पटना शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (पीएनबीओएल), पटना, गुवाहाटी शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (जीबीओएल), गुवाहाटी ।

शासन

शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति नीतिगत निर्देश और रणनीति संबंधी निर्देश देती हैं और संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के विकास एवं कार्यान्वयन को देखती हैं। शासी परिषद् में 25 सदस्य होते हैं, जिसमें केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, उद्योग, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थाओं, उपभोक्ता संगठनों तथा व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ब्यूरो के अध्यक्ष हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ब्यूरो के उपाध्यक्ष हैं ।

शासी निकाय की 26वीं बैठक मसूरी में 7 अप्रैल 2016 को हुई। कार्यकारिणी समिति की 4 बैठकें 5 मई 2016, 16 जून 2016, 06 सितम्बर 2016 तथा 24 जनवरी 2017 को आयोजित की गईं ।



बीआईएस के शासी निकाय की मसूरी में 26वीं बैठक

2016–17 के दौरान बीआईएस की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएँ

- वर्ष के दौरान विभिन्न–विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए 722 भारतीय मानक निर्धारित किए गए । 31 मार्च 2017 को 19 025 मानक लागू थे । इस अवधि के दौरान निर्धारित कुछ महत्त्वपूर्ण मानकों में शामिल थे –भू-संशलिष्ट बिना बुने जियो बैग, तकनीकी वस्त्रादि (संरक्षी वस्त्रादि तथा चिकित्सकीय वस्त्रादि), वर्धित इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड ले–आउट, मोबाइल हैंडसेटों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट, परिवहनीय दोबारा भरे जा सकने वाले पूर्णतः आवृत्त मिश्रित एलपीजी सिलिंडर, हाईवोल्टेज स्विच गियर, उत्पाद मानकों में पर्यावरण के मुद्दों संबंधी मार्गदर्शिका तथा हाइड्रोजन ईंधन के लिए प्रोटोन विनिमय मैम्ब्रेन (पीईएम), ईंधन सैल आदि कुछ महत्त्वपूर्ण मानक हैं।

- देशभर में भवन निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराने वाली व्यापक भवन निर्माण संहिता, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) मार्च 2017 में प्रकाशित की गई। यह संहिता भवन निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों, जैसे लोक निर्माण विभाग, अन्य सरकारी निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय अथवा निजी निर्माण एजेंसियों, के लिए यह भवन निर्माण संहिता अपनाने के लिए आदर्श संहिता का कार्य करेगी। किए गए अन्य परिवर्तनों के अलावा पुनरीक्षित एनबीसी की मुख्य विशेषताओं में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा समक्ष दी गई चुनौतियों के प्रति हमारी प्रक्रिया को सघन बनाना है ।

- मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और सूचना वितरित करने और उनके कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए बीआईएस अपने स्टेकहोल्डरों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है । इस प्रकार के आयोजित किए गए कई कार्यक्रमों में उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :

  – इस्पात तथा इस्पात में नई पहल तथा इस्पात निर्माण में अद्यतन प्रवृत्तियाँ

  – पहाड़ी क्षेत्र के विकास संबंधी इंजीनियरी का महत्त्व, चट्टान मैकेनिक्स

  – भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016 का सिंहावलोकन तथा अग्नि और जीवन सुरक्षा पर गहन दृष्टि

  – तकनीकी वस्त्रादि में ईयू नियामक फ्रेमवर्क

  – विश्व मानक दिवस समारोह

- राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता रहा है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण समितियाँ, जो हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, में भारत की आवाज रखी जा सके। बीआईएस का यह प्रयास रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हों तथा बीआईएस इन विशेषज्ञों का इन समितियों में भाग लेना भी सुगम बनाता है। बीआईएस ने वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण समितियों में अपना जुड़ाव और सहभागिता बढ़ायी । एक नीति के रूप में बीआईएस का यह प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव भारतीय मानकों को आईएसओ और आईईसी के साथ सुमेलित किया जाए । सुमेलित करते हुए राष्ट्रीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाता है । वर्ष के दौरान आईएसओ/आईईसी मानक के साथ लगभग 5 151 भारतीय मानक अंर्तराष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किए गए ।

  राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के विकास परसामूहिक रूप से प्रभाव डालने और एक–दूसरे के अनुभव से लाभ प्राप्त करने के लिए देश मानकीकरण और अनुरूपता के क्षेत्रों में एक–दूसरे के साथ सहयोग करते हैं । वर्ष के दौरान बीआईएस ने अन्य देशों के संगत राष्ट्रीय मानक निकायों से सहयोग के लिए करार किया । बीआईएस और केन्या ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्डस (केईबीएस) तथा बीआईएस और नेशनल स्टैण्डर्डाइजेशन एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया (बीएसएन) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

■ अनुरूपता मूल्यांकन बीआईएस की एक प्रमुख गतिविधि है। इसमें बीआईएस प्रमाणन उत्पाद मुहर योजना (आईएसआई मुहर) में विदेशी आयातकों के लिए प्रमाणन योजना तथा अनिवार्य पंजीकरण योजना स्वर्ण तथा चॉदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रबंध पद्धति प्रमाणन तथा प्रमाणन के प्रयोजन के लिए उत्पाद के नमूनों के परीक्षण के माध्यम से उत्पाद प्रमाणन शामिल है । व्यवसाय आसान बनाने की सरकारी नीति के अनुरूप बीआईएस ने प्रमाणन की सरलीकृत प्रक्रिया और अपनी पंजीकरण योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ की ।

- वर्ष के दौरान, 4 098 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2017 को प्रचालित उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या 33 230 थी।
- वर्ष के दौरान उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 17 उत्पादों को पहली बार शामिल किया गया। ये उत्पाद इस प्रकार हैं :
  - रेत भरने के लिए उच्च घनत्व पॉलिइथाइलिन (एचडीपीई)/पॉलिप्रॉपेलिन (पीपी) के बने बोरे
  - श्वसन संरक्षी उपस्करों में प्रयुक्त पार्टिकल फिल्टर
  - अग्निरोधी द्रवचालित तरल, भाग 2 विपरीत पायस (वाटर–इन–ऑयल) टाइप
  - कार्बन डाइसल्फाइड, तकनीकी
  - लोह से पुष्ट नमक (दुगुना पुष्ट नमक) –खाद्यग्रेड
  - अतप्त हैडिंग/अतप्त बहिर्वेधन अनुप्रयोगों के लिए इस्पात, भाग 1 पिटवाँ कार्बन तथा अल्पमिश्रण इस्पात
  - पादप संरक्षण तथा वेक्टर नियंत्रण के लिए उपस्कर–फॉगिंग मशीन, भाग 1 पल्स–जेट– टाइप तापीय फॉगिंग मशीन
  - कंक्रीट खडंजा और निर्माण (गैर–बहिर्वेधन तथा प्रत्यास्थ टाइप) में विस्तार जोड़ों के लिए पॉलिमर से बने पूर्वनिर्मित फिलर
  - खिड़की के फ्रेमों में उपयोग के लिए पुट्टी
  - मोटर वाहन प्रयोजनों के लिए इस्पात की ट्यूब
  - बर्तनों और रसोई के उपकरणों के लिए अल्प निकिल ओसटेनिटिक स्टेनलैस इस्पात स्टील की चद्दरें और पत्तियाँ
  - 50 किलो/25 किलो चीनी पैक करने के लिए उच्च घनत्व पॉलिइथाइलिन (एचडीपीई)/ पॉलिप्रॉपेलिन (पीपी) के बने बोरे
  - भुनी मूंगफली (पीनट) की गिरी
  - मिश्रित सीमेंट
  - डनेज पैलेट – वैयर हाउसिंग
  - सुपर सल्फेटित सीमेंट की विशिष्टि
  - वाहक पट्टे – भूमिगत खदानों और ऐसे ही अन्य खतरनाक अनुप्रयोगों के लिए अग्निरोधी वाहक पट्टे

- वर्ष 2016–17 के दौरान विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) के अंतर्गत 190 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे 83 भारतीय मानकों के लिए दिए जाने वाले प्रचालनाधीन लाइसेंसों की कुल संख्या 671 हो गई।

- भारत सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत 30 इलैक्ट्रॉनिकी और आईटी वस्तुओं को अधिसूचित किया है। 31 मार्च 2017 को विश्वभर में स्थित निर्माताओं को कुल 8 313 पंजीकरण प्रदान किए गए ।

- बीआईएस प्रयोगशालाओं में 21 467 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें चैन्नई की स्वर्ण रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित 2 965 नमूने शामिल हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएँ (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षायें) आदेश 2012 के तहत आईटी उत्पादों के परीक्षण के लिए शामिल 33 प्रयोगशालाओं सहित, बीआईएस द्वारा मार्च 2017 तक मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं की संख्या 179 थीं।

- 31 मार्च 2017 तक स्वर्ण एवं रजत हॉलमार्किंग के लिए कुल स्वर्ण एवं रजत के लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 18 112 और 1 494 थी। बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रचालनाधीन एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 454 थी। वर्ष के दौरान लगभग 3.16 करोड़ स्वर्ण और रजत आभूषणों/शिल्प वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया।

- बीआईएस ने जून 2016 में चिकित्सा युक्तिप्रबंध पद्धति (एमडीएमसी) प्रमाणन योजना लांच की ।

- वर्ष के दौरान 867 गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 203 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन (ईएमएस) लाइसेंस, 102 व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 14 खाद्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन लाइसेंस, 101 सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन लाइसेंस और 20 ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस), 02 जोखिम विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) स्टैंड एलोन लाइसेंस, 35 क्यूएमएस के साथ एकीकृत एचएसीसीपी लाइसेंस तथा एक चिकित्सा युक्ति प्रबंध पद्धति (एमडीएमसी) लाइसेंस 31 मार्च 2017 तक प्रचालन के अंतर्गत थे ।

- वर्ष के दौरान अन्य उपलब्धियाँ :

  - वर्ष के दौरान मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (निट्स) ने प्रबंध पद्धति पर 13वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 49वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति (एलक्यूएमएस) पर सातवें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न विकासशील देशों के 98 सहभागियों ने हिस्सा लिया ।

  - वर्ष के दौरान, 163 उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, 62 औद्योगिक जागरुकता कार्यक्रम और मानकों के शैक्षिक उपयोग के लिए 39 कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस अवधि में 57 शिकायतें मिलीं और 91 शिकायतों का निपटान किया गया ।

  - बीआईएस ने मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली कंपनियों के विरुद्ध पूरे भारत में 114 तलाशी एवं जब्तियाँ कीं और ऐसे उत्पाद जब्त किए गए। अदालत में दोषियों के विरुद्ध समय से अभियोजन दायर करने के प्रयास किये गये।

  - हरित पहल के रूप में बीआईएस मुख्यालय ने बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में संस्थापित 100 किवॉ बीआईएस, एसआरओ प्रयोगशाला, चेन्नई (100 किवॉ), डब्ल्यूआरओ, मुम्बई (40 किवॉ) तथा एनआईटीएस, नोएडा (50 किवॉ) के वर्तमान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयत्रों के अलावा बीआईएस शाखा कार्यालय, हैदराबाद (40 किवॉ), बीआईएस पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता (24.4 किवॉ) तथा बीआईएस पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता (40 किवॉ) में संस्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को पुनः संस्थापित किया गया तथा बीआईएस ने बीआईएस मुख्यालय, एनआईटीएस, नोएडा तथा बीआईएस शाखा कार्यालय, हैदराबाद में नेटमीट्रिंग भी कार्यान्वित की है।

- वर्ष के दौरान, 2015–16 भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची में शामिल 13 वैज्ञानिकों ने सीधी भर्ती के माध्यम से बीआईएस में वैज्ञानिक 'बी' के रूप में कार्यग्रहण किया। 31 मार्च 2017 तक बीआईएस के रोल पर कुल 1507 कर्मचारी थे ।
- बीआईएस में 31 अक्तूबर 2016 से 06 नवम्बर 2016 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया ।
- बीआईएस के मुख्यालय में 01 सितम्बर 2016 से 14 सितम्बर 2016 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान हिंदी की 06 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और सफल प्रतिभागियों को 27 पुरस्कार दिए गए।

■ भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति बनाए रखी। ब्यूरो ने लगभग रु. 456.93 करोड़ की कुल आय (निवेश पर ब्याज छोड़कर) अर्जित की और पिछले वर्ष की कुल आय रु. 390.83 लाख की तुलना में 2016–17 में आय में लगभग 16.8 % की वृद्धि हुई। ब्यूरो लगातार अट्ठाइसवें वर्ष भी अपने व्यय तथा अन्य देयताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर रहा ।

महानिदेशक

मानकीकरण

मानक निर्धारण

बीआईएस का मुख्य लक्ष्य स्वैच्छिकता के आधार पर सहमति से बने मानकों को सुगम बनाना और उनकी एक निष्ठा सुनिश्चित करने के माध्यम से भारतीय व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और जीवन की गुणता सुधारना है। सामान्यतः इस गतिविधि में मानक बनाना, जारी करना और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शामिल है। मानक सर्वदा आपूर्तिकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान–प्रदान से निकट रूप से जुड़े होते हैं । बीआईएस ने मानकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से दिखने वाले और वास्तविक लाभ दिए हैं– निरापद, विश्वसनीय और गुणता वाली वस्तुएँ उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों को न्यूनतम करना, आयात और निर्यात की स्थानापन्न वस्तुओं को बढ़ावा देना, किस्मों की विविधता पर नियंत्रण करना इत्यादि ।

बीआईएस द्वारा मानकों के विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अच्छी मानकीकरण रीतियों के अनुरूप है और मानकों को तैयार करने, अपनाने, उनके अनुप्रयोग के लिए डब्ल्यूटीओ–टीबीटी की अच्छी रीति संहिता के अनुपालन में है । राष्ट्रीय मानकों के विकास में बीआईएस सभी स्टेकहोल्डरों को साथ लाने और आम करारों की दिशा में काम करने के लिए एक तटस्थ प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है । बीआईएस वर्तमान में 325 विषय समितियों को मंच उपलब्ध कराता है, जो संगठित उपभोक्ता और उपभोक्ता निकायों, नियामकों व अन्य सरकारी निकायों, उद्योग, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, परीक्षण संगठनों और विशेषज्ञों जैसे विभिन्न संबंधितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समितियों में बीआईएस के संबद्ध अधिकारी भी होते हैं। ये समितियाँ सटेकहोल्डरों के परामर्श से स्वैच्छिक राष्ट्रीय मानकों को सहमति के आधार पर बनाने के लिए एक–दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं ।

बीआईएस की उपयुक्त विषय समिति मानक निर्धारण के लिये प्रस्तावों के आधार पर विषय लेती है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासकों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, ब्यूरो के सदस्यों और उसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग परिषद् के अनुमोदन से दिया जा सकता है।

मानक मसौदों एवं संबंधित तकनीकी प्रलेखों पर विस्तार से विचार करने के लिए 2016–17 के दौरान तकनीकी समितियों की कुल 286 बैठकें हुई। बीआईएस की नीति उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक बनाने और अप्रचलित मानकों को वापिस लेने की है। 2016–17 के दौरान 722 मानक (371 नए और 351 संशोधित) मानकों का निर्धारण किया गया। 31 मार्च 2017 को कुल 19 025 मानक लागू थे।

मानकों की समीक्षा

यथा आवश्यक होने पर भारतीय मानकों की समीक्षा की जाती है, लेकिन पांच वर्ष में कम से कम एक बार यह निश्चित किया जाता है कि ये मानक अभी भी प्रासंगिक हैं और इन्हें पुनर्पुष्ट, पुनरीक्षण, संशोधन जारी करने, अप्रचलित घोषित करने अथवा वापिस लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

सुमेलन

बाजार के वर्तमान परिदृश्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। विश्व बाजार में बने रहने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय मानकों को यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए । इसके अतिरिक्त, भारत व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर डब्लूटीओ करार पर हस्ताक्षरकर्ता है। करार के अनुसार, डब्लूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करना आवश्यक हैं। राष्ट्रीय मानक तकनीकी या भौगोलिक विचारों के आधार पर

अंर्तराष्ट्रीय मानकों से भटक सकते हैं बीआईएस जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मानक विद्यमान हैं, उन्हें मानकों को बनाने का आधार मानता है। वर्ष के दौरान 109 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया। अब तक कुल 5 151 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जा चुका है ।

2016–17 के दौरान निर्धारित महत्त्वपूर्ण मानक

आईएस 16653 : 2017 भू–कृत्रिम – तटीय और जलमार्ग संरक्षण के लिए सुई छिद्रित बिना बुने हुए जीयो बैग – यह मानक सुई छिद्रित बिना बुने पॉलिस्टिर (पीईएस) अथवा पॉलिप्रॉपेलीन (पीपी) के तीन प्रकार के जीयो बैगों की विशिष्ट अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है जो तटीय और जलमार्ग संरक्षण अनुप्रयोगों जैसे रिवर्टमेंटय रिवर ट्रेनिंग, पुलिनरोध तथा कृत्रिम जल शैल का निर्माण, इत्यादि के लिए हैं, ताकि मृदाक्षरण न्यूनतम किया जा सके और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। यह प्रौद्योगिकी सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, बजरी, कठोर चट्टानों इत्यादि का प्रयोग करके पारम्परिक संरक्षण कार्य की तुलना में आसानी से संस्थापन, लागत प्रभाविता, उनकी तकनीकी दक्षता तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूलता के कारण विश्वभर में लोकप्रिय हो रही है ।

आईएस 16654 : 2017 भू–कृत्रिम – तटीय और जलमार्ग संरक्षण के लिए मल्टी फिलामेंट बिना बुने हुए जीयो बैग – यह मानक मल्टी फिलामेंट बिना बुने पॉलिस्टिर (पीईएस) अथवा पॉलिप्रॉपेलीन (पीपी) के तीन प्रकार के जीयो बैगों की विशिष्ट अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है जो तटीय और जलमार्ग संरक्षण अनुप्रयोगों जैसे रिवर्टमेंट, रिवर ट्रेनिंग, पुलिनरोध तथा कृत्रिम जल शैल का निर्माण, इत्यादि के लिए हैं, ताकि मृदाक्षरण न्यूनतम किया जा सके और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। यह मानक 200 और 300 जीएसएम के दो प्रकार के जीयो बैग निर्दिष्ट करता है।

आईएस 16655 : 2017 वस्त्रादि – वेल्डिंग तथा संबद्ध प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़े – यह मानक सुरक्षात्मक कपड़ों के लिए न्यूनतम और आधारभूत सुरक्षा अपेक्षाएँ और परीक्षण पद्धतियाँ निर्दिष्ट करता है जिनमें हुड, एप्रेन, स्लिप, तथा गेटर शामिल हैं । ये सिर (हुड) तथा पैरों (गेटर) सहित पहनने वाले के शरीर को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनको तुलनीय खतरे सहित वेल्डिंग तथा संबद्ध प्रक्रियाओं के दौरान पहना जाना अपेक्षित है।

आईएस 16660 : 2017 चिकित्सा वस्त्र– बिना बुने हुए मरहम पट्टी के रोल – यह मानक चिकित्सकीय उपयोग के लिए बिना बुने हुए मरहम पट्टी के रोल की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है । यह मानक बिना बुने हुए मरहम पट्टी के रोल के निर्माण, कारीगरी और परिसज्जा के बारे में सूचना देता है और प्रतिवर्गमीटर प्रभार, अवशोषण, जलधारण करने की क्षमता, जल में घुलनशील पदार्थ, साइटोक्सिसिटी इत्यादि की कार्यकारिता अपेक्षाएँ भी इसमें शामिल की गई हैं।

आईएस 16585 : 2016 चुम्बकीय सामाग्रियाँ– वैयक्तिक सामग्रियों की विशिष्टि – अर्थप्रक्रमित अवस्था में दिए गर्म लोहा आधारित अमोर्फोर्स स्ट्रिप – यह मानक 0.025 मिमी की अभिहित मोटाई के बिना अंतिम ताप उपचार वाले अर्थप्रक्रमित अवस्था में आपूर्ति किए गए लोहा आधारित अमोर्फोर्स स्ट्रिपके ग्रेड परिभाषित करता है। निरीक्षण की क्रियाविधि बताने के साथ–साथ यह मानक सामान्य अपेक्षाएँ, चुम्बकीय गुणधर्म, जियोमिट्रिक लक्षण छूटें तथा प्रौद्योगिकीय लक्षण उपलब्ध कराता है। यह मानक कॉयलों में आपूर्ति की गई तेजी से घनीभूत (सोलिडीफाइड) गर्म लोहा आधारित अमोर्फोर्स स्ट्रिपों और ट्रांसफार्मर के चुम्बकीय परिपथ के निर्माण के लिए वांछित है ।

आईएस 16586 : 2016 – चुम्बकीय सामग्रियाँ–सिंगल शीट टेस्टर के माध्यम से लौहाआधारित अमोर्फोस्ट्रिप पटिट्यों के चुम्बकीय गुणधर्मों को मापने की पद्धतियाँ – इस मानक में 400 हर्ट्स तक की आवृत्तियों पर लौहा आधारित आकार रहित पटिट्यों पर ए.सी.चुम्बकीय गुणधर्मों के मापन की पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस भाग का प्रयोजन एकल शीट टेस्टर के माध्यम से लौहा आधारित अनाकार रहित पटिट्यों के चुम्बकीय गुणधर्मों के मापन के सामान्य सिद्धांत और तकनीकी विवरण को परिभाषित करना है।

आईएस 16350 : 2016 – परिवर्धित इनस्क्रिप्ट कुंजीपटल अभिन्यास – इस मानक में भारतीय भाषाओं को निरूपित करने के लिए कैरेक्टर कोड–सेट और डिजिटल मीडियम – जैसे कम्पयूटर और मोबाइल फोन पर अंर्तवस्तु विषय, पर उनकी स्क्रिप्ट निर्दिष्ट की गई है। इस मानक में भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करते हुए 11 भारतीय लिपियों के कोड चार्ट, कैरेक्टर और कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं जो आईएसओ/आईईसी 10646 – 'यूनिवर्सल कोडिड कैरेक्टर सेट' के सदृश हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी ई–गवर्नेंस प्रणालियों के लिए इस मानक के प्रयोग को अधिसूचित किया है।

आईएस 16333 (भाग 3) : 2016 – मोबाइल फोन हैंडसेट – मोबाइल हैंडसेट के लिए भारतीय भाषा की सुविधा – विशिष्ट अपेक्षाएँ भाग 3 का – इस मानक (भाग 3) में अंग्रेजी, हिंदी और कम से कम एक अतिरिक्त भारतीय भाषा में और उसके साथ भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में संदेश पढ़ने की सुविधा के साथ टैक्स्ट को डालने के लिए मोबाइल हैंडसेट की अपेक्षाएँ दी गई हैं। देश में सभी हिस्सों के लोग बड़ी संख्या में मोबाइल फोन हैंडसेट का उपयोग करते हैं और उपभोक्ता हैं। एसएमएस संदेश और अलर्ट जानकारी के आदान–प्रदान का एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुके हैं जिनमें मौसम और किसानों को मिलने वाले मूल्य संबंधी जानकारी तथा अन्य ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विषय डिजिटल भारत का हिस्सा हैं। भारत सरकार ने बीआईएस की अनिवार्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत इस मानक के कार्यान्वयन का आदेश दिया है।

आईएस 16377 : 2017 – तुल्यकालिक बेल्ट ड्राइव – मोटर वाहन घिरनी – इस मानक में तुल्यकालिक सिराहीन बेल्ट ड्राइव के स्वचल प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली तुल्यकालिक घिरनियों के अभिलक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं। इन अभिलक्षणों में दांते के आयाम और छूट तथा घिरनी छूट एवं गुणता विशिष्टियाँ दी गई हैं।

आईएस 16558 : 2017 – बेल्ट ड्राइव – स्वचल उद्योगों और अनुवर्ती घिरनियों हेतु वी-बेल्ट– आयाम – इस अंतर्राष्ट्रीय मानक में स्वचल उद्योग में आंतरिक दहन इंजनों के ड्राइविंग सहायकांगों के लिए प्रयुक्त बेल्टों हेतु और वी-बेल्ट के लिए घिरनियों की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं।

आईएस 16530 (भाग 1) : 2016 – औद्योगिक आटोमेशन सिस्टम एवं एकीकरण – अंतर्कार्यकारी हेतु विनिर्माण साफ्टवेयर : भाग 1 क्षमता की रूपरेखा – इस मानक में विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त साफ्टवेयर उत्पादों के सेट की अंतर्संचालनीयता हेतु ढांचा तथा विनिर्माण अनुप्रयोग में इसके समेकन की सुसाध्यता निर्दिष्ट की गई है। इस ढांचे में सूचना के आदान–प्रदान का मॉडल, साफ्टवेयर वस्तु मॉडल, इंटरफेस, सेवाएँ, प्रोटोकॉल, क्षमता रूपरेखा और परीक्षण पद्धतियों की अनुरूपता है।

आईएस 16530 (भाग 2) : 2016 – औद्योगिक आटोमेशन सिस्टम एवं एकीकरण – अंतर्कार्यकारी हेतु विनिर्माण साफ्टवेयर क्षमता की रूपरेखा : भाग 2 रूपरेखा पद्धति – इस मानक में साफ्टवेयर सक्षमता विनिर्माण के तंत्र निर्माण की कार्य–प्रणाली और विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त साफ्टवेयर उत्पादों में अनुप्रयोग को निर्दिष्ट किया गया है।

आईएस 16530 (भाग 3) : 2016 – औद्योगिक आटोमेशन सिस्टम एवं एकीकरण – अंतर्कार्यकारी के लिए विनिर्माण साफ्टवेयर क्षमता की रूपरेखा : भाग 3 इंटरफेस सेवाएँ प्रोटोकॉल और क्षमता टैम्पलेट्स – इस मानक में क्षमता रूपरेखा तक पहुँच एवं संपादन में प्रयुक्त इंटरफेस सेवाओं और प्रोटोकॉल तथा आईएस 16530 (भाग 2) के खंड 5 में परिभाषित क्षमता रूपरेखा में प्रयुक्त संबंधित टैम्पलेट की अपेक्षाएँ दी गई हैं।

आईएस 16530 (भाग 4) : 2016 – औद्योगिक आटोमेशन सिस्टम एवं एकीकरण– अंतर्कार्यकारी के लिए विनिर्माण साफ्टवेयर क्षमता की रूपरेखा : भाग 4 अनुरूपता – परीक्षण तरीके, मापदंड और रिपोर्टें – मानक में कार्यान्वयन अर्थात् आईएस 16530 के अन्य भागों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं से यूनिट अंडर परीक्षण में अनुरूपता मूल्यांकन एवं उसके स्तर को घोषित करने में प्रयुक्त परीक्षण पद्धति, संबद्ध परीक्षण मानदंड और ब्यौरे का प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है। इसमें मूल्यांकन के प्रकार का आकलन करने के लिए निर्माता या सप्लायर, (प्रथम पक्ष) प्रयोक्ता अथवा क्रेता (द्वितीय पक्ष), अथवा स्वतंत्र निकाय (तृतीय पक्ष) की सहायता करने के लिए अभीष्ट परिभाषाएँ शामिल हैं।

आईएस 16537 : 2016/आईएसओ 21049 : 2004 – केन्द्रापसारक और रोटरी पम्प के लिए दस्ता सीलसिस्टम पंप – इस मानक में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रसायन उद्योग में प्रयुक्त अपकेन्द्री और घूर्णी पम्पों की सीलिंग प्रणालियों के लिए अपेक्षाएँ और अनुंशसाएँ दी गई हैं। यह मुख्य रूप से उन जोखिमपूर्ण, ज्वलनीय और/अथवा विषैली सेवाओं के लिए प्रयोग में आते हैं जहाँ उपस्कर की उपलब्धता को बेहतर करने और परिवेश में उत्सर्जन एवं जीवनचक्र सीलिंग की लागत, दोनों में कमी के लिए अधिक स्तरीय निर्भरता की आवश्यकता होती है।

आईएस 16485 : 2016/आईएसओ 16852 : 2008 – फ्लेमअरेस्टर – उपयोग के लिए कार्यकारिता अपेक्षाएँ, परीक्षण पद्धतियाँ और सीमाएँ – इस मानक में विस्फोटीय गैस–वायु और वाष्प वायु मिश्रकों की उपस्थिति में फ्लेम को फैलने से रोकने वाले फ्लेम अरेस्टर की अपेक्षाएँ दी गई हैं। इसमें उपयोग हेतु वर्गीकरण, आधारभूत निर्माण और विवरण के एकरूप सिद्धांत हैं जिसमें फ्लेम अरेस्टर का चिन्हांकन और सुरक्षा अपेक्षाओं की जांच की परीक्षण पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं तथा प्रयोग करने की सुरक्षित सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

आईएस 16646 : 2017 – द्रवीय पेट्रौलियम गैस (एलपीजी) के लिए परिवहनीय पुनः भरे जाने वाले रेप्ड संमिश्र सिलिंडर – यह मानक पूर्ण आवरित फाइबर प्रबलित अधात्विक भार रहित शेयरिंग लाइनर वाले संमिश्र सिलिंडरों (टाइप 4 सिलिंडर) से संबंधित है जो कि परिवेशीय तापमान में द्रवित पैट्रोलियम गैसों के भंडारण और परिवहन के लिए होते हैं तथा जिसका परीक्षण दाब 30 बार हो और अभिहित क्षमता 0.5 लिटर तक हो और जो 150 लिटर जल क्षमता वाले हों। इस मानक में सामग्री, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, निरीक्षण, परीक्षण और इन सिलिंडरों पर मुहरांकन की न्यूनतम अपेक्षाएँ दी गई हैं।

आईएस 16542 : 2016 – समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड नलिका सौर संग्रहक हेतु भंडारण पानी की टंकी – इस मानक में समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड नलिकाओं सौर संग्रहक के लिए प्रयुक्त होने वाली 500 लिटर तक की क्षमता वाली सीधे अंतर्विष्ट टाइप की भंडारण पानी की टंकी की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में केवल संवाती टाइप जल भंडारण टैंक शामिल हैं।

आईएस 16543 : 2016 – समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड सौर संग्रहक नलिकाएँ – इस मानक में 80 से. तक की गर्म जल आउटपुट वाली असंकेन्द्रित टाइप की समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड सौर संग्रहक नलियों की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं।

आईएस 16544 : 2016 – समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड नलिकाएँ सौर जल तापन प्रणाली – इस मानक में समस्त ग्लास इवेक्यूएटिड नलिका सौर जल तापन प्रणाली की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में थर्मोसिफॉन सिद्धांत पर आधारित केवल असंकेन्द्रित, सीधे, संवाती सौर संग्रहक शामिल हैं। यह मानक सौर जल तापन प्रणाली के लिए नहीं हैं जिसमें कि सहायक उपकरण हीटर प्रणाली का अंग होता है और सहायक उपरकण इनपुट प्रणाली की कार्यकारिता को प्रभावित कर सकता है।

आईएस 16221 (भाग 1) : 2016/आईईसी 62109–1 : 2010–प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियों में प्रयोग हेतु विद्युत परिवर्तकों की सुरक्षा : भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ – इस मानक में उन प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों में प्रयुक्त पॉवर कन्वर्जन उपस्कर (पीसीई) की अपेक्षाएँ दी गई हैं जहाँ सुरक्षा के लिए एक समान तकनीकी स्तर आवश्यक है। इस मानक में बिजली के झटके, ऊर्जा, आग, यांत्रिक और अन्य जोखिमों से सुरक्षा के लिए पीसीई के डिजाइन और निर्माण की न्यूनतम अपेक्षाएँ परिभाषित की गई हैं।

आईएस 16227 (भाग 2) : 2016/आईइसी 61869–2 : 2012 – उपकरण ट्रांसफार्मर : भाग 2 करंट ट्रांसफार्मरों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ – यह मानक बिजली मापक उपकरणों और 15 हर्ट्ज से 100 रेटित आवृत्ति वाले बिजली संरक्षी उपकरणों के साथ प्रयुक्त होने वाले नव निर्मित प्रेरक करंट ट्रांसफार्मरों के लिए हैं।

आईएस 16463 (भाग 11) : 2016/आईईसी 61643–11 : 2011 – निम्न वोल्टता की सर्ज प्रोटेक्टिव युक्तियाँ : भाग 11 निम्न-वोल्टता पॉवर वितरण प्रणालियों से जुड़े सर्ज प्रोटेक्टिव युक्तियाँ – अपेक्षाएँ एवं परीक्षण पद्धतियाँ – यह मानक वोल्टेजों पर प्रकाश अथवा अन्य चलायमानों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावों से सुरक्षा के लिए हैं। ये युक्तियां 50/60 हर्ट्ज ए.सी. पॉवर परिपथों और 1000 वोल्ट च.प्र.सै. तक की रेटिंग के उपस्कर के साथ तैयार रूप में संयुक्त की जा सकती हैं। मानक में कार्यकारिता अभिलक्षण, परीक्षण हेतु मानक पद्धतियाँ और रेटिंग निर्धारित की गई है। ये युक्तियाँ न्यूनतम एक लीनियर रहित घटक युक्त हैं और सर्ज वोल्टेज को सीमित करने तथा सर्ज करंट को पथांतरित करने के लिए अभीष्ट है।

आईएस/आईईसी 62271–103 : 2011 – उच्च वोल्टता के स्विचगियर और नियंत्रणगियर : भाग 103 1 के.वी. से 52 के.वी. तक की रेटित वोल्टता हेतु स्विच – यह मानक भीतरी और बाहरी संस्थापनों के लिए थ्री फ़ेज, प्रत्यावर्ती करंट स्विचों और करंट रेटिंग को बनाने एवं विलग करने, स्विच कार्य–प्रणाली के स्विच वियोजकों एवं 1 किलो वोल्टेज से ऊपर तक की और 52 किलो वोल्टेज के तथा 162/3 हर्ट्स से और 60 हर्ट्स की रेटित आवृत्तियों के लिए हैं। यह मानक थ्री–फेज प्रणालियों पर प्रयुक्त होने वाले सिंगल–पोल स्विचों के लिए भी है।

आईएस/आईईसी 62271–104 : 2009–उच्च वोल्टता के स्विचगियर और नियंत्रणगियर : भाग 104 52 के.वी. और अधिक की रेटित वोल्टता हेतु प्रत्यावर्ती करंट स्विच – यह मानक भीतरी और बाहरी संस्थापनों के लिए 52 के.वी. और ऊपर की रेटित वोल्टता थ्री–पोल प्रत्यावर्ती करंट स्विचों और करंट रेटिंग को बनाने एवं विलग करने तथा 60 हर्ट्स की और तक की रेटित आवृत्तियों के लिए है।

आईएस 16316 : 2016/आईएसओ/टीआर 21102 : 2013 – साहसिक पर्यटन लीडर कार्मिक सक्षमता – पर्यटन गतिविधियों के प्रकार (राफ्टिंग, हाइकिंग, कैसकेडिंग, क्लाइम्बिंग, एवं अन्य) के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रत्येक साहसिक पर्यटन गतिविधि में कुछ सक्षमताएँ सामान्य होती हैं। ये सामान्य सक्षमताएँ इस तकनीकी रिपोर्ट का केन्द्र हैं।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 54) : 2016/आईईसी 60601–2–54 : 2009 – चिकित्सकीय विद्युत उपस्कर – भाग 2–54 : रेडियोग्राफी और रेडियोस्कोपी के लिए एक्सरे उपकरण की बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्यनिष्ठा के लिए विशेष आवयश्कताएँ – रेडियोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले एक्स–रे उपस्करों हेतु यह मानक रेडियोग्राफी और रेडियास्कोपी के प्रोजेक्शन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बिजली के चिकित्सा उपस्करों और बिजली की चिकित्सा प्रणालियों की मूल सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिताओं के लिए है। यह मानक एक्स–रे प्रणालियों के टाइप परीक्षण से संबंधित है।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 63) : 2016/आईईसी 60601–2–63 : 2012 – चिकित्सकीय विद्युत उपस्कर – भाग 2–63 : दंत एक्सट्रा– ओरल एक्स–रे उपकरण की बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिता के लिए विशेष अपेक्षाएँ – यह मानक डेन्टल एक्सट्रा एक्स–रे उपस्कर की मूल सुरक्षा और अनिवार्य कार्यकारिता के लिए हैं। इन उपस्करों को इसके बाद एमई उपस्कर भी कहा गया है, जबकि ऐसे उपस्करों के लिए पहले के मानक घटकों और उपप्रणालियों के लिए थे। यह मानक विशेष रूप से डेन्टल एक्सट्रा ओरल एक्स–रे उपस्कर के पद्धति स्तर के लिए हैं।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 65) : 2016/आईईसी 60601–2–65 : 2012 – चिकित्सा विद्युत उपस्कर – भाग 2–65 : रेडियोग्राफी और रेडियोस्कोपी हेतु एक्स–रे उपस्करों की बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्यनिष्ठा के लिए विशेष आवयश्कताएँ, अनुभाग 65 –ओरल एक्स–रे उपकरण – यह मानक डेन्टल एक्सट्रा एक्स–रे उपस्कर और उसके प्रमुख घटकों की मूल सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिता के लिए हैं। इस मानक का कार्यक्षेत्र उन एक्स–रे उपस्करों तक सीमित है जहां एक्स–रे ट्यूब एसेम्बली, उच्च–वोल्टता ट्रांसफॉर्मर असेम्बली युक्त होती है। डेन्टल एक्सट्रा–ओरल एक्स–रे उपस्कर को इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। आईईसी 60601–1 : 2025 और उसके समवर्तियों पर आधारित यह मानक डेन्टल एक्स–रे उपस्कर की मूल सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिता की सम्पूर्ण श्रेणी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

आईएस/आईईसी 61010–1 : 2010 – मापन, नियंत्रण और प्रयोगशाला के उपयोग हेतु विद्युत उपकरण की सुरक्षा अपेक्षाएँ – भाग 1 : सामान्य अपेक्षाएँ – इस मानक में निम्नलिखित प्रकार के बिजली के उपस्करों और उनके उपसाधनों, जहां कहीं भी ये प्रयुक्त किए जाने हों, के सामान्य प्रयोग की सुरक्षा अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं।

क) बिजली परीक्षण और मापन उपस्कर,

ख) विद्युत औद्योगिक प्रक्रम–नियंत्रण उपस्कर, और

ग) बिजली के प्रयोगशाला उपस्कर।

आईएस/आईएसओ मार्गदर्शिका 64 : 2008–उत्पाद मानकों में पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने हेतु गाइड – यह गाइड उत्पाद मानकों में पर्यावरण के विषयों का समाधान करने के दिशा–निर्देश प्रदान करती है। यह मुख्यतः उत्पाद मानक लेखकों के लिए हैं। इसका प्रयोजन उत्पाद मानकों में और पर्यावरण पक्षों तथा उत्पाद के प्रभाव के बीच प्रावधानों में संबंध का ढांचा देना है।

आईएस 16061 (भाग 2) : 2016/आईएसओ 14687–2 : 2012 – हाइड्रोजन ईंधन – उत्पाद विशिष्टि : भाग 2 सड़क पर वाहनों के लिए प्रोटोन विनिमय झल्ली (पीईएम) ईंधन सैल अनुप्रयोग – इस मानक में हाइड्रोजन ईंधन के गुणता अभिलक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं जिससे कि सड़क वाहनों की प्रणाली के लिए प्रोटोन विनिमय मेम्बरेन में उपयोग हेतु परिक्षेपित रूप में हाइड्रोजन उत्पाद में एकरूपता रहे। इस मानक में हाइड्रोजन ईंधन को गैसीय और तरल प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।

आईएस 16512 (भाग 1) : 2016/आईएसओ 16110–1 : 2007–ईंधन प्रक्रमण तकनीकी का प्रयोग करने वाले हाइड्रोजन जेनरेटर : भाग 1 सुरक्षा – यह मानक पैकेजबंद, स्व–निहित अथवा फैक्टरी उपयुक्त हाइड्रोजन उत्पादन प्रणालियों के हैं जो कि इनपुट ईंधन को हाइड्रोजन समृद्ध प्रवाह संयोजन में एवं हाइड्रोजन में प्रयुक्त युक्ति की किस्म के लिए अनुकूल उपयुक्त स्थितियों में परिवर्तित करता है। यह आंतरिक एवं बाहरी व्यावसायिक, औद्योगिक, हल्के औद्योगिक एवं आवासीय इस्तेमाल के लिए स्थिर हाइड्रोजन जरनेटरों के लिए है।

2016–17 के दौरान संशोधित महत्त्वपूर्ण मानक

आईएस 14543 : 2016 – पैकेजबंद पेय जल (पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा) (*दूसरा पुनरीक्षण*) – पीने के पानी के रूप में पैकेजबंद जल की खपत देश में बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त कई बार पानी की कमी के कारण और स्वास्थ्य रक्षा की कथित जरूरतों ने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजबंद पेय जल के व्यापार को तेज कर दिया है।

आईएस 16066 : 2016 फेरी लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले – खाद्य सुरक्षा अपेक्षाएँ (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में न्यूनतम अपेक्षाओं एवं जाँच सूची के साथ नियंत्रण जाँच बिन्दु निर्धारित किए गए हैं जिसमें ग्रेडिंग मानदंड भी हैं और यदि इनको लागू किया जाए तो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसमें मानव खपत के लिए तैयार/कच्चा खाने का सामान बेचने वाले सभी चल एवं अचल विक्रेता आते हैं। मानक में न्यूनतम जांच बिन्दुओं से संबंधित वे दिशा–निर्देश दिए गए है जिन्हें यदि लागू किया जाए तो उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलेंगें।

आईएस 14715 (भाग 1) : 2016 – जूट के भू–वस्त्र : भाग 1 सड़क के सब–ग्रेड को मजबूती प्रदान करने हेतु – इस मानक में सड़कों के उप–ग्रेड को मजूबत करने हेतु गुंथे और अगुंथे जूट के भू वस्त्रों की अपेक्षाएँ दी गई हैं। इस मानक में शामिल जूट के भू वस्त्र कमजोर सड़क उप–ग्रेड पर बनी उन स्थिति–अनुकूल पट्टरियों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त हैं जहाँ यातायात का भार और घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है।

आईएस 14715 (भाग 2) : 2016 – जूट के भू–वस्त्र : भाग 2 नदियों तथा पानी के जलाशयों के किनारों को काटने से रोकना (*दूसरा पुनरीक्षण*) – इस मानक में नदियों तथा जलाशयों के किनारों के कटाव को रोकने के लिए गुंथे हुए जूट (जेजीटी) की अपेक्षाएँ दी गई हैं। नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिए गुंथे हुए जेजीटी अनुशंसित हैं क्योंकि ये परंपरागत ग्रेन्युलर फिल्टर का पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं जिसमें ग्रेडिड कंकर–पत्थर और पत्थर रोड़ी, लेटराइट अथवा वांछित विशिष्ट गुरूत्व की समान सामग्री होती है।

आईएस 9755 : 2016 – वस्त्रादि – उर्वरकों की भरपाई के लिए उच्च घनत्व के पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रॉपेलिन (पीपी) के बोरे (*पाँचवाँ पुनरीक्षण*) – इस मानक में स्वदेशी निर्मित अथवा आयात किए गए सभी प्रकार के उर्वरकों को पैक करने के लिए एचडीपीई/पीपी के बुने बोरों की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस पुनरीक्षण में रिसाइकिंलग लोगो के मुहरांकन के साथ राख के अंश की महत्त्वपूर्ण अपेक्षा दी गई है तथा बोरों की बेहतर कार्यकारिता के लिए फैब्रिक की टूटन सामर्थ्य और निचले जोड़ की टूटन सामर्थ्य की अपेक्षाओं को बढ़ाया गया है।

आईएस 1417 : 2016 – स्वर्ण और स्वर्ण मिश्रधातुएँ, आभूषण/शिल्पकारी– शुद्धता और मुहरांकन (*चौथा पुनरीक्षण*) – इस पुनरीक्षण में मानक के विषय–क्षेत्र में बुलियन और सिक्कों को परिभाषित तथा शामिल किया गया है। मुहरांकन खंड में संशोधन किया गया है और कैरेट तथा परिशुद्धता को मुहरांकन में इंगित किया गया है। आभूषण निर्माण के लिए शुद्धता ग्रेड 22 के 916, 18के 750 और 14के 585 को रखा गया है और हॉलमार्क की गई ज्वैलरी/शिल्पवस्तुओं के पुनर्परीक्षण पर अधिकतम 2ppt की ऋणात्मक छूट को शामिल किया गया है।

आईएस 513 (भाग 1) : 2016 – अतप्त लघुकृत कार्बन इस्पात की चादर एवं पत्ती : भाग 1 कोल्ड फार्मिंग और ड्रांइग के लिए – वर्तमान संस्करण में मौजूदा मानक को दृढ़ता के स्तर पर दो भागों में बांटा गया है। इसमें नए अभिनामों और ग्रेडों, ग्रेडों के वर्गीकरण और टेम्पर अभिनाम में नए नामों को जोड़ा गया है। इस मानक में 4.0 मिमि तक की मोटाई के लिए अतप्त रूपण एवं ड्रांइग प्रयोजन हेतु अतप्त लघुकृत इस्पात की चादरें और पत्तियाँ शामिल हैं।

आईएस 513 (भाग 2) : 2016 – अतप्त लघुकृत कार्बन इस्पात की चादर एवं पत्ती : भाग 2 उच्च तन्यता और मल्टी–फेस स्टील – वर्तमान संस्करण में मौजूदा मानक को दृढ़ता के स्तर पर दो भागों में बांटा गया है। इस मानक में 3.0 मिमि तक की मोटाई के लिए अतप्त रूपण हेतु अतप्त लघुकृत कार्बन उच्च तनन और मल्टी–फेस इस्पात की चादरों की अपेक्षाएँ शामिल की गई हैं।

आईएस 1893 (भाग 1) : 2016 – संरचनाओं के भूकम्परोधी डिजाइन के मानदंड : भाग 1 सामान्य प्रावधान और भवन (*छठा पुनरीक्षण*) – इस संशोधित मानक में बड़े एवं छोटे भवन, बड़े एवं छोटे बांध, दीर्घ विस्तारित पुल तथा प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं जैसी विशेष संरचनाओं के भूकम्परोधी डिजाइनों का न्यूनतम डिजाइन प्रभाव दिया गया है। इस मानक में भूकम्पीय क्षेत्र, दर्शाने वाले भारत के विभिन्न मानचित्र, विगत भूकम्पों के केन्द्र, सैद्धांतिक विवर्तनिक विशेषताएँ, प्रमुख लिथॉलाजिकल समूह दिए गए हैं। इस विस्तृत पुनरीक्षण में मिट्टी के द्रवीकरण की क्षमता के आकलन संबंधी प्रावधान शामिल करना, अप्रबलित चिनाई पाटित दीवारों के साथ प्रबलित क्रंकीट फ्रेम भवन और ओपन स्टोरी, लैट स्लैब इत्यादि से संबंधित प्रावधान जैसे प्रमुख संशोधन किए गए हैं।

एसपी 7 : 2016 भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) (*तीसरा पुनरीक्षण*) – यह एक विशेष प्रकाशन है जो कि आदर्श कोड का कार्य करता है और जिसका उपयोग भवन नियामक प्राधिकरण, सरकारी निर्माण विभाग और अन्य निर्माण एजेंसियां करती हैं। इसके साथ यह भवन योजनाकारों, डिजाइन एवं निर्माण कार्य करने वाले इत्यादि के लिए भी उपयोगी है। एनबीसी एकल दस्तावेज है जिसमें नेटवर्क की भांति भवन आयोजना, डिजाइन, निर्माण और अन्य संबद्ध पक्षों को निरंतरता के पैटर्न में रखा गया है तथा समग्र दस्तावेज को ठोस रूप देने के लिए इसके विभिन्न अध्यायों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके और उपयुक्तता के साथ जोड़ कर इसके अध्यायों की अंतर्निर्भर अपेक्षाओं को निश्चयात्मक बनाया गया है। इस कोड में प्रशासन; विकास नियंत्रण नियम व सामान्य भवन अपेक्षाओं; आग व सुरक्षा; भवन सेवाओं; प्लम्बिंग सेवाओं; लैडस्केप विकास, चिन्ह एवं बाहरी डिस्पले संरचनाओं; और संवहनीयता के प्रति दृष्टिकोण पर प्रावधानों को कोड के विभिन्न भागों और खंडों में शामिल किया गया है।

भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2016 के संशोधित संस्करण का विमोचन माननीय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री श्री राम विलास पासवान ने 15 मार्च 2017 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के आयोजन के दिन डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में किया।



भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2016 के संशोधित संस्करण का विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 15 मार्च 2017 को नई दिल्ली में विमोचन

आईएस 14820 (भाग 1) : 2016 – लेज़र एवं लेज़र संबधी उपकरण – लेज़र बीम, चौड़ाई, अपसारण कोणों एवं बीम प्रेषण अनुपात की परीक्षण पद्धतियाँ : भाग 1 बिन्दुक एवं सामान्य अबिन्दुक बीम (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में बीम के की चौड़ाई (व्यास), अपसारण कोणों और लेजर बीम के संचरण अनुपात के मापन की पद्धतियाँ दी गई हैं। यह भाग केवल बिन्दुक और सामान्य अबिन्दुक बीम के लिए है।

आईएस 14820 (भाग 3) : 2016 – लेज़र एवं लेज़र संबधी उपकरण – लेज़र बीम, चौड़ाई, अपसारण कोणों एवं बीम प्रेषण अनुपात की परीक्षण पद्धतियाँ : भाग 3 वास्तविक एवं ज्यामितीय लेजर बीम वर्गीकरण, संचरण एवं परीक्षण पद्धतियाँ का विवरण (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में आईएस 14820 (भाग 1) के सहायक रूप में बीम की चौड़ाई (व्यास), अपसारण कोणों और लेजर बीम के संचरण अनुपात के मापन की पद्धतियां दी गई हैं। यह विगनर विस्तार के सैकेंड ऑर्डर मूमेंट के आधार पर लेजर बीम अभिलक्षण का सैद्धांतिक विवरण प्रदान करता है जिसमें ज्यामितीय और वास्तविक बीम अभिलक्षण शामिल हैं तथा यह मानक सीसीडी कैमरे जैसे मैट्रिक्स संसूचकों के लिए अनुशंसित उपयुक्त पृष्ठभूमि की घटाव पद्धति का महत्त्वपूर्ण विवरण भी देता है।

आईएस 5030 (भाग 2) : 2016 – धातु काटने के बेंड आरी ब्लेड : भाग 2 अभिलक्षण एवं आयाम (*दूसरा पुनरीक्षण*) – इस मानक में धातु काटने के विभिन्न प्रकार के पट्टी–आरा ब्लेडों के अभिलक्षण एवं आयाम दिए गए हैं।

आईएस 4296 (भाग 1) : 2016 – दाबन के औजार : भाग 1 60 डिग्री शंक्वाकार शीर्ष और सीधे शैंक वाले गोल पंच (*दूसरा पुनरीक्षण*) – इस मानक में 60 शंक्वाकार शीर्ष और सीधे शैंक के 0.5 मिमि से 20 मिमि व्यास वाले गोल पंचों के मिलीमीटर में मूल आयाम दिए गए हैं। मानक में उपयुक्त सामग्री और दृढ़ता मान एवं पंचों का अभिनाम निर्दिष्ट किया गया है, जो प्रमुख तौर पर इस्पात की चादरों में छेद करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जिसका उपयोग अन्य सामग्रियों के लिए भी किया जा सकता है।

आईएस 6548 (भाग 1) : 2016–रोलिंग बेयरिंग–उपकरण परिशुद्ध बेयरिंग : भाग 1 सीमा आयाम, टोलरेंसिस मीट्रिक श्रृंखला और बेयरिंग के लक्षण (*दूसरा पुनरीक्षण*) – मानक के इस भाग में अभिलक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं जो कि उपकरण परिशुद्ध रोलिंग बेयरिंग, मीट्रिक श्रृंखला, उनके प्रकार, सीमा आयाम, छूट और आंतरिक निर्गम, चुनिंदा असेम्बली के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण, टॉर्क की परिभाषा और परीक्षण स्थितियों तथा बेयरिंग यील्ड दरों को परिभाषित करता है।

आईएस 550 (भाग 2) 2016 – तिजोरियाँ : भाग 2 चोरी से प्रतिरोध संबंधी परीक्षण (*पाँचवाँ पुनरीक्षण*) – इस मानक में तिजोरियों के चोरी से बचाव के आकलन की परीक्षण पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं।

आईएस 1391 (भाग 1) : 2017 – कक्ष वातानूकुलक : भाग 1 एकिक वातानुकुलक (*तीसरा पुनरीक्षण*) – इस मानक में 10500 वॉट क्षमता के, 240 वोल्ट की और तक की रेटित वोल्टेज वाले तथा 50 हर्ट्ज की रेटित आवृत्ति वाले डक्टता रहित एकिक वातनूकुलकों (एयरकंडीशनर) की कार्यकारिता अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में उन एकिक वातानूकुलकों के विभिन्न कार्यकारिता अभिलक्षण निर्धारित करने हेतु परीक्षण स्थितियाँ और अनुवर्ती परीक्षण प्रक्रियाएँ भी दी गई हैं जो मानक रेटिंग स्थितियों में प्रशीतन और अनार्द्रता होने पर नॉन–फ्रॉस्टिंग पर कार्य करता है। इस मानक में हीट पम्प/विद्युत हीटर के अनुप्रयोग से हीटर का काम करने वाले एकिक वातानूकुलकों की विशिष्टि भी दी गई हैं।

आईएस/आईईसी 60947–4–2 : 2011 – निम्न वोल्टता के स्विचगियर और नियंत्रणगियर : भाग 4 कांट्रैक्टर एवं मोटर–स्टार्टर खंड 2 ए.सी.–अर्धचालक मोटर नियंत्रक एवं स्टार्टर – यह मानक ए.सी. अर्धचालक मोटर नियंत्रकों तथा स्टार्टरों के लिए है जिसमें परिपथ के साथ जोड़ जाने वाली यांत्रिक स्विचिंग युक्ति श्रृंखला को भी शामिल किया जा सकता है जिसकी रेटित वोल्टेज 1000 वो ए.सी. से अधिक न हो। इस मानक में बाईपास माध्यमों वाले और उसके बगैर ए.सी. अर्धचालकों को अभिलक्षित किया गया है।

आईएस 13730 (भाग 20) : 2016/आईईसी 60317–20 : 2000 – विशेष प्रकार की कुंडलन तारों की विशिष्टि : भाग 20 सोल्डरेबल पोलीयूरेथन इनैमलित गोलाकार ताँबा तार, वर्ग 155 (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में पोलीयूरेथन रेजिन आधारित एक कोटिंग वाली सोल्डरेबल इनैमलित गोलाकार वर्ग 155 की तांबे की तारों की अपेक्षाएँ दी गई हैं जिसे कि परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी मूल रेजिन की रासायनिक अभिन्नता बनी रहे और यह तार के लिए निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली हों।

आईएस 1459 : 2016 मिट्टी का तेल (*तीसरा पुनरीक्षण*) – इस मानक में प्रकाश व ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले मिट्टी के तेल की अपेक्षाएँ और पद्धतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं। यह विशिष्टि मूल रूप से 1959 में प्रकाशित की गई थी और मिट्टी के तेल के दो ग्रेडों एसके ग्रेड और 1K ग्रेड को शामिल करने के लिए बाद में 1968 में इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान पुनरीक्षण में पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए सल्फर के अंश को चरणबद्ध तरीके से कम किया गया है।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 43) : 2016/आईईसी 60601–2–43 : 2010 चिकित्सकीय विद्युत उपस्कर–भाग 2–43 : हस्तक्षेप प्रक्रियाओं हेतु एक्स–रे उपकरण की बुनियादी सुरक्षा एवं आवश्यक निष्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएँ (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में रेडियोस्कोपिक निर्दिष्ट अंतःक्षेपी प्रक्रियाओं के लिए एक्स–रे उपकरणों के डिजाइन एवं निर्माण की बुनियादी सुरक्षा एवं आवश्यक कार्यकारिता अपेक्षाएँ दी गई हैं। इस मानक में वह विशेष जानकारी दी गई है जो इस प्रकार के अंतःक्षेपी एक्स–रे उपकरणों के साथ दी जानी चाहिए जो विकिरण के जोखिम और उपकरणों की विफलता के जोखिम का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिए सहायक है।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 44) : 2016/आईईसी 60601–2–44 : 2009 चिकित्सकीय विद्युत उपस्कर–भाग 2–44 : कम्प्यूटिड टोमोग्राफी हेतु एक्स–रे उपकरणों की बुनियादी सुरक्षा एवं आवश्यक निष्पादन के लिए विशेष अपेक्षाएँ (*पहला पुनरीक्षण*) – यह मानक सीटी स्कैनरों की बुनियादी सुरक्षा एवं आवश्यक कार्यकारिता

अपेक्षा के लिए है। इस मानक का विषय–क्षेत्र सीटी स्कैनरों तक सीमित है जिसका प्रयोग सिर और शरीर के अन्य हिस्सों, दोनों के लिए होता है और जो टोराइड की शक्ल में सामान्य संरक्षी आवरण में विशेष एक्स–रे स्रोत और इमेजिंग संसूचक एनक्लोजर हो। इसमें सीटी स्कैनरों में प्रयुक्त एक्स–रे जरनेटरों की सुरक्षा अपेक्षाएँ शामिल हैं और इसमें एक्स–रे ट्यूब असेम्बली के साथ एकीकृत उच्च–वोल्टता जनरेटर भी शामिल हैं।

आईएस 13450 (भाग 2/खंड 45) : 2016/आईईसी 60601–2–45 : 2011 चिकित्सकीय विद्युत उपस्कर–भाग 2–45 : मेमोग्राफिक एक्स–रे उपकरण एवं मेमोग्राफिक स्टीरियोटैक्टिक उपकरणों की बुनियादी सुरक्षा एवं आवश्यक निष्पादन के लिए विशेष अपेक्षाएँ (*पहला पुनरीक्षण*) – यह मानक एक्स–रे उपकरणों एवं मेमोग्राफिक स्टीरियोटैक्टिक युक्तियों की बुनियादी सुरक्षा एवं कार्यकारिता अपेक्षा के लिए है। यह मानक मेमोग्राफिक एक्स–रे उपकरणों के पद्धति स्तर से संबंधित है जिसमें एक्स–रे जनरेटर, संबद्ध उपकरण एवं सहायक साधनों का संयोजन शामिल है। इस मानक विशेष में निर्दिष्ट न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाएँ मेमोग्राफिक एक्स–रे उपकरणों के प्रचालन में सुरक्षा के व्यावहारिक स्तर प्रदान करने की न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर निर्दिष्ट की गई हैं।

आईएस 15298–2 : 2016/आईएसओ 20345 : 2011 – निजी सुरक्षा उपस्कर : भाग 2 सुरक्षा फुटवियर (*दूसरा पुनरीक्षण*) – इस भारतीय मानक में सामान्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सुरक्षा फुटवियर की मूल और अतिरिक्त (वैकल्पिक) अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इसमें यांत्रिक जोखिम, फिसलन प्रतिरोधकता, ऊष्मीय जोखिम, श्रम दक्षता संबंधी व्यवहार इत्यादि शामिल हैं। विशेष जोखिमों को अनुपूरक जॉब संबंधी मानकों (जैसे अग्निशामक कर्मचारियों के लिए फुटवियर, विद्युतरोधी फुटवियर, गंभीर चोटों से सुरक्षा, रसायनों और पिघली धातुओं से सुरक्षा, मोटर साइकिल चालकों की सुरक्षा) में लिया गया है। इस मानक में सुरक्षा फुटवियर संबंधी पारिभाषिक शब्दावली एवं परिभाषाएँ, डिजाइन, अपेक्षाएँ और परीक्षण पद्धतियाँ दी गई हैं।

आयोजित संगोष्ठियाँ/सम्मेलन :

भारतीय मानकों को अपनाने और उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस, पहचान किए गए क्षेत्रों में संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करता है जिसमें स्टेकहोल्डरों, जैसे निर्माता, प्रयोक्ता, अनुसंधान एवं रक्षा संगठन, सरकारी संस्थान इत्यादि भागीदारी करते हैं। भारतीय मानकों की जानकारी के प्रसार और मानकों को अद्यतन/बेहतर करने के लिए तथा मानकीकरण के नए क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बीआईएस ने वर्ष के दौरान कई संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष के दौरान आयोजित की गई महत्त्वपूर्ण संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का विवरण निम्नलिखित है :

'नगरपालिका ठोस कचरा कम्पोस्ट, मैन्युर ग्रेड' – 13 फरवरी 2017 को जयपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नगर के कचरे को कृषि उपयोगी कम्पोस्ट में बदलने के लिए सरकार भारतीय मानक का क्रियान्वयन करने जा रही है। इसमें म्यूनिसिपलके ठोस कचरे को कृषि उपयोगी कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के महत्त्व पर बल दिया गया, ताकि नगरपालिका कचरे के लैंडफिल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सके और कृषि के लिए मिट्टी का उपयुक्त पुनरोत्पादन हो। इससे न केवल पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बेहतर किया जा सकता है और उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। संगोष्ठी में भारतीय मानक में निर्दिष्ट की गई कम्पोस्टिंग की विभिन्न पद्धतियों से लाभ–हानि तथा प्रत्येक अपेक्षाओं के महत्त्व के बारे में बताया गया तथा दीर्घकालिक फसल उत्पादन के लिए 'वेस्ट टू वेल्थ' पर एक व्याख्यान भी दिया गया।

'इस्पात निर्माण में नवीनताएँ एवं नवीन प्रवृत्तियाँ' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी – इस विषय पर 7 मार्च 2017 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात में नवीनतम विकास और इस्पात निर्माण में प्रयुक्त की जा रही नई प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस संगोष्ठी में संबद्ध विभिन्न कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया।



इस्पात में नई पद्धतियाँ और इस्पात निर्माण प्रचलन पर 07 मार्च 2017 को नई दिल्ली में संगोष्ठी

"पहाड़ी क्षेत्र विकास प्रौद्योगिकी के महत्त्व और शैल मैकेनिक्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी"– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की और इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी – रूडकी चैप्टर, के साथ 20 मार्च 2017 को संयुक्त रूप से रूड़की में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान हुए प्रस्तुतीकरण और विचार–विमर्श में पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए कुशल इंजीनियरिंग रीतियों पर जोर दिया गया जिसमें विशेष महत्त्व ढलान की स्थिरता और भूस्खलन नियंत्रक उपायों पर दिया गया।

"भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 और अग्नि और जीवन संरक्षा पर अंतर्दृष्टि" पर संगोष्ठी – हाल ही में पुनरीक्षित की गई राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 पर इंजीनियर संस्थान (इंडिया) और भारत के अग्नि और जीवन सुरक्षा संघ द्वारा 30 मार्च 2017 को संयुक्त रुप से एक संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रस्तुतीकरण में पुनरीक्षित संहिता की अंतर्दृष्टि, इसकी प्रमुख विशेषताएँ, संहिता में विद्यमान सभी चैप्टरों में संशोधन, जोड़े गए नए पाठ उनकी विशेषताओं सहित और पूरे देश में संहिता के व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए संभव कार्य पद्धति शामिल थी।



भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता का सिंहावलोकन 2016 और अग्नि और जीवन सुरक्षा अंतर्दृष्टि पर 30 मार्च 2017 को संगोष्ठी

"साइकिल और इसके घटक – मानकीकरण" पर संगोष्ठी – दिनांक 27 मार्च 2017 को लुधियाना में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी साइकिलों एवं उसके घटकों के क्षेत्र में साइकिल विषय समिति, टीईडी 16 द्वारा निर्धारित मानकों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों के बारे में उद्योगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई। संगोष्ठी में 75 प्रतिभागी उपस्थित थे, जिसमें विभिन्न हितधारक, जैसे साइकिल विनिर्माता और इसके घटकों के विनिर्माता शामिल थे।



साइकिल और इसके घटकों के मानकीकरण पर 27 मार्च 2017 को लुधियाना में संगोष्ठी

आईटी सुरक्षा पर संगोष्ठी – इस संगोष्ठी ने डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर सूचना के आदान–प्रदान और भारत तथा जर्मनी में इस क्षेत्र में निजता और मानकीकरण के लिए विशिष्ट मंच प्रदान किया । बीआईएस ने इस पर दृष्टिकोण और संबद्ध समिति एलआईटीडी 17 "सूचना पद्धति सुरक्षा और बायोमेट्रिक्स" में हुई प्रगति को सामने रखा । जर्मनी ने जर्मनी में उपलब्ध और यूरोपियन स्तर पर उपलब्ध विनियमों और मानकों को प्रस्तुत किया। नेटवर्क सिक्योरिटी पर दिशानिर्देशों और सूचना पद्धति (एनआईएस दिशानिर्देश) जिन्हें यूरोपियन संसद ने अंगी.त किया है, उन पर प्रस्तुतीकरण दिया गया जिससे इसके कार्यान्वयन और अनुपालन संबधी कई शंकाओं का समाधान हुआ ।

स्मार्ट ग्रिड में प्रयुक्ति के मामलों पर कार्यशाला – डीकेई, जर्मनी से विभिन्न विशेषज्ञों ने मानकीकरण में यूज केस पद्धति की प्रयुक्ति पर और स्मार्ट ग्रिड क्षेत्र में केस निरुपण पर प्रस्तुतीकरण दिया।

"हाइड्रोलिक्स, जल संसाधन और तटीय इंजीनियरिंग" पर 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (हाइड्रो 2016) – यह सम्मेलन 8–10 दिसंबर 2016 के दौरान इंडियन सोसाइटी फॉर हाइड्रोलिक्स के सहयोग से सीडब्लयूपीआरएस, पुणे ने आयोजित किया और इसे बीआईएस ने कोस्पोन्सर किया। इसमें जल संसाधन और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोमीट्रोलॉजी, तरल यांत्रिकी में कंप्यूटर अनुप्रयोग, पर्यावरणीय और मौसम परिवर्तन, तटीय इंजीनियरिंग, जलाशय और संबंधित ढांचे, हाइड्रोइंस्ट्रूमेंटेशन और भूमिजल जैसे विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए गए।

"नदी घाटी परियोजना के लिए जल संचालक पद्धति पर संगोष्ठी" – कोलकाता में 17 मार्च 2017 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई । संगोष्ठी में विभिन्न संगठनों और संस्थानों जैसे– केंद्रीय जल आयोग; वापकोस लिमिटेड; ब्रहमपुत्र बोर्ड; जल संसाधन विभाग, पश्चिम बंगाल; जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश; जल संसाधन विभाग, झारखंड; हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड; फरक्खा ब्रिज प्रोजेक्ट; दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन; आईआईईएसटी; शिबपुर, स्कूल ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग; जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।



नदी घाटी परियोजना के लिए जल संचालक पद्धति पर 17 मार्च 2017 को कोलकाता में आयोजित संगोष्ठी

"तकनीकी टेक्सटाइल में यूरोपियन यूनियन का विनियामक ढांचा" पर जागरुकता कार्यशाला – मानकीकरण में सहयोग के लिए गुणता ढांचे पर इंडो जर्मन वर्किंग समूह के ढांचे के अंदर, मानकीकरण में सहयोग, अनुरूपता मूल्यांकन और उत्पाद संरक्षा पर 5 अक्टूबर 2016 को मुंबई में एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला हुई जिसका विषय "तकनीकी टेक्सटाइल में यूरोपियन यूनियन का विनियामक ढांचा" था। कार्यशाला संयुक्त रूप से बीआईएस और जीआईजेड, जर्मनी द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान, भारत और जर्मनी के बीच विकसित होने वाली सर्वोत्तम रीतियों और साधनों पर विचार–विमर्श किया गया, ताकि व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए मानकों के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी, भारतीय हितधारकों में क्षमता निर्माण, मानकों के कार्यान्वयन, और व्यापार प्रोत्साहित करने के लिए परस्पर मान्यता हेतु इस कदम को आगे बढ़ाया जा सके ।

टेक्नोटेक्स 2017 'विषयवस्तुः एडवांटेज इंडियाः इमर्जिंग ग्लोबल मैनुफेक्चरिंग हब फॉर टेक्निक्ल टेक्सटाइल्स' की पूर्व भूमिका (कर्टेन रेजर) – टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स – 2017 की पूर्व भूमिका 17 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में रखी गई। राष्ट्रीय महत्त्व के पाँच भारतीय मानक, जो जूट टेक्सटाइल, पैकटेक, और बिना बुनी परीक्षण पद्धतियों पर हैं, उनका विमोचन माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी, ने किया। इन पाँच भारतीय मानकों का विमोचन तकनीकी टेक्सटाइल्स में मानकीकरण के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा, जल संरक्षण और ग्रामीण ढांचे के विकास के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।



टेक्नोटेक्स – 2017 नई दिल्ली में 17 जनवरी 2017 को आयोजित

खादी और हैंडलूम की संस्कृति और धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठी – भारतीय मानकों की भूमिका – संगोष्ठी 21 फरवरी 2017 को आयोजित की गई। खादी और हैंडलूम संस्थानों, कारीगरों, नियामक निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकार के प्रतिनिधियों एवं महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताओं समेत लगभग 80 प्रतिनिधि उक्त संगोष्ठी में उपस्थित हुए। एक दीर्घ प्रश्नोत्तरी सत्र के बाद यह सिफारिश की गई कि बीआईएस को खादी और हैंडलूम उद्योगों के साथ मिलकर, भारतीय मानकों के उपयोग से होने वाले तकनीकी और आर्थिक लाभ के विषय में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए पूरे देश में संवादात्मक कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ आयोजित करनी चाहिए। खादी और हैंडलूम उद्योगों ने भी अपने उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बीआईएस प्रमाणन योजना में रुचि दिखाई।

सामान्य इंजीनियरिंग और बंधकों के क्षेत्र में मानकीकरण पर संगोष्ठी – बीआईएस ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशियेशन ऑफ इंडिया, पुणे में इस विषय पर 25 जुलाई 2016 को संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में हितधारक, समिति सदस्य और सामान्य इंजीनियरिंग और बंधक एवं संबंधित उद्योगों के इच्छुक आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए। प्रतिभागियों को इन सभी चीजों से अवगत कराया गया । बीआईएस की मानकीकरण प्रक्रिया एवं पद्धतियों, एआरएआई और ऑटोमोटिव उद्योगों द्वारा पालन किए जा रहे विनियमों, बंधकों के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, वाहनों और इंजनों के डिजाइन में नवीनतम परिवर्तनों से अवगत कराया गया ताकि वैकल्पिक ईंधन प्रयोग किया जा सके और वायु प्रदूषण कम किया जा सके ।

मानकीकृत पंपों के माध्यम से उर्जा दक्षता पर संगोष्ठी – संगोष्ठी अमृतसर में 30 सितम्बर 2016 को आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य पंपों पर बन रहे एवं प्रकाशित हो चुके भारतीय मानकों पर जानकारी का प्रसार करना था ताकि मानकों को अद्यतन/निरुपित करने के लिए उद्योगों और दूसरे हितधारकों की अपेक्षाएँ समझी जा सकें एवं आईएसआई मुहरांकित पंपों के हितधारकों में जागरुकता लाई जा सके ताकि उर्जा बचे और दक्षता बढ़े।



30 सितंबर 2016 को अमृतसर में मानकीकृत पंपों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता पर आयोजित संगोष्ठी

बैंकों और अन्य संस्थानों में भौतिक सुरक्षा उत्पादों पर संगोष्ठी – संगोष्ठी का आयोजन 09 मार्च 2017 को मुंबई में किया गया, ताकि बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा उपस्करों पर बन रहे और प्रकाशित हो चुके भारतीय मानकों पर सूचना को प्रसारित किया जा सके ।

निम्न वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एलवीडीसी) और स्मार्ट ग्रिड पर यूज केस कार्य प्रणाली पर संगोष्ठी – संगोष्ठी 15 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। संगोष्ठी में लगभग 25 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। संगोष्ठी के दौरान, बीआईएस ने 48 एलवीडीसी वितरण कार्य प्रणाली पर इसके मानक के प्रारुप की जानकारी दी। भारत और जर्मनी के विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रयोग मामलों से एलवीडीसी और स्मार्ट ग्रिड पर ज्ञान सांझा किया।



15 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में निम्न वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एलवीडीसी) और स्मार्ट ग्रिड पर यूज केस कार्य–प्रणाली पर आयोजित संगोष्ठी

एलवीडीसी पर बेबिनार – नई दिल्ली में 21 फरवरी 2017 को एक बेबिनार आयोजित किया गया। बेबिनार में 20 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बेबिनार में आईसी स्तर पर एलवीडीसी के मानकीकरण के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया ।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में सुशासन पर संगोष्ठी – यह संगोष्ठी सभी संबद्ध स्टेकहोल्डरों को एक मंच पर लाने के लिए बीआईएस द्वारा 24 मार्च 2017 को आयोजित की गई जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व पर मानकों का निर्धारण करना था, ताकि दीर्घकालिक विकास में योगदान दिया जा सके। संगोष्ठी सीएसआर के विभिन्न पहलुओं और विशेषकर, सीएसआर के प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित थी, जिससे भारतीय संदर्भ में समुचित और मार्गदर्शी मानक बनाने में मदद मिलेगी।



24 मार्च 2017 को कॉरपोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में सुशासन पर आयोजित संगोष्ठी

खेल के सामान के क्षेत्र में मानकीकरण पर संगोष्ठी – मेरठ में 29 जून 2016 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी भारतीय मानकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अंतर (जहाँ भी हो) ज्ञात करने और उपभोक्ताओं की मानकीकरण की आवश्यकताओं को जानने के लिए की गई ।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सूचना विज्ञान प्रारंभ करने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी – 11 जनवरी 2017 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसके दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिए गए, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारत के प्रति इसका दृष्टिकोण और डिजिटल स्वास्थ्य विज्ञान के लिए मानकों का महत्त्व, भारत के स्वास्थ्य विज्ञान के डिजिटलाइजेशन की उपलब्धियाँ और उसके समक्ष चुनौतियाँ, बीआईएस द्वारा अंगी.त स्वास्थ्य विज्ञान मानक आइएसओ/टीसी–215 आदि।



11 जनवरी 2017 को भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सूचना विज्ञान प्रारंभ करने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

"दंतचिकित्सा में मानकीकरण" पर संगोष्ठी – 15 मार्च 2017 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डेंटल और ओरल सर्जरी विभाग के सहयोग से एक संगोष्ठी आयोजित की गई । संगोष्ठी के दौरान विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिए गए एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे मर्करी से मुक्त दंत रीतियों पर चर्चा, आईएसओ मानकों की भूमिका, दंत चिकित्सा में भारतीय मानकों का निर्धारण और उनका कार्यान्वयन और दंत रीतियों में संक्रमण की रोकथाम।



15 मार्च 2017 को "दंतचिकित्सा में मानकीकरण" पर आयोजित संगोष्ठी

मानकों का प्रकाशन

बीआईएस अपने प्रकाशन विभाग द्वारा भारतीय मानकों का इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन और संशोधन करता है तथा प्रकाशित मानकों को अधिसूचित करता है एवं भारत के सरकारी राजपत्र में संशोधन प्रकाशित करता है। वर्ष के दौरान 302 नए मानक, 187 पुनरीक्षित मानक, और 195 संशोधन प्रकाशित किए गए ।

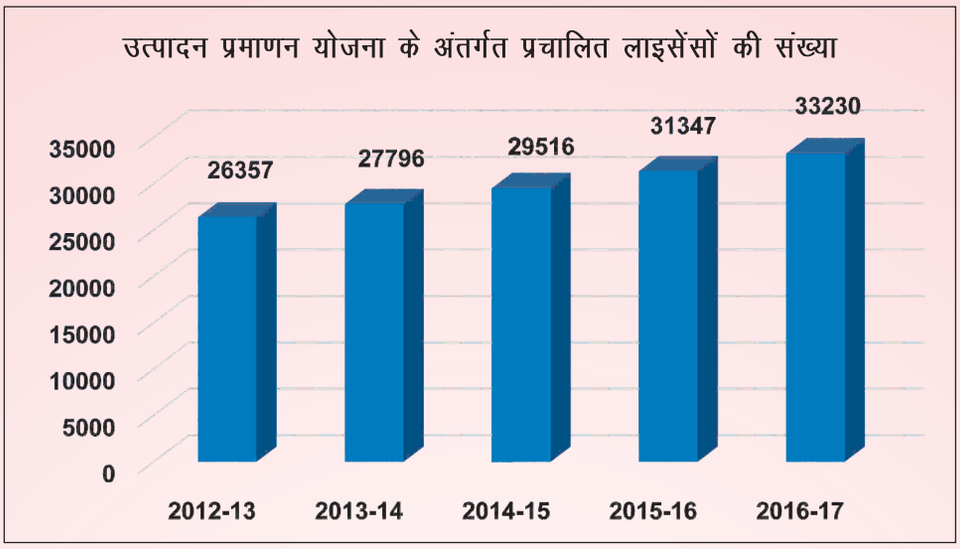
प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

बीआईएस *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और उसके अंतर्गत नियम एवं विनियमों के अंतर्गत उत्पाद प्रमाणन योजना चलाता है। इस प्रमाणन योजना के अंतर्गत एक विशेष उत्पाद के विनिर्माता को उसके उत्पाद पर बीआईएस मानक मुहर (आईएसआई) के मुहरांकन का अधिकार उत्पाद की संबद्ध भारतीय मानक से अनुरूपता सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता है। किसी भी उत्पाद पर आईएसआई मुहर का होना उसकी संबंधित भारतीय मानक से अनुरूपता को दर्शाता है। किसी भी विनिर्माता को लाइसेंस देने से पूर्व बीआईएस उसके पास आवश्यक ढांचे की उपलब्धता, उत्पाद के विनिर्माण और भारतीय मानक के अनुरूप उसका परीक्षण करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। प्रयोगशालाओं/मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में संबद्ध भारतीय मानक से अनुरूपता के लिए बीआईएस उत्पादन क्षेत्र एवं बाजार से नमूने लेकर उनका परीक्षण करता है। लाइसेंसी के उत्पाद की भारतीय मानक से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बीआईएस लाइसेंसी के परिसर में निगरानी दौरे भी करता है। उन 109 उत्पादों, जिन्हें केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और संरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य किया है, को छोड़ कर प्रमाणन योजना स्वैच्छिक प्रति की है।

वर्ष के दौरान, 4098 नए लाइसेंस प्रदान किए गए जिसमें इस योजना के अंतर्गत आने वाले 17 उत्पाद शामिल है। ये उत्पाद हैं आईएस 14252 : 2015 – उच्च घनत्व की पॉलीथिलीन (एचडीपीई) पोलीप्रोपेलिन (पीपी) की रेत भरने के लिए बुने बोरे, आईएस 15322 : 2003 – श्वसन प्रणाली संरक्षण उपस्करों में प्रयोग होने वाले पार्टिकल फिल्टर, आईएस 10532 (भाग 2): 1983 – अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक द्रव्य : भाग 2 इंवर्ट इमल्शन (वाटर–इन– ऑयलटाइप), आईएस 717 : 1998 – कार्बन डाइसल्फाइड टेक्निकल, आईएस 16232 : 2014 आयरन पुष्ट नमक (दुगना पुष्ट नमक)– फूड ग्रेड, आईएस 11169 (भाग 1) : 1984 – अतप्त हेडिंग/अतप्त बर्हिवेधन अनुप्रयोगों हेतु इस्पात : भाग 1 पिटवां कार्बन और अल्प मिश्रधातु का इस्पात, आईएस 14855 (भाग 1) : 2000 – पौध सुरक्षा और वेक्टर नियंत्रण उपस्कर – फोगिंग मशीन : भाग 1 पल्स–जेट प्रकार की फॉगिंग मशीन, आईएस 1838 (भाग 3) : 2011 – कंक्रीट के फुटपाथों एवं संरचनाओं में विस्तार जोडों के लिए पॉलीमर आधारित पूर्वरचित फिलर (बहिर्वेधी रहित एवं तन्यटाइप), आईएस 419 : 1967 – खिड़की फ्रेम में उपयोग के लिए पुट्टी, आईएस 3074 : 2013 स्वचल प्रयोजन की इस्पात नलिकाएँ, आईएस 15997 : 2012 – बर्तनों और रसोईघर उपकरणों के लिए अल्प निकेल आस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील चादरें एवं पट्टियाँ, आईएस 14968 : 2015 – 50 किग्रा/25 किग्रा चीनी की पैकिंग के लिए उच्च घनत्व की पॉलीइथाइलिन (एचडीडीपीई) पोलीप्रोपेलिन गुंफित बोरे, आईएस 10065 : 1981– भुनी हुई मूंगफली (पीनट) की गिरी, आईएस 16415 : 2015–संमिश्र सीमेंट, आईएस 13714 : 1993 – डनेज पैलेट–वेयरहाउसिंग, आईएस 6909 : 1990 – सुपर सल्फेटित सीमेंट की विशिष्टि, आईएस 3181 : 1992–भूमिगत खानों और ऐसे अन्य जोखिमपूर्ण अनुप्रयोगों हेतु अग्नि प्रतिरोधक संवाहक बेल्टिंग।

बीआईएस प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत आने वाले भारतीय मानकों की कुल संख्या 927 है। 31 मार्च 2016 तक प्रचालन में कुल लाइसेंसों की संख्या 31 347 जो मार्च 2017 में बढकर 33 230 हो गई ।



निगरानी

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान कुल 10 162 निरीक्षण किए गए और 8256 लॉट निरीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र परीक्षण के लिए (बाजार से खरीदे नमूनों सहित) 21 384 नमूने लिए गए।

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)

बीआईएस विदेशी विनिर्माताओं के लिए अलग योजना का प्रचालन करता आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मुहर अपने उत्पाद(दों) पर लगाने के लिए बीआईएस से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। 2016–17 के दौरान, एफएमसीएस के अंतर्गत 190 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे 83 भारतीय मानकों के लिए लागू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 671 हो गई । विश्व के लगभग 48 देशों को प्रदान किए गए लाइसेंसों में इस्पात एवं इस्पात उत्पाद; सीमेंट; पीवीसी रोधी केबल; ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए टायर एवं ट्यूब; प्लास्टिक की दूध पिलाने की बोतलें; स्विचगियर उत्पाद; प्लग एवं सॉकेट–आउटलेट और स्विच; एचडीपीई एवं यूपीवीसी पाइप; शिशुओं हेतु खाद्य आहार फार्मूला; एसी स्थैतिक ऊर्जा मीटर इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं ।

अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस)

बीआईएस के साथ परामर्श करके इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), जिसे पहले इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) कहा जाता था, ने 03 अक्तूबर 2012 को ''इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएँ (अनिवार्य प्रमाणन की अपेक्षाएँ) आदेश, 2012'' अधिसूचित किया जिसमें 15 इलैक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों को भारतीय मानकों से अनुरूपता के आधार पर बीआईएस से अनिवार्य पंजीकरण के लिए अधिदेश दिया । 13 नवम्बर 2014 को दूसरा आदेश अधिसूचित किया गया, जिसमें 15 और इलैक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया । यह अनिवार्य प्रमाणन योजना बीआईएस द्वारा, *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रचालित की जाती है ।

इस योजना की शुरूआत अनिवार्य प्रमाणन की वैकल्पिक व्यवस्था है, जिससे कि आईटी जैसे तेजी से विकसित होते क्षेत्र की प्रगति को आसान बनाया जा सके और उपभोक्ताओं को नकली तथा घटिया आयातित उत्पादों से बचाया जा सके और भारत में उत्पाद निर्मित किए जा सके ।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य उत्पाद निम्नलिखित हैं :

– एलईडी फिक्सचर, लैम्प और ड्राइवर

– मोबाइल फोन, पोर्टेबल पावर बैंक

- पुनः चार्जेबल सैल/बैटरियॉं
- 5 केवीए और कम क्षमता के यूपीएस और इनवर्टर
- माइक्रोवेव ओवन
- 32 और अधिक के स्क्रीन साइज वाले प्लाज्मा/एलसीडी/एलईडीटीवी/विजुअल डिसप्ले यूनिट/मॉनीटर
- आईटी, एवी एवं इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एडेप्टर
- बिक्री टर्मिनल प्वांइट, एडीपी मशीन
- लेपटॉप/नोटबुक/टेबलेट
- प्रिंट और प्लॉटर, फोटोकॉपियर, स्कैनर
- सेट टॉप बाक्स

बीआईएस द्वारा पहला पंजीकरण जून 2013 को प्रदान किया गया। 31 मार्च 2017 को बीआईएस ने विभिन्न देशों के निर्माताओं सहित घरेलू निर्माताओं को 8316 पंजीकरण प्रदान किए।

प्रयोगशाला सेवाएँ

उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के कार्यों के लिए बीआईएस की उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता पूरा करने के लिए ब्यूरो ने देश में आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित कीं, इसका आरंभ 1962 में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ शुरु हुआ।इसके बाद मोहाली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और पटना, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित शाखा कार्यालयों में तीन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, सूक्ष्म जैविकीय, विद्युत और यांत्रिक क्षेत्र के उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएँ हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीआईएस की प्रयोगशालाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के साथ गति बनाए रखें, इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली और साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आइईसी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशशोधन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित कराया गया ।

बीआईएस प्रयोगशालाओं में 376 भारतीय मानकों के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाएँ हैं और इसके अतिरिक्त 358 भारतीय मानकों के लिए आंशिक परीक्षण की सुविधाएँ हैं। वर्ष के दौरान बीआईएस प्रयोगशालाओं ने उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों के 18 502 नमूनों का परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान स्वर्ण और रजत आभूषण/शिल्पवस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना में सहायता करने के लिए चेन्नई की गोल्ड रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 2 965 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

परीक्षण सुविधाओं का सृजन/उन्नयन

बीआईएस प्रोयगशाला में आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत नई परीक्षण सुविधाओं का सृजन एवं चालू सुविधाओं का उन्नयन किया गया। इनमें पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (डब्ल्यूआरओएल), गुवाहाटी शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (जीबीओएल), और पटना शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (पीबीओएल) में पैकेज बंद पेय जल (पीडब्ल्यूडी) कंटेनर परीक्षण सुविधा, पटना शाखा कार्यालय प्रयोगशाला, गुवाहाटी शाखा कार्यालाय प्रयोगशाला में प्लाईवुड परीक्षण सुविधा और बंगलौर शाखा कार्यालय प्रयोगशाला में एलईडी की परीक्षण सुविधा शामिल है।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

बीआईएस की प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन, परीक्षण का नियमित अंग है, जिसके द्वारा परीक्षण की गुणता सुनिश्चित की जाती है। वर्ष के दौरान, बीआईएस प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन गतिविधियों के अंतर्गत 854 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें दक्षता परीक्षण/अन्तर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान परीक्षित नमूने भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण

क) बीआईएस प्रयोगशालाओं में श्रमशक्ति को नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान, 34 अधिकारियों को आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणता प्रबंध के लिए प्रशिक्षित किया गया।

ख) वर्ष 2016–17 के दौरान, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के लिए 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रयोगशाला मान्यता योजना

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत आने वाले नमूनों के परीक्षण का कार्यभार बीआईएस की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधा और क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण बीआईएस ने बाहरी प्रयोगशालाओं (ओएसएल) को मान्यता देने के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) प्रारंभ की है। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ

बीआईएस प्रयोगशालाओं में आर्थिक दृष्टि से परीक्षण सुविधाएँ विकसित करना व्यावहारिक न हो अथवा बीआईएस प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकठ्ठे हो जाएँ। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 पर आधारित है और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंश शोधन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुरूप है। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं को निम्नलिखित आवश्यक पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना होता है :

– प्रयोगशाला संबद्ध क्षेत्र में एनऐबीएल द्वारा प्रत्यायित हो।

– प्रयोगशाला को संबद्ध भारतीय मानक के अनुरुप परीक्षण पूर्ण करने होंगे।

– प्रयोगशाला को भारतीय मानक के अनुरूप उत्पादों के परीक्षण में सक्षम होना होगा।

वर्ष 2016–17 के दौरान 25 नई प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई व 6 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई। 31 मार्च 2017 के दौरान बीआईएस से मान्यता प्राप्त 179 प्रयोगशालाएँ प्रचालन में थीं, जिनमें अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएँ एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीआईएस द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष प्रकृति की 47 सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग भी किया जाता है।

नई आरंभ की गई बीआईएस पंजीकरण योजना की सहायता के लिए 33 बाहरी प्रयोगशालाएँ आईटी उत्पादों का परीक्षण कर रही हैं जो इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएँ) इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाई) आदेश, 2012 के अंतर्गत आते हैं।

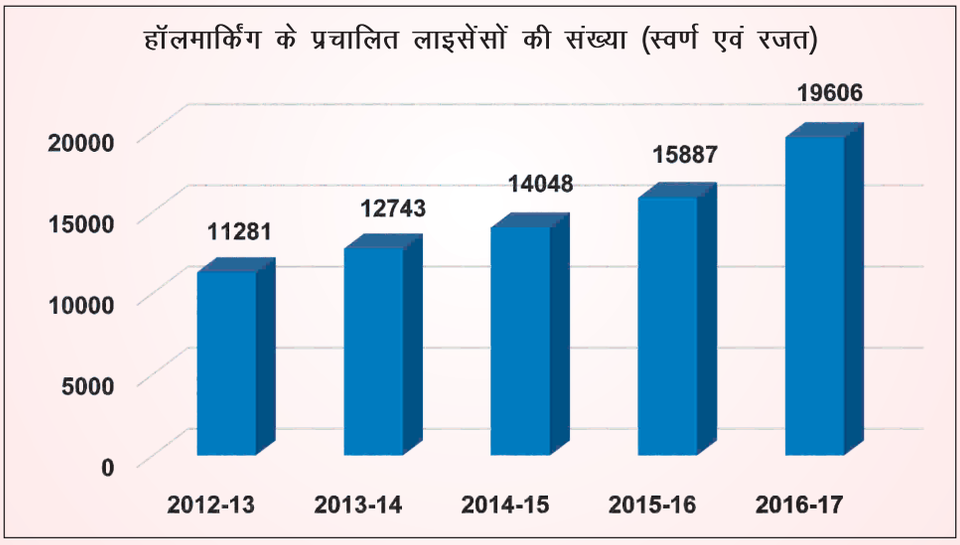
हॉलमार्किंग

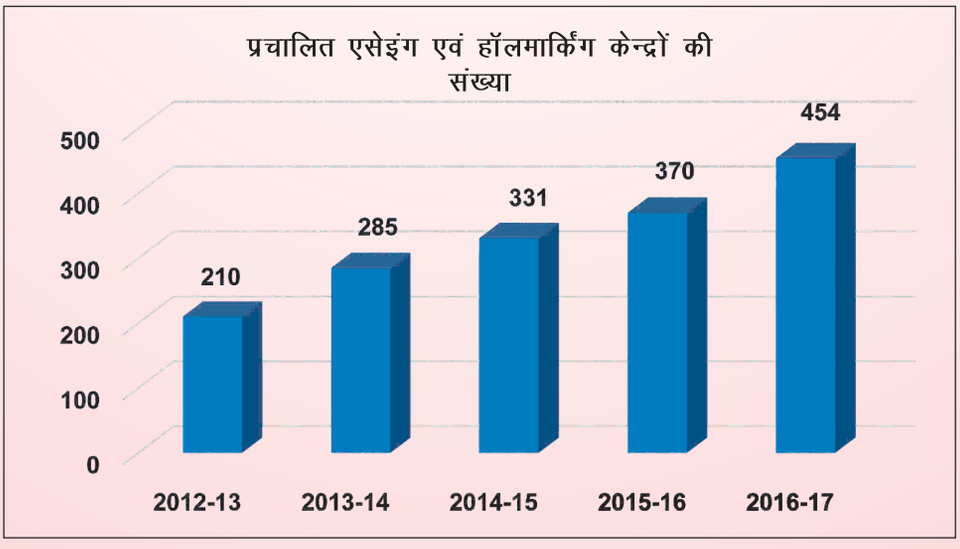
स्वर्ण/चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग योजना

(i) स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों/शिल्प वस्तुओं की हॉलमार्किंग

बीआईएस में स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग योजना अप्रैल 2000 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के लिए उपभोक्ताओं को तीसरे पक्ष के रूप में आश्वासन देना था। चाँदी के आभूषणों/शिल्प वस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना अक्तूबर 2005 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ज्वैलर को हॉलमार्क लगे आभूषण बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है तथा एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों को शुद्धता की घोषणा के साथ लाइसेंस प्राप्त ज्वैलर द्वारा दिए गए आभूषणों की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए मान्यता दी जाती है। महीनता की घोषणा सहित भारतीय मानकों के अनुरूप पाई गई ऐसी ज्वैलरी पर एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्र हॉलमार्क लगाता है।

31 मार्च 2017 को स्वर्ण एवं चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग के चालू लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 18 112 और 1 494 थी। प्रचालन के अंतर्गत बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 454 थी। वर्ष के दौरान, 3.16 करोड़ रूपये मूल्य के स्वर्ण एवं चाँदी के आभूषणों/शिल्प वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया ।





(ii) स्वर्ण बुलियन/सिक्के की हॉलमार्किंग

रिफाइनरियों/टकसाल को लाइसेंस देकर 999 और 995 की शुद्धता के स्वर्ण बुलियन/सिक्कों की हॉलमार्किंग अक्टूबर 2015 में आरंभ की गयी थी । वर्ष 2016–17 के दौरान, स्वर्ण बुलियन/सिक्कों की हॉलमार्किंग के लिए दो रिफाइनरियों को लाइसेंस दिया गया। 31 मार्च 2017 तक, स्वर्ण बुलियन और सिक्कों के लिए 10 रिफाइनरियों/भारत सरकार की टकसाल को लाइसेंस दिए गए ।

(iii) स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

भारत सरकार ने 5 नवम्बर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना प्रारंभ की थी। बीआईएस ने आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को अंतिम रूप देने और इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के अंतर्गत बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हालमार्किंग केन्द्र, संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केन्द्र (सीपीटीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त है। अब तक 48 एसेइंग एवं हालमार्किंग केन्द्र और एक ज्वैलर को सीपीटीसी के रूप में कार्य करने की अर्हता प्राप्त है। सीपीटीसी द्वारा एकत्रित किया गया स्वर्ण बीआईएस द्वारा लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों में परिष्कृत किया जाता है।

(iv) स्वर्ण हॉलमार्किंग पर पुनरीक्षित भारतीय मानक आईएस 1417 : 2016 का कार्यान्वयन

स्वर्ण हॉलमार्किंग पर भारतीय मानक का पुनरीक्षण नवंबर 2016 में किया गया था और इसे 1 जनवरी 2017 से कार्यान्वित किया गया । उपभोक्ता के हित के साथ–साथ उनके मन से भ्रम को हटाने के लिए हॉलमार्क लगी स्वर्ण ज्वैलरी पहले के 10 ग्रेडों के स्थान पर अब 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के तीन ग्रेडों में उपलब्ध होंगी । उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए महीनता के अतिरिक्त ज्वैलरी पर कैरेटेज जैसे 22 कैरेट ज्वैलरी, 916 (22K916) के अतिरिक्त 22K भी चिह्नित होगा। 1 जनवरी 2017 से हॉलमार्क में निम्नलिखित चिह्न होगे :

बीआईएस चिह्न	कैरेट और महीनता में शुद्धता (अर्थात् 22K916)	एसेइंग केन्द्र की पहचान का चिह्न/संख्या	ज्वैलर की पहचान

(v) हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन

स्वर्ण आभूषणों की खरीद में प्रभावी उपभोक्ताओं संरक्षण हेतु देश में हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिए बीआईएस देश भर में अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के माध्यम से ज्वैलरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है । वर्ष 2016–17 के दौरान, ज्वैलरों के लिए ऐसे 53 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

बीआईएस ने संबद्ध मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध पद्धति प्रमाणन सेवाएँ जारी रखीं और इनके विकास की गति स्थिर रही ।

i) आईएस/आईएसओ 9001 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस में गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) सितम्बर 1991 में आरंभ की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021–1 : 2015''अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाएँ – भाग-1 अपेक्षाएँ'' के अनुसार प्रचालित की जाती है। क्यूएमएससीएस प्रचालन के अधीन लाइसेंसों की कुल संख्या 867 हो गई इसमें औद्योगिक क्षेत्र, जैसे रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएँ, खनन, मशीनरी, पेट्रौलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि और वित्त, स्वास्थ्य, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि जैसे सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

ii) आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन (ईएमएस) पद्धति योजना

बीआईएस द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) प्रारंभ की गई थी और आईएसओ/आईईसी 17021 – 1: 2015 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार इसका प्रचालन किया जा रहा है। प्रचालन के अंतर्गत कुल 203 लाइसेंस हैं जिसमें तकनीकी क्षेत्र, जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप पावर संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली, वैगन वर्कशाप, फार्मस्यूटिकल, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन इत्यादि शामिल हैं।

iii) आईएस/आईएसओ 18001 : 2007 के अनुसार व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस ने आईएस 18001 : 2007 के अनुसार व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना आरंभ की है। इससे कोई संगठन उन महत्त्वपूर्ण खतरों और जोखिमों जिन खतरों और जोखिमों को संगठन नियंत्रित कर सकता है, से जुड़ी विधायी अपेक्षाओं एवं जानकारी को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए नीति और लक्ष्य तय कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंधन कर सकता है। कुल प्रचालित 102 ओएचएसएमएस लाइसेंसों में ताप पॉवर संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कर्मचारी विकास केन्द्र, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत एवं दूरसंचार केबल, पैट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक और विस्फोटक रसायन, रेलवे आदि तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।

iv) आईएस 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) योजना

बीआईएस आईएस 15000 : 1998 के अनुसार स्टैंड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2017 को दो एचएसीसीपी स्टैंड एलोन लाइसेंस तथा क्यूएमएस के साथ एकीकृत 35 लाइसेंस प्रचालन में थे।

v) आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (एफएसएमएस) का प्रचालन कर रहा है। इस पद्धति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी

प्रकार के संगठन खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। 31 मार्च 2017 को 14 एफएसएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे।

vi) आईएस 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना

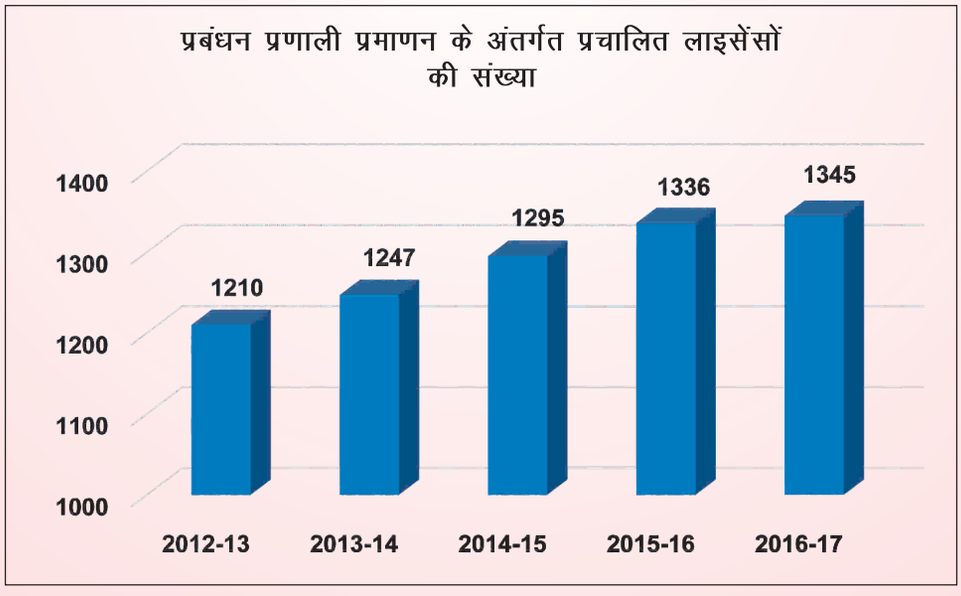
सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) योजना अप्रैल 2007 में आरंभ की गई थी। यह आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धतियाँ – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक जन सेवा संगठनों द्वारा एक्रॉस द काउंटर गुणतायुक्त सेवा की सुपुर्दगी पर बल देता है यह लाइसेंस उन जन सुपुर्दगी संगठनों को दिया जाता है जो इस मानक का कार्यान्वयन करते हैं। 31 मार्च 2017 को कुल 101 लाइसेंस प्रचालन में थे।

vii) आईएस 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) प्रमाणन योजना

बीआईएस ने आईएस 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना 2013 में प्रारंभ की । इस योजना को कार्यान्वित करके कोई भी संगठन अनुकूलतम ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, जिससे वह ऊर्जा की लागत को न्यूनतम कर सकता है तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। 31 मार्च 2017 को 20 ईएनएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे ।

viii) आईएस/आईएसओ 13485 : 2003 के अनुसार चिकित्सा उपकरण प्रबंध पद्धति (एमडीएमएस) प्रमाणन योजना

चिकित्सा उपकरण प्रबंध पद्धति बीआईएस द्वारा जून 2016 में आरंभ की गई थी। मानक के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए इस पद्धति में एक लाइसेंस दिया गया है, ताकि चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं को इस पद्धति में अपने उत्पादों की मार्किटिंग में लाभ मिल सके, इसलिए इस मानक के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा रहा है ।



ix) क्यूएमएस और ईएमएस का प्रत्यायन

बीआईएस की गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएँ, प्रमाणन निकायों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और भारतीय गुणता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा अनेक क्षेत्रों के लिए प्रत्यायित हैं।

x) प्रबंध पद्धति प्रमाणन का संवर्धन

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए, बीआईएस ने मारुति सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के विक्रेताओं और बीआईस के बीच मारुति सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (एमएसीई) के साथ दिनांक 18.5.2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। बीआईएस ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के माध्यम से मारूति उद्योग लिमिटेड के विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गुणवत्ता के प्रचार के लिए मारूति सेंटर ऑफ एक्सलेंस (एमएससीई) के साथ 18 मई 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi) ऑडिटरों की बैठकें

इस अवधि के दौरान पूर्वी, दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालयों – प्रत्येक में एक–एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में पद्धति प्रमाणन ऑडिट करने के लिए पंजीकृत बाहरी ऑडिटरों और बीआईएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ और तकनीकी सूचना सेवाएँ

क) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में सहभागिता

- भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) का सदस्य है तथा इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेता है। ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में विभिन्न तकनीकी समितियों और उप–समितियों के भागीदारी (पी) सदस्य या पर्यवेक्षक (ओ) सदस्य के रूप में; और कार्यकारी समूहों में तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करके सक्रिय योगदान देता है।

  31 मार्च 2017 तक बीआईएस आईएसओ की 433 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 86 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'पी' सदस्य है तथा आईएसओ की 219 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईइसी की 72 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'ओ' सदस्य है। भारत के हितों से जुड़े विषयों की 8 महत्त्वपूर्ण आईएसओ समितियों के सचिवालय बीआईएस के माध्यम से भारत के पास है।

- वर्तमान में बीआईएस 16 आईएसओ कार्यकारी समूहों का संयोजनकर्त्ता है जिनमें से दो कार्यकारी समूहों, अर्थात् ''व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग की प्रबंध पद्धति पर मानक'' आईएसओ/आईईसी जेटीसी 1/एससी 40/एसजी 4 तथा कंक्रीट परीक्षण से संबंधित आईएसओ/टीसी 71/एससी 1/डब्ल्यूजी 5 का दायित्व 2016–17 में बीआईएस को मिला है। इसी प्रकार आईईसी प्रबंध के 5 वर्किंग समूह/टास्क समूह की कन्वीनरशिप भारत के पास है।

- बीआईएस आईएसओ और आईईसी की विभिन्न नीति–निर्धारण बैठकों में भी भाग लेता है। भारत (बीआईएस) 2015–2017 तक आईइसी के स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का सदस्य है और 2017–2019 तक की अवधि के लिए आईएसओ परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है। बीआईएस आईएसओ की तीन नीति निर्धारक समितियों, कमेटी ऑफ कन्फर्मिटी अफेयर्स (सीएएससीओ), कमेटी ऑन कन्ज्यूमर पोलिसी (सीओपीओएलसीओ) और कमेटी ऑफ डवलपिंग कन्ट्री मैटर्स पर समिति (डीईवीसीओ) का 'पी' सदस्य है।

- बीआईएस की तकनीकी समिति के सदस्य और बीआईएस के अधिकारियों ने विभिन्न आईएसओ/आईइसी की तकनीकी समितियों में भाग लिया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मुख्यतः पर्यावरण प्रबंध, सूक्ष्म प्रोद्यौगिकी, आईटी सुरक्षा उपकरण, रबर इत्यादि के निर्धारण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। भारत खाद्य एवं शिक्षा, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, बाह्य संक्षारण से संरक्षण के लिए प्रणाली, रबर उत्पाद और इसके परीक्षण के तरीके, स्वचल वाहनों के लिए रबर पल्ला, हाईड्रोमीटरी, प्राकृतिक डाई ज्ञात करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न आईएससो परियोजनाओं में अग्रणी है। इस अवधि के दौरान, भारत ने सूक्ष्म प्रोद्यौगिकी, कंक्रीट रोड़ी और ऑनलाइन प्राइवेसी सूचना और सहमति से संबंधित नई कार्य मदों को भी प्रस्तावित किया। भारतीय विशेषज्ञों ने ऐसे क्षेत्र, जहाँ भारत का विशेष हित हो, में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण कार्य संचालित करने के लिए विभिन्न कार्य समूहों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- बीआईएस के अधिकारियों ने आईएसओ/आईईसी की विभिन्न तकनीकी समिति के 24 प्रतिनिधिमंडलों में भाग लिया।

आईएसओ/आईईसी बैठकों और अन्य संबंधित आयोजनों में सहभागिता

- बीआईएस ने 4 से 8 अप्रैल 2016 के दौरान नई दिल्ली में आईएसओ/टीसी 85 'नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, और रेडियोलॉजिकल संरक्षण', इसकी उपसमितियों और कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित कीं।

आईएसओ/टीसी 85 के नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग, नाभिकीय प्रौद्योगिकी और विकिरणों के आयनीकरण के सभी स्रोतों के खिलाफ वैयक्तिक और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में आईएसओ मानकों के विकास में शामिल किया जाता है ।

- आईईसी महासचिव और सीईओ, श्री फ्रांस ब्रीजविक ने अगले आईईसी मास्टर प्लान पर भारतीय उद्योग और बीआईएस के साथ संवाद करने के लिए 25 अप्रैल 2016 को बीआईएस का दौरा किया ।

- आईएसओ कार्यकारी महासचिव, श्री केविन मैककिंले ने 28 अप्रैल 2016 को आईएसओ रणनीतिक योजना 2016–2020 के कार्यान्वयन पर भारत के स्टेकधारकों को अपडेट करने के लिए, 2016–20 के विकासशील देशों के लिए आईएसओ एक्शन प्लान और सिंगापुर में आईएसओ के क्षेत्रीय कार्यालय का संचालन करने के लिए बीआईएस का दौरा किया ।

- बीआईएस ने अपने युवा व्यावसायिकों के लिए 21 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य मानकों के महत्त्व की सराहना करने के लिये विद्युत तकनीकी उद्योग के युवाओं को मदद करना था । यह 17 फरवरी 2017 को मुम्बई में आयोजित दूसरे युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के बाद किया गया। उपरोक्त कार्यशालाओं में श्री डेनिस च्यू, क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी), एशिया प्रशांत क्षेत्रीय केंद्र ने विद्युत तकनीकी सेक्टर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण पर स्पीकर के रूप में भाग लिया ।

- महानिदेशक बीआईएस के नेतृत्व में तीन सदस्यीय का प्रतिनिधि मंडल ने 11–14 सितंबर 2016 के दौरान बीजिंग, चीन में आईएसओ महासभा (जीए) और संबंधित बैठकों में भाग लिया । इस मौके पर बेलारूस, यूरोपीय संघ, फ्रांस, ईरान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर अनौपचारिक बैठकें आयोजित की गई ।

- महानिदेशक बीआईएस के नेतृत्व में तीन सदस्य का प्रतिनिधि मंडल ने 11 से 14 अक्तूबर 2016 तक फ्रेंकफर्ट, जर्मनी में आईईसी महासभा 2016 में भाग लिया । आईईसी बैठकों के अतिरिक्त, आईईसी की फ्रांस राष्ट्रीय समिति और विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी (वीडीई) की एसोसिएशन, जर्मनी की अनौपचारिक बैठकें, मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए, की गईं ।

- भारत ने अल्प वोल्टता प्रत्यक्ष करंट (एलवीडीसी) पर आईईसी पद्धति मूल्यांकन समूह 4 की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया । एलवीडीसी और विद्युत एक्सेज पर हाल ही में बनाई गई पद्धति समितियों के संयोजक के रूप में भारतीय नामित व्यक्ति को संयोजक नियुक्त किया गया।

- बीआईएस ने 19–20 जनवरी 2017 के दौरान एनआईटीएस, नोएडा में आईएसओ/आईईसी तकनीकी समितियों के संयोजक और अध्यक्ष के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों और समितियों को हैंडल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- बीआईएस ने भारतीय मसाले बोर्ड के सहयोग से 24–25 जनवरी 2017 के दौरान कोच्ची में आईएसओ/टीसी34/एससी7 'मिर्च मसाले, व्यंजन जड़ी–बूटी और मसाले' की बैठक आयोजित की। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और इसके पास आईएसओ/टीसी34/एससी/7 का सचिवालय है ।

क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों में सहभागिता

- बीआईएस पेसिफिक एरिया स्टैण्डर्डस प्रशांत कांग्रेस (पीएएससी) के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। महानिदेशक, बीआईएस के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 10–14 मई 2016 में बाली, इंडोनेशिया में 39वीं

पीएएससी बैठक में भाग लिया । पीएएससी द्वारा किये जा रहे मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन करने से संबंधित गतिविधियों के अपडेट पीएएससी देशों और अन्य प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन को दिये गये और पीएएससी रणनीति योजना 2016–20 के साथ इसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर निर्णय लिया गया।

- बीआईएस सार्थक रूप से साउथ एशियन रीजनल स्टैण्डर्डस ऑर्गेनाइजेशन (सारसो) की गतिविधियों में योगदान देता आ रहा है । भारत ने अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक सारसो के तकनीकी प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। भारत को मार्च 2017 से लेकर दो वर्ष की अवधि के लियेसारसो गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ।

- भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मई 2016 में कोलम्बो, श्री लंका में 'खाद्य और कृषि उत्पादों' और भवन निर्माण सामग्रियों पर सारसो सेक्टोरल तकनीकी समिति (एसटीसी) की बैठकों में भाग लिया ।

- बीआईएस ने सारसो के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया में मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुमेलन पर सारसो की संवर्धनात्मक गतिविधियों के भाग के रूप में 27 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय मानकीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया ।

- सारसो तकनीकी प्रबंध बोर्ड (एसएआरएसओ) की चौथी बैठक और सारसो गवर्निंग बोर्ड की पाँचवी बैठक क्रमशः 27 फरवरी 2017 और 28 फरवरी से 1 मार्च 2017 तक ढाका, बंगलादेश में हुई और उनकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। पहले तीन सार्क मानकों (बिस्कुट, परिष्कृत चीनी और स्वच्छता संबंधी रीति संहिता) को इन बैठकों में अनुमोदित किया गया। इन बैठकों में एसएआरएसओ निर्देशों को अंतिम रूप देकर अनुमोदित किया गया ।

- 'वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित भारत–यूरोपीय सहयोग का व्यापार विकास, जिसमें से बीआईएस पहचान किये गये लाभार्थियों में एक है, की क्षमता निर्माण पहल, इस (ईयू–सीआरटीटी) परियोजना के अन्तर्गत बीआईएस के 5 अधिकारियों का दल और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के एक अधिकारी ने 30 जनवरी से 3 फरवरी 2017 को मानकीकरण पर यूरोपियन कमेटी ऑफ स्टैण्डर्डाजेशन (सीईएन), ब्रूसेल्स और ब्रिटिश स्टैण्डर्डस इन्स्टीट्यूट (बीएसआई), लंदन में अंर्तराष्ट्रीय मानकीकरण, क्षेत्रीय मानकीकरण और आईटी संबंधित सेवाओं में इस संगठनों द्वारा अपनाई जा रही रीतियों को समझने के लिए अध्ययन दौरे में भाग लिया ।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में सहभागिता

- बीआईएस ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेशों मंत्रालय के निकट सहयोग से जर्मनी, बंगलादेश, भूटान, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, ओमान, स्लोवाकिया, ताईवान और, कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखा। बीआईएस ने विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ मानकों, अनुरूपता मूल्यांकन, परीक्षण और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और एक–दूसरे की अनुरूपता मूल्यांकन के परिणाम कीआपसी स्वीकार्यता के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और एमआरए किया । बीआईएस ने अभी तक 32 समझौता ज्ञापनों और 6 एमआरए पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से 7 समझौता ज्ञापन और 1 एमआरए को 2016–17 के दौरान अंतिम रूप दे दिया है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान की गई महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नानुसार है :

  i) बीआईएस और सऊदी स्टैण्डर्डस मैट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन (एसएएसओ), सऊदी अरब के बीच तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर 3 अप्रैल 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के 2–3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान हस्ताक्षर किये गये ।

  ii) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केन्या ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्डस (केईबीएस) के बीच 11 जुलाई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री के केन्या के सरकारी दोरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

iii) भारतीय मानक ब्यूरो और डाइरेक्टॉरेट फॉर स्टैण्डर्डस मैट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ वियतनाम (एसटीएएमईक्यू) के बीच मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 सितंबर 2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

iv) बीआईएस और स्टैण्डर्डस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाइजीरिया मानक संगठन के बीच 27 सितंबर 2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये ।

v) बीआईएस और डायरेक्शन नेशनल डे इंडस्ट्रीज, माली के बीच मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए 29 सितंबर 2016 को भारत सरकार एवं माली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये ।

vi) बीआईएस और एबीएनटी, ब्राजील के बीच दोनों पक्ष देशों के बाजार में पहुँच की सुविधा प्रदान करने के लिए व एक–दूसरे की अनुरूपता मूल्यांकन के परिणामों की आपसी स्वीकार्यता के लिए 24 अक्तूबर 2016 को परस्पर मान्यता करार (एमआरए) पर हस्ताक्षर किये गये ।

vii) भारत–ग्रीस की संयुक्त आर्थिक समिति का सातवाँ सत्र 23 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में हुआ जिसके दौरान द्विपक्षीय चर्चाओं में, बीआईएस और हैलोनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैण्डर्डाइजेयान (एनक्यूआईएस/ईएलओटी), ग्रीस के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया ।

viii) बीआईएस और नेशनल स्टैण्डर्डाजेशन एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया के राष्ट्रीय एजेंसी (बीएसएन) के बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान 12 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में मानकीकरण, तकनीकी सूचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

ix) बीआईएस ने यूरोपीय संघ के क्षेत्रीय मानक निकाय अर्थात् सीईएन के साथ भारत में राष्ट्रीय अधिग्रहण के लिए एस्केलेटर के निर्माण और संस्थापन और यात्री के सुरक्षा नियम के ईएन 115:1995+ए2:2004 अंश के उपयोग के लिए मार्च 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

- मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग के लिए इंडो–जर्मन कार्यकारी समूह गुणता अवसंरचना :

i) जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड एनर्जी और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 11 अप्रैल 2013 को हुई संयुक्त घोषणा के आधार पर इंडो–जर्मन कार्यकारी समूह स्थापित किया गया । इंडो–जर्मन जे डब्ल्यू जी का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना, उपभोक्ताओं तथा उद्योग के लाभ के लिए उत्पाद सुरक्षा पर वार्तालाप को अधिक सघन करना और द्विपक्षीय व्यापार में सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के क्षेत्र में समन्वित गतिविधियों का संवर्धन करना है। 2016–17 वर्ष के दौरान, वर्ष 2016 के लिये कार्य योजना के अंतर्गत पहचान की गई विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण किया गया, उनमें स्मार्ट ग्रिड, एलवीडीसी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधक उत्पाद सुरक्षा, इत्यादि के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

ii) मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग के लिए गुणता अवसंरचना पर इंडो–जर्मन कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 6–7 मार्च 2017 को बर्लिन, जर्मनी में हुई । सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया । बैठक के दौरान 2016 के दौरान कार्यकारी समूह द्वारा की गई प्रगति तथा मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रत्यायन, उत्पाद सुरक्षा और बाजार निगरानी के क्षेत्रों में 2017 की गतिविधियों की चर्चा की गई । अगले वर्ष के लिए विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्य योजना पर सहमति दी गई जिसमें अन्य के अलावा, मशीनरी सुरक्षा, स्मार्ट ग्रिड, एलवीडीसी, खिलौने, दाबकृत उपस्कर, स्वचल, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा पर सहयोग शामिल हैं ।

ख) तकनीकी सूचना सेवाएँ एवं डब्ल्यूटीओ–टीबीटी जाँच बिंदु

बीआईएस उद्योग, आयातकर्त्ता, निर्यातकर्त्ता और सरकारी एजेंसी को उनके प्रश्नों के उत्तर में मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में तकनीकी सूचना सेवाएँ प्रदान करता है । अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 1079 प्रश्नों के उत्तर दिये गये ।

डब्ल्यूटीओ–टीबीटी पूछताछ बिंदू और व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ

- बीआईएस ने भारत के डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ बिंदु के रूप में अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं बीआईएस ने बीआईएस वेबसाइट पर सभी डब्ल्यू–टीबीटी अधिसूचनाओं को होस्ट करने के साथ–साथ ई–मेल द्वारा पंजीकृत स्टेकहोल्डरों के टीबीटी अधिसूचना वितरित करने के लिए अपने टीबीटी नोटिफिकेशन पोर्टल को विकसित किया और इसे आपरेशनल बनाया । यह पोर्टल स्टेकहोल्डरों को टीबीटी अधिसूचनाओं को प्राप्त करने और उन पर ऑनलाइन सम्मतियाँ देने के लिए एक कॉमन विंडो प्रदान करता है। यह साफ्टवेयर भारतीय निर्यातकर्त्ताओं के सामने की आ रही व्यापार से संबंधित चुनौतियों पर सूचना एकत्रित करने की आशा से बनाया गया है, ताकि उनको डब्ल्यूटीओ में उचित रूप से उठाये जा सके ।

- बीआईएस ने टीबीटी समिति की बैठकों में मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं, विशेष रूप से टायर, इस्पात, अनिवार्य पंजीकरण योजना और विदेशी विनिर्माताओं की प्रमाणन योजना का अनिवार्य प्रमाणन, के संबंध में तत्संबंधी मुद्दों पर अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा उठाये गये विशेष व्यापार मुद्दों (एसटीसीएस) पर उत्तर तैयार करना जारी रखा ।

- बीआईएस ने यूरोपीय संघ – भारत टीबीटी/एसपीएस संयुक्त कार्यकारी समूह की 11 नवंबर 2016 को ब्रूसेल्स में हुई बैठक में भाग लिया जहाँ भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच टीबीटी/एसपीएस से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई ।

- बीआईएस ने आरएसईपी के तहत 'मानकों, तकनीकी नियमों और अनुरूपता प्रक्रियाओं (एसटीआर एसीएपी) के चैप्टर पर इनपुट और विचार–विमर्श के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित की गई विभिन्न बैठकों में भाग लिया, 16 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता–हुई जिसमें आसियान के 10 सदस्य और उनके 6 सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक भागीदार शामिल थे ।

- बीआईएस ने वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा गैर–टैरिफ मापन (एनटीएम) और सेवाओं पर संगोष्ठी में भाग लिया जो ब्रिक्स सहयोग के फ्रेमवर्क के अन्तर्गत 11 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई बीआईएस द्वारा एनटीएम के सत्र में 'भारत में मानकीकरण' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

पहचान संख्याओं की स्पोन्सरशिप

- **जारीकर्त्ता पहचान संख्या (आईआईएन)**

  बीआईएस, आईएसओ/आईसी 7812 के अनुसार आईएसओ/आईईसी 7812 'पहचान कार्ड – जारीकर्त्ता की पहचान' बैंकों/वित्तीय संगठनों के अमेरिकन बैंकर्स एसोशिएशन (एबीए) से प्राप्त आवेदन को प्रायाजित करके आईआईएन जारी करने को सुगम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय और/अथवा अंतर–उद्योग, विनिमय में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारीकर्त्ताओं की पहचान के लिए एक संख्यांकन पद्धति निर्दिष्ट करता है । आईएसओ/आईईसी 7812 अंतर्राष्ट्रीय तथा/अथवा अन्तर उद्योग अंतर परिवर्तन में प्रयुक्त पहचान कार्ड के जारीकर्त्ता की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली निर्दिष्ट करता है। बीआईएस मैसर्स नेशनल पेमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत में रिटेल भुगतान के लिए (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अम्ब्रेला संगठन के रूप में संस्थापित स्वायत्त निकाय) का आवेदन

लिया है ताकि कार्ड स्कीम ब्लॉक होल्डर के अंतर्गत 3000 आईआईएन के प्रक्रमण के लिए भारत सरकार के डिजिटल भारत की पहल को आगे बढ़ाने में सुविधा दी जा सके ।

- **विश्व विनिर्माता पहचानकर्त्ता (डब्ल्यूएमआई) संख्या**

सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के समन्वय से बीआईएस भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं एवं निर्यातकों को इस अवधि में आईएसओ 3780 : 2009 'सड़क वाहन – विश्व विनिर्माता पहचानकर्त्ता (डब्ल्यूएमआई) कोड' के अनुसार डब्ल्यूएमआई कोड आबंटित करता है। 2016–17 की अवधि के दौरान विभिन्न वाहनों को 180 डब्ल्यूएमआई कोड आबंटित किये गये ।

प्रशिक्षण सेवाएँ

बीआईएस के अंतर्गत 1995 में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना की गई। इस संस्थान की स्थापना मानकीकरण, गुणता आश्वासन, प्रबंध पद्धति, प्रमाणन प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ती अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के गुणतापरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई थी । एनआईटीएस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लेटिन और दक्षिणी अमरीका के विकासशील देशों के लिए भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये कार्यक्रम बहुत अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित संकाय टीम द्वारा संचालित किए जाते हैं।

2016–17 वर्ष के दौरान एनआईटीएस ने उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों और बीआईएस के अधिकारियों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। इस अवधि के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए और अनेक व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षित किये गए। इस अवधि के दौरान संचालित किये गये कुल कार्यक्रम 177 हैं। उद्योग के लिए 2016–17 के दौरान प्रशिक्षित किये गए व्यक्तियों की संख्या 2 355 थी, जो पिछले वर्ष के 2 075 की संख्या से लगभग 13.5 % अधिक थी।

I. विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2016–17 के दौरान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय मदद से तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसमें प्रशिक्षित किये गये प्रतिभागियों की संख्या 98 थी जो पूर्व वर्ष से 11 अधिक थे। इन कार्यक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क) प्रबंध पद्धतियों पर तेरहवां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 अगस्त – 23 सितम्बर 2016 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें 13 विकासशील देशों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

ख) 'मानकीकरण और गुणता आश्वासन' पर उन्चासवां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अक्तूबर से 9 दिसम्बर 2016 तक आयोजित किया गया और इसमें 27 विकासशील देशों के 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर 49वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईटीएस द्वारा 30 जनवरी से 17 फरवरी 2017 को संचालित किया गया। 3 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 24 देशों के 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।



प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

II. उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2016–17 के दौरान एनआईटीएस ने उद्योग के लिए 142 कार्यक्रम आयोजित किये, जो पिछले वर्ष की संगत संख्या से लगभग 17 अधिक हैं । इसमें आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएस 15700 के लिए लीड ऑडिटर, आईएसओ 9001 : 2015 एवं आईएसओ 14001 : 2015 पर खाद्य निरापादता प्रबंध ट्रांजिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईएसओ 22000 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति पर एप्रिशियेशन कार्यक्रम, आईएसओ 17025 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति, प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति, आईएसओ 15189 के अनुसार चिकित्सा, प्रयोगशाला प्रबंध पद्धति मापन अनिश्चितता, अंतर प्रयोगशाला तुलना एवं स्कोर का मूल्यांकन, पैकेजबंद पेयजल के लिए उत्पाद विशेष परीक्षण इत्यादि शामिल थे। प्रतिष्ठित संगठन, जैसे आयुध कारखाने, एयर इंडिया, आईएआरआई, एनटीपीसी, बीएचएल, अडानी पावर लिमिटेड, एनएटीआरआईपी, एआईआईएमएस, भारतीय रेलवे, नेस्ले लि., डाबर लि., इत्यादि जैसे कुछ ग्राहक शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संगठनों, तकनीकी समिति के सदस्यों इत्यादि के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये।

III. बीआईएस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2016–17 के दौरान केवल बीआईएस अधिकारियों के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

i) वैज्ञानिक –बी (2016 बैच) के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

ii) आईएस/आईएसओ 9001 : 2015 के अनुसार क्यूएमएस पर ट्रांजिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

iii) नये नियुक्त किये गये यूडीसी के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

iv) अनुरूपता की स्वयं–घोषणा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

v) नये भर्ती किये गये तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) एवं वरिष्ठ मास्टर तकनीशियन के लिए प्रेरण कार्यक्रम

vi) उत्पाद प्रमाणन पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

vii) समूह 'ख' एवं 'ग' के कर्मचारियों के लिए छुट्टी, टीए एवं चिकित्सा नियम, जीएफआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

viii) आईएस/आईएसओ 17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति और ऑडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ix) आईएस 12 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

x) आरटीआई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

xi) नये भर्ती किये गये कनिष्ठ आशुलिपिकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण

xii) एलडीसीई परीक्षा के लिए अनुभाग अधिकारी/पीएस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

xiii) निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

xiv) पैकेजबंद पेयजल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

xv) आईएस 694 : 2010 के अनुसार पीवीसीरोधी केबलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

xvi) हॉलमार्किंग पर समूह 'क' अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक हेतु प्रशिक्षण

बीआईएस कार्मिकों के लिए अवधि के दौरान लगभग 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये इन कार्यक्रमों में लगभग 715 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

IV. एनआईटीएस द्वारा विकासित नये कार्यक्रम : अवधि के दौरान निम्नलिखित नये कार्यक्रम विकसित किये गये :

- ईएमएस और ओएचएसएमएस पर आधारित आपात्कालीन तैयारी
- आईएस 16001 : 2012 के अनुसार सामाजिक जवाबदेही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपभोक्ता मामले

बीआईएस अपने सभी स्टेकहोल्डरों को अपनी सेवाएँ और मानकीकरण तथा प्रमाणन के लाभ केंद्रित और समयबद्ध तरीके से देने का प्रयास करता है। बीआईएस का उपभोक्ता मामले विभाग, विभिन्न उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ संचालित करता है। इन गतिविधियों में लोक शिकायतों का निवारण, बीआईएस के स्टेकहोल्डरों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार तथा विश्व मानक दिवस आयोजित करना शामिल है।

i) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम :

उपभोक्ताओं में मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता के प्रति सजगता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित आधार पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान देश भर में ऐसे 163 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii) उद्योग जागरूकता कार्यक्रम :

उद्योगों में मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंध पद्धति प्रमाणन तथा बीआईएस की अन्य गतिविधियों का प्रसार करने के लिए वर्ष के दौरान 62 उद्योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भाषण एवं विचार–विमर्श सत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में क्षेत्र विशेष में उद्योगों की सघनता के अनुरूप विशिष्ट संबद्ध औद्योगिक सेक्टर मानकों पर भी प्रकाश डाला गया।

iii) मानक शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रम :

बीआईएस स्कूल और कॉलेज इत्यादि के छात्रों और अध्यापकों के लिए मानक शैक्षणिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम युवा लोगों को मानकीकरण की अवधारणाओं तथा उनसे होने वाले फायदों के बारे में समझाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारे देश के औद्योगिक विकास में मानकीकरण के महत्त्व को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि तकनीकी संस्थानों के छात्रों को मानकीकरण के सिद्धांतों और रीतियों से अवगत कराया जाए। वर्ष के दौरान बीआईएस ने मानक शैक्षणिक उपयोगिता के 39 कार्यक्रम आयोजित किए।



23 फरवरी 2017 को चेन्नई में मानकों के शैक्षणिक उपयोगिता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन

iv) विश्व मानक दिवस

बीआईएस ने 14 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में विश्व के उन सभी विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया जिनके स्वेच्छा से विकसित किए गए तकनीकी करार अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। 2016 के विश्व मानक दिवस का थीम ''मानक – विश्वास का आधार'' था। इस अवसर पर बीआईएस ने इस थीम पर संगोष्ठी का आयोजन किया। बीआईएस के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों ने देश भर में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किए।



नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस का आयोजन



कोलकाता में विश्व मानक दिवस का आयोजन

v) सार्वजनिक शिकायतें :

बीआईएस सुस्थापित शिकायत निपटान प्रणाली का अनुकरण करता है। उपभोक्ता ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से बीआईएस प्रमाणित उत्पादों से संबद्ध शिकायतें कर सकते हैं व निपटान के लिए शिकायतों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर सकते हैं। वर्ष के दौरान 57 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं वर्ष के दौरान 91 शिकायतों का निपटान किया गया।

vi) सिटीजन चार्टर :

सिटीजन चार्टर कार्यान्वित किया गया है और प्रबंध नियंत्रण रिपोर्टो के माध्यम से प्रत्येक माह, समय–सीमा की मॉनिटरिंग की जाती है।

vii) प्रवर्तन :

बीआईएस मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणता की मुहर है। उपभोक्ताओं के साथ साथ संगठित क्रेता आईएसआई मुहर लगे उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ धोखेबाज विनिर्माता बीआईएस से लाइसेंस प्राप्त किये बिना नकली आईएसआई मुहर लगाकर उत्पादों का उत्पादन तथा मार्केटिंग करके उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास करते हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान बीआईएस ने देशभर में आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर 114 तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाए और ऐसे उत्पाद जब्त किए गए। दोषियों के खिलाफ न्यायालय में समय से अभियोजन शुरू करने के लिए प्रयास किए गए। बीआईएस ने मारे गए प्रवर्तन छापों के बारे में व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ भी जारी कीं, ताकि आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा की जा सके।

प्रचार

बीआईएस की प्रचार गतिविधियों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य बीआईएस की गतिविधियों, मुख्य रूप से मानकीकरण, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रमाणन और सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया।

बीआईएस द्वारा हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों एवं बीआईएस द्वारा प्रमाणित आईएसआई मुहरांकित चीजें खरीदने हेतु आम उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जोर–शोर से प्रचार अभियान चलाया गया तथा उन्हें बीआईएस प्रमाणित सामानों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु बीआईएस द्वारा बनाई गई प्रणाली के संबंध में भी सूचित किया गया। बीआईएस की विविध गतिविधियों की जानकारी के प्रसार के लिए बीआईएस ने लोकप्रिय उपभोक्ता और औद्योगिक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष 2016–17 में प्रचार गतिविधियों का विशेष विवरण निम्नानुसार है :

इलैक्ट्रॉनिक

टीवी

- 9 से 23 अगस्त 2016 को हिंदी में आईएसआई मुहर पर डीडी भारती, डीडी न्यूज़, डीडी उर्दू, डीडी इंडिया एवं डीडी किसान पर 15 दिन का प्रचार अभियान।
- 26 अक्तूबर से 1 नवम्बर 2017 (त्यौहारी मौसम) तक डीएवीपी के माध्यम से राष्ट्रीय समाचार एवं मनोरंजन चैनलों पर प्रचार अभियान।
- 1 फरवरी 2017, केंद्रीय बजट के दिन (स्पॉन्सरशिप द्वारा संयुक्त रूप से) डीडी नेशनल एवं डीडी न्यूज़ पर हॉलमार्किंग स्पॉटों का प्रसारण।

रेडियो

- 20 जुलाई 2016 से आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 30 दिनों का प्रचार अभियान।
- 13 से 23 जनवरी 2017 तक प्रसिद्ध सीरियल 'महाभारत' के प्रसारण के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर हॉलमार्क पर 10 ऑडियो स्पॉट का प्रसारण।

बाहरी

- 20 अप्रैल से 19 मई 2016 तक आईएसआई मुहर पर 30 दिनों के लिए पटना एयरपोर्ट पर प्रचार।
- 4 मई 2016 से 30 दिनों के लिए हॉलमार्क एवं आईएसआई मुहर पर भोपाल एयरपोर्ट पर प्रचार।
- 1 से 30 अक्तूबर 2016 तक 30 दिनों के लिए विभिन्न आउटडोर मीडिया पर डीएवीपी के माध्यम से प्रचार।
- 17 फरवरी 2017 से 30 दिनों के लिए होर्डिंगों, यूटिलिटी, रेलों, मैट्रो, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों पर आईएसआई एवं हॉलमार्क पर अखिल भारतीय स्तर पर अभियान।
- 1 से 15 फरवरी 2017 तक ''सूरज कुंड मेला'' में 4 विशाल होर्डिंग।
- आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क के लिए 1 मार्च 2017 से 30 दिनों के लिए बेस्ट की बसों, बस के पिछले पैनलों, एयरपोर्ट, होर्डिंगों, बस स्टैंडों पर ऑडियो घोषणा कर अभियान।

प्रिंट

- 2 मई 2016 से 'बीआईएस की पंजीकरण योजना' पर एक माह का अभियान।
- हॉलमार्क पर 9 मई 2016 को ''अक्षय तृतीया'' के अवसर पर विज्ञापन प्रकाशित।
- अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में स्वतंत्रता दिवस पर एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।
- अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 14 अक्तूबर 2016 को विश्व मानक दिवस को एक विज्ञापन प्रकाशित।

बीआईएस मीडिया कवरेज

- बीआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं लोकप्रिय करने के लिए बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार रेडियो एवं टीवी पर वर्ष के दौरान दिए ।
- वर्ष के दौरान हॉलमार्क, हैलमेट, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता इत्यादि सहित बीआईएस प्रमाणित उत्पादों एवं बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों संबंधी विशेष न्यूज़ स्टोरी विभिन्न समाचार–पत्रों एवं टीवी चैनलों पर प्रसारित हुई ।

  बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित 31 प्रेस नोट जारी किए गए और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुए।

मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

बीआईएस अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में स्थित 25 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानक और विशेष प्रकाशनों की बिक्री करता है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। बीआईएस भारत में विदेशी मानकों (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जेआईएस, जापान) की भी बिक्री करता है। बीआईएस अपने ई–पोर्टल के माध्यम से भी भारतीय मानकों की बिक्री करता है। मानकों को बीआईएस के ई–पोर्टल से साफ्टकॉपी के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा ई–पोर्टल द्वारा हार्डकॉपी के लिए भी क्रयादेश दिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भी ग्राहक मानकों हेतु भुगतान कर सकते हैं।

भारतीय मानक पूरे सेट के रूप में अथवा सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल इत्यादि जैसे 14 क्षेत्रों के लिए अलग–अलग विशेष सेटों के रूप में डीवीडी पर लीज के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई 2016 से भारतीय मानक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी उपलब्ध कराए गए हैं।

2016–17 के दौरान अब बीआईएस ने शैक्षिक संस्थानों, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं, कन्सोट्रिया के माध्यम से संचालित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संगठनों के लिए सब्सक्रिप्शन के आधार पर डीवीडी/ऑनलाइन भारतीय मानक उपलब्ध करा दिए हैं।

ग्राहकों की सुविधा हेतु बीआईएस मुख्यालय के बिक्री–विभाग में बीआईएस ई–पोर्टल (www.standardsbis.in) से जुड़े टच स्क्रीन कियॉस्क उपलब्ध कराया गया है। इस पर उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार मानक खोज सकते हैं, मानकों का मूल्य, विषय क्षेत्र, संशोधन इत्यादि देख सकते हैं।

हिन्दी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा संबंधी अधिनियमों, नियमों, निर्देशों एवं आदेशों का पालन कर रहा है। तदनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए।

हिंदी कार्यान्वयन– बीआईएस के सभी विभागों को राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया। बीआईएस मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें समय से आयोजित की गईं। चार तिमाहियों की हिंदी की प्रगति रिपोर्ट समय पर मंत्रालय को भेजी गई। वर्ष के दौरान बीआईएस के विभिन्न कार्यालयों में 21 हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 350 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । ब्यूरो ने हिंदी टिप्पण एवं आलेखन संबंधी नकद प्रोत्साहन योजना, हिंदी डिक्टेशन योजना, हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना इत्यादि जैसी सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखा। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों का अनुपालन किया गया। हिंदी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के 24 निरीक्षण किए गए जिसमें मुख्यालय के 12 तकनीकी विभागों का राजभाषा निरीक्षण भी शामिल है।

हिंदी पखवाड़े का आयोजन– ब्यूरो मुख्यालय में 01 से 14 सितम्बर 2016 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी संबंधी छह प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के 27 सफल प्रतियोगियों को 16 सितम्बर 2016 को हुए समारोह में महानिदेशक महोदया द्वारा पुरस्कार दिए गए।



नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

हिंदी प्रशिक्षण– राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी प्रशिक्षण दिलाया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान हिंदी शिक्षण योजना के अधीन 4 कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह 28 अवर श्रेणी लिपिकों को हिंदी टंकण तथा 12 आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया गया।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण एवं अन्य बैठकें– अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने 18 फरवरी 2017 को ब्यूरो मुख्यालय की राजभाषा गतिविधियों का निरीक्षण किया। समिति ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। 03 अक्तूबर 2016 को शिलांग में माननीय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यालय की ओर से महानिदेशक महोदया ने भाग लिया। समिति के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

मानक एवं सामान्य अनुवाद– मानकों के अनुवाद में तेजी लाने के लिए उपायों के रूप में कई कदम उठाए गए। इस अवधि के दौरान 53 मानकों का अनुवाद किया गया। उपरोक्त अवधि में लगभग 540 मानकों के शीर्षकों को द्विभाषी बनाया गया।

मानकों के अनुवाद कार्य के अतिरिक्त ब्यूरो ने प्रोफार्मों, वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग पर सामग्री, विश्व मानक दिवस की सामग्री, निविदा सूचनाएँ, गजट अधिसूचनाएँ, संसदीय प्रश्नोत्तर, संशोधित एनबीसी की विवरणिका, ब्यूरो बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त आदि के लगभग 800 पृष्ठों के अनुवाद का कार्य भी किया।

योजनागत परियोजनाएँ

हॉलमार्किंग

बीआईएस केंद्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेइंग एवं हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना के लिए योजनाएँ चला रहा है। हॉलमार्किंग संबंधी योजना 10वीं योजना से प्रचालित होकर 12वीं योजना में भी जारी है। योजना के घटक निम्नानुसार हैं :

क) ढांचागत भवन निर्माण – एसेइंग एवं हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना

ख) क्षमता निर्माण

i) कारीगरों को प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षणदाताओं को प्रशिक्षण (बीआईएस ऑडिटर)

iii) एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

इस योजना के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्रीय सहायता दो किस्तों में उपलबध कराई गई। वर्ष के दौरान, 5 केंद्रों को पहली किस्त एवं 12 केंद्रों को दूसरी किस्त केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इस योजना से शुरू होकर ऐसी केंद्रीकृत सहायता प्राप्त ए एंड एच केंद्रों की कुल संख्या 78 हो गई । 2016–17 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत बीआईएस ने रू. 117.8 लाख एवं रू. 32.2 लाख (कुल राशि रू. 150 लाख) पिछले वर्ष केरीओवर के रूप में प्राप्त किये और रू. 147 लाख खर्च किये । सोलह कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम, छः ए एंड एच कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 3 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति :

राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति योजना (एनएसएस) को नीचे दर्शाये गये घटकों के साथ XIवीं योजना से शुरू करके XIIवीं योजना में प्रचालित रखा गया :

i) भारतीय मानक की स्थापना/पुनरीक्षण के अनुसंधान एवं विकास परियोजना

ii) तकनीकी समिति बैठकों में बीआईएस तकनीकी समिति सदस्यों की सघन भागीदारी

iii) संगोष्ठी/कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण

iv) अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/द्विपक्षीय बैठकों/प्रशिक्षण में सहभागिता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में बीआईएस कर्मचारियों, तकनीकी समिति सदस्यों, अन्य कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की सशक्त भागीदारी

v) भारत में आईएसओ/आईईसी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/सार्क बहुपक्षीय/द्विपक्षीय बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन

वर्ष 2016–17 के दौरान, बीआईएस ने एनएसएस गतिविधियों पर लगभग रू. 164.53 खर्च किये हैं और कोई ग्रांट प्राप्त नहीं की।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ

कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की पहलों के अनुरूप और बीआईएस के रोजमर्रा के कार्यों को पूर्णतया ऑनलाइन संचालित करने हेतु पद्धतियों के विकास एवं सतत् सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति को संसाधन के रूप में योजनाबद्ध तरीके से समर्थ बनाया जा रहा है । इसका समग्र उद्देश्य बीआईएस के स्टेकहोल्डरों के लिए दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाकर एवं विश्वसनीयता और उनकी समय से डिलीवरी सुनिश्चित करके सेवाओं में सुधार लाना है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रगति हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना

बीआईएस में नेटवर्क एवं इंटरनेट बैंडविड्थ के प्रबंधन को सरल एवं कारगर बनाने हेतु बीआईएस मुख्यालय में यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट (यूटीएम) युक्ति स्थापित की गई है। रायपुर, कोच्ची कार्यालयों तथा नोएडा के प्रशिक्षण संस्थान में 2 एमबीपीएस बैंडविड्थ की लीज लाइनें चालू की गई हैं। हमारे दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा जम्मू में शेष बचे कार्यालयों में भी बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

एकीकृत बीआईएस वेब पोर्टल

बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक एकीकृत वेब–पोर्टल विकसित किया जा रहा है । यह कार्य सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डेक), नोएडा को सौंपा गया है, जो इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन कार्य कर रहा है। इस पोर्टल (http://manakonline.in) का विकास सी–डेक एवं बीआईएस के संबंधित विभाग के साथ समन्वय से चरणबद्ध तरीके से हो रहा है ।

पहले चरण में उत्पाद प्रमाणन के लिए मॉड्यूल का विकास, प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के प्रमाणन के साथ एकीकरण, भुगतान गेटवे, उपयोगकर्ता डैशबोर्ड तथा केंद्रीय लॉगइन पूरा किया गया है। ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा का एकीकरण किया गया है। पोर्टल पर उत्पाद प्रमाणन तथा हॉलमार्किंग गतिविधियों के लाइसेंस एवं आवेदनों को पंजीकृत करने के लिए एक मॉड्यूल भी चालू किया गया है।

मॉड्यूल के दूसरे चरण में प्रबंध पद्धति प्रमाणन, हालमार्किंग, उपभोक्ता मामले प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं, और उत्पाद प्रमाणन के साथ उनके एकीकरण के लिए मॉड्यूल विकसित करने की शुरुआत की गई है और यह कार्य प्रगति पर है। ज्वैलर लाइसेंस योजना के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है। ए एण्ड एच केंद्र माड्यूल विकसित करने का कार्य भी प्रगति पर है। यद्यपि आवेदन जमा एवं जाँच करने पूरा हो चुका है, शेष बचे उप मॉड्यूल विकसित करने का अभी कार्य प्रगति पर है। प्रबंध पद्धति प्रमाणन के प्रचालन के मॉड्यूल अर्थात् पोर्टल में मौजूदा लाइसेंसधारकों का समावेशन, नए आवेदनों को रिकार्ड करने, ऑडिट प्रबंध और लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। पुनः, प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसके परीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

मानव संसाधन एवं वित्त प्रबंध पद्धति (एचएफएमएस)

लेखा एवं वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन, स्थापना, इत्यादि जैसी बीआईएस की सहायक सेवाओं का प्रबंध करने के लिए सीडेक, नोएडा से एक कस्टमाइजेबल एच एफएमएस मॉड्यूल खरीदा गया है और बीआईएस की आवश्यकताओं के अनुसार उसे कस्टमाइज किया जा रहा है। संबंधित विभागों के समन्वयन के साथ गेप विश्लेषण तथा डाटा पोर्टिंग की शुरुआत की गई है।

मानकीकरण गतिविधि हेतु साफ्टवेयर

मानकीकरण गतिविधियों के विभिन्न प्रकार्यों को पूरा करने के लिए मानक निर्धारण साफ्टवेयर का संवर्धन किया गया है। यह साफ्टवेयर मानकों के निर्धारण एवं उनके संशोधनों में शामिल सभी चरणों को स्वचालित करता है। यह तकनीकी

विभागों के कार्य का रीयल टाइम प्रोग्राम जेनरेट करता है। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के लिए एक विचार–विमर्श मंच भी है।

बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध मानक लोकेटर में प्रतिक्रिया समय, उपयोगकर्ता अनुकूलन, बेहतर संचालन करने, आदि के लिए सुधार किया गया है। यह संवर्धित संस्करण बीआईएस वेबसाइट पर लगाया गया है और कार्य कर रहा है।

प्रमाणन मुहर प्रबंध पद्धति (सीएमएमएस)

सीएमएमएस साफ्टवेयर निरीक्षण की योजना बनाने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के गुणता कार्यकारिता पैटर्न के डाटा के विश्लेषण, आवेदकों/लाइसेंसधारियों तथा कार्यशालाओं के लिए विभिन्न पत्र जेनरेट करने तथा लाइसेंस प्रदान करने, नवीकरण करने तथा लाइसेंस में अतिरिक्त वेरायटी शामिल करने, इत्यादि के आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु डाटा फॉरमेट विकसित करने के लिए बहु–उपयोगी रूपों में डाटा की उपलब्धता को सुगम बनाता है ।

अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) पोर्टल

अनिवार्य पंजीकरण योजना का प्रबंध करने के लिए एक ऑनलाइन वेब-पोर्टल चालू किया गया है। ऑनलाइन भुगतान को सरल करने के लिए इस पोर्टल के साथ भुगतान गेटवे का एकीकरण किया गया है।

प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस)

प्रयोगशाला गतिविधियों के विभिन्न प्रकार्यों को पूरा करने हेतु एलआईएमएस का संवर्धन किया गया है। एलआईएमएस ऑनलाइन परीक्षण आवेदन बनाने, नमूना प्राप्ति एवं स्वीकृति, नमूनों को इलैक्ट्रॉनिक रूप में अग्रेषित करने और संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना सरल बनाती है। व्यावहारिक मुद्दों जैसे वग्रीकृत नमूनों के लिए आईएस के अनुसार खोज फिल्टर, गलत परीक्षण आवेदनों को हटाना, नमूनों के प्रकार (आवेदक नमूना, फैक्टरी नमूना, बाजार नमूना, इत्यादि) के अनुसार नमूना कोड बनाने, आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संवर्धित किए गए हैं। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त बाह्य प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों की दैनिक निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग प्रावधान (रिपोर्ट) का समावेशन भी किया गया है।

शिकायतों के ऑनलाइन प्रबंध हेतु सॉफ्टवेयर

शिकायतकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के लिए एक साफ्टवेयर कार्यरत है। यह उन्हें अपनी शिकायतें ट्रैक करने, विवरण देखने, आदि की अनुमति देता है। यह पद्धति में दर्ज अन्य शिकायतों के साथ–साथ ऑनलाइन शिकायतों को उपभोक्ता मामले विभाग (सीएडी) में मॉनिटर करना, देखना तथा बंद करना भी सरल बनाता है। बंद शिकायतों के विभिन्न प्रकार, बंद शिकायतों के विस्तृत विवरण देखना, आदि जैसे व्यावहारिक मुद्दों का वर्गीकरण करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे संवर्धित किया गया है।

स्मार्ट फोन से शिकायतें दर्ज कराने हेतु एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन (बीआईएस केयर) भी विकसित की गई है। यह एप्लीकेशन मोबाइल ऐप प्रौद्योगिकी की वर्तमान अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुरूप अपग्रेड की गई है और इसका परीक्षण किया जा रहा है।

बीआईएस वेबसाइट

भारत सरकार की वेबसाइट दिशा निर्देशों के अनुरूप बीआईएस के मौजूदा वेबसाइट का आगे पुनर्निर्माण करने का आंतरिक कार्य किया जा रहा है। इस पुनर्निर्मित वेबसाइट में विषयवस्तु प्रबंध पद्धति जैसी विशेषताएँ सम्मिलित हैं जो विभिन्न विभागों के लिए अपनी विषय वस्तु को सीधे बीआईएस वेबसाइट पर अपडेट करने को सुगम बनाएँगी।

मौजूदा वेबसाइट में एक खंड पूरी तरह से विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना के लिए समर्पित किया गया है।

डब्ल्यूटीओ–टीबीटी मॉड्यूल

ड्ब्ल्यूटीओ–टीबीटी अधिसूचनाएँ होस्ट करने के लिए बीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग हेतु एक मॉड्यूल विकसित तथा चालू किया गया है। यह बाहरी उपयोगकर्ताओं को अपनी ईमेल आईडी पर अधिसूचनाएँ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने हेतु सक्षम बनाता है। यह स्टेकहोल्डरों के लिए अपनी टिप्पणियाँ ऑनलाइन प्रस्तुत करना भी सुगम बनाता है।

ऐसेइंग तथा हॉलमार्किंग (ए एण्ड एच) केंद्र साफ्टवेयर

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अपने क्षेत्राधिकार में ए एण्ड एच केंद्रों के डाटा प्रबंध (जोड़ने, अपडेट तथा डिलीट) करने हेतु आंतरिक ए एण्ड एच केंद्र साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर के जरिए विभिन्न रिपोर्ट जेनरेट की जा सकती हैं। इस डाटा का समग्र प्रबंध करने हेतु हॉलमार्किंग विभाग के लिए एक एडमिन मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया है।

सुरक्षा ऑडिट

सरकारी मानदंडों के अनुसार, बीआईएस – मुख्यालय में होस्ट की गई वेब एप्लिकेशन का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सीडेक हैदराबाद, सीईआरटी–इन संगठन, सूचीबद्ध किया गया है। इस ऑडिट का प्रथम चरण पूरा हो गया है तथा रिपोर्ट की गई कमियों को रोकने हेतु कार्यवाही शुरु की गई है।

ई–प्रापण

बीआईएस के कार्यालयों में ई–प्रापण के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से एक परियोजना आरंभ की गई थी। पद्धति की अपेक्षाओं के अनुसार नामित अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) प्राप्त किए जा रहे हैं और उन्हें कार्यशालाओं के जरिए ई–संविदा की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।

परियोजना प्रबंधन एवं कार्य

बीआईएस कार्यालयों के नये भवनों के निर्माण एवं वर्तमान भवनों में नवीकरण का कार्य बीआईएस अपने परियोजना प्रबंधन एवं कार्य विभाग (पीएमड्ब्ल्यूडी) के माध्यम से कर रहा है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम के माध्यम से बीआईएस भवनों की छतों पर सौर पावर संयत्रों के संस्थापन हेतु पीएमड्ब्ल्यूडी ''हरित पहल'' परियोजनाएँ भी चला रहा है।

पीएमड्ब्ल्यूडी के अधीन विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :

क) नई भवन निर्माण परियोजनाएँ

1. साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) में बीआईएस शाखा कार्यालय हेतु नए भवन का निर्माण

साहिबाबाद में बीआईएस की केंद्रीय प्रयोगशाला के परिसर में बीआईएस की शाखा कार्यालय हेतु नए भवन का निर्माण करने के लिए सिविल निर्माण स्कन्ध –आकाशवाणी (सीसीड्ब्ल्यू–एआईआर) के साथ बीआईएस ने समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन के पश्चात् जनवरी 2018 तक इस निर्माण कार्य की शुरुआत होने की आशा है।

2. नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में बीआईएस शाखा कार्यालय हेतु नए भवन का निर्माण

बीआईएस कार्यालय भवन का निर्माण करने हेतु नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए), छत्तीसगढ़ सरकार के निकाय ने 2097 वर्ग मीटर जमीन आबंटित की है। बीआईएस ने कार्यालय भवन का निर्माण करने का कार्य केलोनिवि को सौंपा है, जिन्होंने प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं।

3. भुवनेश्वर (ओडिसा) में बीआईएस शाखा कार्यालय हेतु नए भवन का निर्माण

कार्यालय भवन का निर्माण करने हेतु ओडिसा सरकार द्वारा बीआईएस को 1011 वर्ग मी जमीन आबंटित की गई है। ओडिसा सरकार के साथ लीज करार की प्रक्रिया जारी है। लीज के निष्पादन के पश्चात्, केलोनिवि को नए कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा।

ख) नवीकरण परियोजनाएँ

1. बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली का आधुनिकीकरण एवं नवीकरण कार्य

i) **बीआईएस मुख्यालय कैंटीन का नवीकरण:** केलोनिवि द्वारा बीआईएस मुख्यालय कैंटीन का नवीकरण किया गया। इस कार्य में नया फर्श, प्लंबिंग तथा आधुनिक रसोई उपकरण उपलब्ध कराने सहित रसोई तथा डाइनिंग क्षेत्र का संपूर्ण नवीकरण कार्य शामिल था।

ii) **बीआईएस मुख्यालय में लिफ्टों का प्रतिस्थापन:** केलोनिवि द्वारा बीआईएस मुख्यालय की मौजूदा लिफ्टों के प्रतिस्थापन का कार्य शुरू किया है। बीआईएस मुख्यालय में संस्थापित 4 लिफ्टों में से दो, मानक भवन तथा मानकालय, प्रत्येक भवन में एक पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित की गई हैं और कार्य कर रही हैं। शेष दो लिफ्टों के प्रतिस्थापन का कार्य प्रगति पर है, जो दिसंबर 2017 तक पूरा होने की आशा है।

2. बीआईएस शाखा कार्यालय, गुवाहाटी (असम) में आंतरिक नवीकरण तथा फर्नीचर कार्य

बीआईएस गुवाहटी शाखा कार्यालय में आंतरिक नवीकरण तथा फर्नीचर कार्य परियोजना हाऊसफैड, असम सरकार की एजेंसी के माध्यम से पूरा किया गया है।

3. बंगलुरु में बीआईएस शाखा कार्यालय तथा प्रयोगशाला की मरम्मत तथा नवीकरण

बंगलुरु में बीआईएस शाखा कार्यालय तथा प्रयोगशाला भवन की मरम्मत एवं नवीकरण परियोजना सीपीड्ब्ल्यूडी के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। यह कार्य दिसंबर 2016 में प्रारंभ हुआ और कार्य प्रगति पर है।

4. चेन्नई में बीआईएस दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रयोगशाला की मरम्मत एवं नवीकरण

चेन्नई में बीआईएस दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रयोगशाला की मरम्मत एवं नवीकरण परियोजना सिविल निर्माण स्कंध –आकाशवाणी (एआईआर) के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। एआईआर ने प्रयोगशाला भवन में विस्तार जोड़ की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है और विद्युत प्रणाली में सुधार और वर्षा जल संचयन जैसे अन्य नवीकरण कार्यों की योजना की जा रही है।

ग) हरित पहलें–सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

1. बीआईएस भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयत्रों का संस्थापन

बीआईएस (मुख्यालय), नई दिल्ली (100 किवॉ), एसआरओ प्रयोगशाला, चेन्नई (100 किवॉ), ड्ब्ल्यूआरओ, मुम्बई (40 किवॉ) तथा एनआईटीएस, नोएडा में संस्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के अतिरिक्त बीआईएस के विभिन्न भवनों में निम्नलिखित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित किये गये :

क्रमांक	कार्यालय/प्रयोगशाला का नाम एवं स्थान	क्षमता
1	बीआईएस शाखा कार्यालय, हैदराबाद	40.0 किवॉ
2	बीआईएस पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	24.4 किवॉ
3	बीआईएस पश्चिमी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता	40.0 किवॉ

जयपुर, राजकोट, बंगलुरु, साहिबाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ तथा मोहाली में बीआईएस के अन्य भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयत्रों की संस्थापना करने के लिए बीआईएस ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को अपनी आवश्यकता बताई है, जिसने संपूर्ण भारत के भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयत्रों की संस्थापना करने हेतु उनके द्वारा जारी 1000 मैगावाट निविदा में उसे शामिल किया है।

2. नेट मीटरिंग

बीआईएस ने निम्नलिखित ऐसे भवनों में नेट मीटरिंग भी कार्यान्वित की है, जहाँ रूफटॉप ऊर्जा संयत्र संस्थापित किए गए हैं:

i) मुख्यालय, नई दिल्ली

ii) एनआईटीएस, नोएडा

iii) हैदराबाद शाखा कार्यालय

नेट मीटरिंग के माध्यम से बंद दिवसों के दौरान ग्रिड को भेजी गई सौर ऊर्जा मीटर से मापी जाती है और ऊर्जा बिल में हिसाब रखा जाता है, परिणामस्वरूप बीआईएस को वित्तीय लाभ होता है। बीआईएस एसईसीआई तथा संबद्ध राज्य विद्युत प्राधिकरणों के सहयोग से अन्य ऐसे भवनों में नेट मीटरिंग की पहल को विस्तारित कर रहा है, जहाँ सौर ऊर्जा संयत्र संस्थापित किए गए हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सतर्कता सेट–अप में प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) तथा इसके अंतर्गत बीआईएस के मुख्यालय में सतर्कता विभाग है और समूह 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के सचिवालय, जो बीआईएस के अलग–अलग कार्यालयों में हैं, जिनके प्रमुख उपमहानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, में भी सतर्कता अनुभाग है ।

सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के घनिष्ट समन्वय में कार्य करता है। इसे ब्यूरो की सतर्कता संबंधी सभी गतिविधियाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा डीओपीटी, आदि द्वारा इस विषय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित से संबद्ध गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हैं :

क) निवारक सतर्कता (अर्थात् प्रक्रियाओं को सुव्यस्थित बनाना, प्रशिक्षण, सहमत सूची तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों को सूची तैयार करना आदि)

ख) दण्डात्मक सतर्कता (अर्थात् प्राप्त हुई शिकायतों की छान–बीन, जाँच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना आदि)

ग) निगरानी एवं पहचान (अर्थात् सतर्कता ऑडिट, वार्षिक संपत्ति विवरणों की छान–बीन, मॉनिटरिंग, समीक्षा बैठकें आदि)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016

भारतीय मानक ब्यूरो में दिनांक 31 अक्तूबर से 05 नवंबर 2016 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान ''ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनसहभागिता'' विषय पर बैनरों का प्रदर्शन तथा पैम्पलेट वितरण, क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी। बीआईएस कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में सतर्कता

जागरूकता सप्ताह का पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 04 नवंबर 2016 को आयोजित किया गया। देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला में सतर्कता सप्ताह मनाया गया ।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के ''गुड इवनिंग'' कार्यक्रम में दिनांक 03 नवंबर 2016 को ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता'' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। श्री आलोक शर्मा, सीवीओ, बीआईएस तथा श्री पी.वी. रामा शास्त्री, जेएस (सीए) एवं सीवीओ, उपभोक्ता मामले विभाग पैनल में थे।

कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु में दिनांक 04 नवंबर 2016 को ''ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनसहभागिता'' विषय पर एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के भाग के रूप में कैमेलिया इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, वर्धमान (प.बं.) में दिनांक 03 नवंबर 2016 और 05 नवंबर 2016 को हैदराबाद के दो महाविद्यालयों में ग्राहक शिकायतों पर विशेष बल देते हुए भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपायों पर शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता मामलों के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए 'निवारक सतर्कता' विषय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, तथा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में नवंबर 2016 के दौरान तथा पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में फरवरी 2017 के दौरान आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान देहरादून शाखा कार्यालय, पटना शाखा कार्यालय, बंगलुरु शाखा प्रयोगशाला तथा कोच्ची शाखा कार्यालय का निवारक सतर्कता के लिए ऑडिट किया गया ।

मानव संसाधन विकास, प्रशासन एवं सामान्य सेवाएँ

भर्ती

वर्ष के दौरान, 2015–16 की भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षासूची में शामिल 13 वैज्ञानिकों ने सीधी भर्ती के माध्यम से वैज्ञानिक–बी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

तैनाती

वर्ष 2016–17 के दौरान बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों में तैनात कार्मिक निम्नानुसार हैं :

गतिविधि	कार्मिकों की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2017 को)		
	क (वैज्ञानिक संवर्ग)	क (गैर वैज्ञानिक संवर्ग) एवं ख, ग, घ	योग
मानक निर्धारण	81	61	142
प्रमाणन	312	322	634
प्रयोगशालाएँ	49	250	299
तकनीकी सहायी सेवाएँ	31	114	145
प्रशासन / एचआरडी / स्थापना	03	137	140
अन्य (कॉर्पोरेट)	12	135	147
योग	**488**	**1019**	**1507**

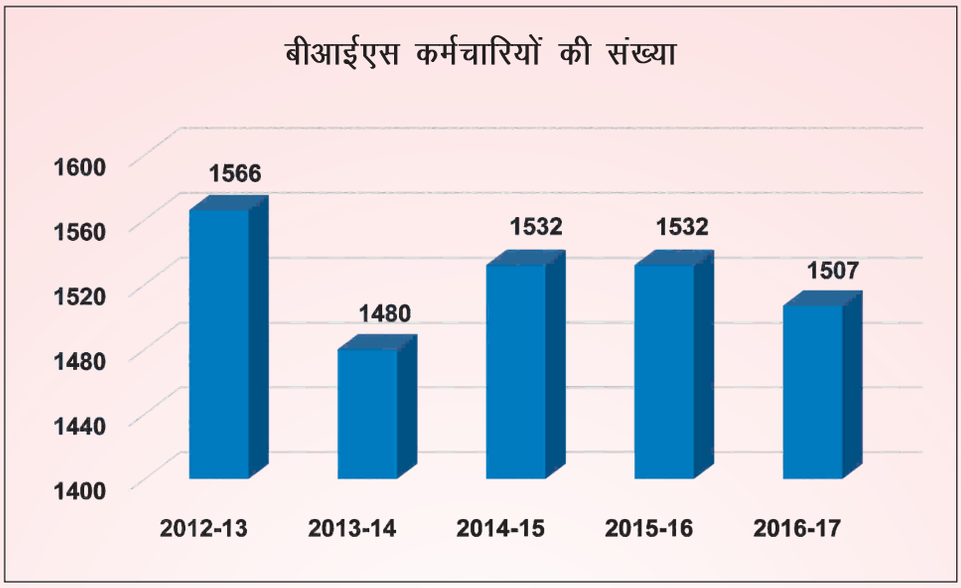
बीआईएस में कर्मचारियों की समूहवार संख्या

31 मार्च 2017 को समूहवार संख्या निम्नलिखित है :

समूह	मौजूदा संख्या	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओबीसी / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक का प्रतिनिधित्व
क (वैज्ञानिक संवर्ग)	488	221
क (गैर–वैज्ञानिक संवर्ग)	36	19
ख	448	122
ग	371	189
घ*	164	80
योग	1507	631

*सरकार के निर्णय के अनुसार पहले के समूह 'घ' कर्मचारियों को विहित प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें समूह 'ग' का कर्मचारी माना जाता है ।

बीआईएस मानव संसाधन विकास पर अपने प्रयास सतत् जारी रखता है। मानव संसाधन विकास के एक हिस्से के रूप में, बीआईएस कार्मिकों को निट्स में इन–हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है।



स्वच्छ भारत मिशन – बीआईएस में स्वच्छ भारत अभियान दो चरणों अर्थात् 16–31 मई 2016 तथा 16–31 अक्तूबर 2016 में चलाया गया।

इस अवधि के दौरान, उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बीआईएस के सभी कार्यलयों में स्वच्छता अभियान चलाए गए। बीआईएस कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और निम्नलिखित कार्य किए।

– कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय परिसर साफ किए गए और धूलमुक्त बनाए गए।

– पुरानी फाइलों की छँटनी की गई/रिकॉर्ड कक्ष को भेजी गई।

– अनुपयुक्त/सेवा देने में अक्षम उपकरणों एवं फर्नीचरों की पहचान की गई एवं उनका निपटान किया गया।

– स्वच्छता पखवाड़े के दौरान बीआईएस वेबसाइट पर स्वच्छ भारत मिशन का लोगो प्रदर्शित किया गया।

– कक्षा 5 तथा उससे ऊपर के छात्रों को ध्यान में रखकर सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्टाफ कल्याण – बीआईएस अपने कर्मचारियों के लिए अपने कल्याण उपाय, नामतः समूह बीमा योजना, होलीडे होम सुविधा, आर्थिक सहायता प्राप्त अल्पाहार, स्वागत काउंटर तथा उपमहानिदेशक एवं उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए समाचार पत्रों का प्रावधान, चिल्ड्रन स्कॉलरशिप योजना इत्यादि सतत् जारी रखता है ।

बीआईएस मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत होलीडे होम नीचे दिए गए हैं –

क) बीआईएस मुख्यालय – शिमला (10 सितंबर 2016 से)

ख) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय – मनाली (1 फरवरी 2017 से)

ग) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – पुरी (1 फरवरी 2017 से)

घ) पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय – महाबलेश्वरम (22 जुलाई 2016 से)

ड़) दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय – कुमारकोम, केरल (1 जुलाई 2016 से)

पुस्तकालय सेवाएँ

बीआईएस के मुख्यालय में स्थित तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय है । इसके संग्रह में विश्वभर के लगभग 4 लाख मानक और 70000 तकनीकी पुस्तकें हैं। 2394 आगंतुकों को संदर्भ सेवाएँ प्रदान की गईं तथा विषयों के 4 व्यापक संदर्भ ग्रंथ तैयार करके उनकी पसंद की संदर्भ सामग्रियां उन्हें उपलब्ध कराई गईं । इसने भारतीय व्यापार और उद्योग से प्राप्त होने वाली 1980 छोटी–बड़ी पूछताछों इत्यादि का उत्तर तुरंत देकर उनकी सहायता की । पुस्तकालय, प्राप्त मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करके उसका रखरखाव करता है । वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 79954 प्रकाशनों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है ।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मानदण्डों के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो में यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया।

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, (i) नियम 3–ग की धारा 4 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,1964 के तहत भारत सरकार के निर्णय (ii) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, अप्रैल 2013 तथा (iii) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, दिसंबर 2013 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया और दिनांक 05 नवंबर 2015 को 2 वर्ष की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन किया गया। बीआईएस मुख्यालय में नवगठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन (एआईडीड्ब्ल्यूए), नई दिल्ली सहित तीन सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आईसीसी गठित की गई हैं।

दिव्यांगों के लिए योजनाएँ

1. भारत सरकार के निर्देशानुसार, बीआईएस समूह क, ख, ग तथा घ की सीधी भर्ती में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) को 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करा रहा है। पुनः, समूह ग तथा घ पदों के लिए पदोन्नति के मामले में, जिसमें सीधी भर्ती का घटक, यदि कोई हो. 75 प्रतिशत से अधिक न होने हो, रिक्तियों का 3 प्रतिशत तो विकलांग (दिव्यांगों) के लिए भी आरक्षित है।

2. बीआईएस सामान्य कर्मचारियों के लिए अनुमत 8 आकस्मिक छुट्टियों के बजाय दिव्यांगों को 12 आकस्मिक छुट्टियों की अनुमति भी देता है।

3. इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य कर्मचारियों को निर्धारित दर से दो गुना परिवहन भत्ता दिया जा रहा है।

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगातार अठारहवे वर्ष, अर्थात् 2016–17 में भी भारतीय मानक ब्यूरो अपनी व्यय और देयता स्वयं पूरी करके आत्मनिर्भर बना रहा । वर्ष 2015–16 के दौरान कुल आय (निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर) रू. 45663.38 लाख थी, जबकि गत वर्ष यह आय रू. 39082.83 लाख थी, जिसके परिणामस्वरूप 16.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । इस आय में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमाणन मुहर शुल्क का था, जो गत वर्ष के रू 32611.05 लाख की तुलना में इस वर्ष रू. 38930.80 लाख रहा अर्थात् इसमें 19.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2016–17 के दौरान कुल राजस्व खर्च रू. 21633.58 लाख हुआ, जबकि 2015–16 के दौरान यह रू 21001.20 था, इसमें 3.01% की वृद्धि हुई ।

वर्ष 2016–17 के दौरान आय और व्यय का वर्ष 2015–16 के साथ तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :

(रु. लाखों में)

		2016–17	2015–16	वृद्धि / गिरावट (–) (%)
	आय			
1	सेवाओं से आय	**43,801.42**	37,277.84	**17.50**
2	मानकों की बिक्री से आय	**660.94**	627.94	**5.26**
3	आईएसओ एवं आईईसी से रेट्रोसेशन	**554.84**	476.75	**16.38**
4	शुल्क अंशदान	**254.32**	234.53	**8.44**
5	अन्य आय	**391.86**	465.77	**–15.87**
	उप–योग	**45,663.38**	39,082.83	**16.84**
6	निवेशों से आय	**2,175.59**	2,743.58	**–20.70**
	योग	**47,838.97**	41,826.41	
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	**14,375.15**	13,497.59	**6.50**
2	प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक व्यय आदि	**6,698.31**	7,076.50	**–5.34**
3	ह्रास	**560.12**	427.11	**31.14**
	उप–योग	**21,633.58**	21,001.20	**3.01**
4	पेंशन तथा ग्रेच्चुटी देयता निधि में वार्षिक अंशदान	**0.00**	2,502.06	
	उप–योग	**21,633.58**	23,503.26	
5	**पेंशन तथा ग्रेच्चुटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान**	**26,205.39**	17,732.12	
	योग	**47,838.97**	41,235.38	
	पूंजीगत निधि से अग्रनीत अधिशेष	**0.00**	591.03	

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि रू0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कार्पस निधि एवं देनदारियां			
कार्पस/पूंजी निधि एवं देयतायें	1	**5,40,78,80,066**	5,40,78,80,066
रिजर्व और सरप्लस		**-**	-
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	2	**17,64,79,19,092**	14,49,41,34,257
प्रतिभूत ऋण और उधार		**-**	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार		**-**	-
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां		**-**	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3	**12,32,47,103**	11,12,51,290
योग		**23,17,90,46,261**	20,01,32,65,613
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियाँ	4	**1,36,89,50,510**	1,31,76,90,186
निवेश : उद्दिष्ट/ अक्षय निधि से	5	**4,39,33,99,663**	1,16,11,02,309
निवेश : अन्य	6	**-**	-
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि।	7	**17,41,66,96,088**	17,53,44,73,118
विविध खर्च (बट्टे खाते में डालने या समायोजित न करने की सीमा तक)		**-**	-
योग		**23,17,90,46,261**	20,01,32,65,613
महत्वपूर्ण लेखा सम्बन्धी नीतियां	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	17		
निवेश का विवरण	18		

(अलका पंडा)	(एच.आर. आहूजा)	(विनोद कुमार)
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रू0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवा से आय	**8**	**4,38,01,41,989**	3,72,77,83,894
अनुदान/सब्सिडी		**-**	-
शुल्क/अंशदान	**9**	**2,54,31,655**	2,34,52,645
निवेशों से आय	**10**	**21,75,58,894**	27,43,58,316
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	**11**	**12,15,78,632**	11,04,69,303
अर्जित ब्याज	**12**	**18,33,013**	7,60,185
अन्य आय	**13**	**3,73,53,188**	4,58,16,677
योग (ए)		**4,78,38,97,371**	4,18,26,41,020
व्यय			
स्थापना खर्च	**14**	**1,43,75,14,967**	1,59,99,65,486
प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्च	**15**	**66,98,31,474**	70,76,50,008
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च		**-**	-
ब्याज		**-**	-
मूल्यह्रास	**4**	**5,60,12,376**	4,27,10,544
पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के प्रति अंशदान		**2,620,538,554**	1,77,32,12,013
योग(बी)		**4,78,38,97,371**	4,12,35,38,051
कार्पस/पूंजी कोष में डाला गया शेष अधिशेष			5,91,02,969
महत्वपूर्ण लेखा सम्बन्धी नीतियां	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	17		
निवेश का विवरण	18		

(अलका पंडा)
महानिदेशक

(एच.आर. आहूजा)
उपमहानिदेशक (वित्त)

(विनोद कुमार)
निदेशक (वित्त)

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

अनुसूची 1 – कार्पस/पूंजी निधि

(राशि रू0 में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में आरंभिक शेष	**5,40,78,80,066**	5,35,08,38,482
जमाः कार्पसपूंजीगत निधि में अंशदान		
i) नियोजित योजना के अंतर्गत मंत्रालय की निधियों से पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	-	33,440
ii) स्पाइस बोर्ड से पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	-	62,175
योग	**5,40,78,80,066**	5,35,09,34,097
घटाएं: पिछले वर्ष में पूंजीकृत और ऊर्जा संयंत्र के लिए सब्सिडी का रिवर्सल [संदर्भ अनुसूची 4(क–2)]	-	21,57,000
योग	**5,40,78,80,066**	5,34,87,77,097
जमाः आय और व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष	-	5,91,02,969
वर्ष के अंत में शेष	**5,40,78,80,066**	5,40,78,80,066

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

अनुसूची–2 उद्दिष्ट/अक्षय निधि (राशि रु. में)

									योग	
	हॉलमार्किंग केन्द्रो की स्थापना हेतु योजनागत योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग से सहायता	उपभोक्ष्ता मामले मंत्रालय से योजनागत परियोजना के अंतर्गत सहायता: उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता ढांचा (योजनागत)	सी.डब्ल्यू.एफ के अंतर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय	हितकारी निधि	सामान्य भविष्य निधि	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि	पेंशन तथा ग्रेच्यूटी देयता लेखा	हॉलमार्किंग शिक्षा एवं संरक्षण निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10
(क) निधियों का आरंभिक शेष	**32,18,310**	**8,87,50,177**	**4,46,049**	**6,44,789**	**1,5,713,01,811**	**28,62,319**	**12,82,54,34,138**	**14,76,664**	**14,49,41,34,257**	11,88,43,92,402
(ख) निधियों में जमा :										
i) सहायता/अनुदान	1,17,81,690	-	-	-	-	-	-	-	**1,17,81,690**	8,75,00,000
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय	1,79,911	7,93,477	6,651	23,814	11,97,89,894	91,028	1,28,92,75,396		**1,41,01,60,171**	1,19,11,90,239
iii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय				8,20,710	19,46,93,890	5,07,76,027		4,66,264	**24,67,56,891**	49,22,86,043
iv) पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान							2,62,05,38,554		**2,62,05,38,554**	1,77,32,12,013
v) अन्य		1,72,546					14,50,419		**16,22,965**	4,84,295
योग (क+ख)	**1,51,79,911**	**8,97,16,200**	**4,52,700**	**14,89,313**	**1,88,57,85,595**	**5,37,29,374**	**16,73,66,98,507**	**19,42,928**	**18,78,49,94,528**	15,42,90,64,992
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/खर्च										
i) पूंजीगत खर्च – अचल परिसम्पत्तियां										33,440
ii) राजस्व खर्च										
- कर्मचारियों, पेंशनरों और हितधारियों को भुगतान				500,000	31,43,60,432	5,12,64,592	73,95,25,463		**1,10,56,50,487**	87,01,64,004
- हॉलमार्किंग केन्द्रों को सहायता	1,49,70,954								**1,49,70,954**	3,69,84,678
- बैठकें, यात्राएं एवं–अन्य खर्च	1,64,53,965			30				**1,64,53,995**	2,77,48,613	
कुल राजस्व खर्च	1,49,70,954	1,64,53,965	-	5,00,030	31,43,60,432	5,12,64,592	73,95,25,463	-	**1,13,70, 75,436**	9,48,97,295
योग (ग)	**1,49,70,954**	**1,64,53,965**	-	**5,00,030**	**31,43,60,432**	**5,12,64,592**	**73,95,25,463**	-	**1,13,70,75,436**	93,49,30,735
31.03.2017 के वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	**2,08,957**	**7,32,62,235**	**4,52,700**	**9,89,283**	**1,571,425,163**	**24,64,782**	**15,99,71,73,044**	**19,42,928**	**17,64,79,19,092**	14,49,41,34,257

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

अनुसूची 3 – चालू देनदारियां और प्रावधान

(राशि रू0 में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देनदारियां		
1. सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियां		
क) अंतःदेशीय	**6,72,42,355**	5,30,93,179
क) अंतःदेशीय	**1,88,04,660**	1,97,84,495
2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमः		
क) बिक्री	**15,94,784**	4,94,625
ख) प्रमाणन	**71,09,662**	1,32,03,134
3. सांविधिक देनदारियां		
अन्य – देय सेवाकर	**74,850**	2,44,357
4. अन्य चालू देनदारियां		
क) धरोहर राशि/प्रतिधारण मूल्य	**2,44,99,101**	2,09,49,862
ख) लेखा कर्मचारियों को देय	**12,80,586**	9,28,054
ग) एबीओं बिल्डिंग खाता	**26,41,105**	25,53,584
योग (क)	**12,32,47,103**	11,12,51,290
B. PROVISIONS	**-**	**-**
TOTAL(A+B)	**12,32,47,103**	11,12,51,290

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

अनुसूची–4 अचल परिसम्पत्तियां (राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	यथा वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	यथा चालू वर्ष 2016–17 के अंत पर	यथा पिछले वर्ष 2015–16 के अंत पर
क. अचल परिसम्पत्तियां:										
1 भूमि	59,35,58,542	**3,87,39,756**	**0**	**63,22,98,298**	0	**0**	**0**	**0**	**63,22,98,298**	59,35,58,542
2 भवन	25,48,13,986	**11,53,66,480**		**37,01,80,466**	18,16,59,336	**2,85,38,741**	**0**	**21,01,98,077**	**15,99,82,389**	7,31,54,650
3 आवासीय फ्लैट	6,22,96,310	**0**	**0**	**6,22,96,310**	4,06,64,803	**6,78,661**	**0**	**4,13,43,464**	**2,09,52,846**	2,16,31,507
4 संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर	26,27,15,330	**1,67,24,626**	**27,70,329**	**27,66,69,627**	21,58,50,045	**90,72,968**	**26,48,089**	**22,22,74,924**	**5,43,94,703**	4,68,65,285
5 वाहन	40,28,549	**0**	**0**	**40,28,549**	26,91,844	**2,00,506**	**0**	**28,92,350**	**11,36,199**	13,36,705
6 फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर	29,97,56,090	**2,09,18,492**	**1,07,31,499**	**30,99,43,083**	24,67,73,870	**1,73,05,846**	**90,38,510**	**25,50,41,206**	**5,49,01,877**	5,29,82,220
7 पुस्तकालय की पुस्तकें	2,71,31,247	**2,10,409**	**0**	**2,73,41,656**	2,70,74,520	**2,15,654**	**0**	**2,72,90,174**	**51,482**	56,727
योग (क) चालू वर्ष का	1,50,43,00,054	**19,19,59,763**	**1,35,01,828**	**1,68,27,57,989**	**71,47,14,418**	**5,60,12,376**	**1,16,86,599**	**75,90,40,195**	**92,37,17,794**	78,95,85,636
पिछले वर्ष	1,46,06,51,051	5,11,57,582	75,08,579	1,50,43,00,054	67,60,94,365	4,27,10,544	40,90,491	71,47,14,418		
ख. प्रगति में पूंजीगत कार्य	52,81,04,550	**2,43,10,743**	**10,71,82,577**	**44,52,32,716**					**44,52,32,716**	52,81,04,550
								योग	**1,36,89,50,510**	1,31,76,90,186

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

अनुसूची 5 – उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश

(राशि रु. में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा		
1.1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	**3,24,19,42,585**	-
1.2	डिबेंचर और बंधपत्र	**2,00,00,000**	2,00,00,000
	योग (1)	**3,26,19,42,585**	2,00,00,000
2	कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		
2.1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	**26,41,03,664**	27,95,88,148
2.2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	**42,00,22,970**	40,71,14,749
2.3	डिबेंचर और बंधपत्र	**12,24,21,850**	13,29,90,818
2.4	आरबीआई के पास विशेष जमा	**31,27,08,594**	31,27,08,594
2.5	इक्विटी एवं संबंधित निवेश – मयुच्अल निधियां	**1,22,00,000**	87,00,000
	योग (2)	**1,13,14,57,078**	1,14,11,02,309
	योग (1)+(2)	**4,39,33,99,663**	1,16,11,02,309

अनुसूची 6 – निवेश–अन्य

(राशि रु. में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	कार्पस पूंजीगत निधि में निवेश	-	-
	योग	-	-

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. वस्तुसूची :		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान	**8,20,218**	12,38,631
ख) स्टेशनरी	**30,62,034**	24,66,675
ग) मरम्मत एवं रख–रखाव उपभोग्य सामग्री	**14,16,608**	5,86,048
घ) स्वर्ण आभूषण	**7,62,018**	7,62,018
योग (1)	**60,60,878**	50,53,372
2. फुटकर लेनदारियां		
क) प्रकाशनों की बिक्री		
i) छह माह से अधिक	**67,309**	60,230
ii) अन्य	**54,376**	16,967
ख) प्रमाणन		
i) छह माह से अधिक	**28,35,789**	19,96,053
ii) अन्य	**77,393**	1,39,123
ग) वसूली योग्य लेखा		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी)	**9,81,750**	13,02,378
ii) सरकारी विभागों से वसूली योग्य लेखा (एमओएफ, एमईए एवं डीओसीए)	**1,03,38,087**	85,14,510
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य)	**2,75,58,548**	2,27,61,999
योग (2)	**4,19,13,252**	3,47,91,260
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित)	**3,17,941**	5,24,230
4. बैंक में शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
i) चालू खातों में	**13,64,15,380**	12,68,43,372
ii) बचत खातों में	**8,84,21,192**	6,23,40,961
4(क) (i – ii) का उप–योग	**22,48,36,572**	18,91,84,333
iii) सावधि जमा खातों में		
A) निवेश – उद्दिष्ट निधि		
I) पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि खाता	**12,73,52,30,460**	12,80,54,34,138
II) सामान्य भविष्य निधि	**31,57,81,000**	31,02,91,000
III) राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि खाता	**24,64,782**	28,62,319
IV) एबीओ भवन परियोजना खाता	**23,33,410**	23,33,410
ख) कार्पस पूंजीगत निधि में सामान्य निवेश	**1,47,26,04,758**	2,15,95,03,543
4(क)(iii) का उप–योग	**14,52,84,14,410**	15,28,04,24,410
योग (4)	**14,75,32,50,982**	15,46,96,08,743
5. चौक हस्तांतरण में	**1,38,12,297**	6,50,000
6. फ्रैकिंग मशीन शेष	**1,85,868**	2,09,560
योग (क)	**14,81,55,41,218**	15,51,08,37,165

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिमः		
i) वाहन खरीदने के लिए	**6,55,410**	14,30,936
ii) आवास निर्माण के लिए	**27,18,917**	37,98,561
iii) कम्प्यूटर के लिए	**4,16,912**	6,67,340
योग (1)	**37,91,239**	58,96,837
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियां अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
i) परियोजना –मुख्यालय केलोनिवि (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.1(i) देखें)	**44,39,676**	70,11,676
ii) क्षेत्रीय/शाखा काया. में भवन निर्माण – केलोनिवि	**2,47,30,221**	1,27,99,773
iii) कंप्यूटीकरण परियोजनाःसी–डीएसी	**3,34,30,653**	2,22,38,853
iv) अन्य (क्षे. का/शा.का/मुख्यालय)	**93,61,551**	1,13,74,256
v) उपभोक्ता कल्याण निधी (एनबीसीसी)	**3,32,260**	3,32,260
vi) परियोजनागत योजना (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7 देखें)	**17,436**	12,17,436
योग (1)	**7,23,11,797**	5,49,74,254
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय	**63,11,602**	15,21,244
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिमः		
i) त्यौहार	**-**	7,15,415
ii) प्राकृतिक आपदाएं	**75,000**	1,58,400
iii) यात्रा व्यय	**8,02,077**	17,47,495
iv) छुट्टी यात्रा रियायत	**8,69,260**	8,58,670
v) सामान्य भविष्य निधि	**76,85,081**	85,12,793
योग (2ग)	**94,31,418**	1,19,92,773
घ) पंजीयक–लघुवाद कोर्ट – मुंबई (अनुसूचि 17 की टिप्पणी सं. 1.3 देखें)	**1,83,60,598**	1,83,60,598
ड.) प्रतिभूति जमा	**75,26,903**	53,05,938
योग (2)	**11,39,42,318**	9,21,54,807
3. प्राप्त आय		
a) उद्दिष्टों/अक्षय निधियां एवं अन्य से निवेश		
i) बीआईएस निधियां	**2,34,24,17,125**	1,79,63,26,587
ii) सामान्य भविष्य निधि	**12,30,24,641**	10,82,74,830
योग (3)	**2,46,54,41,766**	1,90,46,01,417
4. प्राप्ति योग्य दावे		
क) आयकर वापसी	**1,28,07,389**	1,82,15,664
ख) सेवाकर	**51,72,158**	27,67,228
योग (4)	**1,79,79,547**	2,09,82,892
योग (ख)	**2,60,11,54,870**	2,02,36,35,953
योग (क+ख)	**17,41,66,96,088**	**17,53,44,73,118**

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

अनुसूची 8 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	उत्पाद प्रमाणन	**3,89,30,79,533**	3,26,11,05,239
2.	अनुरूपता आकलन (पंजीकरण)	**25,82,66,217**	22,20,45,630
3.	हॉलमार्किंग	**19,06,84,575**	20,05,56,091
4.	पद्धति प्रमाणन	**3,81,11,664**	4,40,76,934
	योग	**4,38,01,41,989**	3,72,77,83,894

अनुसूची 9 शुल्क/अंशदान

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शुल्क	**2,28,25,055**	2,06,63,245
2.	पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	**25,28,000**	27,04,000
3.	स्टैंडर्ड्स इंडिया जर्नल का अंशदान	**78,600**	85,400
	योग	**2,54,31,655**	2,34,52,645

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

अनुसूची 10 – निवेशों से आय

(राशि रू0 में)

		उदिष्ट निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
		वर्तमान वर्ष	वर्तमान वर्ष	**वर्तमान वर्ष**	वर्तमान वर्ष
	(उदिष्ट/अक्षय निधि से निवेश से आय निम्नलिखित निधि में अंतरित)				
1	आय	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650	**21,70,83,863**	27,38,83,287
2	किराया	**-**	**-**	**4,75,031**	4,75,029
	योग	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650	**21,75,58,894**	27,43,58,316
	(उदिष्ट/अक्षय निधियों को अंतरित) [संदर्भ अनुसूची 2, मद ख (ii) –कॉलम 7]	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650		

अनुसूची 11– रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क.	**मानकों की बिक्री से आय**		
1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	**4,04,55,558**	3,92,82,629
2	हार्ड प्रतियां	**2,42,97,828**	2,15,58,445
3	विदेशी निकायों के प्रकाशन की बिक्री पर मार्जिन	**12,27,129**	18,41,093
4	भारतीय मानकों के पुनरोत्पादन से रॉयल्टी	**1,13,800**	1,12,000
	योग (क)	**6,60,94,315**	6,27,94,167
ख.	**भारत में आईएसओ और आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय**	**5,54,84,317**	4,76,75,136
	योग (क+ख)	**12,15,78,632**	11,04,69,303

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची का भाग

अनुसूची 12 – अर्जित ब्याज

(राशि रू0 में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बचत खाते पर	**18,33,013**	7,60,185
योग	**18,33,013**	7,60,185

अनुसूची 13 – अन्य आय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अं)	वाहन, कम्पयूटर व गृह निर्माण अग्रिम से व्याज	**56,37,194**	54,12,839
इ)	सीजीएचएस अंशदान	**40,36,830**	35,04,508
ब)	स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क	**7,81,821**	4,51,844
क)	मुख्यालय में विविध आय	**25,14,496**	1,64,46,330
म)	क्षेत्रीय का/शा. कार्या. में विविध आय	**55,37,803**	1,10,72,148
स)	प्रयोगशालाओं में विविध आय	**1,26,64,508**	89,29,008
ह)	जीपीएफ लेखा में अधिशेष	**61,80,536**	-
	योग	**3,73,53,188**	4,58,16,677

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची का भाग

अनुसूची 14 – स्थापना व्यय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	**वेतन एवं भत्ते**		
	क) वेतन	**52,42,70,257**	47,26,57,066
	ख) भत्ते एवं बोनस	**72,84,28,149**	72,28,49,608
	ग) टर्मिनल छुट्टी भुनाना	**7,37,31,200**	5,46,19,792
	योग (1)	**1,32,64,29,606**	1,25,01,26,466
2.	**सेवा निवृत्ति लाभ**		
	क) पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में वार्षिक अंशदान खाता	**-**	25,02,05,865
	ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	**2,52,61,005**	1,82,04,435
	ग) सामान्य भविष्य निधि खाते में घाटा	**-**	3,72,550
	योग (2)	**2,52,61,005**	26,87,82,850
3.	**कल्याण खर्च**		
	क) चिकित्सा लाभ–कर्मचारी	**2,98,74,650**	2,73,32,177
	ख) चिकित्सा लाभ–पेंशनधारी	**3,07,03,651**	3,49,37,881
	ग) स्टाफ कल्याण	**1,23,20,785**	77,39,164
	घ) छुट्टी यात्रा रियायत	**1,29,25,270**	1,10,46,948
	योग (3)	**8,58,24,356**	8,10,56,170
	योग (1+2+3)	**1,43,75,14,967**	1,59,99,65,486

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची का भाग

अनुसूची 15 – प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	**यात्रा व्यय**		
	क) विदेश	**4,56,487**	6,90,139
	ख) घरेलू	**3,52,26,920**	3,84,14,752
	ग) समिति सदस्य	**1,30,659**	3,68,359
	योग (1)	**3,58,14,066**	3,94,73,250
2.	**अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चंदे**		
	क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन	**2,88,92,068**	3,09,45,885
	ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग	**88,78,276**	99,57,985
	योग (2)	**3,77,70,344**	4,09,03,870
3.	**मुद्रण**		
	क) मानक	**31,19,376**	9,67,396
	ख) बुलेटिन	**2,14,492**	5,77,614
	योग (3)	**33,33,868**	15,45,010
4.	**परीक्षण और निगरानी**		
	क) परीक्षण शुल्क	**11,04,96,572**	13,30,72,280
	ख) प्रयोगशाला एप्रिंटसों को स्टाइपन्ड	**-**	32,95,055
	ग) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख–रखाव	**1,02,22,906**	93,71,043
	घ) बाजार नमूने	**31,89,036**	38,43,034
	ड़) निरीक्षण कार्य के लिए टैक्सी किराए पर लेना	**47,16,363**	44,16,328
	च) भाड़ा और ढुलाई	**1,31,44,365**	1,40,92,399
	योग (4)	**14,17,69,242**	16,80,90,139
5.	**प्रचार**	**16,23,60,120**	17,08,99,480
6.	**कार्यालय व्यय**		
	क) लेखन सामग्री	**1,82,35,022**	1,82,05,064
	ख) पोस्टेज	**76,86,552**	56,61,754
	ग) दूरभाष	**1,40,46,429**	1,35,54,265
	घ) भर्ती	**3,80,273**	2,08,67,789
	ड़) जलपान और मनोरंजन	**15,09,973**	13,30,973
	च) वर्दी	**3,33,255**	5,06,880
	छ) बीमा और बैंक प्रभार	**18,90,530**	17,57,606
	ज) विविध	**23,08,678**	20,69,393
	झ) किराया और सांविधिक कर	**2,94,73,511**	2,80,96,806
	ञ) बिजली और पानी प्रभार	**4,43,19,023**	4,45,76,412
	ट) टैक्सी किराये पर लेने के प्रभार	**86,95,919**	89,57,065
	योग (6)	**12,88,79,165**	14,55,84,007

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची का भाग

अनुसूची 15 – प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय

(राशि रू0 में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
7.	**मरम्मत और रखरखाव**		
	क) फर्नीचर एवं कार्यालय उपस्कर	**77,08,408**	76,70,116
	ख) भवन	**1,78,19,846**	1,56,78,892
	ग) वाहन	**6,54,633**	5,85,369
	योग (7)	**2,61,82,887**	2,39,34,377
8.	**सम्मेलन, उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**		
	क) सम्मेलन, संगोष्ठियाँ एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	**1,26,87,927**	1,01,41,714
	ख) एनआईटीएस में प्रशिक्षण पर व्यय	**87,65,313**	68,04,034
	योग (8)	**2,14,53,240**	1,69,45,748
9.	**अन्य व्यय**		
	क) सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	**1,86,71,551**	1,88,35,210
	ख) पुस्कालय चंदा एवं व्यय	**3,45,382**	3,13,951
	ग) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य परामर्श प्रभार	**40,74,249**	43,44,431
	घ) विधि प्रभार	**57,22,676**	37,39,155
	ड़) श्रम व्यय	**6,81,68,165**	5,33,82,225
	च) तकनीकी जनशक्ति हायर की गई	**33,00,602**	8,18,080
	छ) डूबा ऋण और घाटा बट्टे खाते में डाला *(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.12 देखें)*	**-**	2,64,800
	ज) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल)	**7,94,930**	2,82,303
	झ) गुणता पद्धति प्रभार	**80,10,204**	99,84,532
	ञ) हिंदी प्रोत्साहन गतिविधियाँ	**30,83,988**	30,85,708
	ट) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय	**96,795**	2,14,566
	ठ) विनिमय दर परिवर्तन	**-**	10,77,081
	ड) सेनवेट क्रेडिट व्यय	**-**	39,32,085
	योग (9)	**11,22,68,542**	10,02,74,127
	योग (1 से 9)	**66,98,31,474**	70,76,50,008

भारतीय मानक ब्यूरो
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

अनुसूची 16– विशिष्ट लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेषों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियां

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाषनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा–जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा–जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय के अनुपात के आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्तियां

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा इन्वार्ड भाड़े, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है

4.2 मंत्रालयों के अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती है।

4.3 नॉन–मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि पर संगत जमा द्वारा कथित मूल्य पर पूंजीकृत की जाती है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटर्न डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्धिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूंजीगत निधि में जोड़ के रूप में दिखाई गई है।

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा के लेनदेन उनकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियां वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

वेतन और भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण का भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 एक्चुरियन मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा को उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि के लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 एक्चुरियन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंषन, ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में संगत क्रेडिट सहित आय और व्यय खाते में निधि के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि लेखा

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

अनुसूची 17– लेखा संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

1 आकस्मिक देयताएं

1.1 बीआईएस के निम्नलिखित कार्यालयों की सेवाकर संबंधी विवादित मांगे (जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर)

		राशि (रू.लाखों में)
(1)	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय	161.67
(2)	मुम्बई शाखा कार्यालय	75.78
(3)	पुणे शाखा कार्यालय	21.50
(4)	पटना शाखा कार्यालय	2.67
(5)	भामाब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली	192.87

1.2 **जयपुर भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान नोएडा भवन के सलाहकार एनबीसीसी** ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के लिए क्रमशः **रू. 27.60 लाख** और **रू. 17.04 लाख** के भुगतान का दावा किया है, परन्तु संविदाकार(रों) द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूंकि एनबीसीसी द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियां अभी की जानी हैं तथा उनके साथ लेखों का निपटान कार्य प्रगति पर है, चूंकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जायेगी, इसलिए इसे 31–03–2017 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 **मुम्बई में रिक्त कर दिए गए बीआईएस के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान** : बीआईएस द्वारा माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय, मुंबई के आदेश दिनांक 05.10.2015 की रिट पेटिशन सं. 7380/2006 के विरूद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर स्पेशल लीव पेटिशन की अनुमति न मिलने पर रू. 3,66,60,598/– की आकस्मिक देयता (रू.1,83,60,598/– डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और रू. 1,83,00,000/– बैंक गारंटी द्वारा, दोनों ही रजिस्ट्रार, स्माल कॉसिस कोर्ट,मुम्बई के पक्ष में) की आवश्यकता पड़ सकती है।

आरंभ में, माननीय लघुवाद न्यायालय, मुम्बई ने अपने दिनांक 09 सितम्बर 2005 के निर्णय में मध्यवर्ती लाभ लगाया है जिसका ब्यूरो द्वारा 205/– प्रति वर्गफीट की दर से प्रति माह 3255 वर्गफीट के क्षेत्र के लिए 01 जून 2000 से 30 अप्रैल 2004 तक 6: प्रति वर्ष ब्याज दर से आवेदन की तिथि से अर्थात 27.02.2002 से मध्यवर्ती लाभ की पूर्ण राशि का वादी को भुगतान किया जाना है। न्यायालय मुम्बई की दो सदस्यीय पीठ ने दिनांक 07.09.2006 के निर्णय में, अपील को आंशिक रूप से अनुमत किया तथा प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज 6: की दर से और मध्यवर्ती लाभ को प्रतिमाह रू. 5,17,545/–की दर से कम करके ब्यूरो को कुछ राहत दी है, किन्तु यह ब्यूरो को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.11.2006 को न्यायविधान के कानूनी न्यायालय, मुम्बई में रिट याचिका सं. 7380/2006 दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय ने बीआईएस की याचिका सं.7380/2006 को आदेश संख्या दिनांक 05.10.2015 द्वारा खारिज कर दिया है और निर्णय की तिथि से 12 सप्ताह तक कुल डिक्रीटल एमांउट के निष्पादन पर स्टे दिया गया (बीआईएस द्वारा 50 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट द्वारा और 50 प्रतिशत बैंक गारंटी द्वारा जमा करा दिया गया)।

यद्यपि, भारतीय मानक ब्यूरो ने माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा घोषित दिनांक 05.10.2015 के आदेश को चुनौती दी है । माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 36289/2015 दायर की। उक्त एस. एल.पी. में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.03.2016 को निर्देश दिया है कि मामले का निपटान होने तक याचिकाकर्त्ता बैंक गारंटी का समय–समय पर नवीकरण कराता रहे तथा प्रतिवादी ने विशेष रूप से कहा है कि न्यायालय की अनुमति के बिना वह उक्त बैंक गारंटी को इनकैश नहीं करायेगा। उक्त एसएलपी अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है ।

रू. 1,83,60,598/– की दी गई राषि वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 7 ख [मद 2(घ)] के अंतर्गत रखी गयी है। यदि बीआईएस की इस मामले में जीत होती है तो वापस प्राप्त राषि को समायोजित कर दिया जायेगा अन्यथा दी गई राशि को आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा, जिसके लिए बजट में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से प्रावधान किया जायेगा।

1.4 माननीय उच्च न्यायालय, मुबंई में 2010 का मुकदमा सं0 3016 :– मैसर्स नेशनल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा.लि. ने भारतीय मानक ब्यूरो से ब्याज सहित रू. 7382.90 लाख रूपये के लिए आकस्मिक देयता के रूप में क्षति के लिए दावा किया, जो उसे पैकेजबंद पेयजल के लाइसेंस के नवीकरण में विलम्ब के कारण कथित नुकसान के लिए उठाना पड़ा था।

1.5 बैंक गारंटी : – सिंडिकेट बैंक द्वारा आपदा, प्रतिक्रिया एवं अग्निशमन सेवा महानिदेशक, हैदराबाद के पक्ष में 05.01.2020 तक वैध रू. 5.00 लाख की बैंक गारंटी जारी की गई।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 पूंजीगत वचनबद्धताएं : पूंजीगत लेखा पर ऐसी संविदा, जिस पर कार्य होना शेष है और जिसका प्रावधान (अग्रिमों के निवल) नहीं किया गया है, के मूल्य निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना	कुल अनुमानित लागत	सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान	संविदा का मूल्य जिसका निष्पादन किया जाना है
(i)	मुख्यालय भवन का एयरकन्डीशनिंग	17.02	15.40	1.62
(ii)	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय का भवन निर्माण	17.04	13.00	4.04
(iii)	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, मोहाली का नवीनीकरण	1.02	0.55	0.47
(iv)	राजकोट कार्यालय का भवन निर्माण	5.38	4.00	1.38

क्र. सं.	परियोजना	कुल अनुमानित लागत	सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान	संविदा का मूल्य जिसका निष्पादन किया जाना है
(v)	सरकार से योजना निधि के अंतर्गत प्राप्त सहायता से नोएडा प्रशिक्षण संस्थान के भवन का आधुनिकीकरण	6.51	6.43	0.08
(vi)	जम्मू कार्यालय का भवन निर्माण	4.33	4.33	–
(vii)	गुवाहाटी शाखा कार्यालय का आंतरिक साज–सज्जा कार्य	0.81	0.65	0.16
(viii)	भामाब्यूरो मुख्यालय की लिफ्ट बदलना	1.13	0.38	0.75
(ix)	भामाब्यूरो मुख्यालय की कैन्टीन का नवीनीकरण	0.52	0.32	0.20

2.2 पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2–कॉलम 7)

2.2.1 दिनांक 26.11.2015 को आयोजित की गई 56वीं वित्तीय समिति की अनुषंसा पर 05.05.2016 को आयोजित हुई कार्यकारी समिति ने अपनी 130वीं बैठक में दिनांक 15.12.2015 के पत्र सं. बीआईएस/ईसी/ए–2.130 के सर्कुलेशन के माध्यम से अपने अनुमोदन को अभिपुष्ट किया है कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता के एक्चुरियल मूल्यांकन में 7वें वेतन आयोग के प्रभाव का हिसाब लगाया जाये। तदनुरूप पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि की कुल प्रोद्भूत देयता पर निर्भर पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि की कमी को आय एवं व्यय लेखा से उपलब्ध कराया जाये। चूंकि 7वें वेतन आयोग को मार्च 2017 में कार्यान्वित किया गया है, कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन के आधार पर 31.3.2017 तक किया गया है ।

2.2.2 आईसीएआई के एएस–15 में दिये गये एवं एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुपालन से सेबी में पंजीकृत मैसर्स नलिन कपाड़िया कंसल्टेंट एंड एक्चुरियल द्वारा प्रस्तुत की गई एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2017 तक बीआईएस की कुल प्रोद्भूत पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निम्नानुसार रू. 16,55,31.65 लाख हो गई है :

क्र. सं.	प्रोद्भूत देयता के प्रति	राशि लाख रूपयों में
1.	वर्तमान कर्मचारियों की प्रोद्भूत पेंशन देयता (विगत सेवा हेतु)	7,38,41.97
2.	वर्तमान कर्मचारियों की प्रोद्भूत ग्रेच्युटी देयता (विगत सेवा हेतु)	96,53.05
3.	वर्तमान पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों हेतु प्रोदभूत पेंशन देयता	8,20,36.63
	योग	16,55,31.65

2.2.3 दिनांक 31.03.2016 तक एक्च्युरिल मूल्यांकन के आधार पर उपरोक्त देयता **रू 12,82,54.34 लाख** थी। दिनांक 31.03.2017 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता की वृद्धि की स्थिति निम्नानुसार है :

(i) 7वें वेतन आयोग रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण वेतन एवं पेंशन में वृद्धि ।

(ii) निधि में पुनःनिवेश के प्रयोजनार्थ वर्तमान मूल्यांकन में लिए गए ब्याज की दर में कमी । 31.3.2017 तक वर्तमान मूल्यांकन में ब्याज की अभिगृहीत दर गिरती हुई ब्याज दर के परिदृष्य के कारण 31.3.2016 तक पिछले मूल्यांकन में 7.80 के सामने 6.95 के रूप में लिया गया है ।

2.2.4 31.3.2017 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि की स्थिति निम्नानुसार है :

(i) निधि में आरंभिक शेष :– 01.04.2016 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि में उपलब्ध राशि **रू 12,82,54,34,138** थी ।

(ii) निधि द्वारा अर्जित ब्याज :– उपार्जन आधार पर बीआईएस की विभिन्न निधियों के निवेशों पर कमाया कुल ब्याज **रू. 1,50,64,50,287** है। जिसमें कार्पस/पूंजी निधि में बीआईएस के पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निधि (ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनका पीआरएएन खाता अभी खुला नहीं है) के निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें से **रू. 91,028** की राशि का ब्याज आबंटित किया गया है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निधि खाते में जमा किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अभिदाताओं को, कुल अर्जित **रू. 150,63,59,259** के शेष ब्याज को 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखे के लिए निवेश तथा कार्पस/पूंजी निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाते एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 01.04.2016 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

(रूपयों में राशि)

निवेश	**1.4.2016 के निवेश पर आरंभिक शेष**	**2016–17 हेतु 1.4.2016 के निवेश पर आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रू. 150,63,59,259 का ब्याज**
पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए निवेश {अनुसूची 5 (मद 1) तथा अनुसूची 7क मद4क (iii) (क)} (1) का योग	12,82,54,34,138	1,28,92,75,396
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश {अनुसूची 7क मद 4(क) (iii) (ख)}	2,15,95,03,543	21,70,83,863
योग	14,98,49,37,681	150,63,59,259

रू.1,28,92,75,396 के अर्जित ब्याज को **'पेंशन, ग्रेच्युटी देयता निधि खाते'** (अनुसूची 2 कॉलम 7) में जमा कर दिया है तथा **रू0 21,70,83,863** को शेष ब्याज को **आय और व्यय लेखा** (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

(iii) निधि से किये गये भुगतान : वर्ष 2016–17 के दौरान पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेषन के निवल भुगतानों की कुल राशि **रू. 73,80,75,044** (कुल भुगतान **रू. 73,95,25,463** में से प्रतिनियुक्त पर गए कर्मचारियों आदि से प्राप्त **रू. 14,50,419 रूपये घटाने पर**) थी। इसे **पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते** (अनुसूची 2 कॉलम 7) के नामे डाला गया है।

(iv) आय एवं व्यय लेखा से उपबंधित लेखा में कमी : उपरोक्त क्रमांक (ii) एवं (iii) **पर दिये गये लेन–देन के परिणाम स्वरूप 31.03.2017 को पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में रू. 13,37,66,34,490 की राशि निकाली गई।** चूंकि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में **रू. 3,17,65,30,175** की कमी थी (अर्थात् **रू. 16,55,31,64,665** में से घटाये **रू. 13,37,66,34,490** की प्रोद्भूत देयता), अतः 2016–17 की कुल आय एवं कुल व्यय के बीच के संपूर्ण अंतर से जो रू 2,62,05,38,554 था । पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में **रू. 55,59,91,621** को कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार **'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा' में कमी और 'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा'** (अनुसूची 2, कॉलम 7) में जमा कें अंषदान के रूप में आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया गया है । **'पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा को वर्ष 2017–18 के कार्य एवं व्यय लेखा से पूर्ण किया जाएगा।**

(v) निधि में अंतःशेष : – अतः एक्चुरिअल मूल्यांकन रिपोर्ट में रू 16,55,31,64,665 के मूल्य के प्रति **आय एवं व्यय लेखा पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि में कमी के लिए प्रावधान करने के बाद दिनांक 31.03.2017 तक रू. 15,99,71,73,044 की निधि थी** (अनुसूची 2 कॉलम 7)।

2.3 **1.1.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)** – बीआईएस में 1.1.2004 के बाद सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू है। जो कर्मचारी रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं, उन कर्मचारियों का अंशदान तथा बीआईएस का अंशदान पीएफडीआरए को मासिक आधार पर भेजा जाता है। तथापि, जिनका नामांकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा बीआईएस का अंशदान बीआईएस द्वारा अपने पास एनपीएस खाते में रखा जाता है और इसे निवेश किया जाता है, उस पर ब्याज, जो सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के समान है, उनके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2017 तक बीआईएस की अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि **रू. 26,64,782** थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 बीआईएस निधियों का निवेश

2.4.1 **बीआईएस निधियों का कुल निवेश : दिनांक 31.03.2017 को बीआईएस का कुल निवेश रू. 17,47,22.43 लाख था, जो निम्नानुसार विभिन्न निधियों का प्रतिनिधित्व करता है :**

(राशि रूपयों में)

क्रम सं.	निधियां जिनके लिए निवेश प्रतिनिधान है	पीएसयू बैंक में स्थायी जमा में निवेश	पीएसयू बॉण्ड में निवेश	कुल निवेश
(iii)	पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि	12,73,52.30	3,26,19.43	15,99,71.73
(ii)	कार्पस/पूंजीगत निधि प्रतिनिधान में बीआईएस का सामान्य निवेश	1,47,26.05	—	1,47,26.05

क्रम सं.	निधियां जिनके लिए निवेश प्रतिनिधान है	पीएसयू बैंक में स्थायी जमा में निवेश	पीएसयू बॉण्ड में निवेश	कुल निवेश
(iii)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि	24.65	——	24.65
	कुल निवेश	**14,21,03.00**	**3,26,19.43**	**17,47,22.43**
		(अनुसूची 7(क)(मद 4 क) (iii) के अंतर्गत दर्शाये गये)	(अनुसूची 5 की मद सं. 1.1के अंतर्गत दर्षाये गये)	

31 मार्च 2017 तक कुल निवेश के विवरण अनुसूची 18 में भी दर्शाये गये हैं ।

2.4.2 बीआईएस ने यू.पी. कॉपरेटिव एंड स्पनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यूपीसीएसएमएफएल), उत्तर प्रदेश के उपक्रम के बॉण्ड में दिनांक 17.12.1998 को 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रू. 2,00,00,000 का निवेश किया था। यूपीसीएसएमएफएल परिपक्वता तिथि को ब्याज एवं मूलधन के भुगतान में डिफाल्टर रहा था । मूलधन की परिपक्वता पर 30.04.2003 (33 प्रतिशत), 30.10.2003 (33 प्रतिशत) एवं 30.04.2004 (34 प्रतिशत) देय था । दिनांक 01.05.2000 से ब्याज देने में चूक हुई है, जो कूपन दर की परिपक्वता की तारीख तक रू. 1,28,00,000 था । बीआईएस ने माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष याचिका सं. 451/2002 के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। माननीय एनसीडीआरसी ने दिनांक 01.02.016 को निर्णय सुनाया एवं वादी पक्ष सं. 01 (यूपीसीएसएमएफएल) एवं वादी पक्ष सं. 02 (उत्तर प्रदेश सरकार ग्रांटर) को आदेश दिया कि वे प्रापण की तिथि तक 01.05.2000 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बीआईएस को रू. 200 लाख का संयुक्त रूप से एवं अलग–अलग ढंग से भुगतान करें । बीआईएस द्वारा दिनांक 03.03.2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपत्ति याचिका भी दर्ज कराई गई है ।

दिनांक 16.12.2016 को आयोजित अंतिम सुनवाई में माननीय एनसीडीआरसी ने मैसर्स यू.पी. कॉपरेटिव एंड स्पनिंग मिल्स फेडरेशन लि. से जब तक वसूली नहीं होती, तो दिनांक 01.05.2000 से 9 प्रतिषत ब्याज सहित आज्ञप्ति राशि तक अर्थात् रू 2 करोड़ की वसूली/भरपाई के लिए क्लैक्टर लखनऊ और क्लैक्टर कानपुर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किए हैं ।

2.5 **नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता** (अनुसूची 2, कालम 3) : 31.03.2017 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित राशि (रू. 3,32,260 के अग्रिम को खाते में लेने के बाद) **रू. 1,20,440** राशि (अर्थात अनुसूची 2 के अनुसार रू. 4,52,700 के अग्रिम से एनबीसीसी पर समायोजित की जाने वाली रू 3,32,260 राशि घटा कर है। {अनुसूची 7 (ख) मद 2(क) (v)} हो गई ।

2.6 **केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजनागत योजना** : बीआईएस द्वारा यह योजना खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.2.2004– बीआईएस, दिनांक 30.09.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की

योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। 2016–17 के दौरान मंत्रालय से रू. 1,17,81,690 प्राप्त हुए । 31.03.2017 को इस योजना के अंतर्गत अव्ययित अधिशेष **रू. 2,08,957/–** था, जिनसे वर्ष 2017–18 में अग्रानीत किया गया है (अनुसूची 2, कॉलम 1)।

2.7 **उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता अवसंरचना के लिए भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं (अनुसूची 2, कॉलम 2):** दो योजनाओं को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं विवरण सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बीआईएस द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत प्राप्त निधियों की स्थिति, 2016–17 के दौरान बीआईएस द्वारा व्यय निधियॉ एवं 31.03.17 को खर्च नहीं की गई राशि, का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	योजना/विवरण	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सुदृढ़ करना	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	योग
(i)	01.04.2016 को षेश	2,70,01,373	6,17,48,804	8,87,50,177
(ii)	2016–17 में उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निधियां	–	–	–
(iii)(क)	योजना खाते में उपार्जित ब्याज नामे	7,83,140	10,337	7,93,477
(iii)(ख)	अन्य प्राप्तियां	–	1,72,546	1,72,546
(iv)	कुल {(i)+(ii)+(iii)}	2,77,84,513	6,19,31,687	8,97,16,200
(v)	2016–17 में व्यय			
(क)	पूँजी	–	–	
(ख)	राजस्व	1,64,53,865	100	1,64,53,965
	2016–17 में कुल व्ययअ {(d)+([k)}	1,64,53,865	100	1,64,53,965
(vi)	31.3.2017 को शेश{(iv)-(v)} {अनुसूची 2, कॉलम 2 के अनुसार}	1,13,30,648	6,19,31,587	7,32,62,235
(vii)	निधि के प्रति पूंजीगत कार्य – प्रगति में (संदर्भ अनुसूची 4)	–	6,42,82,564	6,42,82,564
(viii)	31.03.2017 को उपलब्ध निधि	1,13,30,648	(23,50,977)*	

*उपलब्ध निधियों से ज्यादा खर्च की गई राशि को उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से वसूली योग्य लेखों के रूप में दर्शाया गया है। {अनुसूची 7 (क) मद 2ग (ii)}

2.8 **एनबीसीसी द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र** – मुख्यालय के मानक भवन के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्श 2003–04 में षुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी.) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। रू 86.07 लाख का भुगतान एनबीसीसी को किया गया । किंतु, यह परियोजना जून 2006 में बद कर दी गई। एनबीसीसी को भुगतान योग्य परामर्शी खर्चों की गणना के तरीके के संबंध में विवाद के कारण लेखे का समायोजन नहीं किया जा सका । अतः यह निर्णय किया गया कि इस परियोजना के लिए एनबीसीसी के साथ जब तक लेखों का निपटान नहीं हो जाता, तब तक जयपुर शाखा कार्यालय भवन एवं एनआईटीएस के निर्माण जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । 2008–09 में **रू. 86,07,396** का भुगतान किया गया था। स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में इस परियोजना को पूंजीगत कार्य में प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ईसी) की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी. के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह परियोजना पूर्ण की गई और एसी प्लांट प्रचालन में है [(संदर्भ टिप्पणी सं. 2.1 (i)]। परियोजना के कुछ हिस्से प्रगति अधीन हैं ।

एनबीसीसी से विवादित मुद्दों पर परस्पर रूप से स्वीकार्य हल हेतु अनुरोध किया गया है । एनबीसीसी के साथ लेखों के निपटान के बाद इस संबंध में प्रस्ताव बीआईएस के परियोजना प्रबंधन विभाग द्वारा कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा । एनबीसीसी के साथ जिस राशि का निपटान किया जाएगा, वह पूँजीगत व्यय होगा तथा उसे कार्यकारी समिति (भामाब्यूरो परिसरों में पड़ी सामग्री को कंडम करने और बिक्री के बाद समायोजन मूल्य को समायोजित करने के बाद) द्वारा बट्टे खाते में डाला जाएगा, क्योंकि एनबीसीसी को किए भुगतान तथा निपटान की गई राशि में कोई परिसम्पत्ति ही नहीं बची है ।

2.9 भारतीय मानक ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय

2.9.1 वर्ष 2016–17 के दौरान बीआईएस की निधि (समायोजित अग्रिम तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी में परिवर्धन सहित) निकायों में से किया गया पूंजीगत व्यय **रू. 21,62,70,506** निम्नानुसार है (अनुसूची 4 देखें) :

(राशि रू.में)

स्थिर सम्पत्तियों में बढ़ोतरी	2016–17
जमीन तथा भवन	15,41,06,236
फर्नीचर, कार्यालय उपकरण एवं कंप्यूटर	2,09,18,492
प्रयोगशाला उपस्कर	1,67,24,626
पुस्तकालय में पुस्तकें	2,10,409
योग	19,19,59,763
वर्ष के दौरान चालू विभिन्न भवन परियोजनाओं में जारी पूँजीगत कार्य में वृद्धि	2,43,10,743
योग	21,62,70,506

2.9.2 **प्रगतिशील पूंजीगत कार्य** : विभिन्न भवन परियोजनाओं एवं मुख्यालय में एयर कंडीशनिंग परियोजना सहित स्थिर परिसंपत्तियों अनुसूची (अनुबंध 4) के तहत दर्षाए गए प्रगतिशील पूंजीगत कार्य । अनुसूची 4 में दर्शाये गये प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की परियोजनावार राशि निम्नानुसार है :

(राशि लाख रू.में)

क्र. सं.	**परियोजना**	**31.3.2017 तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य**
(i)	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण एवं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगषाला भवन, मोहाली–सीपीडब्ल्यूडी	1273.50
(ii)	राजकोट कार्यालय भवन का निर्माण–सीपीडब्ल्यूडी	395.94
(iii)	जम्मू कार्यालय भवन का निर्माण–सीपीडब्ल्यूडी	423.36
(iv)	परियोजना निधि के तहत सरकार से प्राप्त सहायता से प्रशिक्षण संस्थान भवन, नोएडा का आधुनिकीकरण–सीपीडब्ल्यूडी	642.83
(v)	मुख्यालय भवन की एयर कंडीशनिंग–सीपीडब्ल्यूडी	1520.36
(vi)	बीआईएस मुख्यालय की लिफ्ट की बदली–सीपीडब्ल्यूडी	22.63
(vii)	बीआईएस मुख्यालय की कैंटीन का आंतरिक सज्जा कार्य–सीपीडब्ल्यूडी	22.73
(viii)	गुवाहाटी शाखा कार्यालय का आंतरिक सज्जा कार्य–हाउसफेड	64.91
(ix)	केन्द्रीय एसी प्लांट (एनबीसीसी के माध्यम से–कार्य रोक)	86.07
	योग	**4452.33**

क्रम सं. (i) से (iv) के भवन पहले ही बीआईएस के अधीन हैं । इन भवनों पर हुए खर्च श्रेणीवार एवं इंवेंटरी स्टेटमेंट मदवार 31.03.2017 तक पूंजीगत नहीं किए गए हैं, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । अतः इन भवनों संबंधी मूल्य ह्रास उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं । इन भवनों पर खर्च पूंजीगत किए जायेंगे और मूल्य ह्रास सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त होने पर ब्यौरे के स्टेटमेंटों के बाद प्रभारित किए जायेंगे । क्रम सं. (v) से (viii) पर अन्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।

2.10 सामान्य भविष्य निधि लेखों में सरप्लस : 2016–17 के दौरान बीआईएस कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों में **रू 61,80,536** (खर्च पर आय की अधिकता) सरप्लस था । यह वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन पर ब्याज की दर में कटौती के कारण है । जबकि पिछले निवेशों के समय उच्च दरों पर हैं । लेखाकरण नीति के अनुसार यह ब्यूरो की आय के रूप में माना गया है {अनुसूची 13, मद (छ)}।

2.11 आय कर में छूट :

2.11.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 23.12.2014 की अधिसूचना संख्या 88/2014 द्वारा बीआईएस को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक अधिसूचित किया गया है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बीआईएस

को दिनांक 01.12.2016 की अधिसूचना सं. 111/2016 द्वारा निर्धारण वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन भी अधिसूचित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन वर्ष 2021–22 तक बीआईएस की आय कर योग्य नहीं होगी ।

2.11.2 बीआईएस को धारा 10(23) (सी) (iv) द्वारा प्रदान की गई आयकर में छूट डीजीःआईटी (ई) द्वारा 24.02.2012 के आदेश द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009–10 और उसके बाद के लिए वापस की गई छूट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 04.12.2012 के आदेश द्वारा पुनः शुरू कर दी गई थी । अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(सी)(iv) के अंतर्गत बीआईएस को दी गई छूट भी उपलब्ध है। डीजीःआईटी (ई) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ब्यूरो की रिट पेटीशन पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा अनुमति देने के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल की है। डीजी आईटी (ई) द्वारा फाइल एसएलपी सिविल अपील में कंवर्ट कर दी गई है, जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

2.12 बीआईएस के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.13 अंतिम लेखों में आंकड़े निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुसूची 18 : निवेश

31 मार्च 2017 तक निवेश का विवरण

राशि लाख रूप, में

क्र. सं.	संस्थान का नाम		लागत पर निवेश	निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य*
1	**बीआईएस की निधियों के निवेश**			
1.1	**बैंकों में सावधिक जमा राशियों पर निवेश**			
1.1.1	आंध्रा बैंक		2880.00	2880.00
1.1.2	बैंक ऑफ इंडिया		9089.00	9089.00
1.1.3	केनरा बैंक		12260.00	12260.00
1.1.4	कॉर्पोरेशन बैंक		19726.00	19726.00
1.1.5	इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया		12420.00	12420.00
1.1.6	पंजाब एंड सिंध बैंक		6212.00	6212.00
1.1.7	पंजाब नेशनल बैंक		12986.00	12986.00
1.1.8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर		10740.00	10740.00
1.1.9	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद		500.00	500.00
1.1.10	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		6150.00	6150.00
1.1.11	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर		2280.00	2280.00
1.1.12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला		13970.00	13970.00
1.1.13	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर		9165.00	9165.00
1.1.14	सिंडिकेट बैंक		23725.00	23725.00
	कुल (1.1)		**142103.00**	**142103.00**
1.2	**भारत सरकार की प्रतिभूति – उद्धृत**			
	फेस वेल्यू	29700.00		
	प्रीमियम (परिशोधन का निवल)	2719.43	32419.43	32055.10
	कुल (1.2)		**32419.43**	**32055.10**
1.3	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश**			
1.3.1	उ. प. सहकारी कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल) बोंड (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें)		200.00	200.00
	कुल (1.3)		**200.00**	**200.00**
	कुल		**174722.43**	**174358.10**

	निम्नलिखित निधियों में कुल 174722–43 लाख का बीआईएस का कुल निवेश		
	(अनुसूची 17 का नोट 2–4–1 देखें)		
क)	पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाता अनुसूची 7(क), मद 4(क), (iii), (क) (i) के अंतर्गत अनुसूची 5 (मद 1) 127352.30 32619.43	159971.73	
ख)	कार्पस/पूंजी निधि अनुसूची 7 (क), मद 4(क) (iii) (ख) के अंतर्गत	14726.05	
ग)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि 7(क), मद 4(क) (iii) (ख) के अंतर्गत	24.65	
	बीआई,स निधियों का कुल निवेश	174722.43	
2	कर्मचारी निधि निवेश		
2.1	**सामान्य भविष्य निधि {अनुसूची 5 देखें और अनुसूची 7क– मद 4 (क)(iii)(ए)(ii)}**		
2.1.1	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित	2641.04	2791.86
2.1.2	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित	4200.23	4447.46
2.1.3	आरबीआई में विशेष जमा	3127.08	3127.08
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में डिबेंचर तथा बांड में – उद्धरित	1224.22	1229.84
2.1.5	इक्विटी तथा संबंधित निवेश– म्युचुअल फंड संबंधी – उद्धरित	122.00	139.34
2.1.6	बैंकों में सावधि जमा	3157.81	3157.81
	कुल (2)	**14472.38**	**14893.39**
3	**निवेश – अन्य**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक में (देखें अनुसूची 7(क) मद 4 (क) (iii) (क) (IV)	23.33	23.33
	कुल योग (1+2+3)	**189218.14**	**189274.82**

टिप्पणी : *निवेशों का बाजार मूल्य बीआईएस के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार कोट उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे, वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। यूपीसीएफएमएफएल बांड, में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे, बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शाई गई है। इसका ब्रेक–अप निम्नानुसार है:*

सकल उद्धरित निवेश	40606.92 (बाजार मूल्य 40663.60)
सकल अनुद्धरित निवेश (फिक्स्ड डिपोजिट सहित)	148611.22
कुल निवेश	**189218.14**

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

क. भारतीय मानक ब्यूरो का 2016–17 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष	**18,69,59,400**	**12,04,57,154**	**I.** स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चे	**2,07,23,14,683**	**2,02,72,07,792**
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**1,17,81,690**	**8,75,00,000**	**II.** विभिन्न परियोजनाओं के लि, निधियों		
			से किया भुगतान		
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज	**96,27,41,018**	**79,63,92,351**	क) हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित करने के लिय योजना	**1,49,70,954**	**3,69,84,678**
			ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढांचा–ग्यारहवीं योजना	**1,68,70,065**	**2,77,48,613**
IV. उद्दिष्ट अक्षय से आय	**10,03,852**	**24,64,639**			
			III. किया गया निवेश और जमा (निवल)	**2,48,68,25,000**	**1,98,30,00,000**
V. ब्याज प्राप्त – बचत बैंक खाते	**18,33,013**	**7,60,185**			
			IV. स्थायी परिसम्पत्तियों पर खर्च	**7,42,63,548**	**4,97,59,175**
VI. उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए गुणता अवसंरचना 11वीं योजना	0	**0**	**V.** अन्य भुगतान		
			क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, वर्तमान देयता, तथा अंतर लेखा (निवल)	**85,61,23,263**	**60,19,09,660**
VII. आय–सेवाएं, बिक्री और विविध	**4,58,31,09,409**	**3,90,46,18,829**	ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ	**73,95,82,894**	**59,02,40,036**
			ग) परोपकारी निधि लाभ	**5,00,000**	**6,60,042**
VIII. अन्य प्राप्तियाँ			**VI** रोकड़ शेष		
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि	**73,83,50,419**	**59,14,64,033**	– नकद और अग्रदाय	**3,17,941**	**5,24,230**
ख) परोपकारी निधि	**8,20,710**	**8,12,205**	– बैंक	22,48,31,163	18,64,35,170
योग	**6,48,65,99,511**	**5,50,44,69,396**	**योग**	**6,48,65,99,511**	**5,50,44,69,396**
ख. वर्ष 2016–17 का सामान्य भविष्य निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा					
I. आरंभिक बैंक अधिशेष	**27,49,164**	**18,55,789**	**I.** वापसी एवं अंतिम भुगतान	**31,39,05,805**	**23,46,58,883**
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज	**11,40,95,461**	**10,15,58,527**	**II.** कर्मचारियों को अग्रिम	**13,14,968**	**16,50,828**
III. कर्मचारियों का अंदान	**19,46,93,890**	**19,34,98,377**	**III.** मृत्यु बीमा	**1,80,000**	**3,96,000**
IV. अग्रिम की वापसी	**16,88,053**	**22,02,221**	**IV.** किया गया निवेश एवं जमा (निवल)	**10,01,41,101**	**17,11,90,161**
V. अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	**10,21,22,549**	**11,13,50,605**	**V.** अन्य भुगतान		
			क) वर्तमान देयताएं		
VI. सेविंग बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	**1,99,497**	**1,83,976**	ख) बैंक प्रभार	**1,331**	**4,459**
			VI. बैंक रोकड़ शेष	**5,409**	**27,49,164**
योग	**41,55,48,614**	**41,06,49,495**	**योग**	**41,55,48,614**	**41,06,49,495**

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के खंड 22 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 19(2) के अधीन 31 मार्च 2017 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में भा. मा. ब्यूरो के 23 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय परीक्षण एवं अशंशोधन केन्द्र व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बीआईएस का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं मानकों एवं डिस्कलोजर नार्म्स इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी भी शामिल है। कानूनों, नियम एवं विनियमों; प्रोप्रायटी एवं रेगुलेटरीद्ध तथा दक्षता–सह–कार्य कारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन–देनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियाँ की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जांचें, परीक्षण के आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

(ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन–पत्र, आय एवं खर्च/लेखा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एक रूप फार्मेट में लिया गया है।

(iii) हमारी राय में, खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों की समुचित जाँच करने के बाद लगता है कि इन्हें भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22 (1) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क तुलनपत्र

क.1 परिसम्पत्तियॉं

क.1.1 स्थिर परिसम्पत्ति (अनुसूची 4) रू 136.89 करोड़

क.1.1.1 राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (निट्स), नोएडा में जून 2016 में रू 55,650 का कंप्यूटर, डेस्कटॉप खरीदा गया था, किंतु उसे पूंजीकृत नहीं किया गया, जिसके कारण इस राशि का स्थिर परिसम्पत्तियों में न्यून विवरण दिया गया है तथा पूंजी निधि में इस राशिका न्यून विवरण दिया गया।

इसी प्रकार, निट्स द्वारा मार्च 2017 में रू 13,500 में इंवर्टर खरीदा गया था। हालांकि इस परिसम्पत्ति को स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर में दिखाया गया है, किंतु इसे वार्षिक लेखों में लेखांकित नहीं किया गया। अतः समान राशि के लिए स्थिर परिसम्पत्तियों के साथ–साथ पूंजी निधि में न्यून विवरण दिया गया है।

ख. सामान्य

ख.1 2007–08 से 2016–17 की अवधि से संबद्ध रू 4445304 केटीए/डीए (अनुसूची 3) के लिए फुटकर देयताओं के यथा शीघ्र निपटान/निवर्तन की आवश्यकता है।

ख.2 अनूसूची की संख्याएँ लेखे के एक–समान फार्मेट के अनुसार नहीं हैं।

ख.3 2005–06 से रू 9.07 करोड़ की राशि का अग्रिम असमा शोधित पड़ा है।

ग. सहायक अनुदान

2016–17 के दौरान, बीआईएस को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से रू. 117.82 लाख का सहायक अनुदान मिला। इसमें रू. 11.52 लाख 'ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में और पिछले वर्ष का रू. 924.15 लाख का अव्ययित शेष था। कुल उपलब्ध रू. 1053.49 लाख की राशि में से रू. 314.25 लाख की राशि वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई, जिसके बाद वर्ष के अंत में रू. 739.24 लाख की राशि शेष थी।

v. पहले के अनुच्छेदों में दिए गए हमारे पर्यवेक्षण के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा को हमने इस रिपोर्ट में लेखा पुस्तकों के करार के अनुसार है।

vi. हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय ब्यौरे तथा इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण मामले और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों के अधीन है और इसके अनुरूप सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं :

क. जहाँ तक कि यह 31 मार्च 2017 को भारतीय मानक ब्यूरो के मामले से तुलन पत्र से संबंधित है; तथा

जहां तक कि यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के **'शून्य'** अधिशेष का आय और व्यय के ब्यौरे से संबंधित है।

भारत के महालेखापरीक्षक की ओर से एवं उनके हेतु

स्थानः नईदिल्ली
तिथिः 08.11.2017

ऑडिट महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

संलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

- चार्टेड अकाउंटेंट फर्म द्वारा मार्च 2017 तक आंतरिक ऑडिट कराया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

- मार्च 2017 को 2007–08 से 2016–17 की अवधि से संबद्ध रू 4445304 के टीए/डीए (अनुसूची 3) के लिए फुटकर देयताएँ असमा शोधित थीं।
- निट्स में मार्च 2017 को 2009–10 से लेकर 2013–14 की अवधि से संबद्ध रु 2.97 लाख की फुटकर देयताएँ असमा शोधित थीं ।
- बीआईएस (गाजियाबाद शाखा कार्यालय) ने सांविधिक देयताओं के विलम्ब से भुगतान पर रू 90 दिए। इसी प्रकार, फरीदाबाद शाखा कार्यालय ने सेवाकर पर ब्याज के रूप में रू 527 दिए ।
- एलटीसी एयर ट्रेवल 'ईजी माई ट्रिप', गोइबिबो जैसे प्राइवेट एजेंट के माध्यम से बुक किया गया।
- 2005–06 से रू 9.07 करोड़ की राशि का अग्रिम असमा शोधित पड़ा है ।

उपरोक्त को देखते हुए बीआईएस के आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करने की आवश्यकता है।

3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- मार्च 2017 तक अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।
- वर्ष 2016–17 के लिए बीआईएस–एनआईटीएस, नोएडा से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। बीआईएस–एनआईटीएस, नोएडा से संबंधित अचल परिसंपत्तियों (2015–16) के भौतिक सत्यापन में यह रिपोर्ट किया गया है कि अचल परिसंपत्तियाँ (993 वस्तुएँ) नहीं दर्शाई गई।

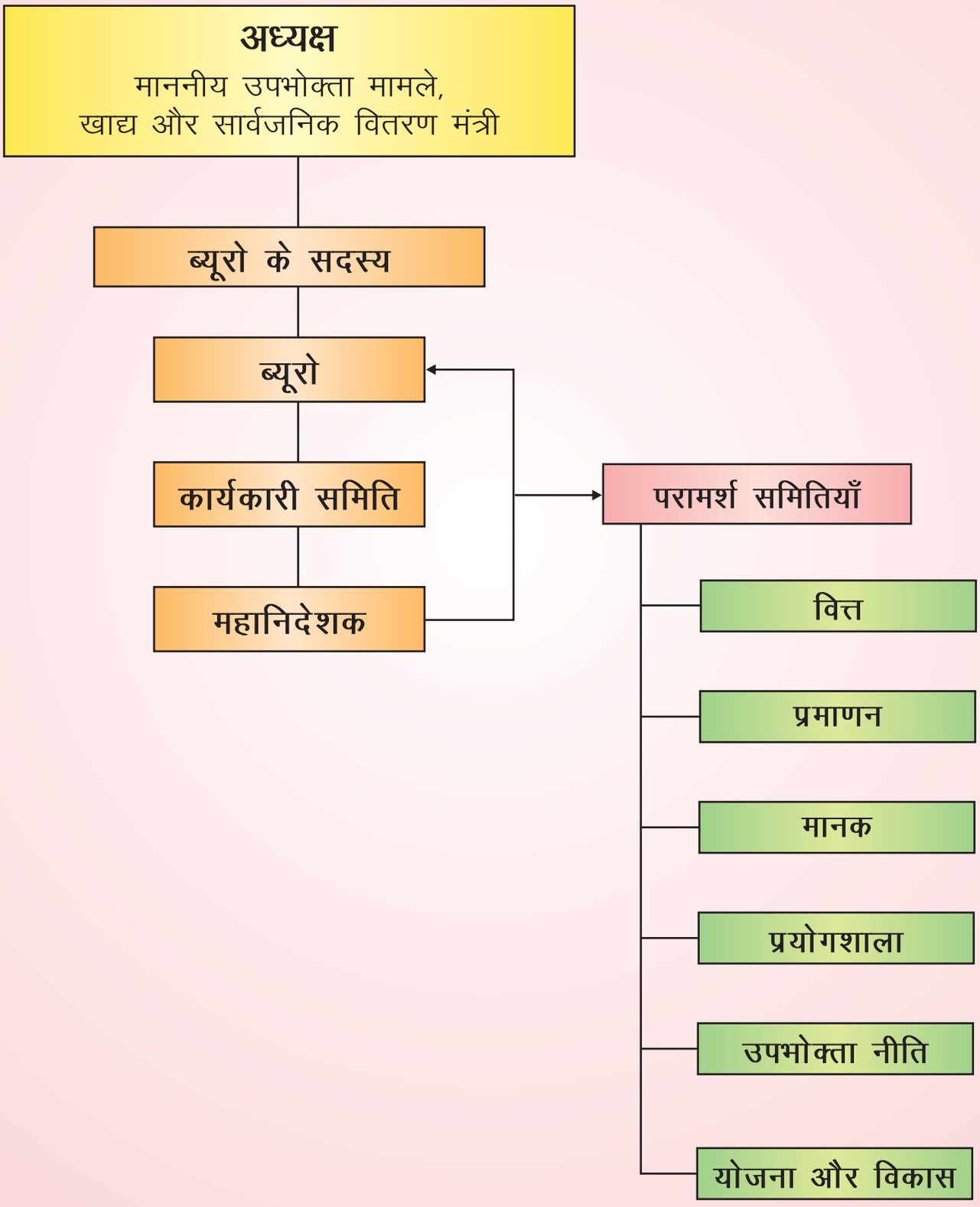
4. मालसूची की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति

- माल सूची का मार्च 2017 तक सत्यापन किया गया ।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- बीआईएस के वार्षिक लेखा के अनुसार, दिनांक 31.03.2017 को छह माह से अधिक सांविधिक देय के संबंध में कुछ भी बकाया नहीं है।

भारतीय मानक ब्यूरो की संरचना



CONTENTS

Sl. No.	CHAPTER	PAGE No.
1.	OVERVIEW	1
2.	STANDARDIZATION	8
3.	CERTIFICATION	25
4.	LABORATORY SERVICES	28
5.	HALLMARKING	30
6.	MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	32
7.	INTERNATIONAL ACTIVITIES AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES	35
8.	TRAINING SERVICES	41
9.	CONSUMER AFFAIRS	44
10.	PUBLICITY	47
11.	SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS	49
12.	HINDI ACTIVITIES	50
13.	PLAN SCHEMES	52
14.	INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	53
15.	PROJECT MANAGEMENT AND WORKS	56
16.	VIGILANCE ACTIVITIES	58
17.	HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES	60
18.	FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT	63

OVERVIEW

The Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standard Body of India was established under the *BIS Act,* 1986, assuming the functions of the erstwhile Indian Standards Institution (ISI). BIS is responsible for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto.

With the integration of global economies, countries around the world are strategically positioning themselves at international level to gain competitive edge and achieve economic benefits. Standards and conformity assessment are significantly influencing global trade. Countries are therefore adopting strategies to seek positions on international standardization forum to influence international standards in their favour.

Standardization supports economic growth, enhances competitiveness and fosters technological developments. It is also a tool to influence public policies such as on health and safety, protection of environment and consumer protection. By ensuring a level playing field and defining common criteria of acceptance of goods, standards are increasingly being used as tools to support regulatory framework and to facilitate trade.

BIS through its core activities of standardization and conformity assessment, has been benefiting the national economy by providing safe, reliable and quality goods; minimizing health hazards to consumers; protecting the environment, promoting exports and imports substitute; controlling over proliferation of varieties, etc. The standards and certification scheme of BIS apart from benefitting the consumers and industry also support various public policies especially in areas of product safety, consumer protection, food safety, environment protection, building and construction, etc.

During the year, BIS worked towards specifically addressing various national priorities and other government initiatives like Swacch Bharat Abiyan, Digital India, Make in India and ease of doing business through its activities of standardization and certification. In standards development, BIS continued to address issues of technology changes and advancements, climate change, environment and energy conservation, health and safety and facilitation of trade. In the area of conformity assessment BIS worked towards making the processes simpler and faster. BIS maintained a satisfactory progress in all its activities during the year.

STATUTORY FRAMEWORK

BIS operates under the framework of the *BIS Act*, 1986 and the Rules and Regulations framed there under.

The *Bureau of Indian Standards Act*, 2016, was published for general information in official gazette on 22 March 2016 and the Rules and Regulations under the act are being framed. The highlights of the new BIS Act are:

- Positions BIS as the National Standards Body.
- Includes services and systems besides articles and processes under standardization regime.
- Allows multiple conformity assessment schemes in line with global practices.

- Enables the Government to authorize any other agency apart from BIS to certify and enforce conformity to a standard.
- Enables the Government to include products under mandatory certification on grounds of health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices.
- Enables the Government to bring Hallmarking of precious metal articles under mandatory certification.
- Provides consumer protection measures like recall of non-conforming standard marked products, compensation to the consumer and more stringent penal provisions.

BIS MANDATE

BIS has the mandate to satisfy the customer needs for quality of goods and services.

OBJECTIVES OF BIS

- Harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods.
- To provide thrust to standardization and quality control for growth and development of industry on one hand and to meet the needs of consumers on the other.

ACTIVITIES

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

i) Standards formulation

ii) Certification : product (including registration), hallmarking and management systems

iii) Laboratory services

iv) Consumer affairs

v) International activities

vi) Information technology services

vii) Training services

viii) Sale of Indian Standards and other publications

ix) Publicity

x) Vigilance

xi) Project management and works

xii) Administration, Finance and Accounts

ORGANIZATIONAL NETWORK

BIS has its Headquarters at New Delhi. It has 5 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional

Offices are the Branch Offices (BOs). There are 33 BOs located at 28 different locations namely Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Durgapur, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot and Vishakhapatnam. The BOs serve as an effective link between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc., of the region. In order to cater to the needs of the state of Jammu and Kashmir, a BIS Branch office was opened at Jammu during 2016-17.

To cater to the needs of testing of samples of certification activity, BIS has eight laboratories in the country namely Central Laboratory (CL), Sahibabad; Western Regional Office Laboratory (WROL), Mumbai; Northern Regional Office Laboratory (NROL), Mohali; Eastern Regional Office Laboratory (EROL), Kolkata; Southern Regional Office Laboratory (SROL), Chennai; Bengaluru Branch Office Laboratory (BNBOL), Bengaluru; Patna Branch Office Laboratory (PBOL), Patna; Guwahati Branch Office Laboratory (GBOL), Guwahati.

GOVERNANCE

The Governing Body and the Executive Committee provides the policy directives and strategic directions and oversees the development and implementation of the organizations objectives and goals. The Governing Body consists of 25 members representing both the Central and the State Governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies. The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is the President and the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution is the Vice-President of the Bureau.

The 26thGoverning Body meeting was held on 7 April 2016 in Mussoorie. Four meetings of Executive Committee were held on 05 May 2016, 16 June 2016, 6 September 2016 and 24 January 2017.



26th Governing Body meeting of BIS at Mussoorie

HIGHLIGHTS OF BIS ACHIEVEMENTS DURING 2016-17:

- 722 Indian Standards covering wide ranges of subjects were formulated during the year. As on 31 March 2017, 19 025 standards were in force. Some of important standards formulated during the period include those on geosynthetic non-woven geobags, technical textiles (protective textiles and medical textiles), enhanced inscript keyboard layouts, Indian language support for mobile handsets, transportable refillable fully wrapped composite LPG cylinders, high voltage switchgears, guide for addressing environmental issues in products standards and proton exchange membrane (PEM) fuel cells for hydrogen fuel.

- The revised National Building Code of India (NBC) 2016, a comprehensive building Code providing guidelines for regulating the building construction activities across the country was published in March 2017. This code serves as a Model Code for adoption by all agencies involved in building construction works, be the Public Works Departments, other government construction departments, local bodies or private construction agencies. The salient features of the revised NBC include, apart from other changes made, the changes specially in regard to further enhancing our response to meet the challenges posed by natural calamities.

- In order to create awareness and disseminate information on standards and to facilitate their implementation, BIS organizes seminars and workshops for stakeholders. A number of such events were organized, notable ones being on:

  – Innovations in Steel and latest trends in Steel Making

  – Importance of Hill Area Development Engineering and Rock Mechanics

  – Overview of National Building Code of India 2016 and Insights to Fire and Life Safety

  – EU Regulatory Framework in Technical Textile

  – World Standards Day celebrations

- BIS, as the National Standards Body has been working to ensure that India has a voice on international standardization committees that are important to the country and to our economy. BIS endeavours to have the experts to participate in international standardization and facilitate their participation. BIS during the year increased its involvement and participation in international standardization committees of International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). As a policy, BIS also endeavours to harmonize the Indian standards with the corresponding International standards of ISO and IEC to the extent possible keeping into consideration national needs and requirements. During the year, Indian Standards were harmonized with ISO/IEC standards and a total of 5 151 Indian Standards have been harmonized with the International Standards.

  Countries collaborate with each other in areas of standardization and conformity assessment in order to collectively influence standards development at international level and to also gain from each other's experiences. During the year, BIS entered into cooperation agreements with corresponding National Standards Body of other countries. Memorandum of Understanding (MoU) between BIS and Kenya Bureau of Standards (KEBS) and between BIS and the National Standardization Agency of Indonesia (BSN) were signed.

- Conformity assessment has been a leading activity of BIS. This includes product certification through the BIS Product Certification Marks Scheme (ISI Mark), Foreign Manufacturers Certification Scheme and Compulsory Registration Scheme, Hallmarking of gold and silver jewellery, Management System Certifications and of testing of product samples in laboratories for the purpose of certification. In line with the Government policy of ease of doing business, BIS introduced simplified procedures of certification and online registration processes for its registration scheme.

  - During the year, 4 098 product certification licences have been granted. As on 31 March 2017, the total number of product certification operative licences was 33 230.
  - During the year, following 17 products were covered for the first time under the product certification scheme. These were:
    - High density polyethylene (HDPE) / polypropylene (PP) woven sacks for filling sand
    - Particle Filters used in Respiratory Protective Equipment
    - Fire-resistant Hydraulic fluids: Part 2 Invert Emulsion (Water-in-oil) type
    - Carbon Disulphide, Technical
    - Iron Fortified Salt (Double Fortified salt) – Food Grade
    - Steels For Cold Heading/Cold Extrusion Applications: Part 1 Wrought Carbon and Low Alloy Steels
    - Plant Protection and Vector Control Equipment — Fogging Machines: Part 1 Pulse-Jet-Type Thermal Fogging Machines
    - Polymer based Preformed Fillers for Expansion Joints in Concrete Pavements and Structures (Non-Extruding and Resilient Type)
    - Putty for Use on Window frames
    - Steel Tubes For Automotive Purposes
    - Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet and Strip for Utensils and Kitchen Appliances
    - High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (PP) woven sacks for packaging 50 kg /25 kg Sugar
    - Roasted Groundnut (Peanut) Kernels
    - Composite Cement
    - Dunnage pallets — Ware housing
    - Specification for super sulphated cement
    - Conveyor belts — Fire resistant conveyor belting for underground mines and such other hazardous applications
- 190 licenses were issued during 2016-17 under the Foreign Manufacturers Certification Scheme (FMCS), taking the total number of operative licences to 671, against 83 Indian Standards.

- Government of India, has notified 30 Electronics and IT goods under the Compulsory Registration Scheme. As on 31 March 2017, total number of registrations granted to manufacturers located throughout the world was 8 313.
- 21 467 samples were tested by BIS Laboratories which include 2 965 samples tested by Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai. As on March 2017, 179 outside labs stood recognized by BIS including 33 labs for testing of IT products, which were covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.
- As on 31 March 2017, the number of operative licences for hallmarking of gold and silver jewellery was 18 112 and 1 494, respectively. The number of operative BIS recognized assaying and hallmarking centres was 454. During the year, about 3.16 crore articles of gold and silver jewellery/ artefacts were hallmarked.
- BIS launched the Medical Devices Management System (MDMS) Certification Scheme in June 2016.
- 867 Quality Management System (QMS) Certification licences, 203 Environmental Management Systems (EMS) Certification licences, 102 Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) Certification licences, 14 Food Safety Management System (FSMS) Certification licence, 101 Service Quality Management System (SQMS) Certification licences, 20 Energy Management System (EnMS) Certification licences, 2 Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) stand-alone licences, 35 HACCP integrated with QMS licences and one Medical Devices Management System (MDMS) licence were operative as on 31 March 2017.

- Other achievements during the year:
  - In an endeavour to build the capacity of the developing world in the fields of standards and conformity assessment, the 13th International Training Programme on Management Systems, the 49th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance and the 7th International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems (LQMS) were organised by National Institute of Training for Standardization (NITS) of BIS during the year. These training programmes were sponsored by Ministry of External Affairs and attended by 98 participants from several developing countries.
  - During the year, 163 consumer awareness programs, 62 industry awareness programs and 39 programs for educational utilization of standards were organized. 57 grievances/complaints were received and 91 grievances/complaints were redressed during the year.
  - During the year, BIS carried out 114 search and seizures all over the country on firms misusing ISI mark and such products were seized. Efforts were made for timely launching of prosecution against the offenders in the Court of law.
  - As a green initiative, in addition to the existing Rooftop Solar Power Plants installed in BIS HQ, New Delhi (100 kW), SRO Lab, Chennai (100 kW), WRO, Mumbai (40 kW) and NITS, Noida (50 kW), rooftop solar power plants were further installed at Hyderabad Branch

Office (40 kW), Eastern Regional Office, Kolkata (24.4 kW) and BIS Eastern Regional Office Laboratory, Kolkata (40 kW). BIS has also implemented Net Metering at HQ, New Delhi, NITS, Noida and Hyderabad Branch Office.

- During the year, 13 scientists in waiting list of the recruitment process 2015-16 joined as Scientist B through direct recruitment. As on 31 March 2017, a total of 1 507 employees were on the rolls of BIS.
- Vigilance Awareness Week was celebrated in BIS from 31 October 2016 to 5 November 2016.
- Hindi Pakhwara was celebrated from 1 to 14 September 2016 at BIS headquarters in which six competitions related to Hindi were organized and 27 Prizes were awarded to the successful participants.

■ BIS recorded a total income (excluding interest from investment) of about ₹ 456.63 crore, compared to ₹ 390.83 crore during the previous year, thus marking an increase of about 16.8% in total income during 2016-17 compared to the previous year. BIS continued to be self-sufficient in meeting its expenditure and other liabilities from its own income for the twenty seventh consecutive year.

Director General

STANDARDIZATION

STANDARDS FORMULATION

The primary goal of BIS, is to enhance the global competitiveness of Indian businesses and improving quality of life by promoting and facilitating voluntary consensus standards and ensuring their integrity. Generally the activity consists of the process of formulating, issuing and implementing standards. Standards have always been closely connected with exchange of goods and services between suppliers and consumers. Through formulation of standards, the BIS has provided traceable and tangible benefits to economy in a number of ways - providing safe, reliable, quality goods; minimizing health hazards to consumers; promote exports and import substitution; control over proliferation of varieties, etc.

The process of standards development adopted by BIS follows internationally accepted good standardization practices and in compliance with the WTO-TBT code of good practice for preparation, adoption and application of standards. In the development of National Standards, BIS provides all interested stakeholders, with a neutral platform to come together and work towards common agreements. BIS currently provides a forum for 325 Sectional Committees, representing over a thousand experts from organized consumers and consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts. Also includes concerned officials of BIS. These committees work cooperatively to develop consensus based voluntary National standards with stakeholder consultations.

The appropriate Sectional Committee of BIS takes up a subject for formulation of Indian Standard(s) based on proposals which may be submitted by any Ministry / Department under the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees with the approval of the concerned Division Council.

A total of 286 Technical committee meetings were held during 2016-17, to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and to withdraw obsolete standards. During 2016-17, 722 (new 371 and revised 351) standards were formulated. The total number of standards in force, as on 31 March 2017 was 19 025.

REVIEW OF STANDARDS

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years to establish whether these standards are still relevant and to take appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdrawal.

HARMONIZATION

In the present market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International Standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro-technical Commission (IEC). Further, India is a signatory to the World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of

WTO are required to align the National Standards to the extent possible with International Standards. National Standards may deviate from International Standards on grounds of technological or geographical considerations. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for standards development. During the year, 109 Indian Standards were harmonized with International Standards. A total of 5 151 Indian Standards have so far been harmonized with International Standards.

IMPORTANT STANDARDS FORMULATED DURING 2016-17:

IS 16653:2017 - Geosynthetics — Needle punched non-woven geobags for coastal and waterways protection — This standard specifies requirements for three types of geobags made from needle punched non-woven fabric of polyester (PES) or polypropylene (PP), used for coastal and waterways protection applications such as revetments; river training; construction of groynes and artificial reefs; etc, in order to minimize soil erosion and control floods. The technology has been popular worldwide due to its easier installation, cost effectiveness, their technical efficiency and environmental friendliness in comparison to the conventional erosion protection work using cement concrete block, gravel, hard rock, etc.

IS 16654:2017- Geosynthetics — Polypropylene multifilament woven geobags for coastal and waterways protection — This standard specifies requirements for geobags made from polypropylene (PP) multifilament woven geotextiles, used for coastal and waterways protection applications such as revetments, river training, construction of groynes and artificial reefs, etc, in order to minimize soil erosion and control floods. This standards specify two type of geobags of 200 and 300 GSM.

IS 16655:2017 - Textiles — Protective clothing for use in welding and allied processes — This Indian Standard specifies minimum basic safety requirements and test methods for protective clothing including hoods, aprons, sleeves, and gaiters that are designed to protect the wearer's body including head (hoods) and feet (gaiters) and that are to be worn during welding and allied processes with comparable risks.

IS 16660:2017 - Medical textiles – Non-woven bandage roll – This standard specifies the requirement of non-woven bandage rolls intended for medical use. This standard provides the information about manufacture, workmanship and finish of nonwoven bandage roll and covers the performance requirements such as weight per square meter, absorption, water holding capacity, tensile strength, water soluble substance, cytotoxicity, etc.

IS 16585 : 2016 - Magnetic materials – Specification for individual materials – Fe-based amorphous strip delivered in the semi processed state — This standard defines the grades of Fe-based amorphous strip supplied in the semi-processed state that is without final heat treatment, of nominal thickness 0.025 mm. In particular, it gives general requirements, magnetic properties, geometric characteristics, tolerances and technological characteristics, as well as inspection procedures. This standard applies to the rapidly-solidified Fe-based amorphous strip supplied in coils with as-cast edges and intended for the construction of magnetic circuits of a transformer.

IS 16586:2016 - Magnetic materials – Methods of measurement of magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of single sheet tester — This standard specifies methods for the measurement of a.c. magnetic properties of Fe-based amorphous strips at frequencies up to 400 Hz. The object of this part is to define the general principles and the technical details of the measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strips by means of a single sheet tester.

IS 16350 : 2016 - Enhanced inscript keyboard layouts — This standard specifies the character code-sets for representing Indian Languages and their scripts on digital medium - like contents in computers and mobile phones. The standard covers code charts, characters and character names for 11 Indian scripts covering all 22 official languages of India which are identical to ISO/IEC 10646 – 'Universal Coded Character Set'. Ministry of Communication and Information Technology (MCIT), Government of India, has notified the use of this standard for all e-governance systems

IS 16333 (Part 3):2016 - Mobile phone handsets - Indian language support for mobile phone handsets – Specific requirements — This standard (Part 3) defines the requirements for mobile phone handsets for inputting of text in English, Hindi and at least one additional Indian official language along with facility of message readability for all 22 Indian official languages. Mobile phone handset is being used by the vast cross-section of consumers across all segments of people in the country. SMS messages and alerts have also become a very powerful medium of conveying information regarding weather and prices to farmers, and in other e-Governance applications, such as education, health and welfare, as part of Digital India. Government of India has mandated implementation of this standard under Compulsory Registration Scheme (CRS) of BIS.

IS 16377:2017 - Synchronous belt drives - Automotive pulleys — This standard specifies the characteristics of synchronous pulleys for use in automotive applications of synchronous endless belt drives. The characteristics include tooth dimensions and tolerances and pulley tolerances and quality specifications.

IS 16558:2017 - Belt drives – V-belts for the automotive industry and corresponding pulleys – Dimensions — This International Standard specifies the requirements for belts and pulleys for V-belt drives used for driving auxiliaries of internal combustion engines for the automotive industry.

IS 16530 (Part 1):2016 - Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability — This standard specifies a framework for the interoperability of a set of software products used in the manufacturing domain and to facilitate its integration into a manufacturing application. This framework addresses information exchange models, software object models, interfaces, services, protocols, capability profiles and conformance test methods.

IS 16530 (Part 2):2016 - Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability: Part 2 Profiling methodology — This standard specifies a methodology for constructing profiles of manufacturing software capabilities, and is applicable to software products used in the manufacturing domain.

IS 16530 (Part 3):2016 - Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability: Part 3 Interface services protocols and capability templates — This standard specifies requirements for interface services and protocols used to access and edit capability profiles and associated templates used in the capability profiling method defined in **5** of IS 16530 (Part 2).

IS 16530 (Part 4):2016 - Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability: Part 4 Conformance- Test Methods Criteria and Reports — This Standard specifies the test method, the associated test criteria and the statement format used to evaluate and declare the degree of conformance of an implementation, that is a unit under test (UUT), to the requirements specified in other parts of IS 16530. It includes definitions

intended to assist a manufacturer or supplier (first party), a user or purchaser (second party), or an independent body (third party) to perform the assessment for type evaluation.

IS 16537:2016/ISO 21049:2004 - Pumps — Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps — This standard specifies requirements and gives recommendations for sealing systems for centrifugal and rotary pumps used in the petroleum, natural gas and chemical industries. It is applicable mainly for hazardous, flammable and/or toxic services where a greater degree of reliability is required for the improvement of equipment availability and the reduction of both emissions to the atmosphere and life-cycle sealing costs.

IS 16485:2016/ISO 16852:2008 - Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use — This standard specifies the requirements for flame arresters that prevent flame transmission when explosive gas-air or vapour-air mixtures are present. It establishes uniform principles for the classification, basic construction and information for use, including the marking of flame arresters, and specifies test methods to verify the safety requirements and determine safe limits of use.

IS 16646:2017 - Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) — This standard deals with fully wrapped fibre reinforced composite cylinders with non-metallic non-load sharing liner (Type 4 cylinders) intended for storage and transportation of liquefied petroleum gasesexposed to ambient temperature and with the test pressure of 30 bar of nominal capacity exceeding 0.5 litre up to and including 150 litre water capacity. This standard specifies the minimum requirements for the materials, design, manufacture, construction, inspection, testing and marking on these cylinders.

IS 16542:2016 - Direct insertion type storage water tank for all glass evacuated tubes solar collector — This standard specifies requirements of direct insertion type storage water tank of water capacity up to 500 litre for use with all glass evacuated tubes solar collector. This standard covers only vented type storage water tank.

IS 16543:2016 - All glass evacuated solar collector tubes — This standard specifies requirements of all glass evacuated solar collector tubes of non-concentrating type solar collector hot water output up to 80°C.

IS 16544:2016- All glass evacuated tubes solar water heating system — This standard specifies requirements of all glass evacuated tubes solar water heating system. This standard covers only non-concentrating, direct, vented solar collector system based on thermosiphon principle. This standard do not apply to solar water heating systems which have an auxiliary heater as an integral part of the system, since the operation of the auxiliary input may influence the performance of the system.

IS 16221(Part 1):2016/ IEC 62109-1:2010 - Safety of power converters for use in photovoltaic power systems: Part 1 General requirements — This standard applies to the power conversion equipment (PCE) for use in Photovoltaic (PV) systems where a uniform technical level with respect to safety is necessary. This standard defines the minimum requirements for the design and manufacture of PCE for protection against electric shock, energy, fire, mechanical and other hazards.

IS 16227(Part 2):2016/ IEC 61869-2:2012 - Instrument transformers: Part 2 Additional requirements for current transformers — This standard is applicable to newly manufactured inductive current transformers for use with electrical measuring instruments and/or electrical protective devices having rated frequencies from 15 Hz to 100 Hz.

IS 16463(Part 11):2016/IEC 61643-11:2011 - Low-voltage surge protective devices: Part 11 Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test method — This standard is applicable to devices for surge protection against indirect and direct effects of lightning or other transient over voltages. These devices are packaged to be connected to 50/60 Hz a.c. power circuits, and equipment rated up to 1 000 V r.m.s. Performance characteristics, standard methods for testing and ratings are established. These devices contain at least one non-linear component and are intended to limit surge voltages and divert surge currents.

IS/IEC 62271-103:2011 - High-voltage switchgear and controlgear: Part 103 Switches for rated voltages above 1 kV Up to and including 52 kV — This standard is applicable to three-phase, alternating current switches and switch disconnectors for their switching function, having making and breaking current ratings, for indoor and outdoor installations, for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV and for rated frequencies from 162/3 Hz up to and including 60 Hz. This standard is also applicable to single-pole switches used on three phase systems.

IS/IEC 62271-104:2009 - High-voltage switchgear and control-gear: Part 104 Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above — This standard is applicable to three-pole alternating current switches for rated voltages 52 kV and above, having making and breaking current ratings, for indoor and outdoor installations, and for rated frequencies up to and including 60 Hz.

IS 16316:2016/ ISO/TR 21102:2013 - Adventure tourism leaders personnel competence — Depending on the type of adventure tourism activity (rafting, hiking, cascading, climbing, among others), different competences are required. Nevertheless, there are some competences that are common to every adventure tourism activity. These common competences are the focus of this Technical Report.

IS 13450(Part 2/Sec 54):2016/IEC 60601-2-54:2009 - Medical electrical equipment - Part 2 - Section 54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy — This standard applies to the basic safety and essential performance of medical electrical equipment and medical electrical systems intended to be used for projection radiography and radioscopy. This standard is about type testing of X-ray systems.

IS 13450(Part 2/Sec 63):2016/IEC 60601-2-63:2012 - Medical electrical equipment — Part 2 - Section 63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment — This standard applies to the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment, hereafter also called ME equipment. While the previously existing standards for such equipment were dedicated to components and subsystems, this particular standard addresses the system level of dental extra-oral X-ray equipment.

IS 13450(Part 2/Sec 65):2016/IEC 60601-2-65:2012 - Medical electrical equipment - Part 2 - Section 65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment — This standard applies to the basic safety and essential

performance of dental intra-oral X-ray equipment and its main components. The scope of this standard is restricted to X-ray equipment where the X-ray tube assembly contains the high-voltage transformer assembly. Dental extra-oral X-ray equipment is excluded from the scope of this standard. This particular standard has been formulated to provide, based on IEC 60601-1:2005 and its collaterals, a complete set of basic safety and essential performance requirements for dental intra-oral X-ray equipment.

IS/IEC 61010-1:2010 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 1: General requirements - This standard specifies general safety requirements for the following types of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used.

a) Electrical test and measurement equipment,

b) Electrical industrial process-control equipment, and

c) Electrical laboratory equipment

IS/ISO Guide 64:2008 - Guide for addressing environmental issues in product standards — This Guide provides guidance on addressing environmental issues in product standards. It is primarily intended for product standards writers. Its purpose is to outline the relationship between the provisions in product standards and the environmental aspects and impacts of the product.

IS 16061(Part 2):2016/ISO 14687-2:2012 - Hydrogen fuel – Product specification: Part 2 Proton exchange membrane (PEM) Fuel cell application for road vehicles — This standard specifies the quality characteristics of hydrogen fuel in order to ensure uniformity of the hydrogen product as dispensed for utilization in proton exchange membrane fuel cell road vehicle systems. This standard classifies hydrogen fuel into gaseous and liquid types.

IS 16512 (Part 1):2016/ISO 16110-1:2007 - Hydrogen generators using fuel processing technologies: Part 1 Safety — This standard applies to packaged, self-contained or factory matched hydrogen generation systems that convert an input fuel to a hydrogen rich stream of composition and conditions suitable for the type of device using the hydrogen. It is applicable to stationary hydrogen generators intended for indoor and outdoor commercial, industrial, light industrial and residential use.

IMPORTANT STANDARDS REVISED DURING 2016-17:

IS 14543:2016- Packaged drinking water (other than packaged natural mineral water) (*second revision*) — Consumption of packaged water for drinking purposes has been increasing considerably in the country. Apart from water shortages at times, real and perceived needs to safeguard health have also contributed to an escalating trade in packaged drinking water at the national and international level.

IS 16066:2016 - Street food vendors — Food safety requirements (*first revision*) — This standard lays down control check points with minimum requirements and checklist with grading criteria which if exercised would ensure safe food to the consumer. It covers all mobile and fixed food vendors serving prepared/raw food for human consumption. This standard provides guidelines with respect to minimum check points which if exercised would ensure a safe food to the common consumer.

IS 14715 (Part 1):2016 - Jute geotextiles: Part 1 Strengthening of sub-grade in roads(*second revision*) — This standard lays down requirements of woven and non-woven jute

geotextile (JGT) for strengthening of road sub-grades. Jute geotextiles covered under this standard are suitable for strengthening of flexible pavements on weak road sub-grades subjected to relatively low traffic load and intensity.

IS 14715 (Part 2):2016 - Jute geotextiles: Part 2 Control of bank erosion in rivers and waterways (*second revision*) — This standard provides requirements of woven jute geotextile (JGT) in control of erosion in rivers and waterways. Use of woven JGT in controlling river bank erosion is recommended as an eco-friendly substitute of the conventional granular filter comprising graded boulders and ballasts of stone, laterite or similar materials of the desired specific gravity.

IS 9755:2016 - Textiles-high density polyethylene (HDPE)/polypropylene (PP) woven sacks for packing fertilizers (*fifth revision*) — This standard prescribes the requirements of HDPE/PP woven sacks for packing all types of fertilizers produced indigenously or imported. In this revision, important requirement of ash content along with marking of recycling logo has been included and requirement for breaking strength of fabric and breaking strength of bottom seam has been enhanced for better performance of bags.

IS 1417:2016 - Gold and gold alloys, jewellery/artefacts – Fineness and marking (*fourth revision*) — In this revision, bullion and coin have been defined and included in the scope of the standard. Marking clause has been modified and both carat and fineness are indicated in marking. The grades of purity 22k 916, 18k 750 and 14k 585 have been retained for jewellery making, and a negative tolerance of maximum 2ppt has been introduced on re-testing of hallmarked jewellery/artefact.

IS 513(Part 1):2016 - Cold reduced carbon steel sheet and strip: Part 1 Cold forming and drawing purpose — In the present version existing standard is divided into two parts based on the strength level. New designations and grades, classification of grades and new designations in temper designations have been added. This standard covers the requirement of cold reduced carbon steel sheets and strips for cold forming and drawing purpose for thickness upto 4.0mm.

IS 513(Part 2):2016 - Cold reduced carbon steel sheet and strip: Part 2 High tensile and multi-phase steel — In the present version existing standard is divided into two parts, based on the strength level. This standard covers the requirements of cold reduced carbon high tensile and multi-phase steel sheets and strips for forming for thickness upto 3.0 mm.

IS 1893(Part 1):2016 - Criteria for earthquake resistant design of structures: Part 1 General provisions and buildings (*sixth revision*) — This revised standard provides the minimum design force for earthquake resistant design of special structures such as large and tall buildings, large and high dams, long-span bridges and major industrial projects. This standard also provides for various maps of India depicting seismic zonation, epicentres of past earthquakes, principle tectonic features, principle lithological groups. In this comprehensive revision, the major modifications include among others, incorporation of provisions relating to assessment of liquefaction potential of soils, reinforced concrete frame buildings with unreinforced masonry infill walls, and for those with open storeys, flat slabs, etc.

SP 7:2016 - National Building Code of India (NBC) (*third revision*) — It is a special publication which serves as a model Code for adoption and use by building regulatory authorities, government construction departments and other construction agencies, and is also useful for all connected with building planning, design and construction, etc. NBC is a single document in which, like a network, the various information related to building planning, design, construction and other concerned

aspects is woven into pattern of continuity and cogency with the interdependent requirements of its different chapters, carefully analysed and fitted in, to make the whole document a cogent continuous volume. The Code mainly contains provisions on administration; development control rules and general building requirements; fire and life safety; building materials; structural design; construction management, practices and safety; building services; plumbing services; landscape development, signs and outdoor display structures; and approach to sustainability, in different Parts and Sections of the Code.

The revised National Building Code of India 2016 was formally released by the Hon'ble Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan on 15 March 2017 during World Consumer Rights Day Celebration at DRDO Bhavan, New Delhi.



Revised National Building Code of India 2016 released on World Consumer Rights Day Celebration on 15 March 2017 at New Delhi

IS 14820(Part 1):2016 - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths divergence angles and beam propagation ratios: Part 1 Stigmatic and simple astigmatic beams (*first revision*) — This standard specifies methods for measuring beam widths (diameter), divergence angles and beam propagation ratios of laser beams. This part is only applicable for stigmatic and simple astigmatic beams.

IS 14820(Part 3):2016 - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths divergence angles and beam propagation ratios: Part 3 Intrinsic and geometrical laser beam classification propagation and details of test methods (*first revision*) - This part of the standard specifies methods for measuring beam widths (diameter), divergence angles and beam propagation ratios of laser beams in support of IS 14820 (Part 1). It provides the theoretical description of laser beam characterization based on the second-order moments of the Wigner distribution, including geometrical and intrinsic beam characterization, and offers important details for proper background subtraction methods recommendable for matrix detectors such as CCD cameras.

IS 5030(Part 2):2016 - Metal cutting band saw blades: Part 2 Characteristics and dimensions (*second revision*) — This part of the standard specifies the characteristics and dimensions of the various types of metal-cutting band saw blades.

IS 4296(Part 1):2016 - Tools for pressing: Part 1 Round punches with 60° conical head and straight shank (*second revision*) — This standard specifies the basic dimensions, in millimeters, of round punches with 60° conical head and straight shank in the diameter range of 0.5 mm to 20 mm. It gives example material and hardness values, and specifies the designation of the punches, whose main use is punching holes in steel sheets but that can also be used on other materials.

IS 6548(Part 1):2016 - Rolling bearings instrument precision bearings: Part 1 Boundary dimensions tolerances and characteristics of metric series bearings (*second revision*) — This part of the standard specifies the characteristics that define instrument precision rolling bearings, metric series, their types, boundary dimensions, tolerances and internal clearance, classifications used for selective assembly, torque definitions and test condition, and limitations of bearing yield rates.

IS 550(Part 2):2016 – Safes: Part 2 Test for burglary resistance (*fifth revision*) — This standard lays down the methods of test for assessing the burglary resistance of the safes.

IS 1391(Part 1):2017 - Room air conditioners: Part 1 unitary air conditioners (*third revision)* - This standard prescribes the constructional and performance requirements of non-ducted unitary air conditioners upto and including capacity of 10 500 W, upto and including rated voltage of 240 V and rated frequency of 50 Hz. This standard also prescribes the test conditions and the corresponding test procedures for determining various performance characteristics of unitary air conditioners which operate non frosting when cooling and dehumidifying at standard rating conditions. This standard specifies unitary air conditioners which may also serve as heaters by heat pump/ electric heater application.

IS/IEC 60947-4-2:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear: Part 4 Contactors and motor-starters, Section 2 a.c semiconductor motor controllers and starters (*first revision*) — This standard applies to a.c. semiconductor motor controllers and starters, which may include a series mechanical switching device, intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. This standard characterizes a.c. semiconductor motor controllers and starters with and without bypass means.

IS 13730(Part 20):2016/IEC 60317-20:2000 — Specification for particular types of winding wires: Part 20 Solderable polyurethane enamelled round copper wire, round copper wire, class 155 (*first revision*) — This standard specifies the requirements of solderable enamelled round copper winding wire of class 155 with a sole coating based on polyurethane resin, which may be modified providing it retains the chemical identity of the original resin and meet all specified wire requirements.

IS 1459: 2016 - Kerosene (*third revision*) — This standard prescribes requirements and methods of sampling and test of kerosene intended for use as an illuminant and as a fuel. This specification was originally issued in 1959 and subsequently revised in 1968 to include two grades of kerosene, namely, SK grade and 1K grade. In the present (third revision), sulphur content limit has been reduced to address the environmental concern in phased manner.

IS 13450(Part 2/Sec 43): 2016/IEC 60601-2-43:2010 - Medical electrical equipment - Part 2 - Section 43 : Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures (*first revision*) — This standard establishes particular basic safety and essential performance requirements for the design and manufacture of X-ray equipment for radioscopically guided interventional procedures. It specifies information which is to be provided with such interventional X-ray equipment for the assistance of the responsible organization and operator in managing the radiation risk and equipment failure risk arising from these procedures which could affect patients or staff.

IS 13450(Part 2/Sec 44): 2016/IEC 60601-2-44 : 2009- Medical electrical equipment — Part 2 Section 44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography (*first revision*) — This standard applies to the basic safety and essential performance of CT scanners. The scope of this revision is limited to CT scanners intended to be used for both head and body characterized by an enclosure of the X-ray source(s) and imaging detector(s) in a common protective cover in the shape of a toroid. It includes safety requirements for the X-ray generators used in CT scanners, including those where high-voltage generators are integrated with an X-ray tube assembly.

IS 13450(Part 2/Sec 45) : 2016/IEC 60601-2-45 : 2011 - Medical electrical equipment — Part 2 - Section 45 : Particular requirements for the basic safety and essential performance of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic (*first revision*) — This standard applies to the basic safety and essential performance of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic devices. This standard addresses the system level of mammographic X-ray equipment, which consists of a combination of an X-ray generator, associated equipment and accessories. The minimum safety requirements specified in this particular standard are considered to provide for a practical degree of safety in the operation of mammographic X-ray equipment.

IS 15298-2:2016/ ISO 20345:2011 - Personal protective equipment: Part 2 Safety footwear (*second revision*) — This standard specifies basic and additional (optional) requirements for safety footwear used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks, ergonomic behaviour. Special risks are covered by complementary job-related standards (e.g. footwear for firefighters, electrical insulating footwear, protection against chain saw injuries, protection against chemicals and molten metal splash, protection for motor cycle riders). This standard prescribes the terms and definitions, designs, requirements and methods of test related to safety footwear.

SEMINARS/ CONFERENCES ORGANIZED:

To promote adoption and implementation of Indian Standards, BIS organizes seminars/workshops in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions, etc, to participate. During the year, BIS organized various seminars/ workshops and also participated in conferences with a view to disseminate information about the Indian Standards and to get feedback for further improvement/updating of standard as well as to identify new areas of standardization. Important seminars/ workshops organized during this year are as under:

Seminar on 'Municipal Solid Waste Compost, Manure Grade' – The seminar was organized on 13 February 2017 at Jaipur. During the Seminar, it was highlighted that Government is likely to implement the Indian Standard for converting city garbage in to city compost which can be useful for

agriculture. Importance of conversion of municipal solid waste into compost for agricultural use so as to overcome the environmental hazards of landfill of municipal wastes and for proper regeneration of soil for agriculture was emphasized. This would not only help to reduce environment hazards but also improve agricultural productivity and reduce dependence on use of fertilizers. The pros and cons of various methods of composting and the significance of each of the requirements specified in the Indian Standards were explained. A talk on Waste to Wealth for Sustainable Crop production was also delivered.

National Seminar on 'Innovations in Steel and latest trends in SteelMaking' — The Seminar was organized on 7 March 2017 at New Delhi. The objective of the seminar was to create awareness about latest developments in steel and new processes being used in steel making, nationally as well as globally. The seminar was attended by over 50 participants, representing various stakeholders.



Seminar on Overview of National Building Code of India 2016 and Insights to Fire and Life Safety held on 30 March 2017

National Seminar on 'Importance of Hill Area Development Engineering and Rock Mechanics' — A Seminar was organized jointly with the Indian Institute of Technology Roorkee and Indian Geotechnical Society - Roorkee chapter on 20 March 2017 at Roorkee. The presentations made and deliberations held during the Seminar emphasized on sound engineering practices in hilly terrain for their sustainable development, with special importance given to stability of slopes and landslide control measures.

Seminar on 'Overview of National Building Code of India 2016 and Insights to Fire and Life Safety' — A Seminar was organized on the recently revised National Building Code of India 2016, jointly with the Institution of Engineers (India) and Fire and Security Association of India on 30 March 2017. The presentation included an overview of the revised Code, its salient features, important modifications in all the existing chapters of the Code, new chapters added along with their features, and possible methodologies for large scale implementation of the Code throughout the country.



Seminar on Overview of National Building Code of India 2016 and Insights to Fire and Life Safety held on 30 March 2017

Seminar on 'Bicycle and its components – Standardization' — A Seminar was organized on 27 March 2017 at Ludhiana, to create awareness among the industry about the standards formulated by the Bicycle Sectional Committee, TED 16 in the field of bicycle and its components and create awareness among the industry about the work done at international level. The seminar was attended by over 75 participants from various stakeholders including bicycle manufacturers and components manufacturers.



Seminar on 'Bicycle and its components – Standardization' held on 27 March 2017 at Ludhiana

Seminar on 'IT Security' — The Seminar provided a unique platform for exchange information on the issue of data protection and privacy and standardization in this area in India and Germany. BIS presented the approach adopted and progress made in its concerned committee, LITD 17, 'Information System Security and Biometrics'. The German side presented the regulations and standards available in Germany and at European level. A presentation on the directive on Security of Network & Information

System (NIS Directive) adopted by European Parliament was made, clearing several doubts about its implementation and compliance.

Workshop on 'Use Cases for smart Grids' — Various experts from DKE, Germany gave presentation on application of Use Case method in standardization and Case demonstration in the field of Smart Grids.

21st International Conference on 'Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering (Hydro 2016)' — The conference was organized by CWPRS, Pune in association with The Indian Society for Hydraulics (ISH) and cosponsored by BIS, during 8-10 December 2016. Papers were presented on topics such as, water resources and hydrology, hydrometeorology, computer applications in fluid mechanics, environmental and climate change, coastal engineering, reservoirs and appurtenant structures, hydro instrumentation, and ground water.

Seminar on 'Water Conductor System for River Valley Projects' — A seminar was organized on 17 March 2017 at Kolkata. The seminar was attended by delegates from different organizations and institutions, namely Central Water Commission; WAPCOS Limited; Brahmaputra Board; Water Resources Department, West Bengal; Water Resources Department, MP; Water Resources Department, Jharkhand; Himachal Pradesh Power Corporation Limited; Farakka Barrage Project; Damodar Valley Corporation; IIEST, Shibpur; School of Water Resources Engineering, Jadavpur University.



Seminar on Water Conductor System for River Valley Projects held on 17 March 2017 at Kolkata

Awareness Workshop on 'EU Regulatory Framework in Technical Textile' — Within the framework of Indo-German Working Group on Quality Infrastructure for Co-operation in Standardization, Conformity Assessment and Product Safety, a one day "Awareness Workshop on EU Regulatory Framework in Technical Textiles" was held on 5 October 2016 in Mumbai. This workshop was jointly organized by BIS and GIZ, Germany. During the seminar, deliberations took place on the best practices and instruments that could evolve between India and Germany for taking this initiative forward in the field of standards, capacity development of Indian stakeholders for the technical know-how, implementation of standards, and mutual recognition of test results to promote trade.

Curtain Raiser of Technotex 2017 'Theme: Advantage India: Emerging global manufacturing hub for Technical textiles — A curtain raiser of TECHNOTEX-2017, India's premier show on technical

textiles, was held on 17 January 2017 at New Delhi. Five Indian Standards of National Importance on Jute Geotextiles, Packtech and Non-woven test methods were released by Shrimati Smriti Zubin Irani, Hon'ble Union Minister of Textiles, Government of India at the ceremony. The release of the these five Indian Standards marks a vital step towards the Bureau of Indian Standards efforts of standardization in the field of technical textiles towards the objectives of health, safety, water conservation and improving rural infrastructure in India.



TECHNOTEX-2017 was held on 17 January 2017 at New Delhi

Seminar on Promoting Culture and Heritage of Khadi and Handloom — Role of Indian Standards – The seminar was organized on 21 February 2017. Around 80 delegates from Khadi and Handloom Institutions, Artisan, regulatory bodies, testing laboratories, Government and important users attended the above seminar. After an exhaustive question and answer session, it was recommended that BIS along with khadi and handloom industry should hold a series of interactive workshops and seminars throughout the country to educate the users about the technological and economic benefits of using Indian standards. The khadi and handloom industry also showed interest in BIS certification schemes for promoting their products.

Seminar on Standardization in the field of General Engineering and Fasteners – The Seminar on the subject was organized by BIS at Automotive Research Association of India (ARAI), Pune on 25 July 2016. The seminar was attended by stakeholders, Committee members and interested invitees from General Engineering and Fasteners and related industries.The participants were apprised about the standardization processes and procedures of BIS, the regulations being followed by ARAI and automotive industries, the latest developments in the field of fasteners and of the important of change in design of vehicles and engines in order to use alternate fuels and reduce air pollution.

Seminar on Energy Efficiency through Standardized Pumps – The Seminar was organized on 30 September 2016 at Amritsar. The objectives of the Seminar were to disseminate information on published and under formulation Indian Standards on pumps to assess the requirements of the industry and other stakeholders regarding formulation/update of the Indian Standards, create awareness amongst stakeholders for use of ISI marked pumps so as to save energy and improve efficiency.



Seminar on Energy Efficiency through Standardized Pumps held on 30 September 2016 at Amritsar

Seminar on Physical Security Products in Banks (PSP) & Other Institution – The Seminar was organized on 9 March 2017 at Mumbai, to disseminate information on published and under formulation Indian Standards on security equipment for banks and other financial institutions.

Seminar on Use case methodology on Low Voltage Direct Current (LVDC) and Smart Grid – The Seminar was organized on 15 February 2017 at New Delhi. The seminar was attended by approximately 25 delegates. During the seminar, BIS shared information on its draft standard for 48 V LVDC distribution systems. Experts from India and Germany shared information on LVDC and Smart Grid through different use cases.



Seminar on use case methodology on LVDC and Smart Grid was held on 15 February 2017 at New Delhi

Webinar on LVDC — A webinar on LVDC was organized on 21 February 2017 at New Delhi. The Webinar was attended by more than 20 delegates. The webinar focused on familiarizing the Committee members with the latest developments in the field of LVDC standardization at IEC level.

Seminar on Good Governance in Corporate Social Responsibility (CSR) — The Seminar was organized by BIS on 24 March 2017 in order to bring all concerned stakeholders under a common platform aiming to formulate Standard on Corporate Social Responsibility, so as to contribute towards sustainable development. The seminar focused on various facets of CSR primarily on various Management and Implementation issues relating to CSR, which shall further enable in framing a Good Guidance Standard on CSR appropriate to the Indian context.



Seminar on Good Governance in Corporate Social Responsibility held on 24 March 2017

Seminar on Standardization in the field of Sports Goods – A Seminar was organized on 29 June 2016 at Meerut to identify the gaps in Indian standards with that of International standards (wherever available) and to understand the standardization needs of the users.

National Symposium on Ushering Digital Health Informatics in India — A Symposium was organized on 11 January 2017, during which, detailed presentations were made on National Digital Health Authority and its vision for India, importance of standards for digital health informatics, achievements and challenges in digitalization of Health Informatics in India, ISO/TC-215 Health Informatics standards adopted by BIS, etc.



National Symposium on Ushering Digital Health Informatics in India held on 11 January 2017

Seminar on 'Standardization in Dentistry' — A Seminar was organized on 15 March 2017, in association with the Department of Dental and Oral Surgery, Lady Hardinge Medical College. During the seminar, detailed presentations were made and discussions were held on subjects like Standardizing Mercury free Dental practice, role of ISO Standards, formulation of Indian Standards in Dentistry and its implementation, and Infection prevention in Dental practice.



Seminar on 'Standardization in Dentistry' was held on 15 March 2017

PUBLICATION OF STANDARDS

BIS through its Publication Department handles the electronic publishing of Indian Standards and amendments and the notification of published standards and amendments in the official Gazette of India. During the year, 302 new standards, 187 revised standards and 195 amendments were published.

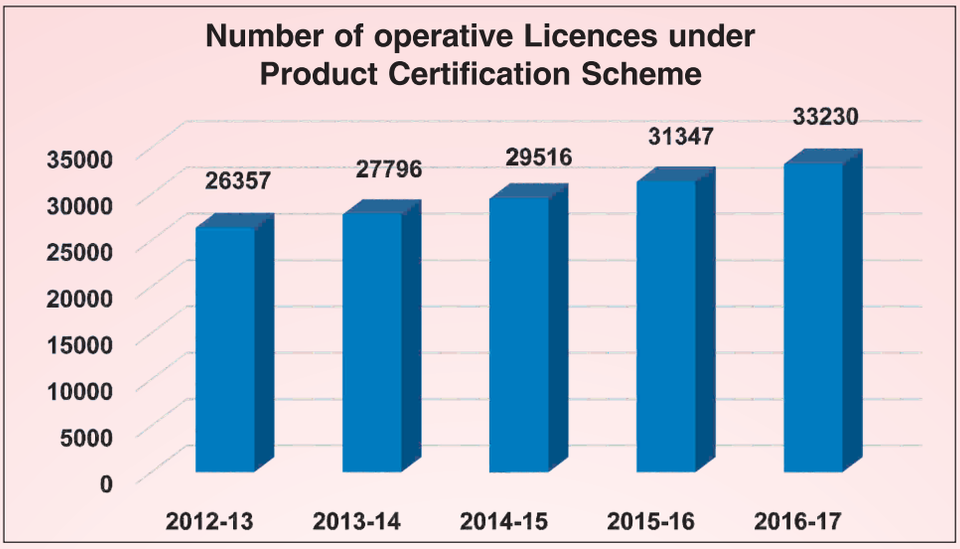
CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification Scheme under the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and the Rules and Regulations framed thereunder. Under this Certification scheme, a manufacturer of a particular product is given the selfmarking rights of the BIS Standards Mark (ISI mark) on his product after ensuring that his product complies with the relevant Indian Standard. Presence of Standard Mark (popularly known as ISI mark) on a product indicates its conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard. Samples drawn from the production line as well as from the market are tested in BIS laboratories/recognized independent laboratories to ascertain conformance of the product to the relevant Indian Standard. BIS also conducts surveillance visits at the licensees premises to ensure conformance of licensees' products to the relevant Indian Standard. The certification scheme is voluntary in nature, except for 109 product standards that have been made mandatory by the Central Government on considerations of health and safety of the consumer.

During the year, 4 098 new licences were granted, which include 17 products covered for the first time under the scheme. These products are IS 14252:2015 - High density polyethylene (HDPE) / polypropylene (PP) woven sacks for filling sand; IS 15322:2003 - Particle filters used in respiratory Protective Equipment; IS 10532 (Part 2):1983 - Fire-resistant Hydraulic fluids; Part 2 ; Invert Emulsion (Water-in-oil) type; IS 717:1998 - Carbon Disulphide, Technical; IS 16232:2014 - Iron Fortified salt (Double Fortified salt) – Food Grade; IS 11169 (Part 1):1984 - Steels For Cold Heading/Cold Extrusion Applications: Part 1 Wrought Carbon and Low Alloy Steels; IS 14855 (Part 1):2000 - Plant Protection And Vector Control Equipment - Fogging Machines: Part 1 Pulse-Jet-Type Thermal Fogging Machines; IS 1838(Part 3):2011 - Polymer based Preformed Fillers for Expansion Joints in Concrete Pavements and Structures (Non-Extruding and Resilient Type); IS 419:1967 - Putty for Use on Window frames; IS 3074:2013 - Steel Tubes For Automotive Purposes; IS 15997:2012 - Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet and Strip for Utensils and Kitchen Appliances; IS 14968:2015 - High Density Polyethylene (HDPE)/Polypropylene (PP) woven sacks for packaging 50 kg / 25 kg Sugar; IS 10065:1981 - Roasted Groundnut (Peanut) Kernels; IS 16415:2015 - Composite Cement; IS 13714:1993 - Dunnage pallets - Ware housing; IS 6909:1990 - Specification for super sulphated cement; IS 3181:1992 - Conveyor belts - Fire resistant conveyor belting for underground mines and such other hazardous applications.

The total number of Indian Standards which have been covered so far under BIS Certification Marks Scheme are 927. The total number of operative licences as on 31 March 2016 was 31 347 which increased to 33 230 by March 2017.



Surveillance

In order to monitor the operation of licences, during the year, a total number of 10 162 inspections and 8 256 lot inspections were carried out. In addition, about 21 384 samples (including samples procured from market) were drawn for independent testing.

Foreign Manufactures Certification Scheme (FMCS)

BIS has been operating separate Scheme for foreign manufacturers. Under this Scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for use of BIS Standard Mark on their product(s). During 2016-17, 190 licences were issued under FMCS, taking the total number of operative licences to 671 against 83 Indian Standards. The licences granted covered products such as Steel and Steel products; Cement; PVC Insulated Cables; Tyres and Tubes for Automotive Vehicles; Plastic Feeding Bottles; Switchgear products; Plugs and Socket-Outlets and Switches; HDPE and UPVC Pipes; Infant milk formula; ac Static Energy Meters, etc, from around 48 countries across the globe.

Compulsory Registration Scheme (CRS)

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), then known as Department of Electronics & Information Technology (DeitY), in consultation with BIS, notified 'Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012' on 3 October 2012 mandating Compulsory Registration from BIS for 15 Electronics and Information Technology products based on its safety compliance to Indian Standards. A second Order was notified on 13 November 2014, bringing 15 more electronics and Information Technology products under the ambit of the Scheme. The Compulsory Registration Scheme is being operated by BIS under the *BIS Act*, 1986 and the Rules, framed thereunder for this purpose.

The introduction of this Scheme is an alternative mechanism to the Compulsory Product Certification to facilitate growth of fast growing sectors like IT and to protect consumers from spurious and substandard imports and products manufactured in India.

The major products under the Scheme are:

– LED fixtures, lamps and drivers

– Mobile phones, portable power banks

- Rechargeable cells/batteries
- UPS and invertors of capacity 5 kVA and below
- Microwave ovens
- Plasma/LCD/LED TVs/Visual display units/monitors of screen size 32" and above
- Adapters for IT, AV and electronic products
- Point-of-sale terminals, ADP machine
- Laptop/notebook/tablet
- Printers and plotters, photocopiers, scanners
- Set top box

The first Registration was granted by BIS in June 2013. As on 31 March 2017, BIS has granted 8 316 registrations to manufacturers in various countries including domestic manufacturers.

LABORATORY SERVICES

In order to support the activities of the product certification marks scheme, BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples generated from Product Certification Scheme, beginning with the establishment of Central Laboratory at Sahibabad in 1962. Subsequently, four regional laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. BIS laboratories have facilities for testing of products in chemical, microbiological, electrical and mechanical discipline.

In order to ensure that BIS laboratories follow internationally accepted practices, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

BIS labs have complete test facilities for 376 Indian Standards and partial test facilities for 358 Indian Standards. During the year, the BIS laboratories tested 18 502 samples of various products covered under BIS Certification. In addition, the Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has issued 2 965 test reports during the year.

Creation/Up-gradation of Testing facilities

Under the modernization project many new testing facilities were created or existing facilities were upgraded in the BIS laboratories. These include Packaged Drinking Water (PDW)container testing facility at Western Regional Office Laboratory (WROL), Guwahati Branch Office Laboratory (GBOL), and Patna Branch Office Laboratory (PBOL), plywood testing facility at Patna Branch Office Laboratory, Guwahati Branch Office Laboratory and testing facility for LED lamps at Bangalore Branch Office Laboratory.

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is a regular part of testing in BIS Labs by way of which the quality of testing is assured. During the year, 854 Samples were tested under Quality Assurance activities by BIS Labs. This includes the samples tested during participation in proficiency testing/ inter-lab comparison program.

Training

a) The manpower working in labs are being trained on regular basis to keep them abreast of the latest developments. During the year, 34 officials were trained for IS/ISO/IEC 17025 Laboratory Quality Management System.

b) During 2016-17, BIS labs organized 18 training programmes for the industry.

Lab Recognition Scheme

As the volume of work for testing of samples generated from product certification scheme is much larger than the available facilities and capacity in BIS labs, BIS has established Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories (OSLs). The services of such laboratories are utilized when it is economically not viable to develop test facilities in BIS labs or when BIS labs are overloaded. The scheme is based on International Standard IS/ISO/IEC 17025:2005, and in line

with the criteria adopted by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) for accreditation of laboratories. OSLs recognized by BIS are required to fulfil following prerequisites:

- The lab shall be accredited by NABL in the respective field
- The lab shall have complete testing facilities as per relevant Indian Standard
- The lab shall have competence to test the products as per Indian Standard

During 2016-17, 25 new labs were recognized and 6 labs were de-recognized. As on 31 March 2017, the total number of operative BIS recognized labs were 179, which included reputed R&D organizations, technical institutions, Government labs and Private sector labs. Besides this, services of 47 Government laboratories of specialized nature are utilized for different products, as and when required.

To support the newly launched BIS Compulsory Registration Scheme, 33 outside labs are testing IT products, which were covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012 of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

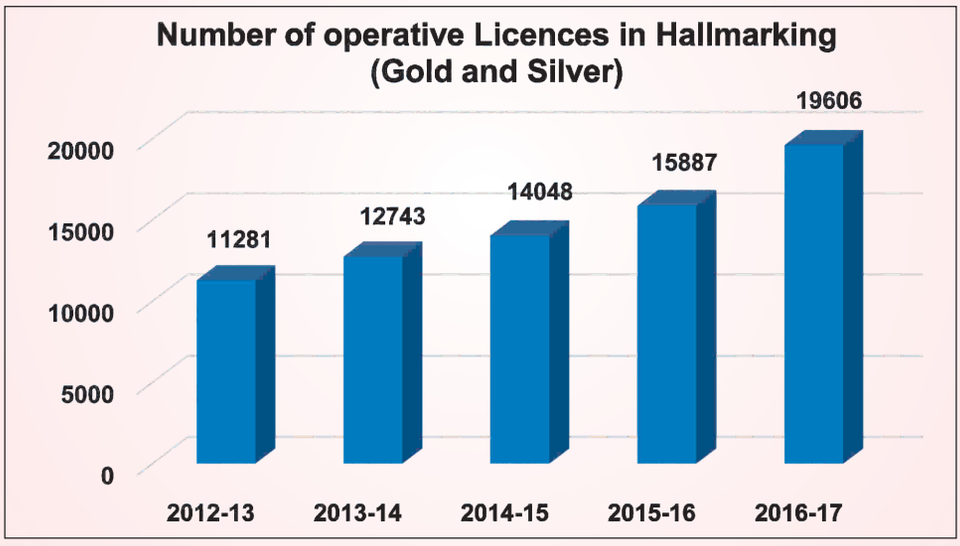
HALLMARKING

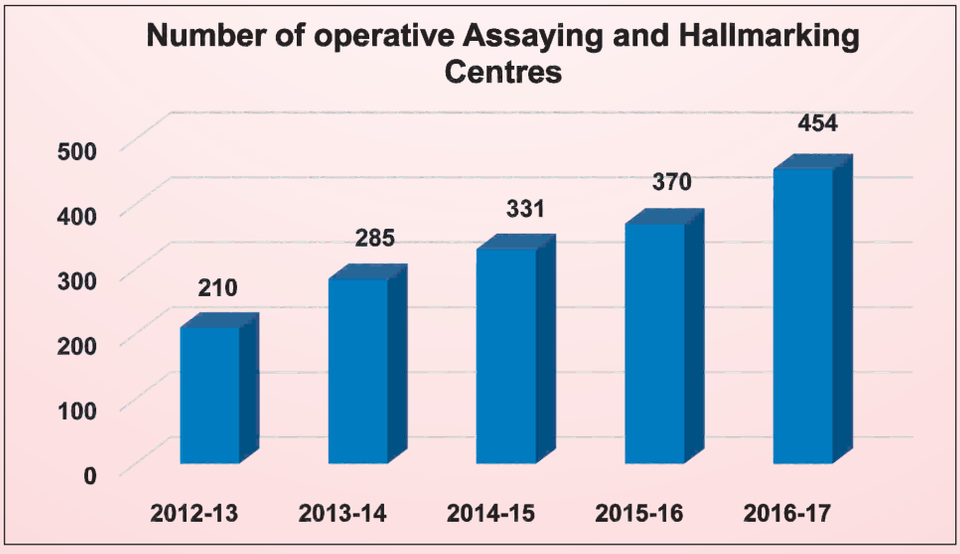
HALLMARKING SCHEME OF GOLD AND SILVER

(i) Hallmarking of Gold/Silver Jewellery/Artefact

Hallmarking of gold jewellery was launched by BIS in April 2000 to provide third party assurance to consumers on the purity of gold jewellery or its fineness. The scheme for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts was launched in October 2005. Under these Scheme, while the jewellers are granted licence to sell hallmarked jewellery, Assaying & Hallmarking (A&H) centres are recognized to assay the purity of the jewellery submitted by the licensed jeweller, along with declaration of purity. The A&H centres apply hallmark on such jewellery which is found conforming to relevant Indian Standard including of declared fineness.

As on 31 March 2017, the number of operative licences for Hallmarking of gold and silver jewellery were 18 112 and 1 494, respectively. The number of operative BIS recognized A&H centres was 454. During the year, 3.16 crore articles of gold and silver jewellery/ artefacts were hallmarked.





(ii) Hallmark of Gold Bullion/Coin

Hallmarking of gold Bullion/Coin in the fineness of 999 & 995 by giving licence torefineries/Mint was started in October 2015. During 2016-17, two licences have been granted to the refineries for the hallmarking of gold Bullions/Coins. As on 31 March 2017, 10 licences have been granted to refineries/ India Government Mint for Gold bullion and coin.

(iii) Gold Monetization Scheme

Government of India has launched Gold Monetization Scheme on 5 November 2015. BIS has played an important role in finalization and implementation of the Gold Monetization Scheme in association with Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Reserve Bank of India. Under the scheme A&H Centres recognized by BIS have been qualified to act as Collection and Purity Testing Centres (CPTC). So far 48 A&H centres and one Jeweller have been qualified to act as CPTC. The gold collected by CPTCs is to be refined by refineries licenced by BIS.

(iv) Implementation of Revised Indian Standard IS 1417:2016 on Gold Hallmarking

The Indian Standard on Gold Hallmarking was revised in November 2016 and has been implemented with effect from 1 January 2017. The Hallmarked Gold jewellery will now be available in three grades of 14 Carat, 18 Carat and 22 Carat only instead of 10 grades earlier keeping in view the interest of the consumer as well as to avoid confusion in their mind. The caratage will also be marked on jewellery in addition to fineness for convenience of consumers, for example for 22 carat jewellery, 22K will be marked in addition to 916 (22K916). With effect from 1 January 2017, Hallmark will have following marks:

BIS Mark	Purity in carat and fineness (for example 22K916)	Assay centre's identification mark / number	Jewellers identification

(V) Promotion of Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in purchase of gold jewellery, awareness programmes for jewellers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. During 2016-17, 53 such jewellers' awareness programmes were organized.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Management Systems Certification services and there has been a steady growth.

i) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991. The Scheme is being operated in accordance with ISO/IEC 17021-1:2015 'Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1 Requirements'. A total of 867 QMS licences are in operation, covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, and service sectors such as financial, health, insurance, information technology, telecommunications, transport, etc.

ii) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001

The Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001 is being operated as per the International criteria laid down in ISO/IEC 17021-1:2015. A total of 203 licences are in operation covering technology areas like integrated steel plants, cement plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power, wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining, public administration, etc.

iii) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007

BIS is operating Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007. This essentially enables an organization to define, plan and manage policies and objectives, taking into account the legislative requirements and the information about significant hazards and risks, which the organization can control. A total of 102 OHSMS licences are in operation covering technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power stations, health services and employee development centres, textiles, plastics, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railways, etc.

iv) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000:1998

BIS is also offering a stand-alone HACCP Certification Scheme as per IS 15000:1998. As on 31 March 2017, two HACCP stand-alone licences and 35 licences integrated with QMS were in operation.

v) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005

BIS is operating Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000. This system is

designed to allow all types of organization within the food chain to implement a food safety management system. As on 31 March 2017, 14 FSMS licences were in operation.

vi) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700:2005

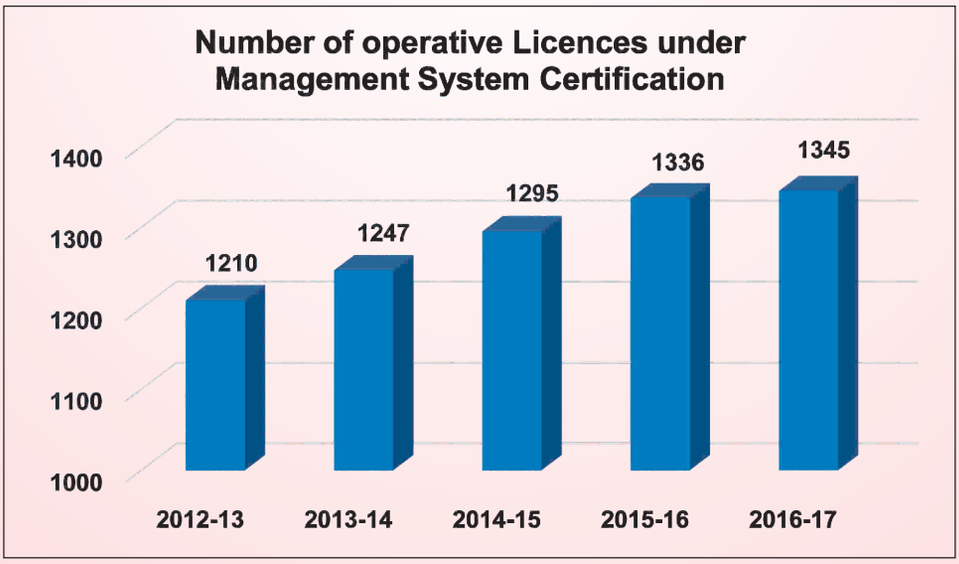
The Service Quality Management System (SQMS) Certification was launched by BIS in April 2007, based on the Indian Standard IS 15700. This standard focuses on delivery of quality service across the counter by public service organizations. These licences are granted to public service delivery organizations implementing this standard. A total of 101 licences were operative as on 31 March 2017.

vii) Energy Management System (EnMS) Certification Scheme as per IS/ISO 50001:2011

BIS launched the Energy Management Systems Certification Scheme as per IS/ISO 50001:2011 in 2013. Implementation of this scheme essentially enables an organization to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization, thereby minimizing energy costs and mitigating environmental effects. As on 31 March 2017, 20 EnMS licences were in operation.

viii) Medical Devices Management System (MDMS) Certification Scheme as per IS/ISO 13485:2003

Medical Devices Management System has been launched by BIS in June 2016. One licence has been granted for this system Efforts are being made to promote implementation of the standard so that the manufacturers of medical devices can take the advantage of the system in marketing their products.



ix) Accreditation of QMS and EMS

The Quality Management Systems Certification and the Environmental Management Systems Certification Schemes of BIS are accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Quality Council of India for a number of sectors.

x) Promotion of Management Systems Certification

BIS has signed a MoU with Maruti Centre of Excellence (MACE) on 18 May 2016, for promotion of quality of products supplied by the vendors of Maruti Udyog Ltd., through implementation of Quality Management Systems.

xi) Auditors' Meet

Auditors' Meets, one each in the Eastern, Southern and Western Regional Offices of BIS was organized. The auditors' meets were attended by external auditors and those BIS officers who are registered for carrying out systems certification audits.

INTERNATIONAL ACTIVITIES AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES

A. INTERNATIONAL ACTIVITIES

Participation in International Standardization Activities

- BIS in its capacity as the National Standards Body of India, is a member of International Organization for Standardization (ISO) and through the Indian National Committee a member of International Electrotechnical Commission (IEC). BIS actively participates in the activities of these International bodies and is involved in development of International Standards as Participating (P) member or Observer (O) member on various Technical Committees and Subcommittees; and nominates technical experts in Working Groups of these bodies.

  As on 31 March 2017, BIS is a 'P' member in 433 Technical Committees/ Subcommittees of ISO and 86 Technical Committees/Subcommittees of IEC, and 'O' Member in 219 Technical Committees/Subcommittees of ISO and 72 Technical Committees/ Subcommittees of IEC. The Secretariat of 8 important ISO Committees dealing with subjects that are of interest to India are being held by India through BIS.

- At present, BIS holds the Convenorship of 16 ISO Working Groups, out of which the convenorship of two Working Groups namely ISO/IEC JTC 1/SC 40/SG 4 on 'Management System Standard (MSS) of business process outsourcing' and ISO/TC 71/SC 1/WG 5 regarding testing of concrete were taken over by BIS during 2016-17. Similarly, India holds the convenorship of 5 Working Groups/ Task Groups/ Management Team of IEC.

- BIS also participates in various policy-making committees of ISO and IEC. India(BIS) is a member in Standards Management Board (SMB) of IEC for the term 2015-2017 and has been elected as member of the ISO Council for the term 2017-2019. BIS also has 'P' membership in three Policy Development Committees of ISO Committee on conformity assessment (CASCO), Committee on consumer policy (COPOLCO) and Committee on developing country matters (DEVCO).

- Members of technical committees of BIS and officers of BIS participated in various ISO/IEC Technical Committees and contributed effectively in the development of various International Standards especially related to environment management, nanotechnology, IT security techniques, rubber, etc. India is leading various ISO projects related to food and agriculture, nanotechnology, external corrosion protection system, rubber products and its test methods, rubber flaps for automotive vehicles, hydrometry, identification of natural dyes, etc. During this period, India also proposed new work items related to nanotechnology, concrete aggregates and online privacy notices and consent. Indian experts have also been taking leadership roles in various working groups for driving the international standardization work in the areas, where India has specific interest.

- BIS officers participated in a total of 24 delegations to various technical committee meetings of ISO/IEC.

Participation in ISO/IEC meetings and Other Related Events

- BIS organized meetings of ISO/TC 85 'Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection', its subcommittees and working groups during 4 to 8 April 2016 at New Delhi. ISO/TC 85 is involved in the development of ISO standards in the field of peaceful applications of nuclear energy, nuclear technologies and in the field of the protection of individuals and the environment against all sources of ionising radiations.
- The IEC General Secretary and CEO, Mr. Frans Vreeswijk visited BIS on 25 April 2016 to interact with the Indian Industry and BIS on the next IEC Master Plan.
- The ISO Acting Secretary General, Mr. Kevin McKinley visited BIS on 28 April 2016 to update India stakeholders involved in standardization activity on the implementation of the ISO Strategic Plan 2016-20, ISO Action Plan for developing countries 2016-20 and the operation of ISO Regional Office at Singapore.
- BIS launched its Young Professionals Programme through a workshop held on 21 July 2016 at New Delhi with the objective to help Young professionals from the electrotechnical industry to appreciate the importance of standards. This was followed by the Second Young Professionals Programme held on 17 February 2017 at Mumbai. In the above workshops, Mr. Dennis Chew, Regional Director, International Electrotechnical Commision (IEC), Asia Pacific Regional Centre, participated as the speaker on International Standardisation in the field of Electrotechnical Sector.
- A three member delegation led by DG, BIS attended the ISO General Assembly (GA) and related meetings at Beijing, China during 11-14 September 2016. On the sidelines, meetings were held with National Standards Bodies of Belarus, European Union, France, Iran, Korea, United Kingdom and USA for bilateral co-operation with them.
- A three member delegation led by DG, BIS participated in the IEC GM 2016 from 11 to 14 October 2016 at Frankfurt, Germany. Apart from IEC meetings, sideline meetings with French National Committee of IEC and Association for Electrical, Electronics and Technologies (VDE), Germany were held with a view to enhance bilateral cooperation in the fields of standards and conformity assessment.
- India actively participated in the activities of IEC System Evaluation Group 4 on Low Voltage Direct Current (LVDC). The Indian nominee has also been appointed the Convenor of the recently formed Systems Committee on LVDC and Electricity Access.
- BIS organized a Training programme for Convenors and Chairs of ISO/IEC technical committees on their roles and responsibilitiesand on handling of committees during 19-20 January 2017 at NITS, Noida.
- BIS organized meeting of ISO/TC 34/SC 7 'Spices, Culinary Herbs and Condiments' during 24-25 January 2017 at Kochi in collaboration with Spices Board of India, Kochi. India is the biggest producer and exporter of spices in the world and holds Secretariat of ISO/TC 34/SC 7.

Participation in Regional Standardization Activities

- BIS has been playing an active role in the work of Pacific Area Standards Congress (PASC). An Indian delegation led by DG, BIS attended the 39th PASC Meeting from 10-14 May 2016 in Bali,

Indonesia. An update on the activities related to standardization and conformity assessment being carried out by ISO, IEC, PASC countries and other eminent International Standard Organization were provided and future activities to be carried by PASC in line with PASC Strategic Plan 2016-20 were decided upon.

- BIS has been significantly contributing in the activities of the South Asian Regional Standards Organization (SARSO). India served as the Chair of Technical Management Board of SARSO from April 2014 to March 2017. India has been elected as Chair of SARSO Governing Board for a two years term starting from March 2017.

- Indian delegation participated in the meetings of SARSO Sectoral Technical Committee (STC) on 'Food and Agricultural Products' and 'Building Materials' held in May 2016 at Colombo, Sri Lanka.

- As a part of promotional activities of SARSO on Regional Harmonization in the fields of Standardization and Conformity Assessment in South Asia, BIS jointly with SARSO organized an Awareness Programme on Regional Standardization on 27 July 2016 at New Delhi.

- The Fourth Meeting of SARSO Technical Management Board (SARSO) and fifth meeting of SARSO Governing Board held on 27 February 2017 and 28 February to 1 March 2017, respectively at Dhaka, Bangladesh were chaired by India. The first three SAARC Standards (on biscuits, refined sugar and Code of hygienic practices) were approved in these meetings. The SARSO Directives were also finalized and approved in these meetings.

- Under the project, 'Capacity Building Initiative for Trade Development (EU–CITD)' of India-EU Cooperation steered by Ministry of Commerce of which BIS is one of the identified beneficiaries, a team of 5 BIS officers and one officer from Ministry of Commerce & Industry (MoCI) participated in a study visit from 30 January 2017 to 3 February 2017 to European Committee on Standardization (CEN), Brussels and British Standards Institution (BSI), London for understanding the best practices being followed by these organization in international standardization, regional standardization and IT related services.

Participation in Bilateral Co-operation Programmes

- BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as Germany, Bangladesh, Bhutan, Brazil, South Africa, Russia, Oman, Slovakia, Taiwan and, Kyrgyzstan in close association with the Ministry of Commerce and the Ministry of External Affairs. BIS has entered into MoUs and MRAs with the National Standards Bodies of various countries for cooperation in the areas of standards, Conformity assessment, testing and training/ capacity building and for mutual acceptance of each other's conformity assessment results respectively. BIS has so far signed 32 MoUs and 6 MRAs of which 7 MoUs and 1 MRA were concluded during 2016-17. The important activities carried out during April 2016 to March 2017 are as below:

  i) A Technical Cooperation Program (TCP) between BIS and Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), Saudi Arabia was signed on 3 April 2016 during the official visit of Hon'ble Prime Minister of India to Saudi Arabia on 2-3 April 2016.

  ii) A MoU between Bureau of Indian Standards (BIS) and Kenya Bureau of Standards (KEBS) was signed during the state visit of Hon'ble Prime Minister of India to Kenya on 11 July 2016.

iii) A MoU was signed between Bureau of Indian Standards and Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam (STAMEQ) on 3 September 2016 for cooperation in the field of standardization and Conformity assessment.

iv) A MoU between BIS and the Standards Organization of Nigeria was signed on 27 September 2016.

v) A MoU for cooperation between BIS and Direction Nationale De Industries, Mali in the field of standardization and conformity assessment was signed between Government of India & Government of Mali on 29 September 2016.

vi) A Mutual Recognition Agreement (MRA) was signed between BIS and ABNT, Brazil on 24 October 2016 for mutual acceptance of results of each other's conformity assessment, in order to facilitate the market access to the country of the Parties.

vii) The 7th Session of India-Greece Joint Economic Committee was held on 23 November 2016 in New Delhi during which in the bilateral discussions, the draft of the MoU between BIS and the Hellenic Organization for Standardization (NQIS/ELOT), Greece was finalized.

viii) A MoU was signed between BIS and the National Standardization Agency of Indonesia (BSN) on 12 December 2016 at New Delhi for cooperation in the field of standardization, technical information and capacity building during the visit of the President of Indonesia to India.

ix) BIS signed a MoU for the use of the content of EN 115:1995+A2:2004 Safety Rules for Construction (Conveyor) and installation of Escalators and Passenger for national adoption in India with the Regional Standard Body of European Union, that is CEN in March 2017.

- Indo-German Working Group Quality Infrastructure for cooperation in Standardization, Conformity Assessment and Product Safety:

i) Indo-German Working Group was established based on the joint declaration signed between the German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India on 11 April 2013. The objective of the Indo-German JWG is to advance bilateral economic and technical cooperation; intensifying dialogue on standardization, conformity assessment, and product safety for the benefit of consumers and industry; and to promote coordinated activities in the sphere of international standardization in order to facilitate bilateral trade. During the year 2016-17, various activities identified under the Work Plan for the year 2016 were carried out, covering cooperation in areas of Smart Grid, LVDC, Solid Waste Management, Product Safety, etc.

ii) The fourth meeting of the Indo-German Working Group on Quality Infrastructure for cooperation in Standardization, Conformity Assessment and Product Safety was held on 6-7 March 2017 at Berlin, Germany. The Indian delegation was led by Secretary, Department of Consumer Affairs. During the meeting, progress made by the Working Group during 2016 as well as the activities for 2017 in the areas of standardization, conformity assessment and accreditation, product safety and market surveillance were discussed. A Work Plan outlining the various activities for the next year was agreed upon which includes amongst

others, cooperation on Machinery Safety, Smart Grid, LVDC, Toys, Pressurized equipment, Automotives, Digital technologies and IT security.

B. TECHNICAL INFORMATION SERVICES & WTO-TBT ENQUIRY POINT

- BIS provides technical information services in the field of standards and conformity assessment to industry, importers, exporters and government agencies in response to their enquiries. 1 079 enquiries were responded during the period from April 2016 to March 2017.

WTO-TBT Enquiry Point and Trade Related Activities

- BIS continued its activities as the WTO/TBT Enquiry Point of India. BIS developed and made operational its TBT notification portal for hosting all WTO-TBT notifications on BIS website as well as disseminating the TBT Notifications to registered stakeholders through e-mail. The portal provides a common window to the stakeholders to receive updates on TBT notifications and submit comments thereon, online. The software is anticipated to facilitate collecting information on trade related challenges being faced by Indian exporters, so that the same can be taken up appropriately at WTO.

- BIS continued to prepare responses on Specific Trade Concerns (STCs) raised by other WTO members in TBT committee meetings on issues relevant to standards and conformity assessment procedures particularly with respect to Mandatory Certification of Tyres, Steels, Compulsory Registration Scheme and Foreign Manufacturers' Certification Scheme.

- BIS also participated in the meeting of EU-India TBT/SPS Joint Working Group held on 11 November 2016 in Brussels where various TBT/SPS related issues between India and EU were discussed.

- BIS participated in various meetings convened by the Department of Commerce for discussion and inputs on the chapter on 'Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)' under RCEP negotiations, a Free Trade Agreement negotiation among 16 countries - the 10 members of the ASEAN and their 6 best trading partners.

- BIS participated in the Seminars on Non-tariff measures (NTMs) and Services organized by Department of Commerce, Government of Indian at New Delhi on 11 April 2016 under the framework of BRICS cooperation. A presentation on 'Standardization in India' in the session on NTMs was made by BIS.

Sponsorship of Identification Numbers

- **Issuer Identification Number (IIN)**

  BIS facilitates issue of IINs as per ISO/IEC 7812 'Identification Cards - Identification of issuers' by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). The ISO/IEC 7812 specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/ or inter-industry interchange. During this period, BIS had taken up the application of M/s National Payment Cooperation of India (NPCI) (an autonomous body set up by the Reserve Bank of India as an Umbrella organization for retail payments in

India) for allotment of 3000 IINs under Card Scheme Block Holder, for enabling them to further the Government of India initiative of Digital India.

- **World Manufacturer Identifier (WMI) Number**

  In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA; BIS issues WMI Codes as per ISO 3780 : 2009 'Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (WMI) Code' to automobile manufacturers and exporters in India. 180 WMI Codes have been allotted to various vehicle manufacturers during 2016-17.

TRAINING SERVICES

National Institute of Training for Standardization (NITS) was set up under the aegis of BIS in 1995 to meet the growing needs and expectations of the industry for quality training in the fields of standardization, quality assurance, management systems, certification, laboratory testing, etc. NITS has also been organizing various International Training Programmes for the developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin and South America. The programmes are conducted by a team of well-experienced, qualified and trained faculty.

During year 2016-17, NITS conducted a number of training programmes for the Industry, International participants and BIS employees. There has been an increase in the number of programmes organized during the period as well as the number of persons trained *vis-à-vis* the number of programmes carried out and the number of persons trained in the previous years. The total number of programmes conducted during this period is 177. The number of personnel trained during 2016-17 for the industry was 2 355 which is about 13.5 percent more than the last year figures of 2 075.

I. International Training Programmes for Developing Countries

Three International training programmes were organized with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India during 2016-17. The number of participants trained were 98 which is 11 more than those in the previous year. The details of these programmes are as under:

a. The 13th International Training Programme on 'Management Systems', was organized during 29 August 2016 - 23 September 2016, attended by 32 participants from 13 developing countries.

b. The 49th International Training Programme on 'Standardization and Quality Assurance', organized during 17 October 2016 to 9 December 2016, was attended by 35 participants from 27 developing countries.



49th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance

c. The 7th International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems was conducted by NITS from 30 January to 17 February 2017. 31 participants from 24 developing countries participated in the 3 week training programme.



7th International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems

II. Training Programmes for Industry

During 2016-17, NITS organized 142 programmes for industry which is about 17 more than the corresponding number last year. This included programmes on Lead Auditor for ISO 9001, ISO 14001, IS 15700, Energy Management, Food Safety Management, transition training programmes to ISO 9001 : 2015 and ISO 14001 : 2015, Appreciation programmes on Food Safety Management systems as per ISO 22000, Service Quality Management System, Laboratory Quality Management System as per ISO 17025, Medical, Laboratory Quality Management System as per ISO 15189, Measurement Uncertainty, Inter Laboratory Comparison and Evaluation of Scores, Product Specific Testing for Packaged Drinking water, etc. The clientele include participants from prestigious organizations like, Ordinance Factories, Air India, IARI, NTPC, BHEL, Adani Power Ltd, NATRIP, AIIMS, Indian Railways, Nestle Ltd, Dabur Ltd, etc, to name a few.

In addition, programmes were conducted for consumer organizations, technical committee members, etc.

III. Training Programmes for BIS Employees

During 2016-17, several programmes were exclusively organized for BIS officials, which included the following:

i. Orientation training programme for Scientist - B (2016 Batch)

ii. Transition Training programme on QMS as per IS/ISO 9001:2015

iii. Induction training programme for newly appointed UDCs

iv. Training programme on self-declaration of conformity

v. Induction training for newly recruited Technical Assistants (Lab) and Senior Master Technicians

vi. Refresher course on product certification

vii. Training programme on Leave, TA and Medical Rules, GFR for Group B and C employees

viii. Training Programmes on Laboratory Quality Management System and Audits as per IS/ ISO 17025

ix. Training programme on IS 12

x. Training programme on RTI

xi. Induction training programme for newly recruited Junior Stenographers

xii. Training programme for SO/PS for LDCE exam

xiii. Training programme on preventive vigilance

xiv. Training programme on packaged drinking water

xv. Training Programme on PVC Insulated Cables as per IS 694:2010

xvi. Training for Trainers on Hallmarking for Group A Officers

About 32 training programmes were conducted during the period for BIS personnel in which around 715 employees have been trained in these programmes.

D. New Programmes developed by NITS

During the period, the following new programmes were developed:

- Emergency preparedness based on EMS and OHSMS
- Training program on Social Accountability as per IS 16001 : 2012

CONSUMER AFFAIRS

BIS endeavours to provide its services and the benefits of standardization and certification to all its stake holders in a focused manner. The Consumer Affairs department of BIS handles various consumer related activities which include redressal of public grievances, organizing various awareness programmes for the stakeholders of BIS and holding of World Standards Day.

i) Consumer Awareness Programmes:

For promoting the concept of standardization, certification and quality consciousness among consumers, awareness programmes were organized on a regular basis through the Regional and Branch Offices. During the year, 163 such programmes were organized across the country.

ii) Industry Awareness Programmes:

To propagate the concept of standardization, product certification, management systems certification and other BIS activities amongst Industries, 62 Industry awareness programmes were organized during the year. These programme consisted of lectures and discussion sessions. Standards relating to specific industrial sectors, depending on concentrations of industries in that area were also highlighted during these programmes.

iii) Educational Utilization of Standards Programmes:

BIS organizes Educational Utilization of Standards Programmes (EUS) for students and teachers of schools, colleges, etc, to inculcate the young minds with the concepts and benefits of standardization. The need for familiarizing the students of technical institutions with the principles and practices of standardization is being increasingly felt due to the importance of standardization in the industrial development of our country. During the year, BIS has organized 39 EUS Programmes.



Educational Utilization of Standards Programmes organized at Chennai on 23 Feb 2017

iv) World Standards Day:

BIS celebrated the World Standards Day on 14 October 2016 at New Delhi to pay tribute to the collaborative efforts of thousands of experts worldwide, who develop voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. The World Standards Day theme for the year 2016 was 'Standards Build Trust'. BIS on the occasion also organized a seminar on this theme. World Standards Day programmes were also held across the country by BIS Regional and Branch Offices.



World Standards Day celebration at New Delhi



World Standards Day celebration at Kolkata

v) Public Grievances:

BIS follows a well-established complaint redressal procedure. Consumers can lodge their grievances relating to BIS certified products through offline and online methods. Complaints are monitored regularly for redressal. During the year, 57 complaints were received and 91 complaints were redressed.

vi) Citizen Charter :

Citizen's Charter has been implemented and time lines are being monitored every month through Management Control Reports.

vii) Enforcement:

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a mark of quality. Consumers as well as the organized purchasers prefer ISI marked products. Some unscrupulous manufacturers try to deceive the consumers by producing and marketing products with ISI mark without obtaining license from BIS.

During 2016-17, BIS carried out 114 search and seizures all over the country on firms misusing ISI mark and such products were seized. Efforts were made for timely launching of prosecution against the offenders in the Court of law. BIS also issued press releases regarding the enforcement raids for giving wide publicity with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers misusing the ISI mark.

PUBLICITY

The publicity activity of BIS is aimed at creating awareness for various BIS activities among its target audience including the Industry and common Consumer, significantly relating to Standardization, Certification of goods and services and Hallmarking of Gold Jewellery. The publicity was done through print, electronic and outdoor media.

Aggressive publicity campaigns were taken up aiming at persuading consumers to buy ISI Marked goods and Hallmarked Gold Jewellery. Consumer were also informed about the mechanism regarding the redressal of complaints relating to BIS. BIS also participated in popular consumer and industrial fairs/exhibitions to disseminate information on the various activities of BIS. The specific details on publicity activities for the year 2016-17 are as follows:

ELECTRONIC

TV

- 15 days campaign on DD Bharti, DD News, DD Urdu, DD India and DD Kisan on ISI Mark in Hindi from 9 to 23 August 2016.
- Campaign on National News and Entertainment channels through DAVP from 26 October to 1 November 2017 (festival season).
- Telecast of Hallmark spots on DD National and DD News on 1 February 2017, union budget day (Co-powered by sponsorship).

RADIO

- Campaign of 30 days in Hindi and regional languages from 20 July 2016 on ISI Mark and Hallmark.
- Broadcast of Audio spots on Hallmark on AIR during broadcast of popular serial 'Mahabharat' for 10 episodes from 13 to 23 January 2017.

OUTDOOR

- Publicity at Patna airport for 30 days from 20 April to 19 May 2016 on ISI Mark.
- Publicity at Bhopal airport from 4 May 2016 for 30 days on Hallmark and ISI Mark.
- Publicity through DAVP on various outdoor media for 30 days from 1 to 30 October 2016.
- Campaign from 17 February 2017 for 30 days on ISI and Hallmark on all India basis on various media like hoarding, utilities, trains, metro, trams, railway stations, airports, etc.
- 4 mega hoardings at 'Suraj kund Mela' from 1 to 15 February 2017.
- Campaign on BEST buses, bus back panels, airport hoardings, audio announcement on bus stands for 30 days from 1 March 2017 for ISI mark and Hallmark.

PRINT

- A month long campaign on 'Registration scheme of BIS' from 2 May 2016.
- Advertisement on the occasion of 'Akshay Tritiya' published on 9 May 2016 on Hallmark.
- An advertisement was published on Independence Day in August in Hindi and Regional languages on all India basis.
- One advertisement on World Standards Day, 14 October 2016 in Hindi, English and Regional languages on all India basis.

BIS MEDIA COVERAGE

- To promote and popularize BIS activities, interviews of senior officials of BIS were organized during the year on radio and TV.
- Specialized news stories related to BIS certified products and various activities of BIS including Hallmark, Helmet, National Building Code of India, etc. appeared in various newspapers and TV channels during the year.

  31 press notes relating to various BIS activities were issued and published in print media.

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

BIS sells Indian Standards and Special Publications through 25 different sales outlets located at the Headquarters (HQs), Regional Offices and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. BIS also sells foreign standards (ISO, IEC, BSI London, DIN Germany, JIS Japan) in India. BIS also sells Indian Standards through e-portal. Standards can be downloaded in the form of soft copy. Alternatively, an order for hard copy can be placed through the e-portal. Online payment can be made over the portal through credit/debit card. Customers can also make payment for standards through NEFT/RTGS.

Indian Standards are also available as a complete set on DVD or 14 different department/ sector specific sets like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, textiles, etc. on subscription basis. In addition, Indian Standards were also made available through online subscription from 1 July 2016.

During 2016-17, BIS has now made available Indian Standards on DVD/online subscription basis to educational institutions, scientific and research laboratories, Central and State Government Laboratories/ Research Institution operating through a consortia.

For the ease of customers, a touch screen kiosk, connected to BIS e-portal (www.standardsbis.in), is provided at the Sales Department of BIS HQs. The customer can search the standard of their requirement, see the price of standards, scope, amendments, etc.

HINDI ACTIVITIES

Bureau of Indian Standards is following all the act, rules, directions and orders issued by the Department of Official Language regarding official language. Accordingly, following work related to progressive use of Hindi have been done.

Implementation of Hindi – Annual Programme of Official Language Department was circulated to all the departments of BIS. Official Language Committee of HQ conducted all its four quarterly meetings on time. All the four quarterly reports of Hindi were also sent in time to the Ministry. 21 Hindi workshops were organized in different offices of Bureau in which 350 officers and employees were trained. Bureau also continued to carry out all incentive schemes of Government such as Cash Incentive Scheme on Hindi Noting and Drafting, Hindi Dictation Scheme, Hindi Incentive Allowance Scheme, Rajbhasha Shield Scheme, etc. All the items of annual programme issued by the Official Language Department were followed to achieve the targets regarding use of Hindi. In order to meet the targets, 24 inspections regarding progressive use of Hindi were carried out during the year in different regional and branch offices of Bureau, which also included inspection of 12 technical departments of Headquarter.

Celebration of Hindi fortnight - Hindi fortnight was celebrated from 1 to 14 September 2016 at HQ in which six competitions related to Hindi were organized. 27 Prizes were awarded by DG, BIS to the successful participants in these competitions in a function held on 16 September 2016.



Hindi fortnight celebrated at New Delhi

Hindi Training – In compliance with Hindi training targets fixed by Department of Official language compulsory training was provided to employees under which 4 officials were provided Hindi language training. Similarly, in Hindi Stenography and typing, training was provided to 12 stenographers and 28 LDCs, respectively.

Inspection of Official Language Parliamentary Committee and Other Meetings — During the period, the Second Sub-Committee of Committee of Parliament on Official Language inspected Headquarter on 18 February 2017. The Committee expressed satisfaction over the progressive use of Hindi in BIS. The DG of BIS took part in meetings of Hindi Advisory Committee of Ministry held in Chairmanship of Honorary Minister of Consumer Affair, Food & Civil Supply at Shilong on 3 October 2016. Follow up actions were taken on the decisions taken in the meeting.

Standard and General Translation – In order to accelerate translation works of Indian Standards, BIS took a number of steps. During the year, 53 standards were translated and titles of 540 standards were also made bilingual.

Besides standards translation, BIS also translated approximately 800 pages of different types of work such as Proformas, Annual Report, material on Hallmarking, World Standards Day material, Tender Notices, Parliament Questions, brochure of revised Nation Building Code, Gazette Notifications, training material, Agenda and Minutes of Bureau meeting, etc.

PLAN SCHEMES

Hallmarking

BIS has been implementing the Plan scheme for setting up of gold Assaying and Hallmarking (A&H) centres in India with central assistance.The scheme on Hallmarking, operative since the Xth Plan has continued in the XIIth Plan. The components of the scheme are indicated below:

a) Infrastructure building — Setting up of Assaying and Hallmarking (A&H) Centres

b) Capacity building:

   i) Training of artisans

   ii) Training of Trainers (BIS auditors)

   iii) Training of personnel of assaying and hallmarking Centres

Under this scheme Central Assistance for creating infrastructure is provided in two instalments. During the year, 1st instalment to 5 centres, and 2nd instalment to 12 centres were provided as central assistance. With this the total number of such centrally assisted A&H centres increased to 78 since the start of the scheme.

During 2016-17, BIS received ₹ 117.8 lakhs and ₹ 32.2 lakhs carry-over of pervious year (total amount 150 lakhs) under this scheme and spent ₹ 147 lakhs. Sixteen artisan training programmes, six A&H personnel training programmes and three Training of Trainers programme were conducted.

National System for Standardization:

The scheme on National System of Standardization (NSS) which commenced during the XIth Plan has continued to operate in the XIIth Plan with the components as indicated below:

i) Research & Development projects for establishment/revision of Indian Standards.

ii) Intensifying participation of BIS Technical Committee Members in Technical Committee Meetings.

iii) Seminars/ Workshops and Training.

iv) Intensifying participation of BIS officials, Technical Committee Members, other officials and experts in International Standardization by participation in International/ Regional/ Bilateral meetings/ Trainings.

v) Organizing ISO/IEC and other International/ Regional/ SAARC Multilateral/ Bilateral Meetings/ Workshops/ Trainings in India.

During the year, BIS has spent about ₹ 164.53 lakhs and no grant received for NSS activities.

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

In line with the Government's initiatives for computerization and to make day to day functioning of BIS online, Information Technology (IT) is being enabled as a strategic resource for development and continual improvement of systems. The overall objective is to improve services by increasing efficiency, transparency and ensuring reliability and timely delivery to BIS stakeholders. To this end, the progress made during the year is given below.

IT Infrastructure

A Unified Threat Management (UTM) device has been installed at BIS-HQ to streamline the management of network and internet bandwidth in BIS. Leased lines of 2 Mbps bandwidth were commissioned in Branch Offices at Raipur, Kochi and Training Institute at Noida. Also, sustained efforts have been made for enhancement of bandwidth in our remaining offices at Durgapur, Jamshedpur and Jammu.

Integrated BIS web portal

An integrated web portal is being developed to automate the major activities of BIS. The work has been entrusted to Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), Noida, an organization functioning under Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY). The development of the portal (http://manakonline.in) is underway in phases in coordination with CDAC and respective user departments.

Development of phase one modules involving development of module for product certification, integration of Laboratory processes with certification, payment gateway, user dashboards and central login has been completed. Facility for online payment has been integrated. Also, a module has been made operational to register the existing licenses and applicants of product certification and Hallmarking activity in the portal.

Development of phase two modules involving development of modules of management system certification, hallmarking, consumer affairs processes and their integration with product certification has commenced and is under progress. Software module for Jeweller Licensing Scheme has been developed. Also, A&H centre module is under development. While the application submission & scrutiny is completed, remaining sub modules are under development. A module for operation of Management System Certification, namely incorporation of existing licenses in the portal, recording of new applications, audit management and grant of licence, has also been developed. Further, a module for monitoring of complaints received has been developed and is under testing.

Human Resource and Finance Management System (HFMS)

A customizable HFMS module for managing support services of BIS, such as Accounts and Finance, Human Resource, Administration, Establishment, etc, has been procured from CDAC, Noida and the same is under customization to suit BIS requirements. Gap analysis and data porting have been initiated in coordination with concerned departments.

Software for Standardization Activity

The Standards Formulation software has been enhanced to cater to the various functions of standardization activity. This software automates all the stages involved in the formulation of standards

and their amendments. It generates real time programme of the work of the technical departments. It has a discussion forum for coordination between various departments.

The standard locator available on BIS website has been modified to enhance response time, user friendliness, better navigation, etc. The enhanced version has been deployed on BIS website and is functional.

Certification Marks Management System (CMMS)

The CMMS software facilitates availability of data in versatile forms to enable inspection planning, analysis of data on quality performance parameters of various sectors of industry, generating various letters to the applicants/licensees and laboratories and evolving data format for internal processing of grant of licence, renewals, inclusion of additional varieties in the licence, etc.

Compulsory Registration Scheme (CRS) portal

An online web portal is operational for managing the Compulsory Registration Scheme. A payment gateway has been integrated with this portal to facilitate payments online.

Laboratory Information Management System (LIMS)

LIMS has been enhanced to cater to various functions of Laboratory activity. LIMS facilitates online test request generation, sample receipt and acceptance, e-forwarding of samples and subsequent uploading of Test Reports by concerned Laboratories. Enhancements have been made to cater to practical issues for example IS wise search filter to classify samples, deletion of wrong test requests, generation of sample code according to sample type (Applicant Sample, Factory Sample, Market Sample, etc), etc. Also, a monitoring provision (report) has been incorporated for monitoring the daily receipt of samples by BIS recognized outside labs.

Software for Managing Complaints Online

A software is operational for online complaint registration by complainants. It allows them to track their complaints, view details, etc. It also facilitates Consumer Affairs Department (CAD) to monitor, view and close the online complaints as well as other complaints entered in the system. Enhancements have been made to cater to practical issues for example search filters to classify different types of closed complaints, detailed views of closed complaints, etc.

An android application (BIS CARE) is also operational for lodging complaints from smart phones. This application has been upgraded in-line with latest trends prevailing in the mobile app technology and the same is under testing.

BIS Website

The existing BIS website is being further revamped in-house in compliance to the guidelines for Indian Government Websites. The revamped website contains features like Content Management System that will facilitate various departments to update their contents directly on BIS website.

A section in the existing website has been dedicated exclusively for Foreign Manufacturer Certification Scheme.

WTO-TBT module

A module has been developed and made operational for International Relations Department, BIS, to host WTO-TBT notifications. It enables outside users to register themselves to receive notifications on their email ids. Also, it facilitates stakeholders to submit comments online.

Assaying and Hallmarking (A&H) Centre Software

A&H centre software has been developed in-house to facilitate Regional Offices to manage (add, update and delete) the data of A&H centres under their jurisdiction. Various reports can be generated through this software. An admin module has also been provided to Hallmarking Department for overall management of this data.

Security Audit

As per the Government norms, the web applications hosted in BIS-HQ are being security audited. CDAC Hyderabad, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), has been empanelled for this task. The phase one of this audit has been completed and action has been initiated for plugging the reported vulnerabilities.

e-procurement

A project was undertaken for implementation of e-procurement in BIS offices through the Central Public Procurement (CPP) Portal of National Informatics Centre (NIC). Digital Signature Certificates (DSCs) are being procured for the nominated officials, as per the requirements of the system and they are being acquainted with the process of e-tendering through workshops.

PROJECT MANAGEMENT AND WORKS

The works relating to construction of new office buildings for BIS Offices and renovation works in existing buildings is undertaken by Project Management and Works Department (PMWD) of BIS.

PMWD has also undertaken a 'green' initiative under which projects for installation of Rooftop Solar Power Plants in BIS buildings are being undertaken through the Solar Energy Corporation of India.

The progress of various works under PMWD are as under:

A) NEW BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS

1. Construction of new building for BIS Branch Office in Sahibabad (Uttar Pradesh)

BIS has executed a MoU with the Civil Construction Wing – All India Radio (CCW-AIR) for construction of a new building for a BIS Branch Office in the campus of BIS Central Laboratory in Sahibabad. Construction is expected to start by January 2018 after approval from concerned authorities.

2. Construction of new building for BIS Branch Office at Naya Raipur (Chhattisgarh)

BIS has been allotted 2 097 m^2 of land in Naya Raipur by Naya Raipur Development Authority (NRDA), a Chhattisgarh State Government body, for construction of an office building. BIS has entrusted the project for construction of the office building to CPWD, who have taken up preliminary works.

3. Construction of new building for BIS Branch Office at Bhubaneswar (Odisha)

BIS has been allotted 1 011 m^2 of land in Bhubaneswar by Government of Odisha for construction of an office building. Execution of lease agreement with Government of Odisha is under process. After execution of the lease, BIS will entrust the project of construction of the new building to CPWD.

B) RENOVATION PROJECTS

1. Modernization and Renovation works at BIS HQs, New Delhi

i. **Renovation of BIS HQs Canteen:** BIS HQs Canteen was renovated through CPWD. The scope of work included complete renovation of the kitchen and dining area including new flooring, plumbing and providing modern kitchen equipment.

ii. **Replacement of lifts in BIS HQ:** The replacement of existing lifts of BIS HQs has been started through CPWD. Out of the total 4 lifts installed in BIS HQ, replacement of two lifts, one each in Manak Bhavan and Manakalaya buildings has been completed and are under operation. The replacement of remaining 2 lifts is in progress is expected to be completed by December 2017.

2. Interior Renovation and Furniture Work at BIS Branch Office, Guwahati (Assam)

The project for interiors renovation and furniture work at BIS Guwahati Branch Office through HOUSEFED, a Government of Assam agency, has been completed.

3. Repair and Renovation of BIS Branch Office and Laboratory at Bengaluru

The project for repairs and renovation at BIS Branch Office and Laboratory building at Bengaluru, is being executed through CPWD. Work has been started in December 2016 and is in progress.

4. Repair and Renovation of BIS Southern Regional Office and Laboratory at Chennai

The project for repairs and renovation at BIS Southern Regional Office and Laboratory buildings at Chennai, is being executed through Civil Construction Wing – All India Radio (AIR). AIR have completed the work of repair of expansion joint in Laboratory building and other renovation works such as electrical system revamping, and rainwater harvesting are being planned.

C) GREEN INITIATIVE - SOLAR POWER PROJECTS

1. Installation of rooftop solar power plants in BIS buildings

In addition to the Rooftop Solar Power Plants installed in BIS HQ, New Delhi (100 kW), SRO Lab, Chennai (100 kW), WRO, Mumbai (40 kW) and NITS, Noida (50 kW), the following rooftop solar power plants were installed in various BIS buildings:

Sl No.	Name and Location of Office/Lab	Capacity
1	BIS Branch Office, Hyderabad	40.0 kW
2	BIS Eastern Regional Office, Kolkata	24.4 kW
3	BIS Eastern Regional Office Laboratory, Kolkata	40.0 kW

BIS has conveyed its requirement for installation of rooftop plants in other buildings of BIS in Jaipur, Rajkot, Bengaluru, Sahibabad, Bhopal, Chandigarh and Mohali to the Solar Energy Corporation of India (SECI), who have included the same in the 1 000 MW tender floated by them for installation of rooftop solar power plants in buildings all over India.

2. Net Metering

BIS has also implemented Net Metering at the following buildings where rooftop solar power plants are installed:

i. Head Quarters, New Delhi

ii. NITS, Noida

iii. Hyderabad Branch Office

Through net metering, solar energy exported to the grid during closed days is metered and accounted for, in the energy bill, resulting in financial gains to BIS. BIS is extending the net metering initiative to other buildings where solar power plants are installed in collaboration with SECI and concerned state electricity authorities.

VIGILANCE ACTIVITIES

The vigilance set up of Bureau of Indian Standards (BIS) is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) and comprises of Vigilance Department at BIS Headquarters and a Vigilance Section in the Secretariat of each of the Disciplinary Authority for Group B, C and D employees (Deputy Director General concerned).

The Vigilance Department functions in close coordination with Central Vigilance Commission (CVC), Central Bureau of Investigations (CBI) and Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. It is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities of the Bureau in accordance with the guidelines on the subject issued by Central Vigilance Commission and DoPT, etc. This, *inter-alia*, include activities related to:

(a) Preventive vigilance (for example streamlining of procedures, training, preparation of 'Agreed List' and 'List of officers of doubtful integrity', etc.)

(b) Punitive Vigilance (for example scrutiny of complaints received, investigations, disciplinary action against the officers at fault, etc.)

(c) Surveillance and detection (for example Vigilance Audits, scrutiny of annual property returns, monitoring, review meetings, etc.)



Vigilance Awareness Week 2016 - Closing Ceremony

Vigilance Awareness Week was celebrated in Bureau of Indian Standards from 31 October 2016 to 5 November 2016. During the week, a number of activities, including display of banners and distribution of pamphlets, Quiz Competition, Essay Writing Competition and Slogan Writing Competition, on the theme 'Public Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption' were organized. BIS employees participated in these events with great zeal. The award ceremony of the Vigilance Awareness Week was organized on 4 November 2016 at BIS, HQ at New Delhi. Vigilance Awareness Week was also

celebrated at various Regional Offices, Branch Offices, National Institute of Training for Standardization (NITS) and Central Laboratory of Bureau of Indian Standards across the Country.

A panel discussion on the subject of 'Transparency in Public Delivery system' was held in the 'Good Evening India' programme of Doordarshan National Channel on 3 November 2016. Shri Alok Sharma, CVO, BIS and Shri P. V. Rama Sastry, JS (CA) & CVO, Department of Consumer Affairs were the panellists.

A consumer Awareness Programme on 'Public Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption' was organized at Coimbatore, Tamil Nadu on 4 November 2016.

Educational utilization programme encompassing measures to curb corruption with special emphasis on customer grievance were organized at Camelia Institute of Engineering & Technology, Bardwan (WB) on 4 November 2016 and in Hyderabad in two different colleges on 5 November 2016 as a part of Vigilance Awareness Week, 2016.

Regional training programs on the subject of 'Preventive Vigilance' covering various aspects related to vigilance matters for senior officers of BIS were conducted at Northern Regional Office at Chandigarh, Southern Regional Office at Chennai and Eastern Regional Office, Kolkata during the month of November 2016 and Western Regional Office at Mumbai during the month of February 2017.

Preventive vigilance audits of Dehradun Branch Office, Patna Branch Office, Bengaluru Branch Laboratory and Kochi Branch Office were carried out during the year.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES

Recruitment

During the year, 13 scientists in waiting list of the recruitment process of 2015-16 joined as Scientist-B through direct recruitment.

Deployment

During the year, deployment of personnel in the various activities of BIS during 2016- 17 is given below:

Activity	Group wise Deployment of Personnel (as on 31 March 2017)		
	A (Scientific Cadre)	A (Non Scientific Cadre) & B,C,D	Total
Standards Formulation	81	61	142
Certification	312	322	634
Laboratories	49	250	299
Technical Support Services	31	114	145
Admin/ HRD/ Estt.	3	137	140
Others (Corporate)	12	135	147
Total	**488**	**1019**	**1507**

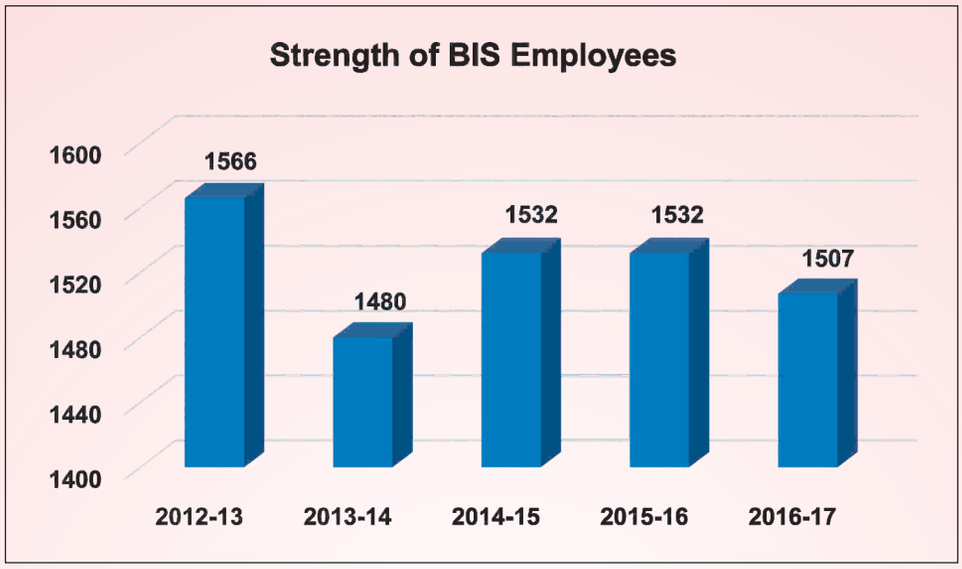
Group wise strength of employees in BIS

As on 31 March 2017, the Group wise strength is as under:

Group	Existing Strength	Representation of SC/ST/OBC/PH/Ex-Ser.
A (Scientific Cadre)	488	221
A (Administrative, Finance & Other Posts)	36	19
B	448	122
C	371	189
D*	164	80
Total	**1507**	**631**

*Subsequent to completion of training as per the decision of the Government, the earlier Group 'D' employees have now been made Group 'C' employees.

BIS continues to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes organized by various agencies from time to time.



Swachh Bharat Mission — The Swachh Bharat drive was carried out in BIS in two phases that is 16 – 31 May 2016 and 16 – 31 October 2016.

During the period, special cleanliness drive was undertaken in all offices of BIS as per instructions received from DoCA. BIS employees had participated in the cleanliness drives and performed the following jobs:

– The work areas and office premises were cleaned and made dust free.

– Old files were weeded out/sent to Record Room.

– The unused/unserviceable/obsolete equipment and furniture were identified and thereafter condemned and disposed off.

– The logo of Swachh Bharat Mission had been displayed on BIS website during the Swachhta pakhwada.

– Awareness programmes were organized in Government schools run by local bodies targeting students of Class 5th and above.

Staff Welfare — BIS continued its welfare measures for its employees namely by way of Group Insurance Schemes, facility of Holiday Homes, subsidized refreshments, provision of newspapers at the reception counter and to officers of the level of Deputy Director General and above, Children Scholarship Scheme, etc.

The details of the Holiday Homes functional under BIS HQs and its Regional Offices are as under:-

a. BIS Headquarters - Shimla (w.e.f. 10 September 2016)

b. Northern Regional Office - Manali (w.e.f. 1 February 2017)

c.	Eastern Regional Office	-	Puri (w.e.f. 1 February 2017)
d.	Western Regional Office	-	Mahabaleshwar (w.e.f. 22 July 2016)
e.	Southern Regional Office	-	Kumarakom, Kerala (w.e.f. 1 July 2016)

Library Services

BIS technical Library located at Headquarters is a national resources centre for information on standards and related matters and meets the needs of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library of standards in the South Asian Region, covering a floor area of 1 000 m^2. The collection includes about 4 lakh standards from all over the world and 70 000 technical books. Reference services were provided to 2 394 visitors by way of preparing 4 exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 1 980 queries as received from them. The Library maintains regular updation of mechanized database of standards received in the library. Under the Annual Action Plan 79 954 numbers of publications have been electronically indexed.

SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN AT WORKPLACE

Following the guidelines and norms laid by the Hon'ble Supreme Court of India in Vishaka & Others v/s State of Rajasthan & Others, the Sexual Harassment Committee was set up in the Bureau of Indian Standards.

In compliance with the guidelines of the Supreme Court of India on the prevention of sexual harassment of women at work place, an Internal Complaints Committee at BIS Headquarters was constituted under Section 4 of (i) Rule 3-C and Government of India's Decisions (25) under said Rule of the *Central Civil Services (Conduct) Rules*, 1964; (ii) *Sexual Harassment of Women at Work Place [Prevention, Prohibition and Redressal] Act*, April 2013; and (iii) *Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules*, December 2013; and re-constituted on 5 November 2015 for a period of two years. The composition of the newly constituted Internal Complaints Committee (ICC) at BIS Headquarters consists of a senior level women employee as Presiding Officer and three other members including from All India Democratic Women's Association (AIDWA), New Delhi. In addition, ICCs have also been constituted in the four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chennai and Chandigarh.

SCHEMES FOR DIVYANGS

1. As per the GOI instructions, BIS is providing 3 percent reservation to the persons with disabilities (Divyangs) in direct recruitment under Group A, B, C and D posts. Further 3 percent of the vacancies, in case of promotion to Group C and D posts, in which element of direct recruitment, if any, does not exceed 75 percent is also being reserved for persons with disabilities (Divyangs).

2. BIS also allows 12 Casual Leaves to the Physically challenged/ disabled people instead of 8 Casual Leaves permissible to a normal employee.

3. Moreover, physically challenged/disable people are being paid Transport Allowance at double the rates prescribed for other employees.

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty Eighth consecutive year i.e. 2016-17, Bureau of Indian Standards continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2016-17 amounted to Rs. 45,663.38 lakh as against Rs. 39,082.83 lakh in the previous year resulting in an increase of 16.84%. The largest contribution to the income was from Product Certification Marking Fee which stood at Rs. 38,930.80 lakh against Rs. 32,611.05 lakh in the previous year i.e. an increase of 19.38%. The total revenue expenditure during the year 2016-17 amounted to Rs. 21,633.58 lakh as against Rs.21,001.20 lakh in 2015-16 registering a increase of 3.01%.

A Comparative Statement of Income & Expenditure during the year 2016-17 vis-a-vis 2015-16 is as under:

(Rupees in lakh)

Sl.No.		**2016-17**	2015-16	**Increase/ decrease(-) (%)**
	INCOME			
1	Income from Services	**43,801.42**	37,277.84	**17.50**
2	Income from Sales of Standards	**660.94**	627.94	**5.26**
3	Retrocession from ISO and IEC	**554.84**	476.75	**16.38**
4	Fees/Subscription	**254.32**	234.53	**8.44**
5	Other Income	**391.86**	465.77	**-15.87**
	Sub Total	**45,663.38**	39,082.83	**16.84**
6	Income from Investment	**2,175.59**	2,743.58	**-20.70**
	TOTAL	**47,838.97**	41,826.41	
	EXPENDITURE			
1	Establishment Expenses	**14,375.15**	13,497.59	**6.50**
2	Operational and Administrative Expenses etc.	**6,698.31**	7,076.50	**-5.34**
3	Depreciation	**560.12**	427.11	**31.14**
	Sub Total	**21,633.58**	21,001.20	**3.01**
4	Annual Contribution to Pension & Gratuity Liability Fund	**0.00**	2,502.06	
	Sub Total	**21,633.58**	**23,503.26**	
5	**Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund A/c**	**26,205.39**	17,732.12	
	TOTAL	**47,838.97**	41,235.38	
	Surplus carried to Capital Fund	**0.00**	591.03	

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

(Amount in ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	**5,40,78,80,066**	5,40,78,80,066
Reserves and Surpluses		**-**	-
Earmarked/Endowment Fund	2	**17,64,79,19,092**	14,49,41,34,257
Secured Loans and Borrowings		**-**	-
Unsecured Loans and Borrowings		**-**	-
Deferred Credit Liabilties		**-**	-
Current Liabilities and Provisions	3	**12,32,47,103**	11,12,51,290
TOTAL		**23,17,90,46,261**	20,01,32,65,613
ASSETS			
Fixed Assets	4	**1,36,89,50,510**	1,31,76,90,186
Investments-from Earmarked/ Endowment Funds	5	**4,39,33,99,663**	1,16,11,02,309
Investment-Others	6	**-**	-
Current Assets, Loans, Advances etc.	7	**17,41,66,96,088**	17,53,44,73,118
Miscellaneous Expenditure(to the extent not written off or adjusted)		**-**	-
TOTAL		**23,17,90,46,261**	20,01,32,65,613
Significant Accounting Policies	16		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
Details of Investment	18		

(ALKA PANDA)
DIRECTOR GENERAL

(H.R. AHUJA)
DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)

(VINOD KUMAR)
DIRECTOR (ACCOUNTS)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

(Amount in ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income from Sales/Services	8	**4,38,01,41,989**	3,72,77,83,894
Grants/Subsidies		-	-
Fees/Subscriptions	9	**2,54,31,655**	2,34,52,645
Income from Investments	10	**21,75,58,894**	27,43,58,316
Income from Royality, Publications etc.	11	**12,15,78,632**	11,04,69,303
Interest Earned	12	**18,33,013**	7,60,185
Other Income	13	**3,73,53,188**	4,58,16,677
TOTAL (A)		**4,78,38,97,371**	4,18,26,41,020
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	14	**1,43,75,14,967**	1,59,99,65,486
Operational and Administrative Expenses	15	**66,98,31,474**	70,76,50,008
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
Interest		-	-
Depreciation	4	**5,60,12,376**	4,27,10,544
Contibution towards Shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account		**2,62,05,38,554**	1,77,32,12,013
TOTAL(B)		**4,78,38,97,371**	4,12,35,38,051
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		-	5,91,02,969
Significant Accounting Policies	16		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
Details of Investment	18		

(ALKA PANDA)
DIRECTOR GENERAL

(H.R. AHUJA)
DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)

(VINOD KUMAR)
DIRECTOR (ACCOUNTS)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		**5,40,78,80,066**	5,35,08,38,482
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			
i)	Cost of Assets capitalized from Funds from Ministry under Plan Schemes	-	33,440
ii)	Cost of assets capitalized from funds received from Spice Board	-	62,175
	Total	**5,40,78,80,066**	5,35,09,34,097
Less:	Reversal of Subsidy for Solar Power Plant capitalized in the previous year [Refer Schedule 4(A-2)]	-	21,57,000
	TOTAL	**5,40,78,80,066**	5,34,87,77,097
Add:	**Surplus transferred from Income & Expenditure Account**	-	5,91,02,969
	BALANCE AT THE END OF THE YEAR	**5,40,78,80,066**	5,40,78,80,066

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 2 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (Amount-in ₹)

									TOTAL	
	Assistance from MOCA under plan scheme for setting up of Hallmarking Centres	Assistance from MOCA under the Plan Project: Quality Infrastrac-ture for consumer protection (Plan)	Assistance from MOCA under C.W.F.	Benevo-lent Fund	General Provident Fund	National Pension Scheme Fund	Pension & Gratuity Liability Fund Account	Hallmarking Education & Protection Fund	Current Year	Previous Year
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10
a) Opening balance of the funds	**32,18,310**	**8,87,50,177**	**4,46,049**	**6,44,789**	**1,57,13,01,811**	**28,62,319**	**12,82,54,34,138**	**14,76,664**	**14,49,41,34,257**	11,88,43,92,402
b) Additions to the Funds:										
i) Assistance/Grants	1,17,81,690	-	-	-	-	-	-	-	**1,17,81,690**	8,75,00,000
ii) Income from Interest on Investments of the funds	1,79,911	7,93,477	6,651	23,814	11,97,89,894	91,028	1,28,92,75,396		**1,41,01,60,171**	1,19,11,90,239
iii) Contribution to the respective				8,20,710	19,46,93,890	5,07,76,027		4,66,264	**24,67,56,891**	49,22,86,043
iv) Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund A/c							2,62,05,38,554		**2,62,05,38,554**	1,77,32,12,013
v) Others		1,72,546					14,50,419		**16,22,965**	4,84,295
TOTAL (a+b)	**1,51,79,911**	**8,97,16,200**	**4,52,700**	**14,89,313**	**1,88,57,85,595**	**5,37,29,374**	**16,73,66,98,507**	**19,42,928**	**18,78,49,94,528**	15,42,90,64,992
c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds										
i) Capital Expenditure - Fixed Assets										33,440
ii) Revenue Expenditure										
- Payments to employees, pensioners & beneficiaries				5,00,000	31,43,60,432	5,12,64,592	73,95,25,463		**1,10,56,50,487**	87,01,64,004
- Assistance to Hallmarking Centres	1,49,70,954								**1,49,70,954**	3,69,84,678
- Meetings, Travels & Others		1,64,53,965		30					**1,64,53,995**	2,77,48,613
Total Revenue Expenditure	1,49,70,954	1,64,53,965	-	5,00,030	31,43,60,432	5,12,64,592	73,95,25,463	-	**1,13,70,75,436**	93,48,97,295
TOTAL(c)	**1,49,70,954**	**1,64,53,965**	-	**5,00,030**	**31,43,60,432**	**5,12,64,592**	**73,95,25,463**	-	**1,13,70,75,436**	93,49,30,735
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2017 (a+b-c)	**2,08,957**	**7,32,62,235**	**4,52,700**	**9,89,283**	**1,57,14,25,163**	**24,64,782**	**15,99,71,73,044**	**19,42,928**	**17,64,79,19,092**	14,49,41,34,257

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
A.	**CURRENT LIABILITIES**		
	1. Sundry Creditors for Goods and Services		
	a) Inland	**6,72,42,355**	5,30,93,179
	b) Abroad	**1,88,04,660**	1,97,84,495
	2. Advances received from Customers:		
	a) Sales	**15,94,784**	4,94,625
	b) Certification	**71,09,662**	1,32,03,134
	3. Statutory Liabilities		
	Others- Service Tax Payable	**74,850**	2,44,357
	4. Other Current Liabilities		
	a) Earnest Money/Retention Money	**2,44,99,101**	2,09,49,862
	b) Accounts Payable Employees	**12,80,586**	9,28,054
	c) ABO Building A/c	**26,41,105**	25,53,584
	TOTAL(A)	**12,32,47,103**	11,12,51,290
B.	**PROVISIONS**	**-**	-
	TOTAL(A+B)	**12,32,47,103**	11,12,51,290

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS (Amount-in ₹)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the Year-end	As at the Current year-end 2016-17	As at the Previous year-end 2015-16
A FIXED ASSETS:										
1 LAND	59,35,58,542	**3,87,39,756**	**0**	**63,22,98,298**	0	**0**	**0**	**0**	**63,22,98,298**	59,35,58,542
2 BUILDINGS	25,48,13,986	**11,53,66,480**		**37,01,80,466**	18,16,59,336	**2,85,38,741**	**0**	**21,01,98,077**	**15,99,82,389**	7,31,54,650
3 RESIDENTIAL FLATS	6,22,96,310	**0**	**0**	**6,22,96,310**	4,06,64,803	**6,78,661**	**0**	**4,13,43,464**	**2,09,52,846**	2,16,31,507
4 PLANT, MACHINARY & EQUIPMENTS	26,27,15,330	**1,67,24,626**	**27,70,329**	**27,66,69,627**	21,58,50,045	**90,72,968**	**26,48,089**	**22,22,74,924**	**5,43,94,703**	4,68,65,285
5 VEHICLES	40,28,549	**0**	**0**	**40,28,549**	26,91,844	**2,00,506**	**0**	**28,92,350**	**11,36,199**	13,36,705
6 FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS & COMPUTERS	29,97,56,090	**2,09,18,492**	**1,07,31,499**	**30,99,43,083**	24,67,73,870	**1,73,05,846**	**90,38,510**	**25,50,41,206**	**5,49,01,877**	5,29,82,220
7 LIBRARY BOOKS	2,71,31,247	**2,10,409**	**0**	**2,73,41,656**	2,70,74,520	**2,15,654**	**0**	**2,72,90,174**	**51,482**	56,727
TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	1,50,43,00,054	**19,19,59,763**	**1,35,01,828**	**1,68,27,57,989**	**71,47,14,418**	**5,60,12,376**	**1,16,86,599**	**75,90,40,195**	**92,37,17,794**	78,95,85,636
PREVIOUS YEAR	1,46,06,51,051	5,11,57,582	75,08,579	1,50,43,00,054	67,60,94,365	4,27,10,544	40,90,491	71,47,14,418		
B CAPITAL WORK IN PROGRESS	52,81,04,550	**2,43,10,743**	**10,71,82,577**	**44,52,32,716**					**44,52,32,716**	52,81,04,550
								TOTAL	**1,36,89,50,510**	1,31,76,90,186

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
1	**Pension & Gratuity Liability Fund Account**		
1.1	**Government of India Securities**	**3,24,19,42,585**	-
1.2	**Debentures and Bonds**	**2,00,00,000**	2,00,00,000
	TOTAL(1)	**3,26,19,42,585**	2,00,00,000
2	**General Provident Fund of Employees**		
2.1	**Government of India Securities**	**26,41,03,664**	27,95,88,148
2.2	**State Government Securities**	**42,00,22,970**	40,71,14,749
2.3	**Debentures and Bonds**	**12,24,21,850**	13,29,90,818
2.4	**Special Deposits with RBI**	**31,27,08,594**	31,27,08,594
2.5	**Equities & related investments-Mutual Funds**	**1,22,00,000**	87,00,000
	TOTAL(2)	**1,13,14,57,078**	1,14,11,02,309
	TOTAL(1)+(2)	**4,39,33,99,663**	1,16,11,02,309

SCHEDULE 6 - INVESTMENTS-OTHERS

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
1	**Investments towards the Corpus/Capital Fund**	-	-
	TOTAL	-	-

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES, ETC.

(Amount in ₹)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:		
a) Laboratory apparatus and stores	**8,20,218**	12,38,631
b) Stationery	**30,62,034**	24,66,675
c) Repair & Maintenance Consumables	**14,16,608**	5,86,048
d) Gold Jewellary	**7,62,018**	7,62,018
Total (1)	**60,60,878**	50,53,372
2. Sundry Debtors		
a) Sale of Publications		
i) Exceeding six months	**67,309**	60,230
ii) others	**54,376**	16,967
b) Certification		
i) Exceeding six months	**28,35,789**	19,96,053
ii) others	**77,393**	1,39,123
c) Accounts Recoverable		
i) Accounts recoverable (employees)	**9,81,750**	13,02,378
ii) Recoverables from Government Departments (From MOF, MEA & DoCA)	**1,03,38,087**	85,14,510
iii) Accounts Recoverable (Others)	**2,75,58,548**	2,27,61,999
Total (2)	**4,19,13,252**	3,47,91,260
3. Cash Balance in Hand (Including Imprest)	**3,17,941**	5,24,230
4. Bank Balances:		
a) With Schedule Banks		
i) On Current Accounts	**13,64,15,380**	12,68,43,372
ii) On Saving Accounts	**8,84,21,192**	6,23,40,961
Sub Total of 4(a) (i & ii)	**22,48,36,572**	18,91,84,333
iii) On Fixed Deposit Accounts		
A) Investment - Earmarked Funds		
I) Pension & Gratuity Liability Fund A/c	**12,73,52,30,460**	12,80,54,34,138
II) General Provident Fund	**31,57,81,000**	31,02,91,000
III) National Pension Scheme Fund A/c	**24,64,782**	28,62,319
IV) ABO Building Project A/c	**23,33,410**	23,33,410
B) General Investments towards Corpus/ Capital Fund	**1,47,26,04,758**	2,15,95,03,543
Sub Total of 4(a)(iii)	**14,52,84,14,410**	15,28,04,24,410
Total (4)	**14,75,32,50,982**	15,46,96,08,743
5. Cheque in Transit	**1,38,12,297**	6,50,000
6. Franking Machine Balance	**1,85,868**	2,09,560
TOTAL(A)	**14,81,55,41,218**	15,51,08,37,165

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2017

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES, ETC.

(Amount in ₹)

	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Advances to Staff for:		
i) Purchase of Conveyance	**6,55,410**	14,30,936
ii) House Building	**27,18,917**	37,98,561
iii) Computer	**4,16,912**	6,67,340
TOTAL (1)	**37,91,239**	58,96,837
2. Advances and other amounts recoverable or for value to be received		
a) On capital Account & others to outside parties		
i) Projects - HQ CPWD(*see Note No. 2.1(i) of Sch.17)*	**44,39,676**	70,11,676
ii) Building Construction ROs/BOs -CPWD	**2,47,30,221**	1,27,99,773
iii) Computerization Project:C-DAC	**3,34,30,653**	2,22,38,853
iv) Others(ROs/BOs/HQ)	**93,61,551**	1,13,74,256
v) Consumer Welfare Fund(NBCC)	**3,32,260**	3,32,260
vi) Plan Project Schemes*(See Note No. 2.7 of Sch. 17)*	**17,436**	12,17,436
TOTAL (2a)	**7,23,11,797**	5,49,74,254
b) **Prepaid Expenses**	**63,11,602**	15,21,244
c) **Advances to Staff for**:		
i) Festival	**-**	7,15,415
ii) Natural calamities	**75,000**	1,58,400
iii) Travel	**8,02,077**	17,47,495
iv) Leave Travel Concession	**8,69,260**	8,58,670
v) General Provident Fund	**76,85,081**	85,12,793
TOTAL (2c)	**94,31,418**	1,19,92,773
d) Registrar-Small Causes Court - Mumbai (*see Note No. 1.3 of Sch. 17)*	**1,83,60,598**	1,83,60,598
e) Security Deposits	**75,26,903**	53,05,938
TOTAL (2)	**11,39,42,318**	9,21,54,807
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds & Others		
i) BIS Funds	**2,34,24,17,125**	1,79,63,26,587
ii) General Provident Fund	**12,30,24,641**	10,82,74,830
TOTAL (3)	**2,46,54,41,766**	1,90,46,01,417
4. Claim Receivable		
a) Income Tax Refund	**1,28,07,389**	1,82,15,664
b) Service Tax	**51,72,158**	27,67,228
TOTAL (4)	**1,79,79,547**	2,09,82,892
TOTAL(B)	**2,60,11,54,870**	2,02,36,35,953
TOTAL(A+B)	**17,41,66,96,088**	**17,53,44,73,118**

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 8-INCOME FROM SALE/SERVICES

(Amount in ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Product Certification	**3,89,30,79,533**	3,26,11,05,239
2. Conformity Assessment(Registration)	**25,82,66,217**	22,20,45,630
3. Hallmarking	**19,06,84,575**	20,05,56,091
4. Systems Certification	**3,81,11,664**	4,40,76,934
TOTAL	**4,38,01,41,989**	3,72,77,83,894

SCHEDULE 9-FEE/SUBSCRIPTION

(Amount in ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Confrences & Training Fees	**2,28,25,055**	2,06,63,245
2. Library Membership Fee	**25,28,000**	27,04,000
3. Subscription for Standards India Journal	**78,600**	85,400
TOTAL	**2,54,31,655**	2,34,52,645

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 10-INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in ₹)

		Investment from Earmarked Fund		Investment-Others	
		Current Year	Previous Year	**Current Year**	Previous Year
	(Income on Investment from Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)				
1	Interest	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650	**21,70,83,863**	27,38,83,287
2	Rent	**-**	-	**4,75,031**	4,75,029
	TOTAL	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650	**21,75,58,894**	27,43,58,316
	(TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS) [Refer Schedule 2, Item b(ii) - Col 7]	**1,28,92,75,396**	1,06,18,74,650		

SCHEDULE 11-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
A.	**INCOME FROM SALE OF STANDARDS**		
1	Electronic Media	**4,04,55,558**	3,92,82,629
2	Hard copies	**2,42,97,828**	2,15,58,445
3	Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	**12,27,129**	18,41,093
4	Royalty from reproduction of Indian Standards	**1,13,800**	1,12,000
	TOTAL(A)	**6,60,94,315**	6,27,94,167
B.	**Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India**	**5,54,84,317**	4,76,75,136
	TOTAL(A+B)	**12,15,78,632**	11,04,69,303

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 12-INTEREST EARNED

(Amount in ₹)

	Current Year	Previous Year
On Saving Account	**18,33,013**	7,60,185
TOTAL	**18,33,013**	7,60,185

SCHEDULE 13-OTHER INCOME

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
a)	Interest from Conveyance, Computer & House Building Advances	**56,37,194**	54,12,839
b)	CGHS Contribution	**40,36,830**	35,04,508
c)	Licence Fee- Staff Quarters	**7,81,821**	4,51,844
d)	Miscellaneous Income at HQ	**25,14,496**	1,64,46,330
e)	Miscellaneous Income at ROs/BOs	**55,37,803**	1,10,72,148
f)	Miscellaneous Income at Laboratories	**1,26,64,508**	89,29,008
g)	Surplus in GPF Account	**61,80,536**	-
	TOTAL	**3,73,53,188**	4,58,16,677

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 14 -ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
1.	**PAY & ALLOWANCES**		
	a) Pay	**52,42,70,257**	47,26,57,066
	b) Allowances and Bonus	**72,84,28,149**	72,28,49,608
	c) Terminal Leave Encashment	**7,37,31,200**	5,46,19,792
	TOTAL(1)	**1,32,64,29,606**	1,25,01,26,466
2.	**RETIREMENT BENEFITS**		
	a) Annual Contribution to Pension & Gratuity Liability Fund A/c	**-**	25,02,05,865
	b) Employer's Contribution to National Pension Scheme	**2,52,61,005**	1,82,04,435
	c) Deficit in General Provident Fund A/c	**-**	3,72,550
	TOTAL(2)	**2,52,61,005**	26,87,82,850
3.	**WELFARE EXPENSES**		
	a) Medical Benefits-Employees	**2,98,74,650**	2,73,32,177
	b) Medical Benefits-Pensioners	**3,07,03,651**	3,49,37,881
	c) Staff Welfare	**1,23,20,785**	77,39,164
	d) Leave Travel Concession	**1,29,25,270**	1,10,46,948
	TOTAL(3)	**8,58,24,356**	8,10,56,170
	TOTAL(1+2+3)	**1,43,75,14,967**	1,59,99,65,486

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 15 -OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
1.	**TRAVELLING EXPENSES**		
a)	Overseas	**4,56,487**	6,90,139
b)	Domestic	**3,52,26,920**	3,84,14,752
c)	Committee Members	**1,30,659**	3,68,359
	TOTAL(1)	**3,58,14,066**	3,94,73,250
2.	**SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS**		
a)	International Standards Organization	**2,88,92,068**	3,09,45,885
b)	International Electrotechnical Commission	**8,878,276**	99,57,985
	TOTAL(2)	**3,77,70,344**	4,09,03,870
3.	**PRINTING**		
a)	Standards	**31,19,376**	9,67,396
b)	Bulletin	**2,14,492**	5,77,614
	TOTAL(3)	**33,33,868**	15,45,010
4.	**TESTING & SURVELLIANCE**		
a)	Testing Charges	**11,04,96,572**	13,30,72,280
b)	Stipend to Laboratory Apprentices	**-**	32,95,055
c)	Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Laboratory Equipment	**1,02,22,906**	93,71,043
d)	Market Samples	**31,89,036**	38,43,034
e)	Hiring of Taxies for Inspection Work	**47,16,363**	44,16,328
f)	Freight and Cartage	**1,31,44,365**	1,40,92,399
	TOTAL(4)	**14,17,69,242**	16,80,90,139
5.	**PUBLICITY**	**16,23,60,120**	17,08,99,480
6.	**OFFICE EXPENSES**		
a)	Stationery	**1,82,35,022**	1,82,05,064
b)	Postage	**76,86,552**	56,61,754
c)	Telephone	**1,40,46,429**	1,35,54,265
d)	Recruitment	**3,80,273**	2,08,67,789
e)	Refreshment and Entertainment	**15,09,973**	13,30,973
f)	Liveries	**3,33,255**	5,06,880
g)	Insurance and Bank Charges	**18,90,530**	17,57,606
h)	Miscellaneous	**23,08,678**	20,69,393
i)	Rent and Statutory Taxes	**2,94,73,511**	2,80,96,806
j)	Electricity and Water Charges	**4,43,19,023**	4,45,76,412
k)	Taxi Hiring Charges	**86,95,919**	89,57,065
	TOTAL(6)	**12,88,79,165**	14,55,84,007

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 15 -OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
7.	**REPAIRS AND MAINTENANCE**		
a)	Furniture and Office Equipment	**77,08,408**	76,70,116
b)	Building	**1,78,19,846**	1,56,78,892
c)	Vehicles	**6,54,633**	5,85,369
	TOTAL(7)	**2,61,82,887**	2,39,34,377
8.	**CONFERENCES, CONSUMER AWARENESS AND TRAINING PROGRAMME**		
a)	Conferences, Seminars and Consumer Awareness Programmes	**1,26,87,927**	1,01,41,714
b)	Training Expenses in NITS	**87,65,313**	68,04,034
	TOTAL(8)	**2,14,53,240**	1,69,45,748
9.	**OTHER EXPENSES**		
a)	IT Services Expenses	**1,86,71,551**	1,88,35,210
b)	Library Subscription and Expenses	**3,45,382**	3,13,951
c)	Audit Fees and other Consultancy Charges	**40,74,249**	43,44,431
d)	Legal charges	**57,22,676**	37,39,155
e)	Labour Expenses	**6,81,68,165**	5,33,82,225
f)	Hiring of Technical Manpower	**33,00,602**	8,18,080
g)	Bad Debts & losses written off *(See Note No. 2.12 of Sch. 17)*	**-**	2,64,800
h)	Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	**7,94,930**	2,82,303
i)	Quality System Charges	**80,10,204**	99,84,532
j)	Hindi Promotional Activities	**30,83,988**	30,85,708
k)	Enforcement outsourcing Expenses	**96,795**	2,14,566
l)	Exchange Rate Variation	**-**	10,77,081
m)	CENVAT Credit Expenses	**-**	39,32,085
	TOTAL(9)	**11,22,68,542**	10,02,74,127
	TOTAL(1 to 9)	**66,98,31,474**	70,76,50,008

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transactions denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income & Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay & Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension & gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/ Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Based on the Actuarial Valuation Report, Annual Contribution to the Fund is provided in the Income & Expenditure Account with corresponding credit to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits and recurring pension during the year are debited to Pension & Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2017

SCHEDULE 17–CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Disputed Demands of Service Tax (excluding penalty and interest) at following offices of BIS:

Sl.No.		Amount (₹ in lakh)
(i)	Chennai Regional Office	161.67
(ii)	Mumbai Regional Office	75.78
(iii)	Pune Branch Office	21.50
(iv)	Patna Branch Office	2.67
(v)	BIS (HQ) New Delhi	192.87

1.2 **NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA** has claimed payment of **Rs. 27.60 lakh** and **Rs. 17.04 lakh** in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively. However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.03.2017. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.3 **Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai**: The contingent liability of Rs. 3,66,60,598/- (Rs. 1,83,60,598/- by way of Demand Drafts and Rs. 1,83,00,000/- by way of Bank Guarantee, both in favour of Registrar Small Causes Court, Mumbai) may arise, in case the Special Leave Petition(SLP) filed by the Bureau before the Hon'ble Supreme Court of India against the order dated 05.10.2015 of the Hon'ble Bombay High Court, Mumbai, in Writ Petition No. 7380/2006, is not allowed.

Initially, the Hon'ble Small Causes Court, Mumbai, vide its judgement dated 09.09.2005 had fixed mesne profit, to be paid by BIS at the rate of 205/- per sq. feet per month for the area of 3255 sq. ft. from 01.06.2000 to 30.04.2004 with interest @ 6% p.a. from the date of application, i.e. 27.02.2002 till entire amount of mesne profits paid to plaintiff. On the appeal filed by Bureau, the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai, vide its judgement dated 07.09.2006, partly allowed the appeal and reduced the mesne profit @ Rs. 5,17,545/- per month with 6% interest p.a. thereby giving the Bureau some relief, which was also not acceptable

to the Bureau. Hence, Writ Petition No. 7380/2006 was filed by the Bureau on 08.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai.

The Hon'ble High Court, vide Order dated 05.10.2015, has dismissed the Petition No. 7380/2006 filed by BIS, and granted stay on execution of the total decreetal amount (50 percent deposited by BIS through Bank Drafts and 50 percent through Bank Guarantee) upto 12 weeks from the date of judgement.

However, BIS has challenged the order dated 05.10.2015 pronounced by the Hon'ble Bombay High court and filed a Special Leave Petition(Civil) No. 36289/2015 before the Hon'ble Supreme Court. In the said SLP, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 14.03.2016 has directed that the Bank guarantee would be renewed by the Petitioner from time to time until the matter is disposed of and that the Respondent has specifically stated that it will not encash the said Bank guarantee without the leave of the court. The said SLP is still pending before the Hon'ble Supreme Court for adjudication.

The paid amount of Rs. 1,83,60,598/- has been kept under Current Assets, Loans and Advances{Schedule 7(B), Item 2(d)}. In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income and Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget with the approval of Executive Committee.

1.4 **Suit No. 3016 of 2010 in Hon'ble Bombay High Court:-** Contingent Liability of Rs. 73,82.90 lakh alongwith interest may arise due to damages claimed by M/s. National Food Products(India) Pvt. Ltd. from BIS, for the alleged loss suffered by it for delay in renewal of its licence for Packaged Drinking Water.

1.5 **Bank Guarantee:** Bank Guarantee of Rs. 5.00 lakh valid upto 05.01.2020 was got issued from Syndicate Bank in favour of Director General of Disasters, Response & Fire Services, Hyderabad.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 **Capital Commitments:** The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:

(Amount in crores)

Sl. No.	Project	Total Estimated Cost	Payment made to CPWD	Value of contract remaining to be executed
(i)	Air Conditioning of HQ Building	17.02	15.40	1.62
(ii)	Construction of Chandigarh Regional Office Building	17.04	13.00	4.04
(iii)	Renovation of Northern Regional Office Laboratory Building, Mohali	1.02	0.55	0.47
(iv)	Construction of Rajkot Office Building	5.38	4.00	1.38

Sl. No.	Project	Total Estimated Cost	Payment made to CPWD	Value of contract remaining to be executed
(v)	Modernization of Training Institute Building at Noida from the assistance received from the Government under Plan Fund	6.51	6.43	0.08
(vi)	Construction of Jammu Office Building	4.33	4.33	—
(vii)	Interior work of Guwahati Branch Office	0.81	0.65	0.16
(viii)	Replacement of lifts of BIS:HQ	1.13	0.38	0.75
(ix)	Renovation of Canteen of BIS:HQ	0.52	0.32	0.20

2.2 Pension & Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)

2.2.1 On the recommendation of the 56th Financial Committee held on 26.11.2015, the EC in its 130th meeting held on 05.05.2016 ratified its approval through circulation vide Letter No. BIS/EC/A-2.130 dated 15.12.2015 that the effect of the 7th Pay Commission may be factored in the actuarial valuation of the Pension & Gratuity Liability and depending upon the total accrued liability of Pension & Gratuity, the shortfall may be provided from Income & Expenditure Account. As the 7th Pay Commission Report has been implemented in BIS in March 2017, the actuarial valuation has been conducted as on 31.03.2017 on the basis of revised Pay of the employees.

2.2.2 According to the Actuarial Valuation Report submitted by M/s. Nalin Kapadia, Consultant & Actuaries registered with SEBI, by following the guidelines given in AS-15 of I.C.A.I. and the guidelines of the Actuaries Society of India, the total accrued Pension & Gratuity Liability of BIS as on 31.03.2017 amounted to Rs. 16,55,31.65 lakh as under:

Sl. No.	Accrued Liability towards	Amount in lakh
1.	Accrued Pension Liability (for past service) of existing employees.	7,38,41.97
2.	Accrued Gratuity Liability(for past service) of existing employees	96,53.05
3.	Accrued pension liability for existing pensioners/family pensioners	8,20,36.63
	Total	16,55,31.65

2.2.3 The above liability as per actuarial valuation as on 31.03.2016 amounted to Rs. **12,82,54.34 lakh.** The increase in the Pension and Gratuity Liability valuation as on 31.03.2017 is due to:

(i) Increase in pay and pension due to implementation of the 7th Pay Commission Report.

(ii) Decrease in the rate of interest taken in the current valuation for the purpose of reinvestment of the fund. The assumed rate of interest in the current valuation as on 31.03.2017 has been taken as 6.95% as against 7.80% in the previous valuation as on 31.03.2016 due to falling interest rate scenario.

2.2.4 The position of the Pension & Gratuity Liability Fund as on 31.03.2017 is given as under:

i) Opening Balance in the Fund:- The amount available in the Pension & Gratuity Liability Fund as on 01.04.2016 amounted to **Rs. 12,82,54,34,138.**

ii) Interest earned by the Fund:- The total interest earned on investments of various funds of BIS on accrual basis amounted to **Rs. 1,50,64,50,287** This includes the interest on the Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c, Investment towards National Pension Scheme(NPS) Fund (in respect of employees whose PRAN Accounts are not yet opened) and the General Investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest amounting to **Rs. 91,028** have been allocated and credited to National Pension Scheme (NPS) Fund Account. The remaining interest earnings of **Rs.1,50,63,59,259** have been apportioned between Pension & Gratuity Liability Fund A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 01.04.2016 in the "Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c" and "General Investments towards Corpus/Capital fund A/c" as under:

(Amount in ₹)

Investment	**Opening Balance of Investments as on 01.04.2016**	**Interest of Rs. 150,63,59,259 for 2016-17 apportioned in the ratio of opening balance of Investments as on 01.04.2016**
Investment towards Pension & Gratuity Liability Fund A/c {total of Schedule 5 (Item1) and Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(A)(I)}	12,82,54,34,138	1,28,92,75,396
General Investments towards Corpus/ Capital Fund A/c {Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(B)}	2,15,95,03,543	21,70,83,863
Total	14,98,49,37,681	1,50,63,59,259

The interest earnings of **Rs. 128,92,75,396** have been credited to "**Pension & Gratuity Liability Fund Account**"(Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of **Rs. 21,70,83,863** appear in the **Income & Expenditure Account** (Refer Schedule 10).

iii) Payments made from the Fund:-The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2016-17 amounted to **Rs.73,80,75,044 {Gross payments Rs. 73,95,25,463 minus** receipts from deputationists etc. **Rs. 14,50,419}** This has been debited to '**Pension & Gratuity Liability Fund Account'** {Schedule 2, column 7}.

iv) Shortfall in the Fund provided from Income & Expenditure Account:- **As a result of the transactions given at Sl. No. (ii) and (iii) above, the balance in the Pension & Gratuity Liability Fund A/C as on 31.03.2017 worked out to Rs. 13,37,66,34,490.** Since there was a shortfall **of Rs. 3,17,65,30,175** in the Pension & Gratuity Liability Fund Account (i.e. accrued liability of **Rs. 16,55,31,64,665** LESS Rs **13,37,66,34,490**), therefore, the entire difference between the total income and total expenditure of 2016-17 which amounts to **Rs. 2,62,05,38,554 has been charged to the Income & Expenditure Account as "Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account" and credited to "Pension & Gratuity Liability Fund Account"** (Schedule 2, column 7) in consonance with the decision of the Executive Committee**.** The remaining shortfall **of Rs. 55,59,91,621 in Pension & Gratuity Liability Fund Account will be met out of the Income & Expenditure A/c of 2017-18.**

v) Closing balance in the Fund:- **Therefore, after providing for the shortfall from Income & Expenditure Account, the Pension & Gratuity Liability Fund thus, amounts to Rs. 15,99,71,73,044 as on 31.03.2017** (Schedule 2, column 7) as against the valuation of Rs. 16,55,31,64,665 in the Actuarial Valuation Report.

2.3 **National Pension Scheme (NPS) applicable to recruits from 1.1.2004 onwards:-** The National Pension Scheme(NPS) is applicable to all employees who joined BIS after 01.01.2004. The employees' contribution and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted to PFDRA on monthly basis. However the employees contribution and BIS contribution in respect of employees who are yet to be enrolled with the Regulator is kept with BIS under NPS Fund Account and is invested by BIS. The interest calculated at the rate equivalent to the interest rate of GPF is credited to their accounts. The balance in the NPS Fund with BIS as on 31.03.2017 amounted to **Rs.26,64,782** {Schedule 2, column 6}.

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 The total investments of BIS Funds: The total Investments of BIS **as on 31.03.2017 amounted to Rs**. 17,47,22.43 lakh **which represents various funds as under:**

(Rupees in lakh.)

Sl. No.	Funds against which the Investment is represented	Investment in Fixed Deposits of PSU Bank	Investment in Central Govt. Securities/ Bonds of PSUs (including premium paid on purchase of Government of India Securities)	Total Investment
i)	Pension & Gratuity Liability Fund	12,73,52.30	3,26,19.43	15,99,71.73
ii)	General Investment of BIS representing Corpus/Capital Fund	1,47,26.05	-	1,47,26.05

Sl. No.	Funds against which the Investment is represented	Investment in Fixed Deposits of PSU Bank	Investment in Central Govt. Securities/ Bonds of PSUs (including premium paid on purchase of Government of India Securities)	Total Investment
iii)	National Pension Scheme Fund	24.65	-	24.65
	Total Investment	**14,21,03.00**	**3,26,19.43**	**17,47,22.43**
		(shown under Schedule 7(A) (item 4(a)(iii)	(shown under item No. 1.1 of Schedule 5)	

The details of total investments as on 31 March 2017 are also given in Schedule 18.

2.4.2 BIS had made investment of Rs. 200.00 lakh in the bonds of U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL), an undertaking of Uttar Pradesh Government on 17.12.1998 @ 16% per annum. UPCSMFL had defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The maturity of principal was due on 30.04.2003(33%), 30.10.2003(33%) and 30.04.2004(34%). The interest is under default since 01.05.2000 which amounts to Rs. 128.00 lakh till date of maturity at coupon rate. BIS had filed a case through Petition No. 451/2002 before the Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC). The Hon'ble NCDRC pronounced its judgement on 01.02.2016 and ordered the opposite party No. 01(UPCSMFL) & opposite party No. 02(Government of Uttar Pradesh, the guarantor) to pay a sum of Rs. 200 lakh jointly and severally to BIS alongwith the interest @ 9% only from 01.05.2000 till the date of realization. A Caveat Petition has also been filed by BIS in the Hon'ble Supreme Court on 03.03.2016.

The Hon'ble NCDRC in the last hearing held on 16.12.2016, has issued Recovery Certificate(s) to Collector Lucknow and Collector Kanpur for the realization/recovery of amount to the extent of decretal amount, i.e. Rs. 2 crore, alongwith 9% interest w.e.f. 01.05.2000 till its realization from M/s U.P. Cooperative Spinning Mills Federation Ltd. The implementation of the Recovery Certificate issued by the Hon'ble NCDRC is being followed up with the Collectors' office at Lucknow and Kanpur by our Lucknow Branch Office.

2.5 **Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida** [Schedule 2, column 3]: The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.03.2017 amounted to **Rs. 1,20,440** [i.e. Rs.4,52,700 as per Schedule 2 less Rs. 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B), Item 2(a)(v)].

2.6 **Plan Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance:** This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer

Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Government of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.09.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance. The funds of Rs.1,17,81,690 were received from the Government during 2016-17. The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2017 amounted to **Rs. 2,08,957** which has been carried over to 2017-18. (Schedule 2, column 1).

2.7 **Plan Schemes of Govt. of India- "Quality Infrastructure for Consumer Protection"** (Schedule 2, column 2): The position of funds received, funds spent by BIS during 2016-17 and the unspent balance as on 31.03.2017 under the two schemes which are being implemented by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Government of India is given as under:

(Amount in ₹)

Sl. No.	Scheme/Particulars	Strengthening Standardization at National and International Level	Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building	Total
(i)	Balance as on 01.04.2016	2,70,01,373	6,17,48,804	8,87,50,177
(ii)	Funds received from DoCA in 2016-17	-	-	-
(iii)(a)	Interest earned credited to Scheme A/c	7,83,140	10,337	7,93,477
(iii)(b)	Other Receipts	_	1,72,546	1,72,546
(iv)	Total {(i) + (ii) + (iii)}	2,77,84,513	6,19,31,687	8,97,16,200
(v)	Expenditure in 2016-17			
(a)	Capital	-	-	
(b)	Revenue	1,64,53,865	100	1,64,53,965
	Total Expenditure in 2016-17 v{(a)+(b)}	1,64,53,865	100	1,64,53,965
(vi)	Balance as on 31.03.2017 {(iv) – (v)} {as per Schedule 2, column 2}	1,13,30,648	6,19,31,587	7,32,62,235
(vii)	Capital Work in Progress against the fund (refer Schedule 4)	_	6,42,82,564	6,42,82,564
(viii)	Funds Available as on 31.03.2017	1,13,30,648	(23,50,977)*	
*The amount spent in excess of the funds available has been reflected as Accounts Recoverable from DoCA,GOI [Refer Sch. 7 (A) Item 2C (ii)]				

2.8 **New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC -** The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The payment of Rs. 86.07 lakh was made to NBCC. However, the project was stopped in June 2006. The settlement of Account could not be made due to dispute regarding the manner of calculation of consultancy charges payable to NBCC. It was therefore, decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS Noida till the settlement of accounts with NBCC towards this project. The payments of **Rs. 86,07,396** made upto 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule 4]. Executive Committee(EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through CPWD. This Project by CPWD has been executed and the AC plant is in operation.[(refer Note No. 2.1(i)]. Some of the components of this project are in progress.

NBCC has been requested for a mutually acceptable solution on the disputed matters. After the settlement of the Account with NBCC, the proposal in this regard, will be placed before the Executive Committee by Project Management Department of BIS. The amount which will be settled with NBCC will be a capital expenditure requiring write off by the Executive Committee (after adjusting the realizable value from the condemnation and sale of the material lying in BIS premises) since no assets have been generated out of the payment made and amount to be settled with NBCC.

2.9 **Capital Expenditure out of BIS Funds**

2.9.1 The capital expenditure out of BIS Funds (including adjustment of advances and additions to Capital WIP) during 2016-17 amounted to **Rs. 21,62,70,506** as under (Refer Schedule 4):

(Amount in Rs.)

Addition to Fixed Assets	**2016-17**
Land & Building	15,41,06,236
Furniture, Office Equipments & Computers	2,09,18,492
Laboratory Equipments	1,67,24,626
Library Books	2,10,409
Total	**19,19,59,763**
Addition to Capital work in progress during the year in various ongoing Building projects	2,43,10,743
TOTAL	**21,62,70,506**

2.9.2 Capital Work-in-Progress : The Capital work-in-progress reflected under Fixed Assets Schedule (Schedule 4) includes various building projects and Air-Conditioning project at HQ. The project-wise amount of capital work in progress reflected in Schedule 4 is given as under:

(Amount in lakh)

Sl. No.	Project	Capital work in progress as on 31.03.2017
(i)	Construction of Chandigarh Regional Office Building and Renovation of Northern Regional Office Laboratory Building, Mohali-CPWD	1273.50
(ii)	Construction of Rajkot Office Building-CPWD	395.94
(iii)	Construction of Jammu Office Building-CPWD	423.36
(iv)	Modernization of Training Institute Building at Noida from the assistance received from the Government under Plan Fund-CPWD	642.83
(v)	Air Conditioning of HQ Building-CPWD	1520.36
(vi)	Replacement of lifts of BIS:HQ-CPWD	22.63
(vii)	Renovation of Canteen of BIS:HQ-CPWD	22.73
(viii)	Interior work of Guwahati Branch Office-HOUSEFED	64.91
(ix)	Central AC Plant(through NBCC-discontinued)	86.07
	Total	**4452.33**

The buildings at Sl. (i) to (iv) have already been occupied by BIS. The expenditure incurred on these buildings has not been capitalized as on 31.03.2017 as the category-wise & item-wise inventory statements have not been provided by CPWD. Therefore, depreciation on these Buildings could not be provided. The expenditure on these buildings will be capitalized and depreciation will be charged after the detailed statements are received from CPWD. The other projects at Sl. (v) to (viii) are in progress.

2.10 **Surplus in General Provident Fund Accounts:** There was a surplus (i.e. excess of income over expenditure) of **Rs. 61,80,536** in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2016-17. This surplus is due to reduction in rates of interest on subscription during the year whereas the past investments of this fund are at higher rates. This has been treated as income of the Bureau as per the Accounting Policy [Schedule 13 Item (g)].

2.11 **Income-Tax Exemption:**

2.11.1 Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India, vide its Notification No. 88/2014 dated 23.12.2014 had notified BIS under Section 10 (46) of

Income-tax Act, 1961 for the Assessment Years 2012-13 to 2016-17. The CBDT has further notified BIS under Section 10 (46) of Income-tax Act, 1961 for the Assessment Years 2017-18 to 2021-22 vide Notification No. 111/2016 dated 01.12.2016. As a result of this notification of Govt. of India, the income of BIS is not taxable till Assessment Year 2021-22.

2.11.2 Income-tax Exemption granted to BIS under section 10(23)(c)(iv) which was withdrawn by DG:IT(E) vide order dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and onwards was restored by it vide order dated 04.12.2012 in compliance with the order of Hon'ble High Court of Delhi. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is also available. The DG IT(E) had filed SLP in Hon'ble Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India against allowing the Writ Petition of BIS by the Hon'ble High Court of Delhi. The SLP filed by DG:IT(E) has been converted into Civil Appeal which is pending in the Hon'ble Supreme Court.

2.12 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.13 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2017

SCHEDULE 18: INVESTMENT

(Amount in Lakh)

Sl. No.	Name of Institution	Investment at cost	Indicative Market Value of investment*
1	**INVESTMENT OF BIS FUNDS**		
1.1	**Investment with Banks in Fixed Deposits**		
1.1.1	Andhra Bank	2,880.00	2,880.00
1.1.2	Bank of India	9,089.00	9,089.00
1.1.3	Canara Bank	12,260.00	12,260.00
1.1.4	Corporation Bank	19,726.00	19,l726.00
1.1.5	Industrial Development Bank of India	12,420.00	12,420.00
1.1.6	Punjab & Sind Bank	6,212.00	6,212.00
1.1.7	Punjab National Bank	12,986.00	12,986.00
1.1.8	State Bank of Bikaner & Jaipur	10,740.00	10,740.00
1.1.9	State Bank of Hyderabad	500.00	500.00
1.1.10	State Bank of India	6,150.00	6,150.00
1.1.11	State Bank of Mysore	2,280.00	2,280.00
1.1.12	State Bank of Patiala	13,970.00	13,970.00
1.1.13	State Bank of Travancore	9,165.00	9,165.00
1.1.14	Syndicate Bank	23,725.00	23,725.00
	TOTAL (1.1)	**1,42,103.00**	**1,42,103.00**
1.2	**Government of India Securities - Quoted**		
	Face Value 29,700.00		
	Premium (Net of amortization) 2,719.43	32,419.43	32,055.10
	TOTAL (1.2)	**32,419.43**	**32,055.10**
1.3	**Investment with PSUs & Financial Institutions in Bonds & Deposits**		
1.3.1	U.P. Co-operative Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL) Bonds (see note 2.4.2 of Schedule 17)	200.00	200.00
	TOTAL (1.3)	**200.00**	**200.00**
	TOTAL	**1,74,722.43**	**1,74,358.10**

	TOTAL INVESTMENT OF Rs. 1,74,722.43 LAKHS OF BIS REPRESENTS FOLLOWING FUNDS:		
	(see Note 2.4.1 of Schedule 17)		
a)	Pension & Gratuity Liability Fund Account: Under Schedule 7(A),Item 4(a) (iii) (A) (I) 1,27,352.30 Under Schedule 5 (Item 1) 32,619.43	1,59,971.73	
b)	Corpus/Capital Fund under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(B)	14,726.05	
c)	National Pension Scheme Fund Under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(A)(III)	24.65	
	Total Investments of BIS Funds	**1,74,722.43**	
2	**INVESTMENT OF EMPLOYEES FUND**		
2.1	**General Provident Fund{(see Schedule 5 and Schedule 7(A), item 4(a)(iii)(A)(II)}**		
2.1.1	Government of India Securities - Quoted	2,641.04	2,791.86
2.1.2	State Government Securities - Quoted	4,200.23	4,447.46
2.1.3	Special Deposits with RBI	3,127.08	3,127.08
2.1.4	Debentures and Bonds of PSUs & Financial institutions - Quoted	1,224.22	1,229.84
2.1.5	Equities and related investment-Mutual Funds - Quoted	122.00	139.34
2.1.6	Fixed Deposits with Banks	3,157.81	3,157.81
	TOTAL(2)	**14,472.38**	**14,893.39**
3	**INVESTMENT-OTHERS**		
3.1	ABO Building Project- Fixed Deposit- with Syndicate Bank (See Schedule 7(A), item 4(a)(iii)(A)(IV)	23.33	23.33
	GRAND TOTAL(1+2+3)	**1,89,218.14**	**1,89,274.82**

NOTE* : *Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of UPCSMFL Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:*

The aggregate quoted investment	40,606.92 (Market value 40,663.60)
The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	1,48,611.22
Total Investment	**1,89,218.14**

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT

A. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2016-17

RECEIPTS			PAYMENTS		
PARTICULARS	**Current Year**	Previous Year	**PARTICULARS**	**Current Year**	Previous Year
I. Opening Cash and Bank Balances	**18,69,59,400**	**12,04,57,154**	**I. Establishment & Administrative Expenses**	**2,07,23,14,683**	**2,02,72,07,792**
II. Grants received from Govt. of India	**1,17,81,690**	**8,75,00,000**	**II. Payments made against Funds for**		
			various Projects		
III. Interest received on Investments	**96,27,41,018**	**79,63,92,351**	**a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres**	**1,49,70,954**	**3,69,84,678**
			b) Quality Infrastructure for Consumer	**1,68,70,065**	**2,77,48,613**
IV. Income from Earmarked Endowment	**10,03,852**	**24,64,639**			
			III. Investments and Deposits made (Net)	**2,48,68,25,000**	**1,98,30,00,000**
V. Interest received- Saving Bank Accounts	**18,33,013**	**7,60,185**			
			IV. Expenditure on Fixed Assets	**7,42,63,548**	**4,97,59,175**
VI. Quality Infrastrucutre for Consumer Protection- XIth Plan	0	**0**	**V. Other Payments**		
			a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	**85,61,23,263**	**60,19,09,660**
VII. Income- Services, Sales and Miscellaneous	**4,58,31,09,409**	**3,90,46,18,829**	b) Pension/Gratuity Benefits	**73,95,82,894**	**59,02,40,036**
			c) Benevolent Fund Benefits	**5,00,000**	**6,60,042**
VIII. Other Receipts			**VI Closing Balance**		
a) Pension & Gratuity Liability Fund	**73,83,50,419**	**59,14,64,033**	**- Cash and Imprest**	**3,17,941**	**5,24,230**
b) Benevolent Fund	**8,20,710**	**8,12,205**	- Bank	22,48,31,163	18,64,35,170
TOTAL	**6,48,65,99,511**	**5,50,44,69,396**	**TOTAL**	**6,48,65,99,511**	**5,50,44,69,396**
B. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF GENERAL PROVIDENT FUND FOR THE YEAR 2016-17					
I. Opening Bank Balance	**27,49,164**	**18,55,789**	**I. Withdrawals & Final Payments**	**31,39,05,805**	**23,46,58,883**
II. Interest Received on Investments	**11,40,95,461**	**10,15,58,527**	**II. Advances to employees**	**13,14,968**	**16,50,828**
III. Employees' Subscriptions	**19,46,93,890**	**19,34,98,377**	**III. Death Linked Insurance**	**1,80,000**	**3,96,000**
IV. Refund of advances	**16,88,053**	**22,02,221**	**IV. Investments and Deposits made(net)**	**10,01,41,101**	**17,11,90,161**
V. Other Receipts - Current Assets	**10,21,22,549**	**11,13,50,605**	**V. Other Payments**		
			a) Current Liabilities		
VI. Interest received- Saving Bank Accounts	**1,99,497**	**1,83,976**	b) Bank Charges	**1,331**	**4,459**
			VI. Closing Bank Balance	**5,409**	**27,49,164**
TOTAL	**41,55,48,614**	**41,06,49,495**	**TOTAL**	**41,55,48,614**	**41,06,49,495**

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards for the year ended 31 March 2017

We have audited the attached Balance Sheet of the Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2017, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the *Bureau of Indian Standards Act.,* 1986. These financial statements include the accounts of twenty three Branch Offices, Four Regional Offices and the Central Testing and Calibration Centre at Sahibabad and the Training Institute of BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-*cum*-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under Section 22(1) of *Bureau of Indian Standards Act,* 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Fixed Assets (Schedule-4): Rs 136.89 crore

A.1.1.1. In the case of National Institute of Training for Standardization (NITS), a Computer Desktop amounting to Rs 55650 was purchased in June 2016,however the same was not capitalized. This has resulted in understatement of fixed assets as well as capital fund by the like amount.

Similarly, an inverter was purchased by NITS in March 2017 for Rs 13500. Though the asset was taken in fixed assets register, it was not accounted for in annual accounts. This has resulted in understatement of fixed assets as well as capital fund by the like amount.

B. General:

B.1 Sundry creditors towards TA/DA (Schedule 3) of Rs. 4445304 pertaining to the period 2007-08 to 2016-17, need to be settled/disposed at the earliest.

B.2 Schedule numbers are not in accordance with the Uniform Format of Accounts.

B.3 Advances amounting to Rs 9.07 crore were lying outstanding since 2005-06.

C. Grants-in-aid:

During 2016-17, BIS received Grants-in-aid of Rs. 117.82 lakh for Setting up of Hallmarking Centres from the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. It had Rs. 11.52 lakh as 'interest and other receipts' and unspent balance of Rs 924.15 lakh of the previous year. Out of total available amount of Rs.1053.49 lakh, a sum of Rs. 314.25 lakh was utilized during the year, leaving a balance of Rs. 739.24 lakh at the end of the year.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards as at 31 March 2017; and

In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the **'Nil'** balance for the year ended on that date.

For and on behalf of C& AG of India

Place: New Delhi
Date: 08.11.2017

Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

- Internal audit has been conducted by Chartered Accountant Firm up to March 2017.

2. Adequacy of Internal Control System

- Sundry creditors towards TA/DA (Schedule 3) of Rs. 4445304 pertaining to the period 2007-08 to 2016-17 was outstanding as of March 2017.
- Sundry Debtors amounting to Rs. 2.97 lakh were outstanding as of March 2017 which pertained to the period 2009-10 to 2013-14 in NITS.
- BIS (Ghaziabad branch) paid Rs. 90 as interest on delayed payment of Statutory dues . Similarly, Faridabad Branch office paid Rs. 527 as interest on service tax.
- LTC air travel was booked through private agents like 'ease my trip', goibibo', etc.
- Advance amounting to Rs 9.07 crore were lying outstanding since 2005-06.

In view of the above, the Internal control system of BIS needs to be strengthened.

3. System of Physical Verification of Assets

- The physical verification of fixed assets has been conducted upto March 2017.
- Physical verification of fixed assets of BIS NITS Noida has not been conducted for the year 2016-17. It was reported in physical verification of fixed assets (2015-16) that fixed assets (993 items) were not shown in the fixed assets register pertaining to BIS-NITS, Noida.

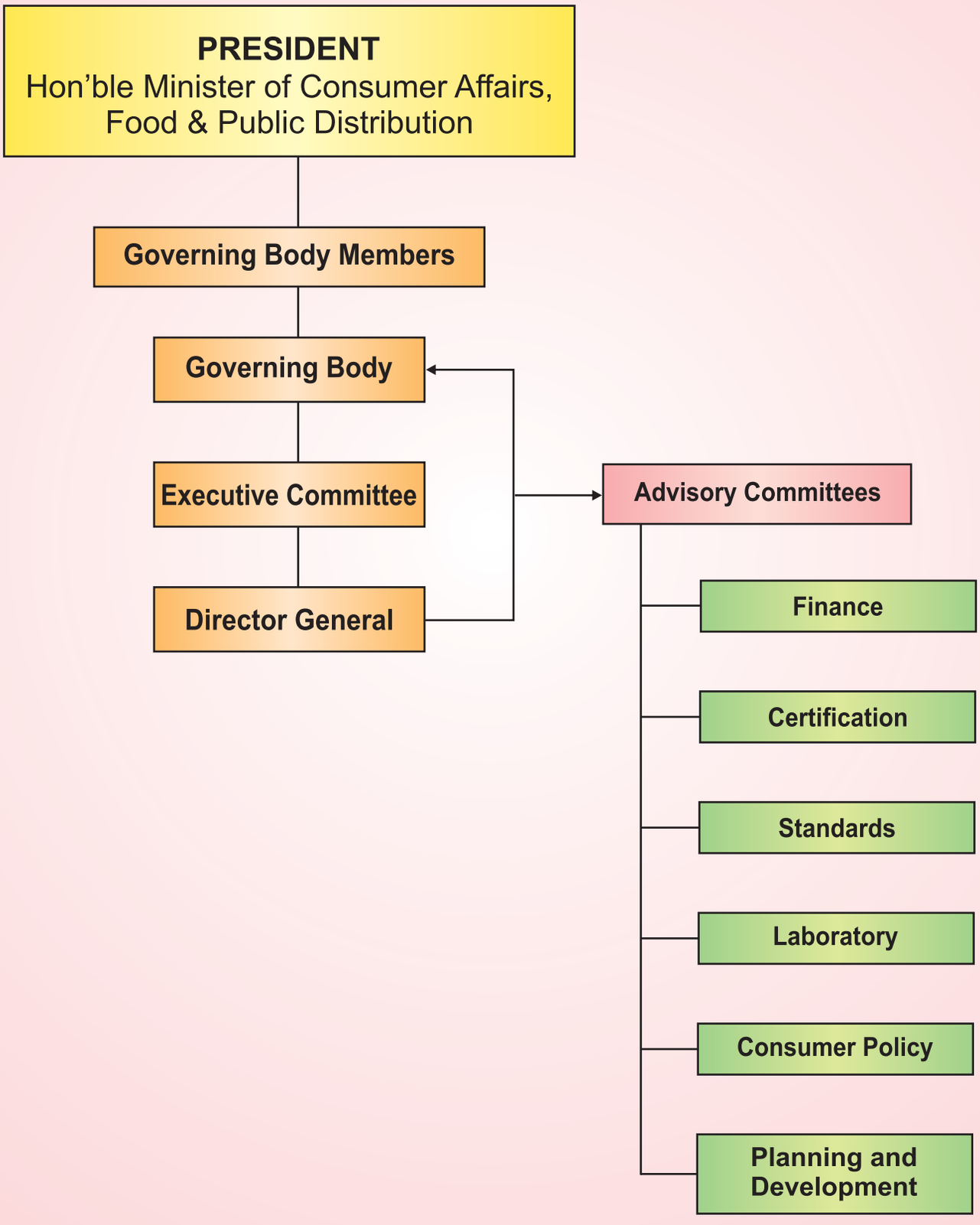
4. System of Physical Verification of Inventory

- Physical verification of inventory had been conducted upto March 2017.

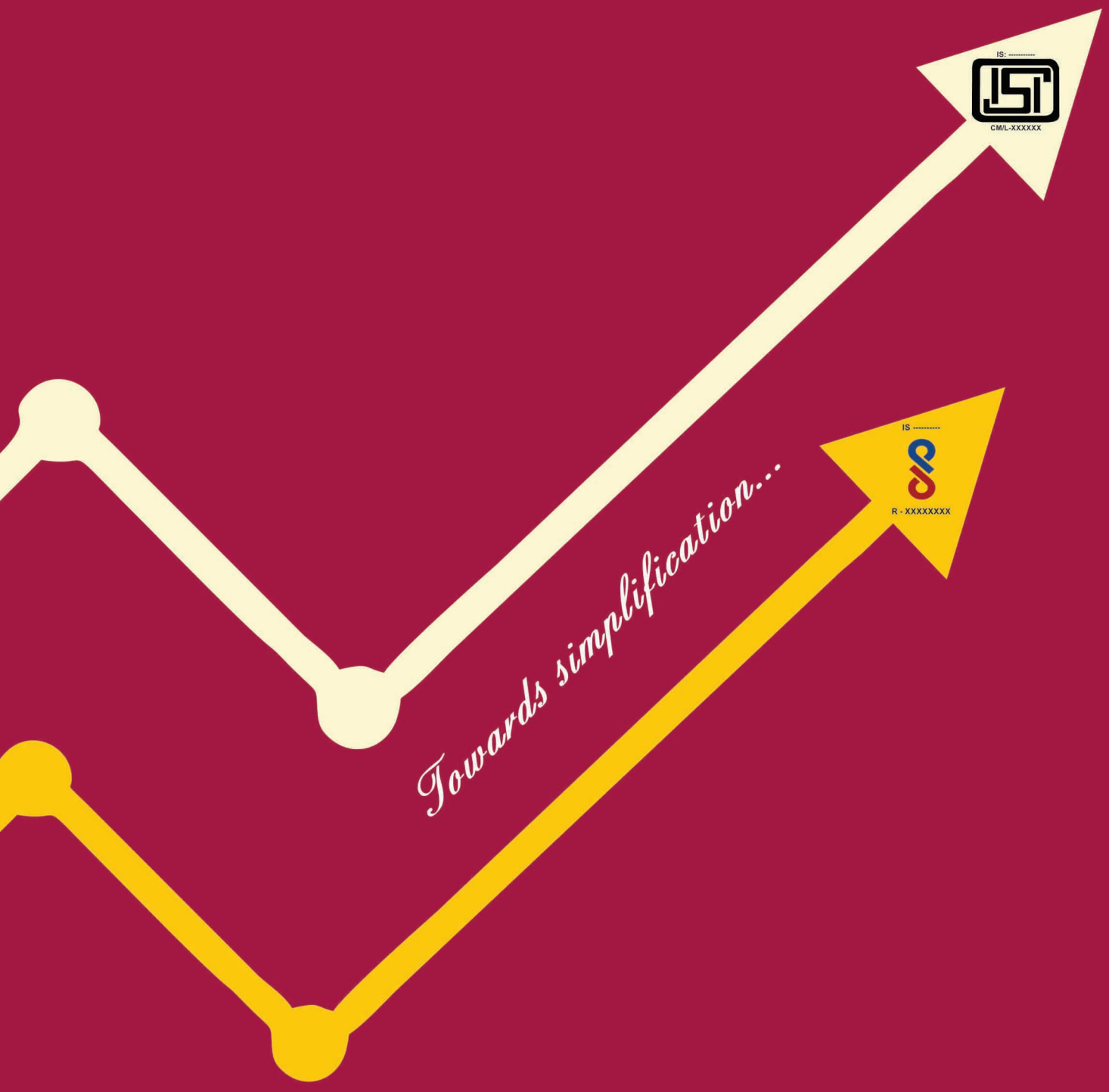
5. Regularity in Payment of Dues

- As per annual accounts of BIS, no Payment over six month in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2017.

STRUCTURE OF BIS




INDIA
BIS - LOCATIONS
Jammu
Parwanoo
Mohali
Chandigarh
Dehradun
Delhi
Ghaziabad
Noida
Faridabad
Jaipur
Lucknow
Patna
Guwahati
Ahmedabad
Durgapur
Jamshedpur
Kolkata
Bhopal
Rajkot
Nagpur
Raipur
Bhubaneshwar
Mumbai
Pune
Vishakhapatnam
Hyderabad
HEADQUARTERS
BRANCH OFFICES (33 IN 28 PLACES)
REGIONAL OFFICES (5)
LABORATORIES (8)
TRAINING INSTITUTE (NITS)
Bangalore
Chennai
Coimbatore
Kochi
NORTHERN REGION
CENTRAL REGION
EASTERN REGION
WESTERN REGION
SOUTHERN REGION



मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards
मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110 002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi–110 002
वेबसाईट / **Website:** www.bis.gov.in